छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

षोडश सत्र

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023

(फाल्गुन 23, शक सम्वत् 1944)

[अंक 07]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023

(फाल्गुन 23, शक सम्वत् 1944)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रणाम। आप बहुत जोरदार, स्मार्ट लग रहे हैं। you are looking smart.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है।

अध्यक्ष महोदय :- क्यों ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि माननीय अमितेश शुक्ल जी का पहली बार 5 नंबर में प्रश्न लगा है। वह प्रश्न पूछने के लिए सुबह 9 बजे से आकर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, स्वागत है। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- प्रश्नकाल में उनका प्रश्न लगा है। तैं गंभीर काहे हस ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, अध्यक्ष जी स्मार्ट लग रहे नहीं, स्मार्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर से तो स्मार्ट लग रहे हैं। मैं देख रहा हूं। वह बहुत खुश हैं, बाकी का तो आप जानेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप थोड़ा सा नजदीक तो आओ, कितने स्मार्ट हैं, आपको समझ में आ जायेगा। वह बहुत स्मार्ट हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आज अतिमेश जी के प्रश्न को आप व्यवस्था देकर एक नंबर में ले लीजिए। वह सुबह 9.00 बजे से आकर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ये व्यवस्था तो आप लोगों से चाहता हूं। अमितेश जी का प्रश्न आया है। उन्हें आप लोग पर्याप्त समय दें। चलिये, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शाला भवनों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 822) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास खंडों में संचालित कितने व कौन-कौन से प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय जर्जर एवं कितने विद्यालय अति जर्जर अवस्था में हैं ? कितने विद्यालय भवन विहीन है ? ऐसे विद्यालयों की विकासखंड वार विद्यालय के नाम सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश" क" अनुसार जर्जर या अति जर्जर होने के कारण कितने व कौन-कौन से विद्यालय की कक्षाएं अन्य शासकीय व अशासकीय भवनों में लगाई जा रही है? जानकारी देवें। **(ग)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने व कौन-कौन से हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का स्वयं का शाला भवन नहीं है । ऐसे स्कूलों की कक्षाएं कहां लग रही हैं? जानकारी प्रदान करें। **(घ)** प्रश्नांश "क" एवं "ग" अनुसार जर्जर भवन विहीन विद्यालय का भवन या अतिरिक्त कक्षों की निर्माण कब तक कर लिया जाएगा, जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(घ)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय जर्जर एवं अति जर्जर के संबंध में था। उसकी जानकारी मुझे मिल गई है। मैंने आगे यह प्रश्न किया था कि हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूल जो अति जर्जर हैं जिसमें दर्ज संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण उन स्कूलों में बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही है। खासकर हाईस्कूल भवन उपरवा में दर्ज संख्या 500 के करीब है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये भवन अतिशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शाला भवन के जर्जर, अति जर्जर होने के संबंध में हर विधान सभा सत्र में प्रश्न आता है और सबकी चिंता रहती है, आपकी भी चिंता रहती है। इसके साल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के शासकीय शाला भवनों की जर्जर स्थिति की मरम्मत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन योजना घोषित की है जिसका नाम मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना है। इस योजना के अंतर्गत बजट में

[1] परिशिष्ट "एक"

185 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान कर दिया है। आगामी वर्ष के बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरे प्रदेश में अभी तक 11,375 स्कूलों की मरम्मत की कार्य स्वीकृति हम लोगों ने कर दी है। सभी जिलों को निर्देश दिये गये हैं कि पूरे जिले की स्कूलों, भवनों का सर्वेक्षण करके जहां कहीं भी स्कूल भवन की मरम्मत की आवश्यकता हो तो प्राक्कलन सहित अपने प्रस्ताव तत्काल भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आगामी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व सभी मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जायेगा। माननीय आपके विधानसभा क्षेत्र में भवनविहीन 11, अति जर्जर 14, कुल 25 हैं। ये भवनविहीन एवं अति जर्जर 25 हैं, इनके बनने एवं मरम्मत करने का हमने आदेश जारी कर दिया है

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री रामकुमार यादव।

<u>चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं प्रदत्त सुविधा</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 775) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अन्तर्गत आदिम जाति विभाग द्वारा कौन-कौन से छात्रावास संचालित है? जानकारी देंवे। **(ख)** छात्रावासों में छात्र छात्राओं को क्या-क्या सुविधा प्रदाय की जाती है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु वर्ष 2021-22 से 31.1.2023 तक कितनी राशि दी गई है? पूर्ण विवरण देंवे। **(घ)** छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि विगत बार कब व कितनी की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** [2]अनुसार है। **(ख)** छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को आवास, भोजन, पलंग, कंबल, चादर, तकिया, मच्छरदानी, विशेष कोचिंग, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजनांतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, खाद्यान्न की सुविधा, दैनिक उपयोग में आने वाली उपयोगी वस्तुएं एवं मूलभूत सुविधा दी जाती है।**(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु वर्ष 2021-22 से 31.1.2023 तक दी गई राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(घ)** छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछे रहेंव कि मोर विधान सभा में जो छात्रावास में बच्चे रहथे, ओमा गरीब मन के लिए का-का सुविधा पहुंचथे ? ओकर जानकारी मोल देहे। मै एमा पूरक प्रश्न पूछना चाहत हवं। मोर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र हे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बहुतायत मन लोग उहां रहथे। लेकिन दुख के बात हे के वोहां के लिए बजट में एक भी छात्रावास नई मिले हे। मैं माननीय मंत्री जी से मोर इहां मैं छात्रावास के मांग करत हौं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा था कि उनके विधान सभा क्षेत्र में कितने छात्रावास संचालित हैं और वहां पर क्या-कया सुविधायें दी जाती हैं। मैंने परिशिष्ट में पूरी जानकारी दी है। इनके विधान सभा में करीब 14 छात्रावास संचालित हैं। छात्रावास में जितनी सीट है, वही पूरी नहीं भर पाती हैं। क्योंकि जिस छात्रावास में 50 सीट है, वहां पर कहीं 4 बच्चे, कहीं 15 बच्चे आ रहे हैं। जहां 20 सीट हैं वहां पर करीब 7 बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम छात्रावास खोलेंगे और उसमें बच्चे नहीं आयेंगे तो उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। फिर भी माननीय विधायक जी का ऐसा निवेदन है कि वहां छात्रावास खोला जाये, हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जो भी संभव हो सकता है, उसमें करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं कल मांग करे हव अउ मैं मुख्यमंत्री के सामने भी बात करे हव। माननीय मंत्री जी, मोर आपसे निवेदन हे कि आप घोषणा कर देवा कि अनुसूचित जाति के एक ठन जमगहन अउ अनुसूचित जनताति के एक ठन गिरगिरा में। का होथे। सब भला करही। पूरा प्रदेश देखथे। आपसे निवेदन हे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक से चर्चा कर लूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर लूंगा। जो संभव होगा, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चंदन कश्यप ।

<u>नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर एवं भवन-विहीन शालाओं हेतु भवन व अहाता निर्माण की स्वीकृति</u>

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 807) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है ? उन स्कूलों में कितने भवन विहीन, अति जर्जर, अहाता विहीन एवं शौचालय विहीन हैं ? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) विगत 3 वर्षों से 31 जनवरी, 2023 तक कितने

जर्जर/भवन विहीन शालाओं हेतु जीर्णोद्धार, मरम्मत या नवीन भवन एवं शौचालय, अहाता निर्माण की स्वीकृति मिली है ? उक्त कार्य कितने शालाओं में शेष हैं ? जिलेवार जानकारी देंवे।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में 777 शा.प्राथमिक, 266 पूर्व माध्यमिक, 27 हाई स्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी शालाएं है। शेषांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार**[3] है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्यो की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। शौचालय निर्माण शेष नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9-10/2021/20-एक, नवा रायपुर दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से फलदार/अन्य वृक्षारोपण के माध्यम से अहाता निर्माण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुक्रम में बाउण्ड्रीवाल हेतु पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। नवीन भवन निर्माण हेतु शेष शालाओं की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहा था कि प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है? उन स्कूलों में कितने भवन विहीन, कितने जर्जर हैं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भवन विहीन शाला एवं अति जर्जर शाला भवन निर्धारण का मापदण्ड क्या है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- किसका?

श्री चंदन कश्यप :- मंत्री जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि शाला विहीन और अति जर्जर का मापदण्ड क्या है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन जर्जर है, मतलब वह रिपेयर हो सकता है और जो अति जर्जर है, जो टूट सकता है, उसको डिसमेंटल कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग उसमें जो स्कूल जतन योजना बनाये हैं, उसमें सभी विधान सभा क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया है और उसमें प्राक्कलन सहित बुलाये हैं। माननीय विधायक जी के क्षेत्र में भवन विहीन शाला की संख्या 70 और अति जर्जर शाला की संख्या 5 है, कुल 75 है। उसमें ओरछा में 55 और नारायणपुर में 9, कोण्डागांव में 01 और बस्तर में 10 है। कुल 75 जगहों पर, जहां पर भवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जहां बच्चों की संख्या अधिक है, वहां पर अधिक कमरा बनायेंगे और जो भवन रिपेयर हो सकता है, मरम्मत हो सकता है, उसको मरम्मत करने के लिए हमने स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोण्डागांव जिला में आपने मात्र एक भवन वहीन बताये हैं, जबकि मैं होली के तुरंत बाद शनिवार, रविवार को उस क्षेत्र में गया था। उस क्षेत्र में 10 से अधिक भवन आज भी जर्जर हैं। मैं शायद फोटोग्राफी रख सकता हूं। आपको जो

[3] परिशिष्ट "तीन"

विभागीय जानकारी मिली है, वह गलत जानकारी दिया गया है। क्या विभागीय अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे और पुन: जानकारी मंगायेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में जो जानकारी है और मैंने सभी को निर्देश दिया है कि आपके जिले में जितने भी जर्जर भवन या मरम्मत योग्य भवन हैं, उसको एस्टीमेट सहित यहां पर भेजे। चूंकि मैंने अभी योजना बताई है, उसके साथ हम सभी को स्वीकृत करेंगे। जो आगामी शिक्षा सत्र शुरू होगा, उसके पहले वह रिपेयर भी हो जायेगा, मरम्मत भी हो जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा शिक्षा विभाग जर्जर है, सिर्फ भवन भर जर्जर थोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह तो आपके द्वारा ही किया गया है। आप ही तो उस समय शिक्षा मंत्री थे। पूरा जर्जर आपके तरफ से ही हुआ है। जब आप शिक्षा मंत्री थे, उस समय सारा स्कल भवन जर्जर था।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल तक इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, 4 साल में आपने क्या दिया, यह बता दीजिये?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 4 साल में हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 4 साल में स्वीकृत भी हुआ है और बनाये भी हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने 15 साल में जो बेड़ा गर्क किया है, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव का प्रश्न था, इसलिए मेरा एक पूरा प्रश्न है। प्रायमरी स्कूलों में जो अहाता विहीन हैं, जिसकी संख्या 57 बताया गया है। माननीय मंत्री जी, अहाता विहीन प्रायमरी स्कूलों को कब तक पूरा करेंगे? क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी चलती नहीं है तो क्यों पूछते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप उधर का जवाब दीजिये। अहाता विहीन स्कूलों के बारे में।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा सत्र में अहाता की, जर्जर भवनों की जब चर्चा हो रही थी तो आपने निर्देश दिया था कि जो आपके स्कूल भवन है, वह चूह रहे है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसको रिपेयर कर सकते हैं तो अहाता को उसमें अलग से स्वीकृत करेंगे। अभी फोकस इसमें है कि जो मरम्मत योग्य हैं, उसका मरम्मत करवायेंगे और जहां भवन बन सकता है वहां पर भवन बनायेंगे।

अध्यख महोदय :- धर्मजीत सिंह जी।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जो गलत जानकारी दिया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधानसभा में गलत जानकारी देते हैं, उसकी अलग प्रक्रिया है। प्रक्रिया में आयेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय :- छन्नी जी कुछ पूछना चाहती हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं, पूरे सदस्य, पूरे उम्मीद से अपने विधान सभा की, चाहे जर्जर स्कूल की बात हो, चाहे बाउण्ड्री वॉल की बात हो। हम लोग पूरा उम्मीद से यहां प्रश्न करते हैं ताकि अपने क्षेत्र का जर्जर स्कूल हैं, वह बनें। रही बात बाउण्ड्री की तो आपने बोल दिया कि बाउण्ड्री नहीं होगा, हम तार से फेंसिंग करेंगे। तो यह मौखिक में नहीं है। यदि ऐसा है तो एक लिखित आदेश हो ताकि हम अपने क्षेत्र में जाये तो बाउण्ड्री की मांग न करें ताकि जो तार की फेंसिंग बोल रहे हैं, वह हो जाए।

<u>जिला-मुंगेली, तहसील -लोरमी अंतर्गत ग्राम खुड़िया को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

4. (*क्र. 713) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या ग्राम खुड़िया, तहसील-लोरमी, जिला -मुंगेली वर्तमान में सिंचाई ग्राम है? (ख) क्या कंडिका "क" को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव लंबित है? यदि हां, तो कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जायेगा? विस्तृत विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम खुड़िया, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली सरकारी रिकार्ड में सिंचाई ग्राम दर्ज नहीं है। (ख) ग्राम खुड़िया का ।।I रूड़की द्वारा राजस्व सर्वेक्षण कराया जा रहा है। राजस्व सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार ग्राम खुड़िया को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई बहुत टेड़ा-मेढ़ा प्रश्न भी नहीं है है लेकिन मुझे जयसिंह अग्रवाल जी की कार्यप्रणाली पर बहुत विश्वास है क्योंकि वे अच्छा काम करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- दमदारी से ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां दमदारी से, तकलीफ भले पाते हैं । (हंसी) माननीय मंत्री जी, मैं आपको पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा दो मिनट बता दूं । चूंकि खुड़िया गांव जिसका मैंने प्रश्न पूछा है वहां सारे गांव वाले टेलीविजन के सामने अध्यक्ष जी के लाईव टेलीकास्ट को देख रहे हैं । सन् 2001 में 01 मई को खुड़िया के सिंचाई विभाग की 1000 एकड़ जमीन को माननीय अजीत जोगी जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी और माननीय सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्री प्रेमसाय सिंह जी इन तीनों की उपस्थिति

और मेरी उपस्थिति में उनको पट्टा दिया गया । आपने कह दिया कि वह सिंचाई ग्राम नहीं है । वह सिंचाई ग्राम भी नहीं है, वन ग्राम नहीं है, राजस्व ग्राम नहीं है तो आप पहले यह बताईये कि आपके रिकॉर्ड में यह कौन सा ग्राम है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने सिंचाई ग्राम का जिक्र किया तो आपने इसमें जो दिया है तो यह सिंचाई ग्राम नहीं है और राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये उसकी प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के हिसाब से इसको राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धर्मजीत सिंह जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ भी नहीं पाया कि कौन सा ग्राम है खैर छोड़िए ।

अध्यक्ष महोदय :- ये तीनों ग्राम में नहीं आते, वे मसाती में आती हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- खुड़िया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, वह सिंचाई ग्राम है । इनके यहां रिकॉर्ड में गलत जानकारी दिये हैं । खैर, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता । आपको राजस्व ग्राम करने के लिये बोलने का मेरा अपना उद्देश्य है । आपने लिखा है कि ॥T रूड़की द्वारा राजस्व सर्वेक्षण कराया जा रहा है तो यह राजस्व ग्राम बनाने के लिये ॥T रूड़की ही करता है क्या ? उससे आपने कब एग्रीमेंट किया ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने उसकी सर्वे रिपोर्ट देने के लिये कब तक का प्रावधान किया है और कब तक यह रिपोर्ट आयेगी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व सर्वेक्षण में जिला कलेक्टर को तकनीकी सहयोग के लिये ॥T रूड़की से उसको एजेंसी बनाया गया है । ॥T रूड़की से सहयोग लिया जाता है और उसका मैंने पहले भी बताया कि वह प्रक्रिया में है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी राजस्व ग्राम घोषित हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं फिर अमितेश जी का आ जायेगा । माननीय मंत्री जी उनको पट्टा तो 1000 एकड़ मिल चुका है। हमारे भूपेश बघेल जी राजस्व मंत्री थे, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं । 22 साल में उनको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलने के कारण न तो वे बैंक से कर्जा ले पा रहे हैं, न ट्यूबवेल खुदवा पा रहे हैं, न बॉरवेट वॉयर ले पा रहे हैं, न उनको फर्टिलाईजर मिलता है और उनके धान की बिक्री में भी कई अड़चनें आती हैं और राजस्व ग्राम के पट्टेधारी लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे वे वंचित हैं । वहां मछुआरे हैं, आदिवासी हैं, गोंड़ हैं, केंवट हैं यही लोग हैं तो इतनी धीमी गति से मत चलाईये । 22 साल हो गये हैं, मैं 22 साल में कम से कम 22 बार हर सत्र में इसी विधानसभा में इनकी भी सरकार में और आपकी भी सरकार में 4-4 बार बोल चुका हूं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- 15 साल तो आपके बगल वाले हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, मान लो कि वे थे तो अब आप तो 4 साल वाले हैं, थोड़ा चलिये न । ये तो थोड़ा बहुत चल भी लिये, आप तो सो रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- हम लोग 4 साल में बता तो रहे हैं कि प्रक्रिया में है, चल रहा है । ऊधर वाले कुछ नहीं किये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मुझे यह बताईये कि इसको राजस्व ग्राम कब तक घोषित करेंगे और करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको अगस्त से सितंबर तक राजस्व ग्राम घोषित कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी-जी । आपने क्या बोला ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इसको अगस्त से सितंबर तक राजस्व ग्राम घोषित कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अगस्त से सितंबर तक हो जायेगा । बिफोर इयर्स में ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप करियेगा । मैं माला रखकर आपको पहनाने आउंगा और आप उसको राजस्व ग्राम घोषित कर दीजिये क्योंकि गरीब लोगों का मामला है ।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, पहले पहनाना है तो अभी ही पहना दो न क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- जयसिंह जी, वह सड़क वाले गुलाब से माला नहीं पहनायेंगे । ओरिजनल डच रोज से आपको माला पहनायेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, वह तो सड़क वाले गुलाब में यह हुआ कि वह ढ़ाई किलोमीटर में एक बड़ी नेता चलीं । आप सुन तो लीजिये, उसमें कोई आपत्ति नहीं है । वह बढ़िया है । स्वागत करने का तरीका है । दूसरे दिन बयान आ गया कि इसका गुलाल बनाया जायेगा । इस साल होली में गुलाल की बिक्री कम हो गयी । बिक्री खत्म हो गयी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद । अच्छा, चलिये अमितेश जी का स्वागत किया जाये ।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय तथा छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (*क्र. 758) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 मैं दिनांक 31.1.2023 तक गरियाबंद जिला अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय तथा छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत कितने-

कितने दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? (ख) कंडिका ''क'' के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर) के नियमितिकरण के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं ? क्या शासन दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है ? नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका ''क'' के तहत अपात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। उल्लेखित अवधि में जिला अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत 90 दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि स्थापना में नियमित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) आकस्मिकता निधि नियमित वेतनमान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जी हां। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी का ब्लड प्रेशर भी नपवा लिया जाये । आपने एलोपैथिक कैम्प लगवाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- अमितेश जी का स्वागत है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी आपके साथ अन्याय हो रहा है । जवाब देने की जगह आपको प्रश्न करना पड़ रहा है इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी छात्रावास का यह बड़ा अत्यधिक गंभीर मामला है । कृपया मेरा आग्रह है कि आप लोग शांति से इसको सुनें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं जो बोल रहा हूं । आप मेरी बात समझ रहे हैं । जवाब देने वाले व्यक्ति को प्रश्न करना पड़ रहा है इससे दुर्भाग्यजनक घटना क्या होगी ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, वे शांति से इसको सुनें क्योंकि यह आदिवासी छात्रावास का अत्यधिक गंभीर मामला है । इसमें घपला हुआ है। बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे मंत्री जी, ये तो बेचारे सीधे और भले हैं। । इनको जो पूरक प्रश्न जो दिया गया है, उसमें सब गलत जानकारी दी गई है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि विपक्ष को बोलें कि ध्यानपूर्वक इनके प्रश्न को सुने और टोका-टाकी न करें। मेरा निवेदन है कि आप विपक्ष को निर्देश दें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इतने गंभीर-गंभीर मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल-बिल्कुल निर्देश है।

श्री अतितेश शुक्ल :- नहीं, वे टोका-टाकी क्या करते हैं। वे खुद ही टोका-टाकी करते हैं और खुद ही भ्रष्टाचार का लगातार हल्ला करते हैं और जब भ्रष्टाचार की बात करो तो खड़े हो जाते हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी को न छेड़ा जाए। ये कोई छेड़ने वाली चीज नहीं हैं। आप इन्हें क्यों छेड़ रहे हैं? जिनको छेड़ना चाहिए, आप उन्हें छेड़ते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं। आप दोनों निपटते रहिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रश्न करना चाहता हूं कि यहां पर मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक गरियाबंद जिला अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय तथा छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत कितने-कितने दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया गया है? इसका जवाब आया है कि प्रश्नाधीन अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री अमितेश शुक्ल :- यही जवाब गलत दे दिया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें नियमितीकरण किया गया है या नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने जवाब में तो दिया है न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अमितेश शुक्ल :- जवाब में जो दिया गया है, नियमित नहीं किया गया है, उसका मेरे पास 28/02/2022 का आदेश है। पूरा नियमितीकरण किया गया है। पूरा उसमें 90 लोगों को किया गया है। उसमें लगातार भ्रष्टाचार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे बैच के श्री सोमलाल नेताम दैनिक वेतनभोगी जो साढ़े 4 साल तक गायब था, उसको उन्होंने पैसा खाकर फिर से उसका नियमितीकरण कर दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर आरोप है कि पैसा खाके। सत्तारूढ़ दल का विधायक आरोप लगा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- जांच भी होनी चाहिए और जो असिस्टेंट कमिश्नर दोषी पाया गया है, उसे निलंबित भी करना चाहिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इन्हें बोलिए कि ये बार-बार डिस्टर्ब न करें। बार-बार इन्हें परेशान करते हैं। प्रश्न में इन्हें डिस्टर्ब करते हैं।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिले में 80 छात्रावास आश्रम हैं। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता स्थापना की स्वीकृति 277 स्वीकृत पद 233 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं और रिक्त पद के विरूद्ध दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर 90 कर्मचारियों को आकस्मिकता

निधि स्थापना में समाहित किया गया है। उसे नियमित नहीं किया गया है। उसके बाद जिसकी 10 साल से अधिक की सेवा होगी, तो फिर उसमें उसके नियमितीकरण करने की पात्रता बनती है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं, उन्हें जो नियमित किया जाता है, वे चतुर्थ श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं न?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आते हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- आते हैं तो फिर आपने कैसे लिख दिया है कि प्रश्नाधीन अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। जबकि मेरे पास आदेश है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अमितेश शुक्ल :- जब आप बोल रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी के लोग नियमितीकण में यहां पर जो आये हैं, चतुर्थ श्रेणी के लोग इसमें आते हैं तो फिर आपने किस तरीके से बोल दिया कि ये नियमितीकरण में नहीं हुआ है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ये कर्मचारियों का जो कलेक्टर दर पर रहते हैं, उसके बाद फिर आकस्मिकता निधि से उसकी स्थापना होती है, लेकिन इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि जो 4 साल से..।

श्री अमितेश शुक्ल :- साढ़े 4 साल से।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- साढ़े 4 साल से बाहर रहा, अगर उसकी उसमें कोई नियुक्ति की है तो मैं इसमें जांच भी करा लूंगा।

श्री अमितेश शुक्ल :- असिस्टेंट कमिश्नर को निलंबित कीजिए। माननीय मंत्री जी, एकाध उदाहरण पेश करिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं इसमें सहायक आयुक्त को निलंबित करता हूं।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप निलंबित करिए, जिससे भ्रष्टाचार का लगातार आरोप न लगा सके।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं जांच भी कराउंगा और जो सहायक आयुक्त है, उसे निलंबित करता हूं।

श्री अमितेश शुक्ल :- धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो पैसा खाने का आरोप लगा है, अध्यक्ष महोदय, गंभीर बात है। निलंबित क्यों करेंगे? सदन की समिति से जांच करवाइए। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- निलंबित कर दिया और क्या करेंगे। मंत्री जी ने निलंबित कर दिया। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका हल हो गया न?

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पूरक प्रश्न पूछना प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय धर्मजीत भैय्या जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप या तो उनके घर चाय पीने चले जायें या उन्हें चाय पीने बुला लेते। सदन में इतना टाइम नहीं लगता। खुद ही हल कर लेना था।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, वे आगे-पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते।

श्री अमितेश शुक्ल :- इसलिए इन्होंने सदन में घोषणा की। आप लोगों के लगातार आरोप रहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहता है, उसका उन्होंने जवाब दिया।

अध्यक्ष महोदय :- गजब।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर का 2012-13 का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या ? गरियाबंद का चल रहा है, बस्तर कहां से आएगा ?

श्री राजमन बेंजाम :- इसी से संबंधित है ।

श्री मोहन मरकाम :- इसी से संबंधित है, अनुमति दीजिए अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री राजमन बेंजाम :- 2012 से लेकर 2013-14 तक 276 लोगों की भर्ती की गई है । उनकी भर्ती शासन के किस आदेश के तहत् की गई है और आज उनका निष्कासन हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2013-14 में शासन के किस नियम के तहत् भर्ती की गई थी और अभी उनको क्यों निकाला गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल गरियाबंद जिले का है, उद्भूत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास अभी जवाब नहीं है, ऑफिस में जाकर दे दीजिएगा ।

श्री राजमन बेंजाम :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उनको 276 चपरासियों को वापस लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्नकाल के बाद मंत्री जी के कक्ष में चले जाइएगा और उनको एक दरख्वास्त दे दीजिएगा, वे करा देंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, 276 लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । पहले उनको किस आदेश के तहत् भर्ती किया गया और अब उनको निकाला जाता है । वे कहीं न कहीं पसोपेश में हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया है कि माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आ जाएं, मैं देख लूंगा उसमें क्या हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- सहानुभूतिपूर्वक विचार करना है उसमें ।

<u>सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति संबंधित</u>

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 591) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति हेतु विगत 03 वर्षो में विभाग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है? वेतन विसंगति दूर करने के लिये कब-कब,कौन सी समिति का गठन किया गया था तथा उनको रिर्पोट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या-क्या थी? **(ख)** क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है? यदि हां तो रिपोर्ट में क्या-क्या बातें कही गयी है तथा समिति में कौन -कौन अध्यक्ष, सदस्य थे? **(ग)** आदेश क्रमांक/एफ 12-17/2018/20-2 अटल नगर, दिनांक 07/03/2019 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है? **(घ)** क्या घोषणा पत्र में 1998 से कार्यरत शिक्षकर्मी वर्ग - 03 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गयी थी? यदि हां तो क्या उक्त घोषणा पूर्ण कर दी गयी है? यदि नहीं की गयी तो कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क) छ.ग.**शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 9-31/2021/1/5 नवा रायपुर, दिनांक 16.09.2021 द्वारा सहायक शिक्षकों की वेतनमान में विसंगति के परीक्षण हेतु अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है । समय-सीमा तीन माह थी । (ख) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । समिति गठन निम्नानुसार किया गया :-

01. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग - अध्यक्ष
02. सचिव, छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग-3 - सदस्य
03. संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन वित्त विभाग - सदस्य

(ग) जी हां । (घ) जी हां । शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आज संशोधन के साथ उत्तर दिया है । इस उत्तर में ही विरोधाभास है, चार प्रश्न है मेरे । एक में आपने समिति का गठन किया जाना स्वीकार किया है और तीन महीने का समय दिया है कि समिति तीन महीने में रिपोर्ट देगी । समिति 16.09.2021 को गठित हुई है और आज पर्यन्त इस समिति की रिपोर्ट नहीं आई है । दूसरी तरफ मैंने (ग) में पूछा है कि 07.03.2019 के बिंदु क्रमांक 3 में उल्लेखित क्रमोन्नति/समयमान पर

क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई । उसके जवाब में "जी हां" लिखा है । (घ) के जवाब में लिखा है कि शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है । अध्यक्ष जी, शिक्षा कर्मियों का पहला संविलियन 2018 में हुआ । 2018 में संविलियन के बाद जब शिक्षा कर्मी हड़ताल पर गए तो माननीय भूपेश बघेल जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय वे वहां गए और उनका भाषण हुआ था, राज्य सरकार के वर्तमान फैसले से सभी वर्गों को लाभ नहीं मिलेगा । इसमें सिर्फ वर्ग-1 और वर्ग-2 को ही लाभ मिलेगा । वर्ग-3 अब भी विसंगति से जूझ रहा है । पीसीसी चीफ ने कहा कि शिक्षा कर्मियों में सरकार के फैसले को लेकर नाराजगी है । संविलियन और वेतनमान का लाभ सभी शिक्षा कर्मियों को नहीं होगा । उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया था कि हम वेतन विसंगति दूर करने के लिए कार्य करेंगे । आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 16.09.2021 को आपने समिति गठित की । रिपोर्ट आई नहीं और आपने लिख दिया कि शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है । वेतन विसंगति है क्या, आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ? पहले आप मुझे बता दीजिए कि वेतन विसंगति क्या है ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपने समझ लिया है क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- क्या है इसमें बताइए तो । क्या है ? वेतन विसंगति क्या है यह बता दीजिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस बात के लिए आपने कमेटी बनाई है । आपने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कमेटी बनाई है ना ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बनाई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने वेतन विसंगति को क्या समझा, पहले यह तो स्पष्ट करो कि किस प्रकार की वेतन विसंगति थी, जिसके लिए आपको समिति बनाने की आवश्यकता पड़ी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसीलिए तो कमेटी बनाई है । कमेटी की बैठकें होंगी । इसमें कई लोग हैं । इसमें शिक्षा विभाग के लोग रहेंगे, इसमें वित्त विभाग के लोग रहेंगे, इसमें जी.ए.डी. के लोग रहेंगे । जब इनकी बैठक होगी तब तो कुछ हल निकलेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आप स्वयं उत्तर देख लीजिए । उत्तर में आपने लिखा है कि वेतन विसंगति दूर करने के लिए आपने प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति बनाई है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आई नहीं है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- समिति तो बनी है ना, इसमें शंका किस बात की है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- रिपोर्ट के लिए आपने 3 महीने का समय निर्धारित किया है ना ।

श्री अमितेश शुक्ल :- इसके लिए तो आपको धन्यवाद् देना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया है और 18 महीने हो गये । आपने लिखित में तीन महीने का समय निर्धारित किया है और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई है । मैं आपसे प्रश्न यह कह रहा हूं कि वेतन विसंगति क्या है जिसके लिए आपको समिति गठित करनी पड़ी ? किन-किन बिंदुओं पर बात करने के लिए समिति गठित की गई थी, उन बिंदुओं को बता दीजिए ? उस समिति को जांच के लिए कौन-कौन से बिंदु दिए गए थे ? समिति की रिपोर्ट नहीं आई, उसके पीछे क्या कारण हैं और लेट होने के लिए आप दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- वेतन विसंगति के लिए आपके जितने भी मुद्दे हैं, उसमें क्या-क्या हो सकता है, इसीलिए तो कमेटी बनाई गयी है। जो कमेटी बनाई गयी है, (व्यवधान) अगर कमेटी समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं देती है तो उस कमेटी के समय को बढ़ा सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने वही बिन्दु पूछा है। आपने वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो समिति बनाई, उस समिति को किन-किन बिंदुओं पर विचार करना था। आपने कौन-कौन से बिंदु तय किये थे, आप मेरे को यह बता दीजिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वेतन विसंगति के संबंध में एक कमेटी बनी हुई है, समिति उसमें विचार करेगी। अगर वह समय पर नहीं हो पाया तो उसमें समय वृद्धि के लिए भी निवेदन किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत प्वाईंटेड प्रश्न किया है। आप समिति बनाना स्वीकार कर रहे हैं, आप बिंदु बताईए।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, शर्मा जी जानना चाहते हैं कि किन-किन बिंदुओं पर परीक्षण होगा ? आपने कोई बिंदु निर्धारित किया है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेतन विसंगति के संबंध में उसमें जो भी बिंदु होंगे उसी में तो विचार होगा। अभी तो वह बिंदु पता नहीं है। यह समिति तय करेगी कि कौन-कौन से बिंदु होंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कब तक करेंगे, घोषणा तो कर दीजिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, क्या आप मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप दूसरा प्रश्न करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी बिंदु नहीं बता पा रहे हैं कि समिति को किन-किन बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, पहले बिंदु तो बता दें तब हमारा अगला प्रश्न होगा। दूसरी बात, आपने

तीन महीने का समय निर्धारित किया और समिति को गठित किए 18 महीना हो गया, 18 महीने में रिपोर्ट नहीं आई, उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- समय हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- कार्यकाल तो बढ़ता रहता है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति अगर समय पर रिपोर्ट नहीं देती है तो उसका कार्यकाल बढ़ायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने समिति का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश कब दिया है यह बता दीजिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शर्मा जी, एक मिनट उत्तर तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- सुन लीजिए, सुन लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- समिति के समक्ष जो भी फेडरेशन के पदाधिकारी होते हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनका क्या कहना है, उनकी बातों को भी सुनेंगे, उसके बाद उस पर फैसला करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ना, वह पूछ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मेरे प्रश्न का तो उत्तर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- भाई, उनको भी तो पूछ लेने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। लगभग एक लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कब तक करेंगे यह तो बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इतना स्पष्ट उत्तर दिया है, समिति बन गयी है, समिति की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई होगी, समिति का कार्यकाल हो गया तो समय आगे बढ़ेगा, उसमें क्या है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, उनको उलझाइये मत।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरजीत जी, यह साबित कर रहे हैं कि मंत्री अक्षम हैं और वे सक्षम हैं। आप स्वीकार कर लीजिए और अमरजीत जी उत्तर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल अच्छा चल रहा है तो यह बार-बार टोकने की क्या जरूरत है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी तो उत्तर दे ही रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, सक्षम और अक्षम की कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान) अनावश्यक तिल का ताड़ दे रहे हैं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद बात होगी। समिति गठन हुई है।

समिति उसी बिंदुओं में परीक्षण करेगी। यह सक्षम और अक्षम की बात कहां से आ गयी ? हमारे मंत्री जी ने कौन से अक्षम किया। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शिवरतन शर्मा जी का प्रश्न है, उसमें आप खड़ा हो गये। क्या शिवरतन शर्मा जी पूछने में अक्षम हैं ? उसमें आप खड़ा हो गये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रश्नकाल में मंत्री जी व्यवधान कर रहे हैं। (व्यवधान) वह तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं। (व्यवधान) मैं तो आपके बोल रहा हूं, आपके प्रश्न में आपकी सक्षमता खत्म हो जाती है। (व्यवधान) यह व्यवधान करना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिए हो गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि समिति की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद हम चर्चा करेंगे। यह बात कहां से आ गयी। यह अक्षमता की बात कहां से आ गयी ?

श्री रामकुमार यादव :- तुहीं मन के जमाना के गड़बड़ करे हव।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो प्रश्न किए, मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पूछ तो रहा हूं, मैं उन्हीं को पूछ रहा हूं। बिंदु निर्धारित किया गया था क्या कि किन-किन प्रश्नों से जवाब लिया जाएगा या जांच किया जाएगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षकों की वेतन विसंगतियां हैं, यह अंतर्विभागीय समिति गठन किया गया है। उसमें प्रमुख सचिव, शिक्षा सचिव।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह तो उत्तर में लिखा है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो कमेटी हो गयी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सचिव, सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त विभाग। यह सबसे मिला जुला है, समिति के समक्ष फेडरेशन के पदाधिकारी को भी अपने पक्ष रखने का अवसर रहेगा। उनकी क्या मांग है, किस प्रकार की वेतन विसंगतियों हैं ? उसी में तो चर्चा होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप मुझे यह बताईए कि उसमें एकात बैठक हुई है या नहीं ? क्या उस समिति में एक दो बैठक हो गयी है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी, उसमें एक बैठक हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- एक बैठक हो गयी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, तीन महीने में रिपोर्ट आनी थी, 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आई।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने पूछा कि कौन-कौन से बिंदु निर्धारित थे, उसका उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- बिंदु तय नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब मैं मंत्री जी से तीसरा प्रश्न कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- तीसरा प्रश्न कर लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

(माननीय सदस्य (श्री अजय चंद्राकर) द्वारा हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न जो जाए, उसके बाद आपको अवसर देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैं तीसरा प्रश्न कर रहा हूं। मेरे 'ग' के उत्तर में इन्होंने स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गयी है। शिक्षाकर्मियों का संविलियन पहले 2018 में हो चुका था। उसके बाद जन घोषणा पत्र जारी हुआ। जब शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो गया था तो जन घोषणा पत्र में इस विषय को लेने के पीछे क्या कारण था ? क्या आपने अपने जन घोषण पत्र में गलत बात लिखी थी ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षाकर्मियों का संविलियन हमारी सरकार के आने के बाद हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप समय को बर्बाद मत कीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप क्या बात करते हैं ? वर्ष 2018 में शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका था। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने क्या किया था ? आपने तो गौरेकला के लोगों को संविलियन की मांग करने पर डंडा मारा था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, भगत जी। चलिये, आप बताइये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी का प्रश्न (घ) यह है कि क्या घोषणा पत्र वर्ष 1998 में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग-3 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गयी थी ? यदि हां तो क्या उक्त घोषणा पूर्ण कर दी गयी है ? मैं कहा कि जी हां, उस समय यह बात कही गयी थी। अब चूंकि शिक्षाकर्मी का संविलियन सहायक शिक्षक में नियमित हो गया है तो यह प्रश्न इसमें नहीं आता है। इसमें जो क्रमोन्नति उनको मिलनी चाहिए, वह सहायक शिक्षकों को मिलेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है इसमें एक।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- शर्मा जी, आप इनकी कितनी भी वकालत कर लें, इनका वोट आपको नहीं मिलेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है कि आप घण्टे तक जवाब दे चुके हैं। आपके शिक्षा विभाग में एक घण्टे तक प्रश्न चला है इसलिए आप ध्यान से सुनिये क्योंकि अभी 10 मिनट ही हुए हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप पूरा एक घण्टा निकाल दिये लेकिन आप बोल नहीं पाये।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनका प्रश्न 1 घण्टे तक नहीं चला था, इनके पहले वाले का प्रश्न 1 घण्टे तक चला था ताकि इनका प्रश्न न आये। मामला यह था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर है कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन होने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- इस बात को आप 4 बार कह चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको प्रश्न करने भी नहीं आता है। आप इनको प्रश्न करना सिखा दीजिए। इधर-उधर कर रहे हैं। इनको क्या प्रश्न करना है, उसको आप सिखा दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब आप मुझे सिखाएंगे ? आप मुझे प्रश्न करना सिखाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- आप थोड़ा ठीक-ठाक प्रश्न करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, मैं आपसे पहले विधायक बना हूं। आप मुझे प्रश्न करना मत सिखाइये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अमरजीत भगत :- आप प्रश्न तो ठीक-ठाक करिये ताकि उसका उत्तर आये। आप उसी जगह पर अटक गये हैं। काम तो आना चाहिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप मेरे प्रश्न में तो प्रश्न पूछ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, प्लीज। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप केवल 20 रूपये में ध्यान दीजिए। आप केवल 20 रूपये में...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हमें आपका दर्द मालूम है। मुझे आपका दर्द अच्छी तरह से मालूम है।

श्री शिवरतन शर्मा :- लेकिन मुझे कहीं कोई दर्द होता ही नहीं है। मैं सब दर्द से निपटना जानता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपको बता रहा हूं। मुझे आपका दर्द मालूम है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मर्द को दर्द नहीं होता है। अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्लीज। आप बैठने दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल को बाधित करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको यह कैसे मालूम है कि उनका धर्म यह है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको प्रश्न करने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दिनांक 07.03.2019 को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र है और इन्होंने पत्र में लिखा है कि चूंकि वर्तमान में पदोन्नति नहीं दी जा सकती है अत: पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची के आधार पर यथा आवश्यक क्रमोन्नति समयमान, वेतमान की कार्रवाई तत्काल करें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह दिनांक 07.03.2019 का शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पत्र है और आप यह कह रहे हैं कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण से ऐसा हुआ है। इसमें 2 वर्ष वाले शिक्षाकर्मियों का भी संविलियन हुआ, 6 वर्ष वालों का भी संविलियन हुआ और 8 वर्ष वालों का भी संविलियन हुआ तो जो 6 और 8 वर्ष वले शिक्षाकर्मियों का संविलियन हुआ, उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ? आप स्वयं इसे स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको शिक्षा विभाग और बाकी विभागों के सचिवों का भी पत्र पढ़ कर बता देता हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान, वेतनमान यह सतत् प्रक्रिया है। जैसे-जैसे ये सब पात्र होते जाते हैं उसमें उनको ये सब मिलता जाएगा। अभी आप जो बात बोल रहे हैं कि अभी तक शिक्षा विभाग में 13,393 कर्मचारियों को समयमान और क्रमोन्नति का लाभ मिला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं सझता हूं कि आप उनको जाकर समझा दीजिए। इमसें बहुत लंबी चर्चा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनको केवल एक ही चीज समझ में आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहला प्रश्न यह किया था कि वेतन विसंगति क्या है ? आप मेरे उस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कौशिक साहब के प्रश्नों का भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद उनका प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- न पीछे का उत्तर दे पाये। यह बैठक में क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर भी नहीं दे पाये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है। शर्मा जी, जब मैंने यह बता दिया है कि उस कमेटी में कर्मचारी के लोग भी आएंगे। उस कमेटी में चर्चा होगी तभी तो यह बन पाएगा। इसमें हम क्या करें ? इसमें दिक्कतें हैं। इसमें सबका समाधान किया जाएगा। शर्मा जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में यह जो वेतन विसंगति का मामला है इसमें मूल विषय यह है कि इसमें व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों के वेतनमान में अंतर है और इस विषय में यह सरकार को कार्रवाई नहीं कर रही है। जन घोषणा पत्र में इस विसंगति को दूर करने का उल्लेख किया गया है और अब यह इससे पीछे हट रहे हैं। यह सरकार 1 लाख शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को धोखा दे रही है। 1 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें कोई समय-सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आधे घंटे की चर्चा के लिए समय ले लीजिए और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप अन्यथा न लें तो बोलूं ?

अध्यक्ष महोदय :- हां, बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने पहले भी कई बार आधे-आधे घंटे की चर्चा की बात की है, पर एक बार भी आधे घंटे की चर्चा नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- आधे घंटे की चर्चा करा देते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज लिखकर दे देता हूं, आप समय निर्धारित कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- लिखकर दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज लिखकर दे देता हूं, पर निवेदन है कि इसी सत्र में उस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- इस सत्र में आप समय दिलाओगे तो कर देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो आपके ऊपर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग इधर से नहीं जाओगे और समय रहेगा, तब चर्चा करा देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारण तो आसंदी को करना है । मैं आज ही लिखकर दे देता हूं, आप चर्चा करा लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय चन्द्राकर जी, संक्षिप्त में पूछिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एकदम लिमिटेड रहेगा, एक मिनट में पूछूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रशासन में मंत्री रहे हैं, अन्य पदों पर भी रहे हैं। प्रेमसाय जी भी वरिष्ठ मंत्री हैं । कोई समिति बनती है तो उसका उद्देश्य रहता है कि यह काम इतनी अवधि में करेंगे । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि कर्मचारी फेडरेशन से बात करेंगे । उन्होंने केवल इतना ही बताया । क्या उसके उद्देश्यों में सिर्फ फेडरेशन से बात करेंगे, केवल यह बात है या कोई उद्देश्य नहीं है, आदेश में कुछ नहीं लिखा गया है, यह बता देंगे । मैं उससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। तीसरा-माननीय शिवरतन जी ने भाग-ग में प्रश्न किया है कि आदेश क्रमांक एफ 12-17/2018/20-2 दिनांक 07/03/2019 के बिन्दु क्रमांक 03 में समयमान वेतनमान में क्या विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है ? इसमें मंत्री जी ने "जी हां" उत्तर दिया है । क्या कार्यवाही की गई है, वह बता दें । दूसरा, मंत्री जी यह बता रहे हैं कि संविलियन हो जाने के कारण वह नियम निष्प्रभावी हो गया । मैं जानना चाहता हूं कि इनका संविलियन कौन से पद में किया गया और आपने "जी हां" कहा है तो क्या कार्यवाही की गई है, यह बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न छोटा जरूर है, मगर बहुत विस्तृत है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, एकदम छोटा है । मंत्री जी ने जी हां कहा है तो क्या कार्यवाही की गई है, वह बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बता सकते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- और संविलियन कौन से पद में किया गया है, यह बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में आधे घंटे की चर्चा मांग रहे हैं, उसमें पूछ लीजिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह यह है कि पहले भी आसंदी से आदेश दिया गया है कि माननीय मंत्रिगण तैयारी से आयें । तैयारी से नहीं आने के कारण अनावश्यक रूप से सदन का समय जाया होता है । आप आसंदी से सारे मंत्रियों को यह आदेश करें ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न जरूरत से ज्यादा आ गया है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको पूरा सदन देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कितना अच्छा उत्तर आ रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप एक मिनट बैठ जाईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप गलत समर्थन के लिए क्यों खड़े होते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान् जी, मेरी बात सुन लीजिए । आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं । मंत्री जी समिति का बिन्दु तो बता नहीं पा रहे हैं और आपको उत्तर अच्छा लग रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मंत्री जी जैसे ही पढ़ने लगते हैं, आप दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने पहले ही प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर से प्रश्न पूछ लेते हैं । समिति का उद्देश्य बता दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी बिन्दु बता दें, एक ही प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वापस वही प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रश्न रिवर्ट कर लेते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- किन-किन बिन्दुओं में समिति गठित की गई है, मंत्री जी वही बता दें ।

(श्री ननकीराम कंवर के खड़े होने पर)

श्री रविन्द्र चौबे :- भाटो, तै बैठ तो । माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पूरा उत्तर पढ़ रहे हैं । आप इजाजत देंगे तो मीटिंग का एजेंडा तीन-चार पन्ने का है, मंत्री जी उसको भी पूरा पढ़कर सुना देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हो गई ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हो गई न ? तो अब उसमें आगे बढ़िए ।

अध्यक्ष महोदय :- आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हो गई है इसलिए इसमें बाद में चर्चा होगी । माननीय धरमलाल जी कौशिक, अपना प्रश्न करें ।

<u>स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषणाओं पर कृत कार्यवाही</u>

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 725) श्री धरम लाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- आत्मसात किए गए जनघोषणा-पत्र 2018 में क्या बंद स्कूलों को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई थी? प्रदेश में जनवरी, 2019 से दिनांक 31.1.2023 तक कितने नक्सल प्रभावित बंद स्कूलों को प्रारंभ किया गया है ? इसमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कितने बंद स्कूलों को चालू करने की योजना है ? वर्षवार, जिलेवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं । प्रश्नाधीन अवधि में 275 बंद स्कूलों को प्रारंभ किया गया है तथा इनमें 185 शिक्षक कार्यरत् हैं। वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है और प्रश्न में संशोधित जो मैंने ऑनलाईन निकाला है, उसमें कहा गया है कि संशोधित किया गया है । यह जो संशोधित किया गया है, उसमें मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसमें संशोधन में केवल तारीख बदली है । प्रश्न यह है कि उक्त अवधि में केवल 31.1.23 ही बदला हुआ है और संशोधन के बाद में जो प्रिंट हुआ है तो उसमें सिर को अलग कर दिया गया है और धड़ अलग हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रिंटिंग मिस्टेक होगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मतलब प्रश्न करने का औचित्य खतम हो गया। उसकी आत्मा को ही निकाल दिया । मेरा यह कहना है कि ऑनलाईन जो हमारी व्यवस्था है, ऑनलाईन में मेरे पास में उत्तर है और प्रिंट में जो प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें अंतर है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- प्रिंट का जो प्रश्न है और यह जो ऑनलाईन है तो मैं चाहता हूं कि अभी सत्र खतम होने में समय है, इस प्रश्न को अगली तिथि के लिए बढ़ा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । शैलेश पांडे जी ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, आप समय तय करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न। बाद में देख लेंगे । अगर प्रिंटिंग में उत्तर गलत आया है और यहां का जो ऑनलाईन है, उस उत्तर में विरोधाभाष है तो उसको हम सचिवालयीन कर्मचारियों से भी तय कराएंगे और आपका उत्तर किसी दूसरे दिन के लिए रख देंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक, दो प्रश्न पूछ लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब उसकी चर्चा नहीं होगी । हो गया ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धरम भैया, आप इतने नि:सहाय कैसे हो गए ?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। आपका प्रश्न बाद में देख लेंगे। यदि प्रिटिंग में उत्तर गलत आया है तो यहां जो आनलाईन व्यवस्था है, उस उत्तर में विरोधाभास है तो हम सचिवालयीन कर्मचारियों से भी तय करायेंगे और आपका उत्तर किसी दूसरे दिन के लिए रख देंगे। श्री शैलेश पाण्डे।

श्री अमरजीत भगत:- धरम भईया, आप इतना नि:सहाय कैसे हो गये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं कोई नि:सहाय जैसा नहीं हूं। जैसे डॉ. प्रेमसाय सिंह को आपकी जरूरत है, वैसे मेरे साथ बहुत साथी हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके का आगे का और बता देता हूं। मैंने 4 प्रश्न लगाया था। उसमें एक में संशोधित प्रश्न आ गया, एक अग्राह्य हो गया, वह भी ठीक है। एक राजस्व विभाग का प्रश्न है, वह प्रिंट ही नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- वह ठीक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मेरा आज का ही दूसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या-40 है। तीसरा, जो मैंने पूछा नहीं है, विद्यामितान (अतिथि शिक्षक) का नियमितिकरण विषय पर प्रश्नकर्ता नाम में श्री धरमलाल कौशिक, श्री डमरूधर पुजारी, श्री विद्यारतन भसीन, श्री नारायण चंदेल, यह तो ध्यानाकर्षण हो गया। मुझे लगता है कि जो आनलाईन व्यवस्था है, उसको समाप्त कर देना चाहिए, यह मैं आपसे मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हम ऑनलाईन व्यवस्था को ठीक करवायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं तो, जो ऑनलाईन व्यवस्था है, जब हम इसमें निकाल रहे हैं तो ऑनलाईन में है, प्रिंट में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न, हम उसकी ठीक करवाते हैं। यह आपका और हमारा दोनों का मामला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज यह प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपका प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह गंभीर विषय है। आज तक ऐसी त्रुटि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- हो सकता है।

श्री नारायण चंदेल :- आज तक नहीं हुआ है कि 3-4 लोगों का नाम प्रिंट हो गया हो। ध्यानाकर्षण को इसमें प्रिंट कर दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नई-नई व्यवस्था है।

श्री नारायण चंदेल :- लेकिन आप इसको सुधरवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे।

श्री नारायण चंदेल :- ऐसा कभी होता नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :-श्री धरम लाल कौशिक, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, श्री नारायण चंदेल, 4 लोगों के नाम हैं। संसदीय इतिहास में पहली घटना है। प्रश्न 4 लोगों के नाम से हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- [xx]

अध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे, श्री शैलेश पाण्डे।

श्री शिवरतन शर्मा :- 4 लोगों के नाम से प्रश्न प्रिंट हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- [xx] (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- ध्यानाकर्षण को प्रिंट कर दिए हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- [xx] के कारण है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कहीं पर प्रश्न तो चेंज नहीं हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- क्या हो रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- यह तो मंत्री जी जान गये कि कौन-कौन प्रश्न पूछने वाले हैं, उसमें उनका नाम आ गया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया। प्लीज, प्लीज।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप उसमें प्रश्न कीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रश्न ठीक का मामला नहीं है। आपने उसके धड़ को अलग कर दिया है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- बिलासपुर का एक महत्वपूर्ण मामला है। उस पर चर्चा होने दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- कोई संशोधन नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, प्लीज, प्लीज।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, आप अध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी है, कुछ कमी रह गई होगी, त्रुटि होगी, उसको आगे बढ़ने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 3 नाम प्रिंट हुए हैं, उसमें आपकी कोई व्यवस्था आनी चाहिए। यह गंभीर बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप ध्यान आकर्षित किए, मैं उधर ध्यान दूंगा। उसके बाद तो व्यवस्था दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा आज ही राजस्व विभाग का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धरमलाल कौशिक :- राजस्व विभाग का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात मान लिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- न ग्राह्य में है, ना अग्राहय में है, न संशोधित प्रश्न में है। आकाश में उड़ गया, पाताल में खा गये, पता ही नहीं लग रहा है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, बात दरअसल यह है कि जो विधानसभा सचिवालय की व्यवस्था है, उसको आपने आनलाईन भी कर दिया। तो आपने जो आनलाईन प्रश्न किया होगा तो धरम भईया को आनलाईन उत्तर मिल गया होगा। जो लिखकर प्रश्न किया है, वह आपको प्रिंट होकर उत्तर मिला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- वैसे ही हो गया। जैसे आपने राज्यपाल को दिया था, वैसे ही हो गया। यह टोटल मंत्रियों, आप लोगों के अधिकारियों की जो [XX] हैं, वह कारण है।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रिंटिग का काम हमारा नहीं है, [XX][4]

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोगों ने जो राज्यपाल जी को अभिभाषण अंग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग दिया था, वैसे ही यहां पर भी हुआ है। केवल आप लोगों के कारण है। जिस प्रकार से प्रेशराइज करते हो, दबाव बनाते हो, वही कारण है कि ये सब आ रहा है। केवल आप लोगों के कारण है।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसको विलोपित कराईये। [XX]

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप नहीं बना सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं तो, संसदीय कार्यमंत्री की भूमिका क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- जो मैं आपसे अनुरोध करने गया था, वह मेरी भूमिका थी।

<u>बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय खेल के मैदान के विवादित प्रकरण का निराकरण</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

8. (*क्र. 73) श्री शैलेश पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय के खेल के मैदान के विवादित प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं? **(ख)** महाविद्यालय को किस ट्रस्ट ने जमीन दान की है और कब कब कितनी जमीन दान में दी गयी थी कृपया ट्रस्टियों के नाम भी बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** शिवभगवान रामेश्वरलाल चेरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी कमल बजाज के द्वारा मौजा जरहाभाठा स्थित भूमि खसरा नंबर 107/3, 108/3 शामिल 109 कुल रकबा 0.962 हे. भूमि को विक्रय की अनुमति बाबत प्रस्तुत आवेदन को पंजीयक एवं लोक न्याय तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने दिनांक 05/08/2021 को निरस्त किया है। **(ख)** पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर के अभिलेख में भूमि ट्रस्ट के द्वारा दान किये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है। शिवभगवान रामेश्वरलाल चेरिटेबल ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक-13 वर्ष 1944 के ट्रस्टी के रूप में वर्तमान पंजी में कमल बजाज पिता आर.एन. बजाज का नाम दर्ज है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1944 का बिलासपुर का ऐतिहासिक कालेज, जो पहले एस.बी.आर. कालेज के नाम से, आज जे.पी. वर्मा कॉलेज के नाम से है। उस कालेज की जमीन, खेल मैदान, जो बच्चों के खेलने-कूदने के लिए था, वह पिक्चर से अचानक कैसे गायब हो गया

अध्यक्ष महोदय :- कहां से गायब हो गया ?

श्री शैलेश पाण्डेय :- पिक्चर से गायब हो गया । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1944 में ट्रस्टियों ने 1 लाख देकर महाविद्यालय बनाया । उसके बाद ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ जमीन दान दी । महाविद्यालय में ट्रस्ट से हजारों-लाखों बच्चे पढ़कर निकल गये, उसमें ट्रस्टियों ने उस महाविद्यालय के जमीन को बेचने का कैसे निर्णय लिया, उसका क्या नियम था, दूसरी बात यह है कि शासन ने जब इस महाविद्यालय को 1972 में अधिग्रहित किया तो उसके बाद से लेकर आज तक वह जमीन महाविद्यालय की थी और अचानक वह जमीन ट्रस्टियों ने कैसे बेच दी, ट्रस्टियों के क्या नियम थे, उनको ट्रस्टी किसने बनाया, किस नियम से बनाया गया, यह जानना चाहता हूँ, यह पहला प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसका जवाब बहुत स्पष्ट तौर पर दिया गया है, ट्रस्टियों ने कोई जमीन बेची नहीं है । अभी हाई कोर्ट से यह आदेश हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने क्वेश्चन किया है । अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर न मैं हूँ और न माननीय सदस्य है । हाई कोर्ट ने ट्रस्ट को ऑक्शन करने का अधिकार दिये हैं । उसके लिये न्यायालय में जो प्रक्रिया है, सिंगल बेंच का आर्डर है । डबल बेंच में जाये, ऊपर जाये, सुप्रीम कोर्ट में जाये...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, यह प्रश्न हाई कोर्ट में उपस्थित हो चुका है, इसलिए यहां चर्चा नहीं होगी ।

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में निर्णय हो चुका है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, पहले तो एसबीआर कॉलेज नाम था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने उसका नाम जे.पी.वर्मा महाविद्यालय कर दिया । आपने ट्रस्टियों को पहले ही दु:खी कर दिया । उसके बाद वह ट्रस्टी जो है, उसको बेचने के लिये क्यों आतुर हुये । अध्यक्ष महोदय, जो जमीन शासन ने 1972 में अधिग्रहित कर चुका है, वह जमीन तो शासन के अंडर में आ गई है ना । अब ट्रस्टी ने उसको बेचने के लिये हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, यह अलग बात है । जो प्रिमाईसेज हमारी सरकार का था, सरकार के होने के बाद अचानक वह हाई कोर्ट तक क्यों पहुंच गया, यह प्रश्न है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस जमीन की बात कर रहे हैं, वह जमीन दान में नहीं दी गई है । न उसका कोई दान पत्र है, दान पत्र है और दान में दी गई है तो उसको बता दें । उसके बारे में बता दिया जायेगा ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1972 से लेकर अब तक वह जमीन 60-70 सालों से महाविद्यालय की थी, उसके बाद शासन आज यह कहेगा कि हमारे पास दान पत्र के जमीन की रिकार्ड ही नहीं है, यह तो गलत बात है । जो महाविद्यालय परिसर था, इतने सालों से बच्चे पढ़ रहे थे, मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ । आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बात समझने का प्रयास कीजिए । मैं जानता हूँ कि सरकार इसमें दोषी नहीं है, लेकिन ट्रस्टी इस प्रकार से उसको बेचने के लिये कुचक्र कर रहे हैं, उनके मन में अगर लालच आ गया है, इसकी जांच सरकार को करनी चाहिये और इसमें हस्तक्षेप भी सरकार को करनी चाहिये । हमारी जमीन है, सरकारी महाविद्यालय की जमीन है, हम उसको क्यों देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, माननीय मंत्री जी आप इसमें हस्तक्षेप भी करिये, उसमें जांच भी कराईये और वस्तुस्थिति से अवगत कराईये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं, वह सही नहीं है । इसमें एसबीआर ट्रस्ट के नाम से जो वर्तमान में खसरा नंबर 107-108 ट्रस्ट के नाम पर है, जिस जमीन की बात कर रहे हैं, वह 0.962 हेक्टेअर शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है । इसमें दो जमीन अलग-अलग है, जो जमीन ट्रस्ट के नाम पर है, यह उसको खेल मैदान की बात कर रहे हैं । जो जमीन महाविद्यालय के ट्रस्ट के नाम पर है, उसका अलग दिया हुआ है, जमीन जो उसमें दान किया है, वह अलग है और जिस जमीन की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसमें दानपत्र नहीं है । आज तक कोई भी रिकार्ड इस प्रकार का नहीं है । राजस्व न्यायालय में उसका कोई उल्लेख नहीं है, न्यायालय पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट से आदेश भी उसमें पारित हुआ है । उसके बाद ट्रस्टी लोग हाई कोर्ट गये हैं, हाई कोर्ट जो आदेश दिया है, उसके ऊपर हम लोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं ।

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि कॉलेज में जाने के लिये ट्रस्ट जगह दे, रास्ता दे, ऐसा आदेश हुआ है । कालेज पीछे है और मैदान सामने है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि एक ट्रस्टी का बेटा है, वह भी ट्रस्टी बन गया, पहली बात तो यह है कि जिस ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी ही नहीं है, वह उस जमीन को बेचने के लिये कैसे आवेदन कर सकता है, उसका क्या नियम है ? दूसरी बात आप मुझे यह बताईये कि जो जमीन 60 साल तक महाविद्यालय की थी। क्या आपने दूसरे ट्रस्टियों से बात करने का प्रयास किया है ? क्या दूसरे ट्रस्टियों से ...।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, राजस्व में मामला ही नहीं है तो हम बात क्यों करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, प्लीज सुनिये। यह मामला जरा उलझा हुआ है। आप आज आराम से इनके पास बैठ जाईये और उसको सुलझाने के लिये क्या-क्या व्यवस्था होगी वह भी करेंगे और आप मुझे जानकारी देंगे। धन्यवाद्।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पीड़ा है, आप भी वहां गये होंगे तो देखे होंगे कि वह बहुत पुराना कॉलेज है। उसके सामने ग्राउण्ड है। यदि ग्राउण्ड को ही बेच दिया जाये तो कॉलेज का औचित्य खत्म हो जायेगा। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। यह कॉलेज आज का नहीं है। मैं जब पैदा नहीं हुआ था, यह तब का है। मैंने जब स्कूल जाना शूरू किया 6वीं क्लास से, मैं उसको तब से देख रहा हूं। अचानक वह ट्रस्टी आ गया और अचानक उसको सेल करने की स्थिति आ गई।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय कौशिक जी, अध्यक्षीय व्यवस्था आ गई है। अब इस मामले को खत्म करना चाहिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खराब स्थिति है और यह एक उदाहरण है लेकिन लगभग शहरों में यही स्थिति बन रही है। मैं राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मैंने उसको गंभीरता से लिया है। आपकी बात को मैंने गंभीरता से लिया है, उसमें गंभीर चर्चा करवायेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि माननीय सदस्य जिस जमीन की बात कर रहे हैं वह जमीन कॉलेज के पास है और हाई कोर्ट ने जिस जमीन के लिये आदेश पारित किया है, उस हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हम आपको कहां कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर आदेश पारित करिये। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमको उस जमीन को बचाना चाहिए। मेरा यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- जो उलझन है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप उसे बचाने का रास्ता बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय पाण्डे जी, आप घर आकर बात करिये। यहां विधान सभा में बचाने की जगह नहीं है, आप घर आकर बात करिये। ममता चंद्राकर जी।

<u>विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए मूलभूत सुविधा विषयक</u>

[स्कूल शिक्षा]

9. (*क्र. 733) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कबीरधाम जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्र संख्या के अनुपात में आवश्यक भवन, फर्नीचर उपलब्ध हैं ? कितने विद्यालयों में भवन व फर्नीचर की कमी है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत शुद्ध पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की उपलब्ध है ? यदि नहीं तो कारण बताएं ? कितने विद्यालयों में आर ओ वाटर प्लांट उपलब्ध है ? उन विद्यालयों में आर ओ वाटर प्लांट कब स्थापित किया गया और कितनी राशि व्यय हुई तथा उसकी गॉरन्टी अवधि क्या है ? वर्तमान में कितने आर ओ वाटर प्लांट चालू हैं और कितने बंद हैं? बंद होने के क्या कारण है, विद्यालयवार जानकारी

देवें? **(ग)** कितने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर क्लासेस (कक्षा पाठ) के माध्यम से पढाई की जाती है ? प्रत्येक विद्यालय में कितने कंप्यूटर स्थापित हैं ? उन्हें कब क्रय किया गया और कितनी राशि व्यय हुई तथा उसकी गॉरन्टी अवधि क्या है ? उत्तर दिनांक तक कितने विद्यालय में कंप्यूटर चालू है और कितने बंद हैं? विद्यालयवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जी नहीं। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	**विकासखण्ड**	**विद्यालयों की संख्या जहाँ भवन की आवश्यकता है**	**विद्यालयों की संख्या जहाँ फर्नीचर की कमी है**
1	**2**	**3**	**4**
1	कवर्धा	7	18
2	बोड़ला	16	12
3	सहसपुर लोहारा	8	15
4	पण्डरिया	23	28
	योग	54	73

(ख) कंडिका 'क' के अंतर्गत कबीरधाम जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में नलकूप, हेडपंप, नल कनेक्शन व कुंआ से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। 11 विद्यालयों में विभिन्न बैंकों के द्वारा वाटर आर. ओ. स्थापित कराया गया है, विभाग द्वारा राशि व्यय नहीं की गई है। वर्तमान में 07 वाटर आर ओ चालू हैं और 04 बंद हैं। वाटर आर ओ मशीन खराब है इसलिए बंद है। विद्यालयवार आर. ओ. स्थापित दिनांक की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	**विद्यालय का नाम**	**आर.ओ.स्थापित दिनांक**	**चालू/बंद**
1	**2**	**3**	**4**
1	स्वामी करपात्री जी उ.मा.वि. कवर्धा	07 फरवरी 2017	बंद
2	शास आदर्श कन्या उ.मा.वि. कवर्धा कवर्धा	07 फरवरी 2017	चालू
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा	05 फरवरी 2023	चालू
4	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय बोडला	10 फरवरी 2017	बंद
5	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय सहसपुर	08 फरवरी 2017	बंद

	लोहारा		
6	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय पंडरिया	10 फरवरी 2017	बंद
7	शास.उच्च.माध्य. कन्या परिसर कवर्धा	10 फरवरी 2019	चालू
8	शास.उच्च.माध्य. कन्या विद्यालय पंडरिया	10 फरवरी 2017	चालू
9	शास.उच्च.माध्य. कुण्डा	10 फरवरी 2017	चालू
10	शास. हाईस्कूल अमलीडीह	05 फरवरी 2019	चालू
11	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय पोडी	06 फरवरी 2019	चालू

(ग) कबीरधाम जिले के 25 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर कक्षा के माध्यम से कक्षा पाठ पढ़ाई जाती है। 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 5-5 व 21 विद्यालयों में 1-1 कम्प्यूटर स्थापित किया गया है। कम्प्यूटर का क्रय दिनांक 29.09.2021 व दिनांक 01.07.2021 को किया गया, राशि रू. 1 करोड़ 46 लाख व्यय हुई तथा वारंटी अवधि क्रय दिनांक से एक वर्ष की थी। उत्तर दिनांक तक 24 विद्यालय में कम्प्यूटर चालू है एवं 1 विद्यालय में बंद है। विद्यालयवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[5] अनुसार है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि जवाब में आया है, जो स्थान विद्यालय विहीन है, जहां विद्यालय की आवश्यकता है। कबीरधाम जिले में 54 विद्यालयों की आवश्यकता है, उसमें सबसे अधिक पण्डरिया और बोड़ला में है। मैं आग्रह करूंगी कि आगामी 2023-24 के बजट में वहां पर विद्यालय निर्माण की अनुमति प्रदान करें। साथ ही साथ वहां पर फर्निचर की भी कमी है क्योंकि प्रतिवर्ष संकुल स्तर में, विकासखण्ड स्तर में फर्निचर की व्यवस्था होती है फिर भी वहां पर फर्निचर की कमी है। आप उसको भी संज्ञान में लें, साथ ही साथ वहां पर वॉटर आर.ओ. और कम्प्यूटर, वहां स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या के हिसाब से वहां और आवश्यकता है। आप इसको भी संज्ञान में लेकर व्यवस्था कीजिये। मेरा आपसे यही आग्रह है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जहां विद्यालय के भवन की आवश्यकता है तो कवर्धा में 7 जगह, बोड़ला में 16 जगह और सहसपुर लोहारा में 8 जगह और पण्डरिया में 23 जगहों पर आवश्यकता है। वहां पर भवन तो है, यदि वहां पर बच्चों की संख्या अधिक है और कमरे कम है तो वहां पर अधिक कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने सबकी

[5] परिशिष्ट "चार"

जानकारी मंगवा ली है और हम लोग उसकी अनुशंसा भी करेंगे। आपने जहां तक पानी की व्यवस्था के बारे में कहा है तो वहां पर जो आर.ओ. लगाये गये थे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपको सिर्फ संज्ञान में लेना है। कुछ मांग नहीं है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- संज्ञान में लेकर व्यवस्था भी करनी है। क्योंकि हमारी सरकार विकास के लिये हर तरह के प्रयास कर रही है तो आगे ...।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जी, जहां-जहां अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है, हम उसको पूरा कर देंगे। जहां पर रिपेयर की आवश्यकता है, वहां पर रिपेयर भी करवा देंगे। आगामी जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, उससे पहले आपके क्षेत्र के जितने भी स्कूल है, वह ठीक-ठाक हो जायेंगे, रिपेयर भी हो जायेंगे और उसमें अधिक कमरे भी बन जायेंगे। जहां तक आपने कहां कि पानी के लिये चार जगहों पर आर.ओ. लगाये गये हैं, वह बंद है। यह आर.ओ. वहां पर किसी बैंक ने अपने मद से लगाया था, चूंकि अब वह आर.ओ. बंद पड़े हुए हैं, तो अब बैंक से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसे सरकार ने तो लगाया नहीं है। जहां पर कम्प्यूटर लगे थे, वहां एक कम्प्यूटर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जिन्दा में खराब है। उसमें कितना खर्चा आयेगा, उसको हम देख लेंगे और उसको बनवा देंगे।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वरिष्ठतम सदस्य श्री बृहमोहन अग्रवाल का प्रश्न क्रमांक 10 ले रहा हूं। 05 मिनट बचे हैं, उसी हिसाब से सवाल, जवाब हो जाये। मेरा कहना यह है कि आप साथ में प्रश्न कर लीजिये और साथ में उत्तर दे दीजिये नहीं तो समय कम है, यह अधूरा रह जायेगा।

<u>प्रदेश में बंदोबस्त त्रुटि के लंबित आवेदन</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

10. (*क्र. 790) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में बंदोबस्त त्रुटि के कितने प्रकरण/आवेदन लंबित है, जिलेवार तहसील सहित जानकारी देवें? (ख) कंडिका ''क'' के प्रकरणों में विलंब के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, यदि हां तो कितने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं तो क्यों ? (ग) रायपुर जिले के तहसीलों में कंडिका "क" से संबंधित कितने प्रकरण लंबित है, कब से लंबित हैं ? वर्षवार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में

बंदोबस्त त्रुटि के जिलेवार तहसील सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[6] अनुसार है । (ख) '' जी नहीं, बंदोबस्त त्रुटि सुधार का कार्य न्यायालयीन कार्य है एवं प्रकरणों में विधिवत सुनवाई पश्चात् साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर आदेश पारित किया जाता है। न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट होने पर अपील का प्रावधान है।'' (ग) रायपुर जिले कण्डिका- ''क'' संबंधित बंदोबस्त त्रुटि के 160 प्रकरण लंबित है, लंबित प्रकरणों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील	वर्षवार विवरण				**योग**
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
रायपुर	00	00	00	00	00
धरसींवा	00	00	00	00	00
आरंग	01	03	10	01	15
मंदिर हसौद	01	01	16	19	37
अभनपुर	00	00	16	34	50
गोबरा नवापारा	00	13	24	21	58
तिल्दा	00	00	00	00	00
खरोरा	00	00	00	00	00
कुल योग	**02**	**17**	**66**	**75**	**160**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बंदोबस्त की त्रुटि जो सामान्य तरीके से होती थी, उसके ऊपर कब से रोक लगा दी गयी है ? बंदोबस्त की त्रुटि सामान्य तरीके से नहीं हो पा रही है। पूरे प्रदेश में बंदोबस्त की त्रुटि के कुल कितने मामले पेंडिंग है ? आदिवासी जिलों में अभी तक कितने मामले पेंडिंग है ? क्या आपके पास अभनपुर में बंदोबस्त की त्रुटियों में शिकायत आयी है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त त्रुटि के जो निराकरण की बात है, वह बंद नहीं की गई है, उसमें व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं और दूसरा प्रदेश में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के कुल दर्ज प्रकरण 13 हजार 545 और 10 हजार 860 निराकृत किये गये हैं। प्रदेश में लंबित प्रकरण 2 हजार 685 है।

[6] परिशिष्ट "पांच"

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैंने पूछा है। बंदोबस्त की सामान्य त्रुटि सुधार का जो मामला था, वह वर्ष 2000 से लगभग बंद है। अब जो बंदोबस्त की त्रुटि के मामले कलेक्टरों के पास पेंडिंग हैं। अगर कोई कलेक्टर बंदोबस्त की त्रुटियों का सुधार नहीं करते हैं तो क्या उनकी सी.आर. में इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? और रायपुर के अभनपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक में ऐसे सैकड़ों मामले हैं, जिनमें किसानों की बंदोबस्त त्रुटियों के बजाए और जो वास्तविक भूमि धारक हैं, उसकी बंदोबस्त त्रुटि सुधारी जानी चाहिए। उसके बजाए जो भू माफिया हैं, उनका जमीनों पर कब्जा है उनको करोड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है। आप मुझे जरा यह जानकारी दे दें कि यह बंदोबस्त की त्रुटियां पेंडिंग क्यों हैं ? और यह कितने सालों से पेंडिंग हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे रायपुर जिले की जानकारी दे देता हूँ। बाकी मैं आपको अभनपुर जिले का अलग से जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। रायपुर जिले में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के पिछले 4 वर्षों में निराकृत प्रकरणों की संख्या 792 है और त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं जिस जानकारी को चाह रहा हूँ। क्या कलेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदोबस्त त्रुटि को सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ? अगर राजस्व के मामलों का निराकरण, बंदोबस्त त्रुटि एक महत्वपूर्ण मामला है कि किसानों की जमीन भू माफियाओं ने समझौता करके, मुआवजा ले रहे हैं, परन्तु जो उसके वास्तविक मालिक हैं, उनके खाते में पैसा जाना चाहिए, उसके बजाए भू माफियाओं को पैसा गया है । जरा आप मुझे बता दें कि अभनपुर में जो बंदोबस्त त्रुटि के मामले हैं उनमें भूमि अधिग्रहण के तहत कितने भू माफियाओं को उसका पैसा दिया गया है और जो वास्तविक भूमि धारक हैं उसके खाते में पैसा नहीं गया है, आपके पास ऐसी कितनी शिकायतें आईं हैं?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट आ रहा है और वहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बड़े-बड़े भू माफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है। भू माफि, भू अर्जन का पैसा ले रहे हैं। वास्तविक मालिक को पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा है कि आदिवासी जिलों में भूमि बंदोबस्त के मामले कितने सालों से पेंडिंग है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि माननीय सदस्य ने पूरे प्रदेश के बंदोबस्त त्रुटि के मामले पूछे। मैंने उसकी जानकारी दे दी कि 13 हजार 545 मामले जिसमें 10 हजार 860 का निराकरण हो चुका है। तो मामले निराकृत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अगर पर्टीक्यूलर अभनपुर में कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, यह दिखवाने से नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। बलरामपुर, रामानुजगंज 177 मामले पेंडिंग हैं इसी तरीके से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में 74 मामले पेंडिंग हैं। गरियाबंद में 422 मामले पेंडिंग हैं। यह सब आदिवासी जिले हैं। खैरागढ़, छुईखदान इसमें 140 मामले पेडिंग हैं।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, गरियाबंद की स्थिति बहुत गंभीर है। आप तो पूरी जांच करवा दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर जिले में 160 मामले पेंडिंग हैं अगर मैं आपको बताऊं। धमतरी जिले में 272 मामले पेंडिंग हैं आखिर ये बंदोबस्त त्रुटि के मामले कितने सालों से पेंडिंग हैं और कलेक्टर इनका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं ? और नहीं कर रहे हैं तो उनकी सी.आर. में दर्ज किया जायेगा क्या ? राजस्व, क्योंकि कलेक्टर इसी के लिए बनाये गये हैं और वह अगर बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरण निराकरण नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे, आप मुझे यह बता दें ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 13 हजार 545 मामले कुल हैं, उसमें ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं जो जवाब मांग रहा हूँ, वह नहीं दे रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर आप पर्टीक्यूलर कहीं गड़बड़ी बता रहे हैं तो मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं बोल रहा हूँ। आप बता दीजिए कि प्रदेश में कहां गड़बड़ी हुई है, मैं उसकी जांच करवा दूंगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभनपुर का पूछा है आप मुझे अभनपुर का बता दें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभनपुर की ही बात कर रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभनपुर में 50 मामले पेंडिंग हैं, सिर्फ एक बलॉक में पेंडिंग हैं। गरियाबंद में 272 मामले पेंडिंग है। आखिर कलेक्टर इनका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं और निराकरण नहीं कर रहे हैं तो क्या उनकी सी.आर. में दर्ज किया जायेगा ? निराकरण, अगले 3 महीने में बंदोबस्त त्रुटि के मामले निराकरण हो जाएंगे क्या ? क्या आप यह निर्णय कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धनेन्द्र साहू जी, आप भी अपनी बात कह लीजिए, जब तक माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, आपके दो, तीन सालों से रिकॉर्ड में बता रहा है कि बंदोबस्त त्रुटि के मामले पेंडिंग हैं यह कब तक निराकृत हो जाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

<u>नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचनाएं</u>

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 17 सितम्बर, 2018,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018,

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 16 जनवरी, 2020

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 10 जून, 2020,

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 25 जनवरी, 2021,

(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 03 नवम्बर, 2022, तथा

(vii) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2022/18, दिनांक 23 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम-निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम 2022 पटल पर रखता हूं।

<u>पृच्छा</u>

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में चिन्हित करके फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। मनगढंत मामले बनाये जा रहे हैं। उनको असत्य आरोप में फंसाया जा रहा है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्भाग्य है, क्या छत्तीसगढ़ में कोई आपातकाल लागू है ? हम आंदोलन करते हैं, हमारे कार्यकर्ता चक्काजाम करते हैं, अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर असत्य मुकदमे लाद करके उनको फंसाया जा रहा है। पिछले 17 तारीख को हमारे कार्यकर्ता चक्काजाम किये। हमारे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं पर धारायें लगाई गईं, गैर जमानती धारायें लगाई गईं। ये उचित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं

कि कवर्धा में विजय शर्मा, कैलाश चन्द्रवंशी, सौरभ सिंह के ऊपर में जिला बदर की कार्यवाई की जा रही है। क्या ये लोग निगरानी शुदा बदमाश हैं ? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाई पर तत्काल रोक लगायें। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार हर राजनीतिक दल के व्यक्ति को है। ये कुचलने की प्रवृत्ति सरकार को बंद करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण दिया है। आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता जनता के हित में आंदोलन करता है, धरना देता है, चक्काजाम का आयोजन करता है। पुलिस जहां मामले कायम करती है, वहां तक तो ठीक था। अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा जिला बदर की कार्यवाई प्रस्तावित की जा रही है, ये चिंताजनक स्थिति है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने आपके सामने बात रखी है। मैं कवर्धा जिले का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवंशी के खिलाफ में 03 साल में 08 मामले पंजीबद्ध किये गये हैं। यह जो 08 मामले पंजीबद्ध हुये हैं, चक्काजाम के हैं, राशनकार्ड बनाने के लिए खाद्य कार्यालय में घेराव के हैं। वहां जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ तो भगवा ध्वज के समर्थन में अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जुलूस के हैं। ऐसे राजनीतिक मामले में जहां गैर-जमानती अपराध कायम हुआ। 100 लोगों के खिलाफ मामला कायम हुआ। 100 लोगों की सेशन कोर्ट से जमानत हुई। पर जान-बूझ करके उसके ऊपर के कोर्ट में खाली एक व्यक्ति की जमानत खारिज की जाये, इसके लिए जिला प्रशासन कोर्ट में गया। उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई। वहां से असफल होने के बाद अब कैलाश चंद्रवंशी को टारगेट बना कर उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास, दबाने का प्रयास यह सरकार कर रही है। हमने इस विषय पर ध्यानाकर्ष दिया है। यहां माननीय वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हैं। उनको सिर्फ याद दिला देना चाहता हूं कि आपके नेता ने पहले आपातकाल लगाकर विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया था और उसका दुष्परिणाम क्या झेलना पड़ा था, उसको याद रखो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास करोगे तो जो यहां बैठे हों, वह इधर बैठने लायक भी नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। आपके बड़ी नेता भी सदन से बाहर हो गयी थी। इस विषय पर हमारा ध्यानकर्षण है। एक बार इसमें चर्चा कराने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर जी।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, एमन काय-काय काम करथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनकी सूचनार्थ .. (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष की पार्टी किस तरह से व्यवहार कर रही है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- जो लोग बुलडोजर बाबा पर गौरान्वित होते हैं, उन लोग ऐसी बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठ जाईये। उनकी सूचना आने दीजिये।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- जो लोग गर्व के साथ बुलडोजर बाबा कहलवाते हैं, वह लोग ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- बुलडोजर बाबा बया गेहे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। उनकी सूचना आने दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- विपक्ष की पार्टी किस तरह से व्यवहार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठ जाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को (व्यवधान) बनाकर रखा है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- चुनाव के नतीजे आने पर बुलडोजन वाला जुलूस निकालते हैं, वह लोग क्या बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ई.डी., सी.डी.।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शून्यकाल हमारा है। यह शून्यकाल हमारा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बैठिये। उनकी सूचना आने दीजिये।

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी के मीडिया (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग अपनी बात 2 मिनट में रखेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- आपने पूरा मीडिया को खरीद लिया है।

श्री रामकुमार यादव :- ई.डी., सी.डी. भेजने वाला।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनकी बात आने दीजिये। आप अपनी बात भी रख सकते हैं।

श्री अरूण वोरा :- मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वह कभी लाईट जलाकर कपड़ा नहीं बदला करते। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल साहब, अपना सुझाव रख सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के आंदोलनों पर उनको कुचलने की मानसिकता ..।

श्री अमरजीत भगत :- भाजपा की है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बीच में टोका-टोकी न करें।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- आपने लगातार 15 साल तक कुचलने का काम किया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उल्टा चोर कोतवाल को डाटे।

श्री बृजोहन अग्रवाल :- यह जो मानसिकता है, यह लोकतांत्रिक नहीं है। यह मानसिकता आपातकालीन, घबराई हुई सरकार, डरी हुई सरकार, [xx] सरकार। क्या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? मेरे पास में कैलाश चंद्रवंशी के ..।

श्री उमेश पटेल :- बृजमोहन जी, एक मिनट। मैं बस एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। माननीय चौबे जी। उपाध्यक्ष महोदय, इनके सत्ता के समय हमारा एक कार्यकर्ता था। एक गाय पानी टंकी और दीवार के बीच में फंस गई थी। गांव वालों ने उस गाय को बचाने के लिए उस पानी टंकी को तोड़ने का काम किया। चूंकि वह गांव का मुखिया था, सरपंच था तो गांव के सब लोगों ने सलाह ली और गांव वालों ने निर्णय लिया कि उस टंकी को तोड़ दिया जाए ताकि गाय बच जाए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल तक वह पेशी घुमा है। (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- भारतीय जनता पार्टी के मन मा ये बात हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल साहब, इसके बाद अब चंद्राकर जी। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- गौमात के साथ अन्याय।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पहले आप लोग अपनी बात रखिये। जैसे मंत्री जी ने रखा।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने पहले इनको अनुमति दिया हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल साहब, सुनिये तो। मैं आपकी ही सरकार की बात बता रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से कुचला जायेगा। हमें जिस प्रकार से धाखा है। हमें आपत्ति नहीं है, परंतु क्या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जिला बदर किया जाएगा? मेरे पास में कैलाश चंद्रवंशी के एक-एक मामले हैं, जिसमें कलेक्टर ने नोटिस दिया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल साहब, व्यवस्था का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, मैं आपको समय दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धरना करने के ऊपर में, रास्ता रोकने के ऊपर में, राशन कार्ड के आंदोलन को लेकर उनके द्वारा धार्मिक झण्डे को जलाये जाने के विरोध में ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी । डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे । यही बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे प्रभारी मंत्री हुआ करते थे और जब अंबिकापुर में दो-दो महिलाओं की दोहरी हत्याकांड हुई और जब हम लोगों ने उसका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से किया तो 15 दिनों के लिये हम लोगों को जेल भेजा गया । (शेम-शेम की आवाज) (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गयी । इसके बाद चंद्राकर जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय देखिये, कोई प्रमाणिक यहां नहीं बैठे हो । कल आप भी विपक्ष में आओगे, पहले भी थे । हमारे 15 साल के कार्यकाल में एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जिलाबदर की कार्यवाही नहीं हुई है । यह लज्जाजनक है । (व्यवधान) क्या किसी के ऊपर हत्या का आरोप है ? क्या किसी के ऊपर कोई बालात्कार का आरोप है ? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हमारे कई कार्यकर्ताओं को ये लोग गुंडे घोषित किये हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- जब इनकी सरकार थी, तब लोगों ने देखा है । (व्यवधान) 15 साल देखा है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित ।

(12.11 से 12.21 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.21 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग जिस बात को उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिला-बदल की कार्यवाही की जा रही है। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं पर केस दर्ज करके उन्हें दबा दिया जाएगा। ये दबाने वाली मानसिकता को हम दबाने की ताकत रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये खुद मान रहे हैं कि ई.डी. द्वारा ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 15 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक अत्याचार हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये कैलाश चन्द्रवंशी..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी भी बात आयेगी। माननीय को बोलने दीजिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपकी ताकत तो पिछली विधान सभा में दिख गई। आप लोग 14 के 14 रह गये। (व्यवधान)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अभी राम राज्य है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 15 साल में सबसे ज्यादा कांग्रेसियों को जबर्दस्ती अंदर कर दिया जाता था। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- निर्दोष लोगों को अंदर किया जाता था। (व्यवधान)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- ये सब आपके ऊपर में लागू होता है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये कैलाश चंद्रवंशी के ऊपर कौन सा आपराधिक केस है? ये विजय शर्मा के ऊपर कौन सा आपराधिक केस है? ये सौरभ सिंह के ऊपर कौन सा आपराधिक केस है? राजनीतिक आंदोलन करने वाले लोगों को अगर जिला-बदल किया जायेगा, वहां के मंत्री जी बैठे हैं। वहां से विधायक हैं। क्या ऐसा कुचलकर आप राजनीति कर सकते हैं? हम आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कलेक्टर ने दिनांक 02/01/2023 को जिला-बदल का नोटिस दिया है। क्या राजनीतिक कार्यकताओं को आंदोलन करने पर जिला-बदल का नोटिस दिया जायेगा ? (शेम-शेम की आवाज) धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर। ये राशनकार्ड के लिए आंदोलन करने पर। ये राजनीतिक दल को कुचलने वाली मानसिकता, ये कभी इस देश में सफल नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- केन्द्र से जो..। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इसीलिए आप लोग 15 सीट पर सिमट गये हैं। प्रदेश की जनता जानती है। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेताओं को अंदर किया जा रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप अपनी बात बोलिए। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी ने..। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 15 साल तक कांग्रेसियों को अंदर किया गया। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी आप जवाब दें कि क्या कार्यकताओं का जिला-बदल किया जायेगा? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल साहब, आपकी बात आ गई है। माननीय धरमलाल कौशिक जी। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या जिला बदल का नोटिस दिया जायेगा? इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि राजनीतिक आंदोलन करने वालों पर क्या जिला-बदल की कार्यवाही की जाती है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जिसका नाम ले रहे हैं, वह क्रिमिनल आदमी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरजपुर की घटना है, मार खाने वाला मंडल अध्यक्ष, मारने वाला (व्यवधान) पुतला जलाते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अंदर करने का काम आप लोग करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृजमोहन जी।

श्री अमितेश शुक्ल :- कुचलने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, इसके बाद।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जिन नामों का उल्लेख कर रहे हैं । कैलाश चंद्रवंशी, सौरभ सिंह के खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं । जिला बदर की कार्रवाई बिल्कुल उचित है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए । उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, शिव डहरिया जी । माननीय मंत्री शिव डहरिया जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, मारने का प्रयास किया है । मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा । क्या पुलिस को मारने का अधिकार है ? पुलिस को धक्का दे रहे हैं । सारी चीजों का वीडियो है । अनर्गल कुछ भी आरोप लगाते हैं आप । मैं कहता हूं बिल्कुल उचित है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- बिल्कुल उचित है । एक्शन होकर रहेगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिए । माननीय धरमलाल कौशिक जी ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी अपनी बात कहें । शून्यकाल में दो-दो मिनट में अपनी बात रखिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री ने धमकी दी है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिए । (व्यवधान) सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(12.27 से 12.33 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:33 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, कौशिक साहब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गयी है, आपने दो मिनट में बात की है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी ने धमकी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल साहब आपकी बात दो मिनट में आ गयी है, माननीय कौशिक साहब को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बी.जे.पी. कार्यकर्ताओं को कुचलने की मानसिकता को हम कुचल देंगे। अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता पर कार्रवाई हुई तो...। (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- क्रीमिनल हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनकी बात आई तो किसानों के उपर एफ.आई.आर. करवायेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गयी। माननीय कौशिक जी। (व्यवधान) आप बोलिए। आप नहीं बोल रहे हैं। माननीय कौशिक जी, दो मिनट में अपनी बात कहिए। शून्यकाल है, अपनी-अपनी बात आना चाहिए। चलिए आप बोलिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल में किसानों को जेल में भरने का काम करते थे। (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अपराधियों के उपर कार्रवाई होगी। (व्यवधान) अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी इसके बाद बोलिए। आप लोग शांत रहिए। अग्रवाल साहब उनकी बात आने दीजिए। मैं आपकी सुन चुका हूं, मैं विचार करूंगा। माननीय कौशिक जी मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग शांत रहिए। माननीय कौशिक साहब, अपनी बात दो-दो मिनट में बात रखिए। बात आना चाहिए।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, सूरजपुर की घटना भूल गये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- जिस प्रकार से आपकी जानकारी में लायी गयी है। हमारे जिलाध्यक्ष को गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। (व्यवधान) पुलिस वाले कार्रवाई किए और हम लोग जेल में गये। उसके खिलाफ हम लोग.. (व्यवधान) जिनके उपर प्रकरण हैं, उन्होंनें पुलिस को मारा, जिन्होंने झण्डा उखाड़ा। जिन्होंने वहां पर उन लोगों के खिलाफ में ऐसा किया, उन लोगों के ऊपर 10-10 एफ.आई.आर. हैं। आज पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर हाथ उठा सके क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण है। सरकार का संरक्षण होने के कारण पुलिस की हिम्मत नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह गुंडा-गर्दी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह शांति का टापू था, जिसको...। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- 15 साल में अपराधियों को...। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप गुंडा-गर्दी और बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। चंद्राकर जी, आप दो मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीत सिन्हा :- यह गुंडा-गर्दी को बढ़ावा देते हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह धर्म के नाम पर गुंडा-गर्दी मचाये हैं। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- राजनीतिक रूप से उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोग गुंडा-गर्दी करने वालों को संरक्षण देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आप दो मिनट में अपनी बात कहिये। कौशिक जी, आपकी बात आ गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग गुंडा-गर्दी करवाते हैं।

श्री यू.डी. मिंज :- यह राजनीति करते हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में माफी मांगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग थोड़ा शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह गुंदा-गर्दी करने वालों और बलात्कार करने वालों को संरक्षण देते हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह धर्म के नाम पर गुंडा-गर्दी करते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- उनको कोई नहीं कुचल सकता है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय को माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सब अपनी बात 2-2 मिनट में समाप्त करेंगे। मैं आप सबको मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस को कुचलने की बात कर रहे हैं। यह पुलिस को कैसे कुचल देंगे ? पुलिस कार्रवाई कर रही है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यदि कोई गुंडा-गर्दी करे, दादागिरी करे, जबरदस्ती रौब जमाने की कोशिश करे तो उस पर अंकुश लगाती है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सब अपनी-अपनी बात रख सकते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग क्या बोलना चाहते हैं ? यह पुलिस की कार्रवाई को कुचलने की बात कर रहे हैं। इन्होंने 15 साल में अपराधियों को पाला है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने शून्यकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं से संबंधित जो विषय उठाया तो माननीय मोहम्मद अकबर जी की यहां पर क्या अथॉरिटी है ? जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन अग्रवाल जी, पहले आप यह बताइये कि उसके खिलाफ कितने प्रकरण हैं ? वह अपराधी किस्म का आदमी है। आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं वह अपराधी है। आप ऐसे अपराधियों को बढ़ाने का काम मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1300-1400 निर्दोष आदिवासी जेल में थे।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या वह मजिस्ट्रेट हैं या वह अपराध साबित करने वाले हैं ? वह कौन हैं ? यदि वह ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजनीतिक दबाव है।... (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- आप यह घोषणा दीजिए कि ब्लॉक में...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जब आप गृहमंत्री थे।... (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह राजनीति करने वाली सरकार...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- बलात्कार करने वालों को संरक्षण देते हो।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिये। आप सबको मौका मिलेगा। मैं आप सबको दो-दो मिनट बोलने का मौका दूंगा। मोहले जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह राजनीतिक कार्य है।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई राजनीतिक कार्य नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग थोड़ा शांत रहिये। यह शून्यकाल है। यह बहुत महत्वपूर्ण काल है। आप सब दो-दो मिनट में अपनी बात कहिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यह यहां पर अपराधियों की बात उठाते हैं।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, कमरो जी, इसके बाद आप बोलियेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कैलाश जी चंद्रवंशी हैं, चंद्राकर हैं, विजय शर्मा, सौरभ सिंह अन्य लोगों के ऊपर।... (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के विकास के ऊपर चर्चा करने के लिए है। यह अपराधियों को बचाने का स्थान नहीं है। यह अपराधियों का प्लेटफॉर्म नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष के ऊपर।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, आप बोलिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप कम से कम यह तो बताइये कि उनके खिलाफ कितने केस हैं ? वह पुलिस के ऊपर हमला करेंगे। वह पुलिस को धक्का मारेंगे और आप लोग यहां पर उनको संरक्षण देंगे।

संसदीय सचिव (श्री यू.डी. मिंज) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकर्ता ही ऐसे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- यह पुलिस को कुचलने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग अपनी-अपनी बात रखिये। पुन्नूलाल मोहले जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- गुंडा-गर्दी बंद करो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये शर्मा जी, आप बोलिये। शांत रहिये। शून्यकाल में आप सब की बात आनी चाहिए। आप लोग हल्ला करेंगे तो कैसे बनेगा ? चलिये, गुलाब कमरो जी, आप बोलिये। आपकी बात आ गई।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- कानून का अपमान करना बंद करो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके ही सदस्य बोल रहे हैं आप सुन लीजिए।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में 1300-1400 निर्दोष आदिवासी जेल में थे। मैं आपको दूसरी बात सूरजपुर जिले की घटना बताना चाहूंगा।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- छाबड़ा जी, आप बोलिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बंद करो। आप किसको कुचल देंगे ? आप कुचलने की बात कर रहे थे, आप किसको कुचलेंगे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी कुचलने की बात की थी। आप बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कुचलने की बात करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग ऐसी बात मत करिए कि व्यवस्था बिगड़े। छाबड़ा जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया है, आप बोलिए । (व्यवधान)

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को हम देख चुके हैं । मैं 2017 में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं । भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को दबाव में डालकर हम 17 लोगों के खिलाफ धारा 307 लगवाया था (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- ये कुचलने वाले सूरजपुर में अपने ही मण्डल अध्यक्ष के पांव तोड़े हैं (व्यवधान)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये किसको कुचलने की बात कर रहे हैं ? ये शासन, प्रशासन को कुचलने की बात कर रहे हैं, पुलिस को कुचलने की बात कर रहे हैं । ये लोग माफी मांगे । (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- आप कुचलोगे किसको ? आप छत्तीसगढ़ की जनता को कुचलने की बात कर रहे हो । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री इस तरह की बात करें, यह उचित नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उत्तेजना में मत आईए । मान-मर्यादा का ख्याल कीजिए । मैंने आपकी लोगों की बात सुनी है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री की यह भाषा उचित नहीं है । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित ।

(12:41 से 12:52 तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.52 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथियों ने गंभीर विषय को उठाया था कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार फर्जी और झूठे मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं, जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है, जो लोकतन्त्र में उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह उचित नहीं है। हम मंत्री जी कहते हैं कि वे अपने शब्द ले लें। आपसे आग्रह है, आसंदी से निवेदन है कि यह गंभीर विषय है और इस पर किसी न किसी रूप में चर्चा हो, किसी न किसी रूप में चर्चा कराये। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आ जाये। किसी न किसी रूप में चर्चा कराये, यह गंभीर विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आप सबकी बात सुनूंगा। लेकिन 2-2 मिनट में आप अपनी बात करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सा तरीका है ? सदन में बोल रहे हैं कि कुचल दूंगा।

श्री अमितेष शुक्ल :- बहुत गंभीर बात है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष और सभी सदस्यों को शून्यकाल में अपनी बात कहने की एक परम्परा है। आपने किसी विषय पर अपनी बात कही, लगभग सभी सदस्यों ने अपनी बात कही। बृजमोहन जी की तरफ से भी बात आई। बृजमोहन जी ने माननीय मंत्री जी का जिक्र किया। जब मंत्री जी का नाम आया तो मंत्री जी ने भी अपनी बात कही। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर चर्चा है। आपके पास सारी बातें कहने का अवसर है। उसके बाद माननीय गृहमंत्री जी डिमाण्ड पर भी चर्चा है, आप उसमें भी सारी बातें कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह से सदन की कार्यवाही बहुत अच्छे से चल रहा है, इसका भी पटाक्षेप होना चाहिए। शून्यकाल में जो बात आनी थी, वह आपकी बात आ गई। आज अवसर है और आज अपनी बात कहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आप आगे बढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं यह कह रहा था कि आप जिस विषय पर मेरा ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे थे, मैंने उसको सुना। मैं बाद में किसी न किसी रूप में उस पर चर्चा करा लूंगा। आपके सहयोग से सदन चलेगा। आज अनुदान मांगों पर चर्चा है। माननीय मंत्री जी ने कहा, सबकी लगभग-लगभग बात आ गई। मैं अब आगे बढ़ूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषय पर बोलूंगा। उस पर आपकी व्यवस्था आ गई। हमने 6 मार्च को शिव डहरिया जी ने अपने तारांकित प्रश्न संख्या-3 पर चर्चा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि नहीं दी गई है। उसी दिन एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि राज्यांश की इतनी राशि नहीं मिली है, उन्होंने उस दिन गलत कथन किया और उसके लिये हमने विधान सभा में अवमानना की नोटिस दी है । यह गंभीर विषय है कि एक जिम्मेदार मंत्री उसी दिन एक ही प्रश्नावली में कहे कि केन्द्र का पैसा नहीं मिला है...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय....।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनकी बात आ जाने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें जवाब नहीं होता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक कॉपी दी है । दोनो की कापी लगाई है, पूरे दस्तावेज है जिसमें उन्होंने उत्तर दिया है कि राज्यांश की इतनी राशि बाकी है । मेरा यह कहना है, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, गलत उत्तर देना, यह सीधे-सीधे सदन की अवमानना है । जो हमने कहा है उसमें इस पर आपकी व्यवस्था आ जाये या चर्चा हो जाये, नहीं तो एक नई परम्परा विकसित होगी । एक जिम्मेदार मंत्री गलत उत्तर दे, कोई कार्यवाही न हो, कोई व्यवस्था न आये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, दो मिनट आपकी व्यवस्था दे रहा हूँ । जो उत्तर में भिन्नता के संबंध में आप सबने विषय पर मेरा ध्यानाकर्षण किया है, उसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये ना । परीक्षण कराना एक अलग विषय है । मैं आपकी आसंदी पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहा हूँ । ये भी संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं, यहां दो-दो, तीन-तीन, विधान सभा अध्यक्ष बैठे हैं । जो प्रमाणित हो रहा है कि विधान सभा में गलत बोला गया है, सही नहीं कहा गया है, उसमें परीक्षण करवाने की जरूरत नहीं है, तुरन्त परीक्षण हो जायेगा । उस पर चर्चा, कार्यवाही या उसकी पुनरावृत्ति न हो । यह सदन की अवमानना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैंने व्यवस्था दी है । श्रीमती छन्नी चन्दू साहू।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए परीक्षण के बजाय यह व्यवस्था मत बने । आगे अवमानना मत हो । आप इसके लिये कोई व्यवस्था दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो विषय उठाया है, वह विषय ऐसा है, जो स्वयं में प्रमाणित है और जो अपने आप में प्रमाणित है, उसके बारे में तो सदन में व्यवस्था ही आनी चाहिये कि भविष्य में मंत्री इस प्रकार का काम न करें या अपनी गलती महसूस करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्षमा मांगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल साहब मैं उनको देख लूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो स्वयं प्रमाणित है...।

उपाध्यक्ष महोदय :- जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको करवा लूंगा ।

श्री रामकुमार यादव :- इही च भर ठेका ले हे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो प्रमाणित है, उसमें जांच करवाने की जरूरत नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना पहली बार घट रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा विषय समझ गया हूँ । मैं उसको दिखवा भी लूंगा और व्यवस्था भी दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है, वह प्रमाणित है, हमने कागज लगाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये ना, मैं उसको देखता हूँ चन्द्राकर साहब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर उदाहरण बनेगा । हम कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी विधान सभा में खत्म हो जायेगी । कोई भी कुछ भी उत्तर देगा, फिर दायित्व क्या रहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, सहयोग करिये, आज की कार्यवाही लंबी हो गई है । मैंने व्यवस्था दे दी है । इस संबंध में विचार करूंगा, जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, मैं जरूर करूंगा । चन्द्राकर साहब मैंने बोल दिया है, व्यवस्था दे दी है । जो भी उचित होगा, मैं देख लूंगा, करवा लूंगा । आपकी बात आ गई ।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू (खुज्जी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा 20 से अधिक मजदूर वाले सामुदायिक कार्यों के लिये जारी किये गये मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु मोबाईल मानिटरिंग सिस्टम एप का उपयोग अनिवार्य किया गया है । परन्तु पूरे प्रदेश में विगत तीन दिनों से उक्त एप में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण मजदूरों के लिये जारी किये गये मस्टर रोल में उपस्थिति भर पाना संभव नहीं हो पा रहा है । इससे मजदूर निराश है । इस प्रकार की तकनीकी समस्या वाले एप को अनिवार्य किया जाना मजदूरों के हित में उचित नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार क्षेत्र के दौरे पर थी । मनरेगा मजदूर मोबाईल एप के कारण काम में लगते नहीं है । खुज्जी विधान सभा ही नहीं, पूरे प्रदेश के मनरेगा मजदूर के हित की बात है, जो घर से काम में जाने के लिये मजदूर जाते हैं, मोबाईल एप के कारण मजदूर में काम नहीं लग पाते हैं । मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगी कि जो मोबाईल एप है, उसमें संशोधन करके मजदूरों के लिये एक अच्छी योजना बनाये और मजदूरों के हित में काम करें।

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

<u>पृच्छा</u>

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा-बाजार) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर थोड़ी देर पहले पुलिस के दुरूपयोग की बात हो रही थी। श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी के पति का और मेरा मामला, इसी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने बात हुई थी। मैं पूरे 90 विधायकों में एक ऐसा पहला विधायक होऊंगा जिसके खिलाफ 26 एफ.आई.आर. है। जिसमें से 12 केस में नॉन बेलेबल धारा लगी है। अध्यक्ष महोदय का निर्देश था कि इसमें जांच की जाये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रमोद बाबू, अभी बृजमोहन जी ने क्या कहा कि 68 केस था। हम लोग भी छात्र राजनीति से 25-50 केस लेकर चल रहे हैं। आप भी 70 केस पार करिये, बड़े नेता हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सर, कोई दिक्कत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात खत्म नहीं हुई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बोल रहे हैं कि मुझको गिरफ्तार करिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में अभी आदरणीय विधायक छन्नी चंदू साहू जी ने जो बात रखी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं केस खत्म करने के लिये नहीं बोल रहा हूं। एक मिनट, मैडम एक मिनट मुझे अपनी बात को रखने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट में अपनी बात खत्म करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि मान लीजिये किसी के ऊपर कोई धारा लगी है तो या तो उसको जमानत दी जाती है या तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। मेरा कहना यह है कि या तो मुझे गिरफ्तार करिये या तो मुझे जमानत दे दीजिये। यह दोनों नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा टार्गेट है कि चुनाव के पहले .. (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, या तो मुझे गिरफ्तार करें या विचार व्यक्त करें या जमानत दीजिये। आप लटका के क्यों रखे हुए हो ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय विधायक छन्नी चंदू साहू जी ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप दो मिनट में अपनी बात कहिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- या तो आप मुझे सीधे बाहर करिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, वह वास्तव में श्रमिकों के लिये बहुत ही कठिन बात है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है कि एक कांग्रेसी नेता के कहने पर यह किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनकी पूरी बात आ चुकी है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी नेट की सुविधा नहीं है। आज उनको दो-दो बार फोटो लेनी पड़ती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायक के ऊपर चार साल में 26 केस हो गये और उसको विधान सभा संज्ञान में न ले। उनको डर भय में रखें कि वह कांग्रेस में आ जाये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- वह अपना सारा काम छोड़कर फोटो खिंचाने के चक्कर में कि कहीं से लाइन तो पकड़े, कहीं से नेट मिले।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, उनकी बात आ गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, उनको डराया जा रहा है कि वह कांग्रेस में शामिल हो जाये। इसलिये उनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिये। उनको (व्यवधान) करिये और कार्रवाई करिये, उनको डराया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आप मत बोलिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ई-सिस्टम में मजदूरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सब सहयोग करिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी जी, आपकी बात आ गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के एक सदस्य, हमारे साथी विधायक, यह बोल रहे हैं कि उनके ऊपर पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज की है। एफ.आई.आर. दर्ज होने को क्या शहद लगाकर चाटे।

उपाध्यक्ष महोदय :- साहब, मैंने पूरा सुन लिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप या तो कार्रवाई करिये या उसको जमानत देने के रास्ता बनाओ। आप उसको भयभीत क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ बतायेंगे कि क्या होगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको भयभीत किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी वह सब बात आ गई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह भय की राजनीति नहीं चलेगी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ठीक चुनाव के पहले टार्गेट बनाकर कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसको गिरफ्तार करवा लीजिये न। आप यही हो, आपने महारानी पिक्चर देखी थी या नहीं ? उसमें वहां की मुख्यमंत्री अपने पति को विधान सभा के अंदर पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवाती है। आप पुलिस बुलाकर गिरफ्तार कर दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप डरवाते क्यों हैं ? आप उसको डरा क्यों रहे हैं ? वह भय में ना खा पा रहे हैं, न वह सो पा रहे हैं, न वह घूम पा रहे हैं। उसके साथ उसकी रक्षा कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- धर्मजीत भैया, प्रमोद जी को कोई नहीं डरा रहा है। अभी उनका मन स्थिर नहीं है। कभी इधर, कभी उधर (हंसी)।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उसके बाद बोलते हैं कि मैं जाऊ किधर।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको जल्दी से बलौदा-बाजार पुलिस के हवाले करिये, उनका मन बन जायेगा जो भी बनना होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, नेताओं के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज होते हैं। हम लोगों ने बहुत देखा है। न गिरफ्तारी होती है, न उसके आगे कुछ और होता है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- बृजमोहन जी ने बताया कि उसके आगे .. (व्यवधान)।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, वह परेशान है। उससे रिवॉल्वर के लिये 5 लाख रूपये की रिश्वत मांगी गयी।

श्री बृहस्पत सिंह :- 70 केस के जाते तक चिंता नहीं करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनसे रिवॉल्वर के लिये पैसे मांग रहे हैं, बताईये। आप आत्मरक्षा के लिये रिवॉल्वर नहीं दे रहे हैं और गुण्डे मवालियों को मिल जाता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय धर्मजीत भैया, आप तो जेल में भेंट करने के लिये गये हो ना। इनकी सरकार में आपको कैसे जेल भेजा था, आपको मालूम है ना।

श्री धर्मजीत सिंह :- वैसे ही इनको जेल भेजवा दीजिये और आप बलौदा-बाजार जेल में भेंट करने चले जाना। आपको कौन मना कर रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक सदस्य यदि सदन में इस बात की पीड़ा व्यक्त करता है कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो आसंदी को संज्ञान में लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा ले लिया।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी को संज्ञान में लेकर माननीय गृहमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- शासन के संज्ञान में है। शासन इस विषय पर कार्रवाई करेगी और माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं और वह एक्च्युल में न्यायालय प्रकरण है और आपकी गिरफ्तारी के लिये एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.पी. साहब का कहना है कि किसी कांग्रेसी नेता के कारण रोक कर रखे हुए हैं (व्यवधान)। या तो बेल करें या तो गिरफ्तार कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं है। न्यायालय प्रकरण में एफ.आई.आर. हो चुकी है। उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी।

समय :

1.05 बजे

ध्यानआकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत राशि में ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेन्सी नहीं बनाया जाना.

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.11.2021 को पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में अन्य घोषणाओं के साथ 50 लाख रूपये के निर्माण कार्य की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा प्रदेश की शालाओं में मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें डी.एम.एफ. मद से 9 जिलों के 493 शालाओं हेतु 1223.66 लाख रूपये एवं समग्र शिक्षा द्वारा 33 जिलों के 9854 शालाओं हेतु 62181.08 लाख रूपये की स्वीकृति मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दी गई है। उक्त कार्य की कार्य एजेंसी संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक/भवन 26/जर्जर शा.भवन/2022-23/23 नवा रायपुर, दिनांक 19.01.2023 में समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़ को प्रशासकीय स्वीकृति के अलावा निर्माण एजेंसी का निर्धारण करने की जवाबदारी दी गई है, परंतु आदेश के कॉलम 12 में इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों को इससे वंचित कर विभिन्न विभागों को एजेंसी का दायित्व देकर कार्य को ठेके में दिया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 8256 दिनांक 26.01.2023 संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर एवं कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती को लिखा गया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार से विभिन्न जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा स्वीकृत कार्य यात्री प्रतिक्षालय, बोर खनन एवं पानी टंकी निर्माण, गांव में स्ट्रीट लाईट, विभिन्न शालाओं एवं छात्रावासों में जिम निर्माण, बर्तन, बिस्तर एवं अन्य सामग्री की सप्लाई जिनकी लागत 2 लाख से 50 लाख के मध्य है, अधिकांश कार्यों की एजेंसी विभिन्न विभागों को बनाया जा रहा है एवं कार्य ठेकेदारों से कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत को 40 लाख स्वीकृत किया गया है। गांव के विकास हेतु सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में अधिकांश कार्यों की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को न बनाकर विभिन्न विभागों को बनाया गया है। जो कार्य ठेकेदार द्वारा करवाये जा रहे हैं, उसमें न ही मौके पर कोई बार्ड लगाया जा रहा है, न ही गांव वालों को कार्य एजेंसी का नाम पता ज्ञात है, जिस कारण से गुणवत्ताविहीन एवं निम्न स्तर का कार्य हो रहा है। इससे ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों में शासन/प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.11.2021 को पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं के परिपालन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5417/आर-2025/2022/22-1 दि. 29.08.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को राशि रू. 20.00 लाख की सीमा से बढ़ाकर राशि रू. 50.00 तक अधिकृत किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि अन्य विभागों के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने की अनिवार्यता नहीं है।

यह सही है कि, वर्तमान में संचालक लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा प्रदेश की शालाओं में मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें डी.एम.एफ. मद से 9 जिलों के 493 शालाओं हेतु 1223.66 लाख रूपये, समग्र शिक्षा द्वारा 33 जिलों के 9854 शालाओं हेतु 62181.08 लाख रूपये की स्वीकृति मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु दी गई है। उक्त कार्य के कार्य एजेंसी हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/भवन/26/जर्जर शा.भवन/2022-23/23 नवा रायपुर दिनांक 19.01.2023 द्वारा समस्त कलेक्टर्स छ.ग. को प्रशासकीय स्वीकृति के अलावा निर्माण एजेंसी का निर्धारण की जवाबदारी दी गई है।

यह कहना सही नहीं है कि, विभिन्न जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा स्वीकृत कार्य यात्री प्रतिक्षालय, बोर खनन एवं पानी टंकी निर्माण, गांव में स्ट्रीट लाईट, विभिन्न शालाओं एवं छात्रावासों में जिम निर्माण, बर्तन, बिस्तर एवं अन्य सामग्री की सप्लाई जिनकी लागत 2 लाख से 50 लाख रू. के मध्य है, अधिकांश कार्यों की एजेंसी विभिन्न विभागों को बनाया जा रहा है एवं कार्य ठेकेदारों से कराए जा रहे हैं। अपितु वास्तविक तथ्य यह है कि प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष सह पदेन कलेक्टर कार्य की प्राथमिकता के आधार पर न्यास के उद्येश्यों की पूर्ति के लिए एजेंसी की नियुक्ति करते हैं। सभी जिलों में विभिन्न एजेंसियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत के माध्यम से भी कार्य कराया जा रहा है।

यह सही है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत को 40 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि गांव के विकास हेतु सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में अधिकांश कार्यों की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को न बनाकर विभिन्न विभागों को बनाया गया है। अपितु सही यह है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित गावों की ग्राम विकास योजना में सम्मिलित कार्यों की प्रकृति के आधार पर कार्य एजेंसी का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर, जो कि जिला स्तरीय एप्रेजल एवं कन्वर्जेन्स कमेटी का अध्यक्ष भी है, के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार किसी कार्य विशेष का क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत अथवा कोई विभाग भी हो सकता है।

यह कहना सही नहीं है कि मौके पर कोई बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, न ही गांव वालों को कार्य एजेंसी का नाम पता ज्ञात है, जिस कारण से गुणवत्ताविहीन एवं निम्न स्तर का कार्य हो रहा है। अपितु सही यह है कि स्वीकृत कार्यस्थल पर कार्य का बोर्ड भी लगाया जाता है जिससे कार्य एजेंसी के नाम एवं पता ग्राम वासियों को ज्ञात होता है, साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम विकास योजना का निर्माण/अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। स्वीकृत कार्यों में विभिन्न शासकीय निर्माण एजेंसियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत भी एजेंसी है तथा ग्रामीण स्तर पर होने वाले कार्य ग्राम पंचायत के देखरेख में होते हैं, फलस्वरूप कार्यों के गुणवत्ताविहीन होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

यह कहना सही नहीं है कि, इससे ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण लगाने का आशय माननीय मंत्री जी भी समझ रहे हैं। जिन चीजों को मैं सदन में बोलना चाहता हूं। ये तो मेरे बोलने के पहले माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रदेश के 11,664 पंचायतों के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने बहुत चीजों को स्वीकार किया। लेकिन अब उनकी क्या बाध्यता है कि ग्राम पंचायत के अलावा किसी को भी एजेंसी बनाया जा सकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील मुख्यमंत्री कहा लेकिन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को समाप्त कर दिया। आप 20 लाख रुपये से 50 लाख रुपये किसलिये किये हैं, केवल पंचायत के कार्यों के लिए किये हैं। आपके पंचायत में तो विगत 03 सालों से कोई फंड ही नहीं है। आप एक रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं। आप सब काम ठेकेदारों से करवायेंगे तो ग्राम पंचायत क्या करेगी ? माननीय मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो संचालक ने कलेक्टर को आदेश जारी किया कि प्रशासकीय स्वीकृति दें और एजेंसी का निर्धारण करें। ऐसी क्या बाध्यता है कि ग्राम पंचायत ने ऐसी कौन सी गलती किया है कि उन्होंने 12 कॉलम में लिखा कि इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाया जाना है। ऐसा क्या बाध्यता है कि किनके निर्देश पर ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाये जाने का निर्देश उक्त आदेश में दिया है, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मूल रूप से ग्राम पंचायत का प्रश्न नहीं था। एक तो आपने डी.एम.एफ. की राशि का पूछा, उसका उत्तर माईनिंग डिपार्टमेंट से ले लेना था कि उनकी कार्ययोजना क्या है ? दूसरा आपने ट्राइवल इलाके में जो 40 लाख रुपया प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत गांव के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत को स्वीकृत किया गया है, वह ट्राइवल वेलफेयर का था। तीसरा स्कूल शिक्षा, लोक शिक्षण विभाग का जो अभी स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि गई है, तीन राशि के बारे में एक ध्यानाकर्षण आदरणीय केशव प्रसाद चन्द्रा जी ने लगाया है। मैं आपको बधाई देता हूं। आपने समग्र रूप से मेरे से इसलिए पूछ लिया कि ग्राम पंचायतों को एजेंसी क्यों नहीं बनाया जा रहा

है ? आपका मूल प्रश्न केवल यही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस घोषणा का जिक्र आदरणीय केशव प्रसाद चन्द्रा जी कर रहे है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उन कार्यों के लिए जिसका 20 लाख रुपये तक के कार्य कराने का ग्राम पंचायतों को अधिकार था, उसको हमने उसके लिए 50 लाख किया। लेकिन यह तीनों में मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। माईनिंग, डी.एम.एफ. का अलग न्यास होता है। आप लोग मीटिंग में बैठते हैं। पहले उसका प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, तब भी आप बैठक में जाते थे। अब उसके अध्यक्ष शायद कलेक्टर हो गये हैं, तब भी आप बैठक में जाते हैं। आपके प्रस्ताव के अनुसार। ऐसा नहीं है कि डी.एम.एफ. का काम कोई ग्राम पंचायत कहीं नहीं कर रही है या 40 लाख रूपये ट्रायबल वेलफेयर का दिया है, वहां ग्राम पंचायतें काम नहीं कर रही हैं। आपके जांजगीर-चांपा जिले में 349 काम ग्राम पंचायतों को दिया गया है। मैं बाकी जिलों का नहीं कहता। सभी जिलों में काम हो रहा है। ऐसा कहीं बंधन नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग में इसलिए भेजा गया है कि मरम्मत जैसे छोटे-छोटे काम आर.ई.एस. के देखरेख में जल्दी निपट जायेगा। बहुत सारी पंचायतों में आप खुद समझते हैं कि ऑडिट का क्या होता है। आप पंचायती राज से चुनकर आए हैं, हम लोग पंचायती राज से चुनकर आए हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतों में छोटे काम या तो क्वालिटी जिला स्टैण्डर्ड हो जाता है या उसका ऑडिट नहीं हो पाता। चूंकि वह पूरी राशि वर्ल्ड बैंक की राशि है, कर्ज लिया हुआ राशि है, इसलिए उसको बंधनकारी नहीं किया जा सकता, लेनिक आपकी चिंता स्वाभाविक है। पंचायतों के अधिकार बने रहने चाहिए। हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जितने भी कार्य हैं, Up to limit 50 lacks, वह ग्राम पंचायतों के द्वारा ही किया जाएगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत को काम मिलना चाहिए। 8 लाख रूपये का अतिरिक्त कक्ष टेण्डर में जायेगा। टेण्डर में प्रक्रिया कठीन होगी या आसान होगी। दूसरा, आर.ई.एस. के माध्यम से बोल रहे हैं तो ग्राम पंचायत के काम का निरीक्षण कौन करता है, तकनीकी देखरेख कौन करता है, उसका मूल्यांकन कौन करता है, उसका प्राक्कलन कौन बनाता है, किसके देखरेख में काम होता है? ग्राम पंचायत का सरपंच तकनीकी आदमी नहीं है। केवल उसको जनता चुने हैं। एक एजेंसी बस बनता है, बाकी तमाम काम आपके ही अधिकृत सब इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 11,000 से भी ऊपर पंचायत जो 11,664 पंचायत आपके संरक्षण में है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। केवल टेण्डर आमंत्रित किया गया है। आपने कुछ कामों का जिक्र किया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ग्राम पंचायत को बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है, लेकिन कितने कामों को विभागीय किया गया। यदि यह आंकड़ा भी आप दे देते तो छत्तीसगढ़ के सदन में साफ हो जाता कि सरकार की मंशा ठेकेदारों से करवाने का है या फिर जनप्रतिनिधियों से काम करवाने का है। इसमें आप काम की संख्या देख लीजिये। 10,347 कार्य जो केवल शिक्षा मद से स्वीकृत हुआ है। मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप। मुख्यमंत्री ने घोषणा

किया, काम स्वीकृत हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, 20 लाख को 50 लाख करते हैं। उनकी घोषणा का पालन नहीं हुआ। तो 10,347 काम सीधे-सीधे ग्राम पंचायत को जाता और यदि ग्राम पंचायत के सरपंच इस काम को करता तो ज्यादा जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ करता। इसलिए कि वह जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इसी शिक्षा समग्र का नहीं, बल्कि आपके क्राइटेरिया में जितने भी काम हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ग्राम पंचायत का एजेंसी बनाया जाय। चूंकि आपने कहा कि यह तीन विभाग का है। कलेक्टर डी.एम.एफ. का अध्यक्ष है। हम लोग उसके सदस्य हैं। शिक्षा मंत्री जी के संचालक ने आदेश निकाला। उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। ग्राम पंचायत को नहीं बनाया जाना है। ऐसा ग्राम पंचायत ने या तो कलेक्टर को स्वतंत्र छूट दे देते कि आप एजेंसी तय कर लो। अभी शिक्षा मद और डी.एम.एफ. के जो काम है, मेरे जांजगीर-चांपा जिले में 101 अतिरिक्त कक्ष बना है। 15 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। 26 जनवरी को लोकार्पण हो गया। सभी काम ग्राम पंचायत ने किया है। रामकुमार जी भी बता देंगे। बहुत गुणवत्ता सहित काम किए हैं और अभी आप टेण्डर डालेंगे। कब उसका कार्य एजेंसी तय होगा, कब वह बनाना शुरू करेंगे और उनकी गुणवत्ता की क्या गारण्टी है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जितने भी हाथी लोग बोलते हैं, पूरा मंत्रिमण्डल यह सरकार की संयुक्त दायित्व है। संयुक्त दायित्व का निर्वहन करते हुए कृपया सदन में घोषणा कर दें कि यह सभी काम जो 50 लाख रूपये से नीचे का है, जिसमें तकनीकी रूप से कोई बड़ी बात नहीं है बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत बना रहे हैं, सामुदायिक भवन बना रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत सी.सी. रोड बना रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि यह सभी काम जो है, उसका कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया जाये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छा लगा कि माननीय केशव चंद्रा जी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों का काम जांजगीर जिले में बहुत अच्छा हो रहा है । कितने स्कूल-भवन बनाये गये, मैं आपको बधाई देता हूं । मैं अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं सरपंच लोग उनको भी बधाई देता हूं लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आपने 3-3, 4-4 विभागों का एक-साथ लगा दिये हैं, हर विभाग में अगर इसका लग जाता तो शायद इसका उत्तर हो जाता उसके बावजूद भी विभाग चाहता है कि अपने विभागीय कार्य जो 50 लाख तक की सीमा के हैं उसको ग्राम पंचायत बेहतर करे । अन्य विभाग जिनको जैसा अधिकार दिया गया है, अब डी.एम.एफ. का माईनिंग में जो रूल्स है उसका पालन किया जायेगा । ट्राईबल क्षेत्र में जिनके रूल हैं उनका पालन किया जायेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, हम नियम पालन करने की ही तो बात कर रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपकी बात कह रहा हूं न ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- या फिर वे संवेदनशील नहीं हैं मुख्यमंत्री ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लीजिये, आपने ही लिखा है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, हमने लिखा है । आप उनको असंवेदनशील बना रहे हैं या फिर वे संवेदनशील नहीं हैं । उनकी घोषणा की यह मंत्रिमण्डल जो है कद्र नहीं करता या उनके आदेश का आप लोग पालन नहीं करते । वे तमाम् जनप्रतिनिधि जो 11,664 जनप्रतिनिधि हैं वे आपके विरोधी हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चलिये आप दल के आधार पर राजनीति करते हैं तो आपके दल के सरपंच को आप एजेंसी बना दीजिये । हमारे दल और इनके दल के सरपंच हैं उनको छांट-छांटकर विभाग को दे दीजिये लेकिन आप अपने दल के सरपंचों को कार्यएजेंसी बना दीजिये लेकिन मेरा निवेदन है कि आप उनके अधिकार का हनन मत कीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दल का सरपंच यदि होता तो हम दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा लेते । सरपंच का कोई दल नहीं है, सब हमारे प्रतिनिधि हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- दल नहीं होते । पुन्नूलाल मोहले जी का आने दीजिये फिर आप मूल प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि 50 लाख तक के काम पंचायतों को दिया जाये । शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो या डी.एम.एफ. फंड हो, 50 लाख का काम दिया जाता है और पंचायतों को जब काम दिया जाता है तो उनको 50 लाख तक का अधिकार दिया जाये । जैसे स्कूल वाले में 2 लाख रूपये की मरम्मत या 3 लाख रूपये की मरम्मत होती है लेकिन पूरे क्षेत्र को मिलाकर उसको एक करोड़ का बनाकर विज्ञापन निकालते हैं टेण्डर और पंचायतों को काम नहीं मिलता है तो अगर पंचायतवार किया जाये तो कोई भी विभाग होगा वह मिल सकता है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चाहे डी.एम.एफ. फंड हो, कहीं हो । क्या आप ऐसा आदेशित करेंगे तो पंचायत में सबको काम मिल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी उत्तर दीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ममा, तोर इंहां 157 डी.एम.एफ. के काम मुंगेली जिला के सरपंच मन करत हे । अइसे नइ हे कि कोनो मेर सरपंच मन ला काम नइ मिले हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरा इतना ही कहना है कि 50 लाख तक के बंधन को रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बांधी जी आप भी एक प्रश्न कर लीजिये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के सरपंचों को जो आपने अधिकार दे दिया है लेकिन उसमें परिभाषित नहीं किया था कि इन-इन विभागों को छोड़कर पंचायत को अधिकार दिया जाये । वे तो केवल भलमनसाहत यही समझे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, उसका उत्तर आ गया है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मेरी बात ही नहीं आ पायी है । किसमें सी.एस.आर. मद से भी आता है, उसको भी टेण्डर कर देते। माननीय मंत्री जी, कुल मिलाकर जो

भी पैसा आना है वह ग्राम पंचायत में आना है और ग्राम पंचायत में ही एजेंसी बनाकर के उसको निर्णय करने का है । जो अलग-अलग परिभाषा है उसको ग्राम पंचायत को कर दिया और केशव जी जो एजेंसी बोल रहे हैं, वह एजेंसी तो है ही । आपके पास आर.ई.एस. है, पी.डब्ल्यू.डी. है, हर एजेंसी है । आपके पास जांच है, उसके मार्गदर्शन में निर्माण करेगा लेकिन उनका अधिकार पंचायत को देने का आप निर्णय करें तो आपके लिये भी वाहवाही है नहीं तो लोग आपको इस मामले में अच्छा नहीं समझ रहे हैं । कथनी और करनी में अंतर आ रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब डॉ. साहब ने तो पी.डब्ल्यू.डी. के भी काम उन्हीं को देने के लिये, पी.डब्ल्यू.डी. और सभी विभागों को ग्राम पंचायत को कैसे दे दोगे भई ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, पी.डब्ल्यू.डी. के छोटे-छोटे काम । पी.डब्ल्यू.डी. का अगर कोई काम आता है । अभी तो क्या खेला चल रहा है कि किसी भी विभाग का आयेगा तो पी.डब्ल्यू.डी. को दे दो, आर.ई.एस. को दे दो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- और आपने दूसरा कहा परिभाषित । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख की सीमा को 50 लाख और 20 लाख की सीमा जो थी वह वही थी जिसको आपने तय किया था, वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास की राशि को खर्च करने का ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्रा साहब एक प्रश्न और करिये फिर दूसरे में जायेंगे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो जो गंभीर प्रश्न है उसका माननीय मंत्री जी ने जवाब ही नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- लगभग सब प्रश्नों का तो आ गया ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं-नहीं, संचालक ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि ग्राम पंचायत को एजेंसी न बनाया जाये ? क्या संचालक को यह आदेश जारी करने का अधिकार है या यह आदेश सही है या गलत ? कृपया मंत्री जी यह बता दें कि उन्होंने अगर कहा है पंचायत के प्रति दुर्भावना रखते हुए, कलेक्टर को एक-तरफ तो बोलते हैं कि एजेंसी तय करने का अधिकार है, वे प्रशासकीय स्वीकृति देंगे । दूसरी तरफ बोलते हैं कि ग्राम पंचायत को एजेंसी न बनाया जाए। क्या उस संचालक को अधिकार है? और अगर अधिकार नहीं है तो ऐसा आदेश क्यों दिये? कृपया, मंत्री जी यह बता दें और अगर वह आदेश गलत दिये हैं, ऐसा पंचायत के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति दुर्भावना रखते हुए तो उनके प्रति आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- श्रीमान, मैंने यही कहा कि आपने गलत जगह प्रश्न लगा दिया न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपकी बात समझ गया। अब वहां का आदेश क्यों निकला, इसको बुलाकर पूछ लेंगे। इन सारे कारणों से हम हमने पंचायत विभाग के किसी भी निधि को 50 लाख तक के पंचायत से ही काम करवायेंगे, यह समझ लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न। मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों का यह अपमान है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम सहमत हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था का अपमान है कि किसी ग्राम पंचायत को एजेंसी न बनाया जाए करके एक संचालक आदेश जारी करे। ठीक है, विभाग एजेंसी नहीं बनाता है। मत बनाए, लेकिन क्यों ग्राम पंचायत के प्रति वे ऐसा आदेश निकालेंगे? कृपया, माननीय मंत्री जी, चूंकि आपके विभाग में आ गया। जवाब आपको देना है। आप ग्राम पंचायत के संरक्षक हैं। ये सब, ये तमाम, अगर ये स्पष्ट नहीं होगा, 11 हजार 664 ग्राम पंचायत के प्रति अन्याय होगा तो इन सबको नुकसान होगा। मैं आपको इस सदन में बोल रहा हूं। आपकी राजनीतिक क्षति होगी। इसलिए आप कम से कम अपनी राजनीतिक क्षति को बचाने के लिए उस ग्राम पंचायत को आप अधिकार दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ये सब मौन हैं, मतलब सब की स्वीकृति है। आपके पक्ष में हम लोग भी हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब हमारी राजनीतिक क्षति की चिंता आप कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। (हंसी) आदरणीय केशव जी, अलग-अलग विभाग अपने-अपने नियमों से काम करते हैं..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, सौरभ सिंह जी। आ गया।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह तो आश्वस्त कर दें कि उन विभागों से मैं चर्चा करके इसमें विचार करेंगे। ग्राम पंचायत को देने लायक रहेगा तो वे देंगे, एक बार आश्वासन तो दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी पूरा सक्षम हैं। सौरभ सिंह जी। सब आ गया केशव जी। समझ गया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि..।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसी विषय में?

श्री सौरभ सिंह :- इसी विषय में पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, सौरभ सिंह जी, आप अपने ध्यानाकर्षण में आइए। वह विषय खत्म हो गया।

श्री सौरभ सिंह :- एक मिनट। आपने टेंडर कर दिया। आपने आर.ई.एस. को एजेंसी बना दिया। मेरा आपसे आग्रह है। स्कूल का मामला है। इसको समय-सीमा में टेंडरिंग करके काम कब चालू करायेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौरभ जी ने बहुत बढिया प्रश्न किया है। समय-सीमा में काम हो, इसीलिए यह आदेश जारी किया गया है। हम सुनिश्चित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका खुद का ध्यानाकर्षण।

(2) प्रदेश में पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी होना।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ के 47 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी, 32 सरकारी व 14 निजी पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं। इनमें इस साल में कुल 8664 सीटें थीं, जिनमें केवल 22 प्रतिशत ही भर पाई हैं। सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थिति कुछ बेहतर है। निजी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में स्थिति अधिक खराब है। जो 5 नये पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं, उनके लिए 65 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे। सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज में गर्ल्स की ट्यूशन फीस माफ है, यानी उन्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, फिर भी दाखिले कम हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षा से लड़कियों का पॉलीटेक्निट के प्रति रूझान बहुत कम हो गया है। पॉलीटेक्निक के कुछ ब्रांचेस में छात्रों की सूची ही लगभग खत्म हो गई है। वर्ष 2018-19 में 41.3 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में 40 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 47.6 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 36.5 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 22.2 प्रतिशत सीटें खाली थीं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज्यादातर सीटें खाली हैं। इन ब्रांचेस में पिछले 5-6 सालों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध न होने एवं नए उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। जिन ट्रेड्स में रोजगार की अधिक संभावना है, उनके सीटों की संख्या न बढ़ाने के कारण एवं रोजगार न मिलने से प्रदेश के युवाओं और अभिभावकों में रोष और आक्रोश व्याप्त है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश में कमी आई है और इस वर्ष 22.26 प्रतिशत सीटें ही भरी हैं । सरकारी

कॉलेजों में प्रवेश का प्रतिशत 29.9 है । यह कहना भी सही है कि प्रस्तावित 5 नए कॉलेजों पर लगभग 65 करोड़ रूपए का व्यय अनुमानित है ।

यह कहना सही है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज में छात्राओं की फ़ीस माफ़ है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में छात्राओं के प्रवेश की स्थिति पूरे देश की तुलना में बेहतर है । जहां छत्तीसगढ़ में छात्राओं का प्रवेश प्रतिशत 21.85 है । वहीं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण देश में छात्राओं का प्रतिशत 18.13 है और निकटवर्ती राज्यों में सत्र 2017-18 से 2021-22 तक छात्राओं की भागीदारी मध्य प्रदेश में 13.23 प्रतिशत, ओडिशा में 18.13 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 12.1 प्रतिशत एवं झारखड में 14.96 प्रतिशत रही है ।

इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति रूझान बढ़े । राज्य में जिन ब्रान्चेस में प्रवेश की मांग है उसके अनुरूप नवीन कॉलेजों में उक्त ब्रांच खोले जा रहे हैं । शासन के द्वारा सभी ब्रांचों में पर्याप्त सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ।

प्रदेश के पॉलीटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को न केवल प्रदेश के भीतर बल्कि प्रदेश के बाहर भी रोज़गार प्राप्त होता है । सच यह है कि विभिन्न ब्रांचों में रोज़गार के अवसर घटते बढ़ते रहते हैं जो बाज़ार एवं उद्योग की मांग के अनुरूप होते हैं ।

इसलिए यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में रोज़गार के साधन उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश के युवाओं और अभिभावकों में रोष और आक्रोश व्याप्त है ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में माना है कि 30 प्रतिशत सीटें ही भरी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ़ तो हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी की दर ज़ीरो दशमलव कुछ है और दूसरी तरफ केवल 30 प्रतिशत सीटें भरी हैं । बाक़ी के बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं ? रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है ना, इसलिए वे पढ़ने नहीं आ रहे हैं । मंत्री जी, वे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, जो सौरभ सिंह जी भी पढ़े लिखे हैं । मैंने भी इसी क्षेत्र से पढ़ाई की है इसलिए यह बताना चाहूंगा और वे भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हर क्षेत्र में एक पीक समय आता है और एक डाउन समय आता है । वैज्ञानिक भाषा में उसको Sinusoidal graph कहते हैं । एक बार पीक आता है और फिर बहुत ज्यादा डाऊन आता है । 1998 से 2006 तक का पीरियड ऐसा था जो प्रौद्योगिक क्षेत्र का पीक समय था । अभी दुर्भाग्य से अभी हम लोग एकदम डाऊन की स्थिति में हैं । यह कभी अप होता है और कभी डाउन होता है । ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ग्राफ नीचे जा रहा है । मैं इस बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में एडमिशन की संख्या कम है । लेकिन अगर आप पूरे देश का आंकड़ा देखेंगे तो सभी जगह हर साल दर साल कमी आती जा रही है । यह सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे देश का मामला है और उसी अनुपात में छत्तीसगढ़ में भी

कमी आई है । हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं । हमारे जो प्राचार्य हैं, हर स्कूल, कॉलेज में काउन्सिलिंग सेशन भी लेते हैं । ताकि हमारे बच्चे इसमें आएं । इसकी प्रक्रिया यह है कि प्रवेश परीक्षा होती है उसके बाद काउंसिलिंग होती है और उसके आधार पर प्रवेश होता है । काउंसिलिंग भी ली जाती है ताकि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा एडमीशन हो सके ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है । प्रवेश में कमी आ रही है वह साइक्लिक प्रक्रिया है । मैं वही चीज तो बोल रहा हूं । मेरे ध्यानाकर्षण का अंतिम पार्ट यह है कि यदि उद्योग नहीं आएंगे, ट्रेडों में भर्ती नहीं होगी, उसकी मांग नहीं आएगी तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सीधी बात है । अगर मांग नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 65 करोड़ रूपए की लागत से 5 नए कॉलेज बनाए जा रहे हैं । जब आपके जवाब में है कि केवल 30 प्रतिशत सीटें ही भर रही हैं तो 65 करोड़ रूपए खर्च करके नए कॉलेज क्यों खोल रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, इनके सवाल में ही जवाब है । हमारे प्रदेश में कई नए जिले बने, कई नए ब्लॉक बने, कई नई तहसीलें बनीं । उनको देखते हुए और जनप्रतिनिधियों और वहां के लोगों की मांग को देखते हुए इन कॉलेजों को खोला जा रहा है ताकि एडमीशन की संख्या और बढ़े ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार के पैसे का अपव्यय है।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ भैया, एक सेकंड, नये कॉलेज खोलने से हो सकता है, प्रतिशत में कहीं न कहीं कमी आ जाए लेकिन सीट की संख्या तो बढ़ेगी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पैसे का अपव्यय है। आप 30 प्रतिशत सीट भर रहे हैं। आप जो खाली सीटें हैं उनको भर नहीं पा रहे हैं और 65 करोड़ रूपया खर्च करके 5 नये कॉलेज खोल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी 30 प्रतिशत सीटें भरी हैं, आपने यह सर्वे कराया कि किस-किस ब्रांच में मांग है और कितनी-कितनी मांग है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 65 करोड़ की अनुमानित मांग है, यह अपव्यय है। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर हमारे एक स्टूडेंट का भला इन कॉलेजों से होता है तो हम इसको सफल मानेंगे। अगर इसमें एक स्टूडेंट की जिंदगी संवरती है तो हम इसको सफल मानेंगे। (मेजों की थपथपाहट) यह कहीं अपव्यय नहीं है, यह बच्चों के भविष्य को लेकर है, मांग के अनुरूप है और हम उन ब्रांचों को खोलने जा रहे हैं, जहां मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चंद्राकर जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक छोटी सी मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी सबको मौका मिलेगा। चूंकि यह शिक्षा का विषय है, मैं सबको मौका दे रहा हूं। इनके बाद आपका प्रश्न रहेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के बच्चों के हित का मामला है। यह निहित जनहित का मामला है, शिक्षा का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा साहब, मौका देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह सर्वे कराया कि किन-किन ब्रांचों में मांग है और किन-किन ब्रांचों में मांग नहीं है। क्या आपके पास सर्वे है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शैलेश पाण्डे :- मंत्री जी।

श्री उमेश पटेल :- हम लोगों ने इसको जनप्रतिनिधि की मांग के अनुरूप खोला है। वहां के लोगों की मांग के अनुरूप खोला है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से नये कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं नये कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 70 प्रतिशत सीटें खाली है।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ सिंह जी पूरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा उत्तर आने दीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- भैया एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पेपर की हेडलाईन है, आप सभी ने, पूरे प्रदेश ने, आपने भी पढ़ी होगी, अमेरिका के दो-दो बड़े बैंक दिवालिया घोषित हो गये। क्यों...।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसमें कैसे आ गया ?

श्री शैलेश पाण्डे :- इसमें लिंक है ना। उन्होंने पूरा स्टार्टअप का जो पैसा है, स्टार्टअप का पैसा हमारे देश में भी आया। हमारे देश में स्टार्टअप के लिए फंडिंग की गयी। सौरभ भैया भी जानते हैं, आप भी पढ़े होंगे। दिवालिया घोषित हो गए। माननीय मंत्री जी अब उन स्टार्टअप का क्या होगा ? जो यह है। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह इस बात को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन सभी चीजें मार्केट बेस्ड होती हैं, जॉब भी मार्केट बेस्ड होते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यह उत्तर दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे साहब, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं एक बात माननीय मंत्री जी के पक्ष में रख रहा हूं। उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी बैठिए। मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से औद्योगिक परिस्थितियां हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैटेलर्जी, माईनिंग, सिविल, ये ऐसे ब्रांच हैं, जहां सर्वाधिक मांग आता है। यह हमने अपने अनुभव से देखा है और जो हमने स्टडी की है, उसमें पाया है। जहां तब बात आई है, हमने इन्हीं ब्रांचों को लेकर नये कॉलेज खोलने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए चंद्राकर साहब। आपके 6-7 प्रश्न हो गए।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूं। आपने ए.आई.सी.टी.सी. की बात की। आपने टेक्निकल बातें की। क्या आपने जो आई.आई.टी. में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पालिटेक्निक में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह स्पष्ट दिशा निर्देश है कि बगल के उद्योगों में उनको अपरेंटीशीप कराई जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी, चूंकि वह आगे जाब के लिए वह बेहतर इक्यूप हों, आपने इसके लिए कोई दिशा निर्देश दिया है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरे टेक्निकल एजुकेशन की बात की। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने टाटा कंशलटेंसी के साथ एम.ओ.यू. किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह आई.टी.आई. के लिए है।

श्री उमेश पटेल :- हां जी, इन्होंने पूरे टेक्निकल की बात की है। चंद्राकर जी पूरी बात सुना करें। मैंने अपनी पहली लाईन में कहा कि इन्होंने पूरे टेक्निकल एजुकेशन की बात की है इसलिए मैं उत्तर यहां पर आई.टी.आई. की बात कर रहा हूं। आप पूरा उत्तर सुन लिया करें। आई.टी.आई. में हमने टाटा कंशलटेंसी के साथ एम.ओ.यू. साईन किया है और हमारे 36 ऐसे कॉलेज हैं, जिसको हम नेशनल लेवल के आई.टी.आई. के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो बजट का प्रावधान है, वह इस बजट भाषण में भी आ रहा है। सरकार की तरफ से उसमें जो भी पैसा लगेगा। सौरभ जी, हम इसको अपव्यय की तरह नहीं देखते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जो सवाल पूछ रहा हूं, मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। यह ए.आई.सी.टी.ई. का क्लियर कट गाइडलाइन है कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उनको नियरेस्ट उद्योग में वोकेसनल ट्रेनिंग और अप्रेन्टिसशिप के लिए भेजा जाएगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह व्यवस्था की है? यह एक लाइन की बात है।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है, अब आप मेरी बात सुनिये। आप इधर-उधर देखने के बजाय पूरा उत्तर सुनिये।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, मैं आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका प्वाइंटेड उत्तर दे दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- मैं एक लाइन में उत्तर नही दूंगा, में आपको पूरा उत्तर दूंगा। आपको धैर्य रखना चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- आप भाषण मत दीजिए। आप एक लाइन में बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, मुझे पूरा उत्तर देना है।

श्री सौरभ सिंह :- फिर आप हमारा भी भाषण सुनिये।

श्री उमेश पटेल :- आप बाद में अपना भाषण सुनाइयेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने आई.टी.आई. में यह कोशिश की है कि हम इन्हें हमारे नेशनल लेवल की अन्य जगहों के लेवल तक पहुंचा सके। हम इसको अपव्यय नहीं मानते हैं क्योंकि हम बच्चों के भविष्य को लेकर बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह जो उत्तर चाह रहे हैं, आप उनको वह उत्तर दे दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- जहां तक वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्पष्ट गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और उसकी रिपोर्ट आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी, आप बोलिये।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, आप एक उद्योग बता दीजिए, जहां आपके सरकारी आई.टी.आई. के बच्चे ए.आई.सी.टी.ई. के कानून के तहत् वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए गये होंगे या आपने उनके लिए अप्रेन्टिसशिप की व्यवस्था कराई होगी ? आप मुझे एक उद्योग बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, आप उत्तर मत दीजिए। चंद्राकर जी, अब आप प्रश्न पूछिये, मंत्री जी एकसाथ इसका जवाब देंगे। मंत्री जी, आप देख लीजिएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि मैं भाषण शैली में बोलूंगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया में बहुत सारे नये विषय आये हैं। छत्तीसगढ़ के आई.टी.आई. हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, यदि हम उद्योगों की मांग के हिसाब से उनको तैयार नहीं करेंगे तो वहां पर प्रवेश तो होगा ही नहीं और बच्चे प्राइवेट में या नई जगहों में जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- सही है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं माननीय मंत्री जी से दो लाइन में इतना ही जानना चाहता हूं। पहला, पॉलिटेक्निक कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए इन 4 चार सालों में कितने और नये विषय खोले गये ? मैं इसको और संक्षिप्त कर देता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित है कि पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न स्तर के कितने पद रिक्त हैं ? उनके सेटअप के नाम अलग-अलग होते हैं। विभाग अध्यक्ष से लेकर नीचे तक के कितने पद रिक्त हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप रिक्त पद बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कितने पद रिक्त हैं और कितने पद भरे हैं, मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है। यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको अलग से इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको मंत्री जी अलग से जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। विनय जायसवाल जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, इसके बाद मंत्री जी आपका उत्तर भी दे देंगे। शर्मा जी, अभी इनके बाद आपका प्रश्न है।

श्री अजय चंद्राकर :- पूरे पद खाली हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य का जो ध्यानाकर्षण है, उसमें इन्होंने बोला कि 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 65 करोड़ रूपये का प्रावधान अपव्यय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने माननीय मंत्री जी से मांग की थी और मेरे यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। वह पूरा माइन्स एरिया है और माइनिंग ब्रांच के साथ खासकर एक ऑफिस मैनेजमेंट का दूसरा ब्रांच भी है। मंत्री जी ने हमारे यहां पॉलिटैक्निक कॉलेज खोला और आज हमारे यहां के अधिकतर बच्चे राजस्थान के कोटा में जाकर माननिंग की ट्रेनिंग करते हैं और दूसरी बात यह है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे तो जितने भी वहां पर एस.ई.सी.एल. में वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं। एक साल का वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद एस.ई.सी.एल. अपना पल्ला झाड़ देती है। खैर, यह विषय नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी वहां पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है उससे हमारे बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा और अब वह चिरमिरी में ही अपनी माइनिंग की ट्रेनिंग कर लेंगे। यह तो इतनी अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप तो उत्तर दे रहे हैं। मैंने आपको प्रश्न करने के लिए कहा है। आप अपना प्रश्न करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न ही कर रहा हूं कि उसको जल्दी से जल्दी इस बार का जो सेंक्शन है उसको करवा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी। इसके बाद शर्मा जी का प्रश्न है।

श्री सौरभ सिंह :- आप जो बोल रहे हैं वह खुला ही नहीं है। आप उसको खोलने की मांग कर लीजिए। आप मेरे प्रश्न करने के बाद जो प्रश्न किये, उसमें मंत्री जी खुद बोल रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- आगे मैं उसको जल्दी खोलने की मांग कर रहा हूं। आपने तो उसको अपव्यय बता दिया और हमारे क्षेत्र की पूरी जनता इसको देख रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, आप लोग आपस में बात मत कीजिए। मंत्री जी, आप सीधे इधर उत्तर दीजिए। जायसवाल जी, यह आपका एक अंतिम प्रश्न है।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कि इसको जल्दी से करें।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जो चिरमिरी का क्षेत्र है जिस तरह से वहां खदानें रही हैं और वहां माइनिंग डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि सर्वे हुआ है हमारा भी अनुभव रहा है। हम इसको बहुत जल्द से जल्द खोलेंगे और हम लोगों को उसमें सुविधा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रमोद कुमार शर्मा जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरी एक मांग है, जिसको मैं प्रश्न मैं बदल देता हूं। आप बलौदा बाजार के प्रभारी मंत्री हैं। बलौदाबाजार में पॉलीटेक्निक कॉलेज है और वहां में 7 सीमेंट प्लांट हैं । डी.एम.एफ. में भी भरपूर पैसा है तो वहां के पॉलीटेक्निक कॉलेज में सीमेंट टेक्नालॉजी का कोर्स खुलवा देंगे क्या ? फंड की भी कमी नहीं है, पॉलीटेक्निक कॉलेज में सीमेंट टेक्नालॉजी का कोर्स खुलवा देंगे तो लोगों का भला हो जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है । आप और मैं इस विषय में चर्चा कर लेंगे और बच्चों के लिए जो अच्छा भविष्य होगा, उसको कर लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

समय :
1:46 बजे

<u>नियम 267 क के अंतर्गत शून्यकाल की सूचनाएं</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा:-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री मोहन मरकाम
3. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

समय :

1:46 बजे

<u>अनुपस्थिति की अनुज्ञा</u>

<u>निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-8, सामरी (अ.ज.जा.) के सदस्य श्री चिन्तामणी महाराज</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-8, सामरी के सदस्य श्री चिन्तामणी महाराज द्वारा मार्च-2023 सत्र में दिनांक 13 मार्च, 2023 से दिनांक 17 मार्च, 2023 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है ।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 13 मार्च, 2023 से दिनांक 17 मार्च, 2023 तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा ।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-8, सामरी के सदस्य श्री चिन्तामणि महाराज को मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 13 मार्च, 2023 से दिनांक 17 मार्च, 2023 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये ?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अनुज्ञा प्रदान की गई।

समय :

1:47 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्री पुन्नूलाल मोहले
2. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
3. श्रीमती संगीता सिन्हा

समय :

1:47 बजे

<u>वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और आपके समक्ष अपनी बातें रखना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन सभी विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कार्य किया है, जिनकी घोषणा हमारी सरकार ने की थी । मुझे यह बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं, जिस सरकार ने न्याय और न्याय की परिभाषा को जनता के बीच में लेकर गई है । जिस सरकार ने विश्वास की परिभाषा को प्रस्तुत किया है । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम सरकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" की बात कही थी । एक ऐसा छत्तीसगढ़ जो यहां के मूल विषयों पर आधारित हो, जो जरूरतें, जो उम्मीदें, जो जनता की मांगे हैं, उनके ऊपर आधारित हो । जनता के द्वारा मांगा हुआ विकास हो, उस पर आधारित हो । मुझे इस बात को कहते हुए बेहद खुशी होती है और इस सदन के लिए यह गर्व की बात है कि पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली को अब सी.जी. मॉडल के रूप में पूरे देश में देखा जा रहा है । यह जो सी.जी. मॉडल है, उसे पूरे देश के अंदर अन्य सरकारें भी उस पर चर्चा कर रही है और इसकी योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रही है । यह बड़े उत्साह की बात है कि इस सी.जी. मॉडल से जो हमारे दलों से वैचारिक रूप से मतभेद भी रखते हैं, वह सरकारें भी इस मॉडल का अध्ययन कर रही हैं । आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम शुरूआती दौर की बात करें तो जब किसानों के कर्ज माफी की बात होती थी तो विपक्ष के नेता उसका उपहास करते थे, लेकिन आज के समय में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ का जो मार्केट डेव्हलप है, वह किसानों को समृद्ध करके ही बना है । जहां तक हमने देखा है कि किसान एक ऐसा विषय है, जो हमेशा विपक्ष का प्रिय होता था, लेकिन पहली बार हमारी सरकार, हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने किसानों के पूरे विषय को बहुत बारीकी से देखा, अध्ययन किया और कार्य किया, जिससे पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़ी है। चाहे वह कर्ज माफी की बात हो या 2500 रूपया धान के समर्थन मूल्य की बात हो, वह आज बढ़कर 2900 रूपया हो रहा है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जिससे किसानी को फायदा हुआ है। बिना ब्याज के ऋण, राजीव गांधी भूमिहीन योजना की बात हो, ये सब ऐसे आयाम हैं, जिससे कहीं न कहीं जनता का विश्वास सरकार की ओर बढ़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम गोधन न्याय योजना की बात कर रहे थे। जब हम गोधन न्याय योजना शुरू किए तब हमारे विपक्ष के मित्रों ने छत्तीसगढ़ शासन का जो चिन्ह है, उस पर गोबर की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया में वायरल किया, उसका मजाक उड़ाया, उपहास किया। किसका उपहास किया ? हमारे गांव के गरीब किसानों का उपहास किया। जो गौ पालन से जुड़े हुए लोग थे, उनका उपहास किया। लेकिन आज उनके लिए वह उपहास सिरदर्द बनता हुआ दिखता है। जिस प्रकार से केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोधन न्याय योजना को अध्ययन करा रही है, अन्य राज्यों की दूसरी सरकारें भी इस विषय पर मंचों में भाषण दे रही है। इससे दिखता है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़

के आम गरीब परिवार, जो गौधन, पशुपालन या गोबर से जिनका रोजगार या जिन्दगी जुड़ी हुई थी, उनका उपहास विपक्षियों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम वैसे ही कहे, पहले की 15 साल की सरकार और इस सरकार में बेसिक अंतर गति और निर्णय का है। जनता के जो-जो विषय हैं, यह सरकार बहुत तेज गति से उन पर काम कर रही है। यह निर्णय लेने वाली सरकार है। यह सरकारी कहीं भी किसी भी विषय पर कन्फ्यूजन में नहीं रहती है। यह सरकार परिणाम देने की ओर आगे बढ़ती है। अगर हम पिछले 15 साल के किसानी को देखें तो किसानी में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लोगों ने उसमें अपना भविष्य नहीं देखा था। लेकिन इस 4 साल की सरकार में जितना खेती का रकबा बढ़ा है, जितनी फसलें बढ़ी हैं या अन्य फसलों को भी बढ़ावा दिया गया है, उससे हम जैसे जो युवा हैं, जो पहले यह सोचते थे कि हम इंजीनयरिंग और डाक्टरी करके ही अपनी जिन्दगी गुजार सकते हैं, वे अब कृषि की पढ़ाई करके अपने गांव की जो उनकी पैतृक जमीन है, उस पर से धन कमा रहे हैं और एक उदाहरण के रूप में उनका सेटअप बन रहा है। हमारे ही क्षेत्र, दुर्ग जिले में युवाओं की एडवांस्ड मछली पालन, fish farming की तकनीक मैंने खुद जाकर देखी हैं, जो देखते बनती है। यह इस सरकार का मूल आधार है। लोगों की जो जरूरतें हैं, उस पर सरकार कैसे सहयोग करे, ताकि उनकी जीवनशैली बढ़ें, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हम पिछले समय के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हमें आंखफोड़वा काण्ड याद आता है, गर्भाशय काण्ड याद आता है। हमारी माताओं, बुर्जगों के साथ स्वास्थ्य विभाग में जो अन्याय हुआ है, वह याद आता है। लेकिन अगर इस सरकार को देखें तो सुविधाएं लोगों तक कैसे पहुंचाना चाहिए, कैसे करीब ले जाना चाहिए, इस पर हमारी सरकार ने बेहद करीब से ध्यान दिया है। चाहे दाई-दीदी क्लिनीक हो या मोबाइल मेडिकल यूनिट हो या हमर लैब योजना हो, इस तरह की योजनाओं से हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। आपने बजट में देखा होगा कि मेकाहारा, जो हमारे प्रदेश की धड़कन है, स्वास्थ्य की धड़कन है, मेकाहारा को मजबूत करने के लिए 85 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। वहां पर 700 सौ बिस्तर बनाये जायेंगे। जिससे पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य से जुड़ी जनता वहां आती है, उनको इसका लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहीं हम शिक्षा की बात करे, सबसे पहले लोगों के मन में एक भाव आया। आज विपक्ष के लोग जब भी चर्चा करते हैं तो हमारी घोषणा-पत्र पर चर्चा करते हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं, जिसके घोषणा-पत्र पर जनता विश्वास करती है और उतना ही विश्वास विपक्ष भी करता है। उनके पास कहने की बात होती है तो पहले घोषणा-पत्र निकालते हैं और बताते कि यह पाईन्ट छूटा है या आपने कुछ कर दिया या कुछ बचा है । अगर हम

पिछली सरकारों के पुराने घोषणा पत्रों को हम देखें, उसमें औसतन 20 प्रतिशत की भी मांगे तो यह घोषणायें पूरी नहीं हुई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- देवेन्द्र जी, घोषणा पत्र की बात कर रहे हो, मैं तो आता हूँ तो अपने बस्ते में आपका जनघोषणा पत्र साथ लेकर आता हूँ । उसमें 36 पाईन्ट है । एकाध पाईन्ट पढ़कर बता दो कि इस काम को हमने पूरा किया है ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर ला मैं जेब में धरे-धरे किंजरथंव ।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय, सभी काम पूरा कर रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीति की बात होती है, नियत की बात होती है । हमारी नीति और नियत कितनी साफ है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार कानून आया...।

श्री शिवरतन शर्मा :- 36 बिन्दुओं में कौन सा काम पूरा किये हो, इसका भी जवाब दे दो ना ।

श्री देवेन्द्र यादव :- धैर्यपूर्वक सुनिये । उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार के कानून की बात हुई । हमारी सरकार ने एक ऐसा कानून लाया कि गरीब तबकों के बच्चों को मुख्यधारा में लाने का मौका मिला । हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस शिक्षा के अधिकार कानून को हम बारहवीं तक ले जायेंगे । हमारी सरकार बनते ही तुरन्त इसको लागू किया और विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके विधान सभा में हजारों बच्चे होंगे, जो 10 वीं तक शिक्षा के अधिकार का लाभ पाते थे, अब 12 वीं तक पाते हैं और हमारी सरकार उनको अधिकार देने का काम कर रही है । यह हमसे क्या बात करेंगे, शिक्षा के बारे में क्या बात करेंगे, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इनके कार्यकाल में 3 हजार स्कूलों को बंद किया गया और इससे बड़ी बात अगर कहूं तो जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे रहे हैं, वे जिस स्कूल में पढ़ें हैं, प्रायमरी स्कूल खैरागढ़ में जो पढ़े हैं, उन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 2015 में उस स्कूल को भी बंद किया गया । यह शर्म की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा पर लगातार कार्य किया है । आज देखिये, जनता को विश्वास है, 247 से अधिक हमारे आत्मानंद स्कूल खुल चुके हैं, हम 101 नये स्कूल खोलने जा रहे हैं, आप देखेंगे आज ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है, खुर्सीपार के आत्मानंद स्कूल के बच्चे मुझसे मिलने आये थे, जिन्होंने पूरे प्रदेश में टॉप किया है । हमारी सरकार ऐसी शिक्षा बच्चों को देने का काम कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही अगर अधिकारों की बात करें तो इनकी जो कार्यप्रणाली है, लोगों को कहीं न कहीं गुलाम बना रहे हैं । इन्होंने कभी अधिकारों की बात नहीं की है, हमारी सरकार ने अधिकारों की बात की है और अधिकार दिये हैं । आप देखिये, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है, मैं आपसे इसमें विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा । प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ऐसी योजना जिसमें गरीबों को मौका देना है या मदद करनी है, लेकिन उसके लिये ये सर्वेक्षण नहीं करायेंगे । वर्ष 2007-2008 की बात करें तो सर्वे सूची को आज भी बेस बनाकर लोगों

को तकलीफ होती है । हम लगातार आम जनता से मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे पति गुजर गये हैं, हमारे यहां कोई कमाने वाला नहीं है, पेंशन योजना से जोड़ा जाये, अंत में क्या होता है, वर्ष 2007-2008 की सर्वे सूची, इनकी केन्द्र की सरकार तो सर्वे को करवा नहीं रही है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतनी ताकत, इतना जुनून जनता को मदद करने की है, कहते हैं ना कि सरकार यदि योजना बनाती है तो जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको ध्यान में रखकर योजना बनाये तो सरकार की योजना सफल होती है । वैसे सर्वेक्षण करने की बात हमारी सरकार ने की है, इसकी पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूँ, इससे हजारों-लाखों परिवारों को इस प्रदेश में लाभ और सहयोग मिलेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- देवेन्द्र भाई । केन्द्र सरकार ला वर्ष 2022 में सर्वे करवाना रहिसे । एमा चिट्ठी पत्रिका लिखतिस ना ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से वन अधिकार पट्टा हो गया, पर्यावास अधिकार हो गया, सामूहिक पट्टा हो गया, यह आर्थिक सर्वेक्षण हो गया । यह एक ऐसे पायदान है सरकार के जो निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही हम युवाओं की बात करें । पिछली सरकार ने युवाओं के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं किया था, जिस तरीके से किसानों को पिछली सरकार ने धान के बोनस या कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन केवल चुनावी वर्ष में उनका उपयोग करते थे, उसी तरह युवाओं के साथ भी लगातार छलावा हुआ है । मैं इनकी योजना का याद दिलाना चाहता हूँ, एक गांव एक प्रहरी । इन्होंने कहा था कि एक गांव में एक प्रहरी बनायेंगे। इन्होंने 20 हजार गांव चिन्हित किये थे। मैं भी कभी-भी मुख्यमंत्री जी के साथ क्षेत्रों में घूमने जाता हूं, दूसरी जगहों पर जाता हूं, मुझे तो किसी भी गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक भी प्रहरी नहीं दिखा। इससे यह समझ में आता है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने हर आयाम को छूने की कोशिश की है। राजीव युवा मितान क्लब, एक ऐसी योजना है जिसने आम युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। ऐसे लोगों को जोड़ा है जो संस्कृति से, खेल से, पशु-पालन से और शिक्षा से जुड़े हैं। यह योजना किसलिये है ? हमारे हुनरमंद युवाओं को क्या चाहिए। उनको प्रोत्साहन चाहिए। उनको चाहिए कि कोई उनसे संवाद करें, कोई चर्चा करें ताकि उन्हें अपने जीवन को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिले और यह काम हमारी सरकार राजीव युवा मितान योजना से कर रही है। इसमें पूरे प्रदेश भर में 04 लाख 98 हजार सदस्य जुड़े हैं। वह युवा आज खुश है, संतुष्ट है क्योंकि उनको भूपेश बघेल जी पर, भूपेश सरकार पर भरोसा है। उसी तरह हम बेरोजगारी भत्ता की बात करें। यह 2003 में कहते थे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 500 रूपये भत्ता देंगे। मुझे मेरा छात्र राजनैतिक जीवन याद आता है तो उस समय की यह बात याद आती है कि हम रोजगार कार्यालयों में जाते थे, आंदोलन करते थे, धरना करते थे और यह हम पर एफ.आई.आर. करते थे। लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं देते थे। आज हमारी सरकार ने उन युवाओं को

मुख्य धारा में जोड़ने के लिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिये बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है और निश्चित रूप से यह प्रशंसा योग्य है। (मेजों की थपथपाहट) आज युवाओं में इसको लेकर खुशी की लहर है। आप कायदे, कानून, नियम और पता नहीं क्या-क्या बात करते हैं। मैं भी जब मौका मिलता है तो ज्यादा तो नहीं, ऐसी थोड़ा बहुत देख लेता हूं। मैं देख ही रहा था जब सी.एम.आई.ई. का एक सर्वे आया था, वह सर्वे बता रहा था यदि देश के अंदर कहीं पर सबसे कम बेरोजगारी दर है तो वह आपके और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है। इससे समझ में आता है कि यदि कहीं पर खुशहाली है, कहीं प्रेम है, कहीं सद्भाव है, कहीं अपने लोगों को बढ़ाने की चाह है तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की, हमारी पार्टी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की चाह है।

उपाध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस आखिरी पांच मिनटों में अपनी बातों को खत्म करूंगा। मैं इसके लिये भी धन्यवाद करूंगा। रूरल इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट पार्क, एक ऐसी योजना जिसने छोटे स्तर पर, जो लोग सामूहिक रूप से कार्य करना चाहते थे और बड़े सपने देखते थे, उनके सपने को एक उड़ान दी है। आज हम किसी भी गांव में जाकर हमारी बहनों को, युवाओं को बड़ी खुशी से कह पाते हैं कि हम आपको इण्डस्ट्री लगाने का अधिकार दे रहे हैं क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है, इस सरकार पे भरोसा है। यह सरकार युवाओं को उनकी रूरल इण्डस्ट्री लगाने का मौका दे रही है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लाइट मेट्रो। यह आज धीरे-धीरे करके रेलवे को समाप्त कर रहे हैं। यह एक-एक करके हमारे PSU's को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे समय में जब ट्रांसपोर्टेशन की Easy व्यवस्था की जरूरत हो या हमारे Organization की बात हो तो लाइट मेट्रो छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरीके से महिला समूहों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो पिछले 15 सालों से 350 ही थी, आज उसको भी बढ़ाने का हौसला और हिम्मत यदि किसी सरकार ने दिखाई है तो वह हमारी सरकार ने दिखाई है। मैं इसके लिये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करूंगा। उसी तरह मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे क्षेत्र में मैं आंगनबाड़ी सहायिकाओं से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, मितानिन बहनों से मिला। उन्होंने मुझे रंग लगाया, गुलाल लगाया, हैप्पी होली बोला और बोले कि यह गुलाल विधायक जी तुम्हें नहीं लगा रहे हैं, यह हम हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी के प्रति अपना स्नेह तुम्हें गुलाल लगाकर बता रहे हैं। तुम उनके प्रतिनिधि हो, हमारे विधायक हो, यह खुशी यदि चेहरे पर आयी है तो भूपेश सरकार के कारण आयी है । मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि उनको चिन्ता, दर्द और दु:ख किस बात का है ? क्योंकि हमारी आंगन बाड़ी कार्यकर्त्ताओं के चेहरे पर मुस्कान है, उनको इस बात का दुख है ? अगर बढ़ोत्तरी की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है तो आप समझिए, आप 15 सालों तक सरकार में थे, आप उन्हें केवल 6000 रूपये मानदेय देते थे हमने 35-40 प्रतिशत की

बढ़ोत्तरी की और हम 10,000 रूपये देते हैं। यह हमारा मॉडल है, यह छत्तीसगढ़ मॉडल है। यह हमने डेवलप किया। हम उस श्रेणी में नहीं गये कि 200-500 रूपये बढ़ाकर, अपनी पीठ खुद थपथपायें। हमने उनका मानदेय 4000, 2000 और 3000 रूपये बढ़ाया। हमने कहीं कोई कमी नहीं देखी। भले हमारा रसोईया, सफाई कर्मी, होमगार्ड हो, हमने हर एक वर्ग को सम्मान दिया। इस बजट का अपमान जो आप विपक्ष के लोग कर रहे हो। आप किसका अपमान कर रहे हो ? आप हमारे रसोईये, होमगार्ड का अपमान कर रहे हो, जो हमारी मितानिन बहने हैं, जो क्षेत्र में लोगों के लिए काम करती हैं उनका अपमान कर रहे हो। आप खेलों, संस्कृति, पर्यटन की बात करते हो। हमारा प्रदेश बहुत खूबसूरत प्रदेश है। इस प्रदेश में पहले लोगों को यह लगता था कि हम हवाई जहाज से उतरेंगे और हमारा बाहर नक्सली इंतजार करेगा, आज इस प्रदेश को पूरा देश देख रहा है। भले वह आज आदिवासी नृत्य के महोत्सव के रूप में देख रहा है। पूरा विश्व छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम दो लाईनों में अपनी बात को खत्म करूंगा।

श्री अरूण वोरा:- यह लोग भगवान श्री राम जी की बात करते हैं। भूपेश बघेल जी ने इस बजट में कौशल्या महोत्सव हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी भी बोलने की बारी है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जिस तरीके से खेल को प्रोत्साहन दिया है जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है जैसे मुझे इस बजट में एक बड़ा यूनिक लगा, वह है एडवेंचर स्पोर्टस्। हम एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी में ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम यह क्यूं दे रहे हैं आप देखिए। आप अपने प्रदेश में घूमिए आप बस्तर, कोरबा, जशपुर के क्षेत्रों में जाईये । आप देखिएगा कि वहां पर्यटन या एडवेंचर स्पोर्टस् का कितना स्कोप है। उनके लिए यह अकादमी, ट्रेनिंग दी जायेगी। मतलब कितने बारिक लेवल पर, माईन्यूट लेवल पर हमारी सरकार सोच रही है कि हम जो जहां पर प्रतिभा है अगर उसको एडवेंचर पंसद है तो सरकार उसको भी प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस यही कहूंगा कि यह सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर उस दृष्टिकोण पर काम कर रही है, 15 सालों से जिस दृष्टिकोण में इन्होंने आंख में पट्टी बांधकर रखी थी। इनकी यह आंख की पट्टी नहीं खुलेगी क्योंकि यह अपने दृष्टिकोण से जीवन जीना जानते नहीं हैं, अपने दृष्टिकोण से जीवन को समझना नहीं जानते। इनको ड्रम के धुन के आधार पर यह चलने वाले लोग हैं जैसे ड्रम बजता है जिस

दिशा में हांका जाता है वहां यह लोग चलते हैं। इनका दृष्टिकोण नहीं है कि यह जल, जीवन और लोगों की भावनाओं को समझ कर कह पायें। मैं बस यही कहूंगा कि भूपेश है तो भरोसा है। हम इसी तरह जनता के लिए काम करते रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ए तुहरेच लिए हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी आपका नंबर है ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए मन बइठे हे तो उदाहरण देथौं। हमर देवेन्द्र भईया बोलिस हावए। एमन 15 साल ला कइसे करिन। जइसे मालिक लेहे देहे तइसन झिपरा सिसो। 15 साल जइसे लिये दिये में करिस हे। वइसे एमन झोकिन हे। में ए मन ला कहना चाहत हौं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वर्ष 2023 में यही दोहा के उपयोग हो ही। जइसना जेखर तइसन के..।

श्री रामकुमार यादव :- आप केन्द्र बर देखिहौ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप टोका-टाकी न करें। अभी पर्याप्त समय है हम आपको देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे बजट को पढ़ रहा था। पूरे बजट को देख रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे भागती हुई सेना लूट मार करते जाती है । इन 4 सालों में आपने क्या किया ? यह आखिरी बजट में क्यों रख रहे हैं ? आपने बिन तुगलक बादशाह का नाम सुना है ? आज से 14वीं शताब्दी में 900 साल पहले हुआ था। 900 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया। 900 साल में भारत ने बहुत प्रगति कर ली। परंतु छत्तीसगढ़ ने इन 04 सालों में प्रगति की ? अरे, भैया मुख्यमंत्री जी कुछ तो वास्तविकता में, धरातल पर बात करो। छत्तीसगढ़ में बसें नहीं चल रही हैं। केन्द्र सरकार ने बसें दीं, पर वह नहीं चल रहीं हैं। लाईट मेट्रो ट्रेन चलायेंगे। आप कौन सा सपना देख रहे हैं, कहां का सपना देख रहे हैं। आप कहां से चलाओगे ? क्या आपने छत्तीसगढ़ की जनता को [XX][7] समझ लिया है ? आप सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन चलायेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग स्काई वाक बनाये थे, स्काई वॉक का क्या हुआ ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप लोग स्काई वॉक जैसी योजना चलाते थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि अभी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बृजमोहन भैया, आपने राजेश मूणत जी को समझाया था कि स्काई वॉक नहीं बनाना है, लेकिन आपकी बात को नहीं माने।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- एक्सप्रेस-वे की हालत क्या है, उसको भी देखिये न।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया, टोकाटाकी न करें।

डा. विनय जायसवाल :- भैया, यह बुलेट ट्रेन चालू हो गई है ?

श्री रामकुमार यादव :- ओला आज तक नई समझ पाईस का है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह तुगलकी बजट है। यह चमड़े के सिक्का चला देंगे। राज्य सरकार को सर्वे करवाने का किसने अधिकार दे दिया ? केन्द्र सरकार सर्वे करती है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपको आपत्ति इस बात है कि सर्वे हो जाये, बी.पी.एल. श्रेणी में सर्वे हो जाये.. (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- राज्य सरकार भी अपने हित के लिए सर्वे करेगी। आप क्यों घबरा रहे हैं ? ..(व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अगर गरीब लोगों के लिए सर्वे करा रहे हैं तो इसमें आप लोगों का क्या तकलीफ है ? ..(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे, आप लोग सुनने की थोड़ी हिम्मत रखो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ठीक से बोलेंगे तो जरूर सुनेंगे। ..(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल गड़बड़ किये, इसलिए डर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 900 साल पहले तुगलक करता था तो समझ में आता था। आज ये 23वीं सदी चल रही है। यहां पर भी भूपेश नाम का एक ठगेस आ गया है जो पूरे छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कर रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब घबराहट हो रही है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- दिल्ली में मोहम्मद तुगलक बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो संभव नहीं है, जो असंभव है, जो कोई कर नहीं सकता, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कहीं गई हैं। क्योंकि मालूम है कि 6 महीने समय बचा है। 6 महीने बाद तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमको करना कुछ नहीं है। मैं भी 15 साल मंत्री रहा हूं। आखिरी साल के बजट में 50 प्रतिशत भी पैसा खर्च हो जाये तो बहुत बड़ी बात है। परंतु ये मुख्यमंत्री जी जो मांगोगे, वो मिलेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मिल रहा है न ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मिल रहा है। जो मांग रहे हैं, वह मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया शांत रहिये। टोकाटाकी न करें।

श्री कुलदीप जुनेजा :- हर चीज मिल रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसानों को, गरीबों को मिल रहा है। किसानों को मिल रहा है, वह आपकी नजर में रेवड़ी है।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- सबको मिल रहा है, आप क्षेत्र में जाकर पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में नटवरलाल हुआ, उसका नाम मिथलेश कुमार था। उसको 130 साल की जेल हुई। वह राष्ट्रपति भी बन गया। उसने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के दस्तखत से कुछ लोगों की नियुक्ति भी कर दी। वह धीरूभाई अंबानी के भी दस्तखत कर लेता था।

श्री बृहस्पत सिंह :- अडानी का दस्तखत किया था या नहीं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि मैं आऊंगा न तो मैं बताऊंगा कि कोरबा की माईन्स किसने अडानी को एलाट की। कितने साल अडानी के साथ चले, वह भी मेरे पास है। मैं अभी उस विषय पर नहीं आना चाहता।

श्री अमरजीत भगत :- उसी को बोल रहे हैं मोदी जी और अडानी जी का क्या संबंध है, उसको पूरा देश जानना चाहता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दोनों आगे-पीछे बैठे हैं। वन मंत्री और मुख्यमंत्री, इन्होंने जंगल काटने की परमीशन दी है। बार-बार बोलते हैं कि 8 लाख नहीं 8 हजार कटेंगे। आडवानी के सिपहसलाहकार, जो उसको छत्तीसगढ़ में बसाने का काम कर रहे हैं, आज वह आडवानी के विरोध में दिखावे के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अडानी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आडवानी नहीं है, अडानी है। बृजमोहन जी, अभी आप पर उम्र का असर दिख रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- आप आडवानी बोलेंगे तो मोदी जी बुरा मान जायेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- एक तो आप लोगों ने उनको पहले ही घर बैठा दिया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आडवानी जी को तो चुपचाप बैठा दिया गया है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप आडवानी जी को कहां फंसा रहे हो ?

डॉ. विनय जायसवाल :- आडवानी जी बदनाम मत करिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आडवानी जी, अच्छे और सज्जन आदमी थे, आप उनको घर में बैठा दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर अडानी का खोलेंगे न तो पूरा अध्याय खुल जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार लोभ के कारण, आपको मालूम है जो देश का सबसे बड़ा ठग हुआ, उसके गांव के लोग भी उसके गांव में मूर्ति लगवा रहे हैं। ऐसे ही ये लोग ठगेश की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। मैं कल जायसवाल जी को सुन रहा था। जायसवाल जी, गलफहमी में मत रहिये। 3 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हैं। केन्द्र सरकार ने 270 करोड़ रूपये दे दिया है। राज्य सरकार ने आज तक बजट में प्रोविजन नहीं किया। मैं ठगेश सरकार क्यों बोल रहा हूं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में जो बोला था कि वन टाईम 60 प्रतिशत मेडिकल कॉलेज के लिए केन्द्र की सरकार दे रही है। न तो उसमें अस्पताल की व्यवस्था है और इसमें मेडिकल कॉलेज को चलाने का। क्या मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद चल जाता है क्या? इसके पूरे स्टॉफ का पूरा प्रावधान तो राज्य सरकार को करना है। तो यह पूरा का पूरा जो मोदानी मामिक्स है (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं क्यों ठगेश सरकार बोल रहा हूं। एक मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए 325 करोड़ रूपये चाहिए। तीन मेडिकल कॉलेज कोरबा, कांकेर, महासमुंद, 270 करोड़ रूपये आए हुए तीन साल हो गये । अभी तक 50 करोड़ रूपये से ज्यादा छत्तीसगढ़ के शासन ने नहीं दिया है। यह तीन मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। अभी तक उसकी अनुमति नहीं मिली। पैसे आ गये।

डॉ. विनय जायसवाल :- वहां 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अपना नॉलेज सुधारिये। कोरबा में भी पढ़ रहे हैं, महासमुंद में भी पढ़ रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे सब नॉलेज है। 270 करोड़ रूपये आने के बाद भी आज तक बिल्डिंग का टेण्डर नहीं हुआ है। कहां से लाओगे भैया, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा? लोगों को कितना ठगोगे? कितने ठगोगे? जो पुरानी स्वीकृत काम हैं, उसको तो पूरा कर दो।

श्री गुलाब कमरो :- सब के खाते में 15 करोड़ आया क्या? आदिवासी परिवारों को राहत दिये थे क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- जर्सी गाय कहां हे? भाजपा वाला मन तुमन ला गेरूआ ला बांध के खोजथे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह नटवरलाल, यह तुगलकी सरकार, बेरोजगार पंजीयन कितने हैं 18 लाख। एक महीने में ढाई हजार रूपये देंगे तो एक महीने के लिए कितना लगेगा? कितना लगेगा, बताईये तो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बेरोजगारों को कुछ मिलेगा, उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बेरोजगारों को कुछ मिलेगा, उसमें हल्ला कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 500 करोड़ रूपये एक महीने में लगेगा। ढाई सौ करोड़ रखकर बेरोजगारों को झुनझुना थमा रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह नटवरलाल की सरकार है, यह तुगलकी सरकार है, यह शतुरमुर्गी सरकार है। रेत में मुंडी गड़ाकर कुछ भी कर लो, कोई देख नहीं रहा है। ई.डी. के छापे पड़ रहे हैं, 500 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त हो रही है। वह छत्तीसगढ़िया की संपत्ति नहीं है? यह तो

नटवरलाल से भी बड़ा पाप हो रहा है। नटवरलाल ने तो राष्ट्रपति और अंबानी को [xx][8] था। यह तो छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे देश की जनता को [xx] रहे हैं। बड़े-बड़े कसीदे गढ़े जा रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप जनता के लिए इस तरीके का [xx] जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इस तरह का उल्टे शब्द का इस्तेमाल मत करिये।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल के बाद तो 4 साल काम दिखलाई दिये हैं और आपको याद होगा जब डॉ. रमन सिंह जी ने क्या कहा था कि कमीशनखोरी बंद कर दो, 30 साल तक कोई हिला नहीं सकता। यह बात तो हमारी सरकार नहीं करती है। धर्मजीत भाई, आप उस समय नहीं थे। हम थे, हमने सुना है। इस छत्तीसगढ़ की नक्शे से कांग्रेस गायब हो जायेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप भाजपा की बैठक में थे क्या?

श्री अरूण वोरा :- मैं इसी सदन में था।

श्री सौरभ सिंह :- आप भाजपा की बैठक में थे क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने सुना है। आप भाजपा की बैठक में थे क्या ? (व्यवधान) भवन में आप क्या बोले थे?

श्री अरूण वोरा :- मैं भाजपा की बैठक में नहीं था।

श्री देवेन्द्र यादव :- शिवरतन जी, आप पुष्टि कर रहे हैं कि रमन सिंह जी ने ऐसा कहा था। आप पुष्टि कर रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सब समाचार पत्रों में बड़ा-बड़ा हेडिंग छपा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, लंबी सूची है। आप लोग टोका-टाकी न करें। आप दोनों की बात हो चुकी है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी ने जो बता कही कि राष्ट्रपति को [xx] । मैं समझता हूं कि उन्होंने यदि हस्ताक्षर कर दिया है, और बहुत लोग हस्ताक्षर करते रहते हैं, लेकिन जो [xx] बनाने वाली बात है, उसको वापस ले लें या खेद व्यक्त करें। यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राष्ट्रपति जी को भुलावे में रखा। उपाध्यक्ष जी, मैंने जो [xx] शब्द कहा है, उसको मैं वापिस लेता हूं। उसको आप विलोपित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

---

[8] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं ठगेश सरकार क्यों बोल रहा हूं, तुगलकी सरकार क्यों बोल रहा हूं, नटवरलाल की सरकार क्यों बोल रहा हूं ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी आपत्तिजनक है । (व्यवधान) आप इसको भी विलोपित करें । ठगेस और ये शब्द जो बोल रहे हैं इसको विलोपित करें । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इतना कागजों में सब लिखा हुआ है, वह कहां से ठगेस होगा ? (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- देश में [XX][9]

श्री शिवरतन शर्मा :- डॉ. साहब अब तो छत्तीसगढ़ में हाना बन गे हे गा कि अइसन कोनो सगा नहीं जेन ला, हाना बनगे हे । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ऐहा केंद्र मा लागू होथे । (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- शिवरतन भैया, आपकी सरकार में आपके मुख्यमंत्री जी ने कोरिया जिले को गोद में लिया था लेकिन कोई काम नहीं किया लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाया है, (व्यवधान) मेडिकल कॉलेज है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय अग्रवाल जी । आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ को ठगने का काम, पूरे छत्तीसगढ़ को **नटवरलाल** जैसे काम करने का...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- 15 साल यही काम तो किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री जी ने ठेका ले लिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ठगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था । 15 साल तो यही काम करते आये हो । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको भाजपा ने 15 साल ठगा नहीं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 900 साल पहले तुगलक ने जो काम नहीं किया वह काम यह सरकार कर रही है । तुगलक के जमाने में अकाल पड़ा था, जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था तो वे लोग जंगल में भाग रहे थे। उनको उठाकर तुगलक ने जेल में डाल दिया । आज हमने मामला उठाया कि सरकार के विपक्ष में बोलने वालों को जिलाबदर किया जायेगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां तो अपराधियों को किया जाता है भई । उनके खिलाफ बहुत सारे प्रकरण हैं ।

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं तुगलकी। मैं बोल रहा हूं नटवरलाल की सरकार । आप तो विधानसभा में जवाब देते हो कि 56 हजार करोड़ का कर्जा है । आप जरा बताईये कि मंडल, आयोग, निगम उनके ऊपर में कितना कर्जा है ? 1 लाख 40 हजार करोड़ का कर्जा आपने मंडल आयोग, निगम के माध्यम से लिया है, पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को आपने क्या समझ लिया है ? यह शुतुरमुर्गी सरकार । यह जनता है, यह सब जानती है । आपने मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि 1 लाख 32 हजार करोड़ का बजट, 22 हजार करोड़ रूपये केवल ब्याज में चुका रही है । आखिर छत्तीसगढ़ का पैसा कहां जायेगा ? छत्तीसगढ़ का बजट कहां जायेगा ? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 सालों में आप ही लोगों ने सब बजट को अनबैलेंस कर दिया था । पूरा बजट अनबैलेंस था । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह जो लोन है यह 40 हजार करोड़ आपके समय का है । अब खाये-पीये हो उसको तो पटाना पड़ेगा न ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्जा में तो इन्हीं लोग डूबोये थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- टोका-टाकी न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शुतुरमुर्गी सरकार रेत में अपनी मुंडी गड़ाकर प्रदेश की जनता को सोचती है कि वह कुछ देख नहीं रही है, वह कुछ समझ नहीं रही है वाह रे तुगलक राजा । वाह रे नटवरलाल ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार एक ही बात रिपीट हो रही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब की दुकानों में कल चर्चा हो रही थी कि 50 हजार से डेढ़ लाख, 50 लाख की जो इंकम थी वह डेढ़ करोड़ की हो गयी है । एक पेटी सरकारी, दो पेटी कांग्रेस की ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- होली में तो बढ़ता है भई । होली में बढ़ता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक पेटी सरकारी, दो पेटी कांग्रेस की ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चंद्राकर जी कहां गये हैं, होली में तो बढ़ता है भई । आप लोगों का तो 500 से 5 हजार करोड़ हो गया था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में दूसरे नंबर की सरकार की खपत परइंकम कितनी वाह रे ठगेस । चार साल तक याद नहीं आयी थी कि कमेटी देशभर में शराबबंदी के लिये घूमे । सवा चार साल बाद याद आयी । वाह रे नटवरलाल, वाह रे तुगलक । ये क्या कर रहे हो ?

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय सुनिये न, उत्तरप्रदेश में शराब के बारे में एक छपा है कि 45 लाख करोड़ । नहीं, 45 हजार करोड़ । मैं लाख को कम कर देता हूं । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर 45 हजार करोड़ उत्तरप्रदेश में आ रहा है तो पूरे देश में दूसरे नंबर की शराब की खपत छत्तीसगढ़ में है । यहां 35 हजार करोड़ तो आना चाहिए । खाली 5 हजार करोड़ आ रहा है, 30 हजार करोड़ क्या तुगलक की जेब में जा रहा है या नटवरलाल की जेब में जा रहा है? कहां जा रहा है? कौन खा रहा है?

श्री अमरजीत भगत :- 15 साल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 15 साल में अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाये हो। (हंसी) (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- 400 करोड़ को 5000 करोड़ कौन बनाया आबकारी का? (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी का सरकारीकरण किसने किया? (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप मंत्री रह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विलोपित किया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लेता हूं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आबकारी का सरकारीकरण किसने किया? ज्यादा लाभ कमाने के लिए सरकारीकरण किया गया। (व्यवधान) आबकारी का सरकारीकरण किसने किया? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- ये तो संसदीय है। कहां असंसदीय है। आप बता दीजिए कि यह यह असंसदीय है क्या? (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय बृजमोहन जी ने जिस शब्द का उपयोग किया, क्या वह असंसदीय है? आप बताओ। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक मिनट। बृजमोहन जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यह बृजमोहन जी जानें, लेकिन लोकतंत्र में वे जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं न, ये अभी 14 में हैं। आ रहा है चुनाव। इस बार 71 अगली बार 75 पार समझ लो। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां-हां। हमें मालूम है। तुगलक का क्या हाल हुआ था? हमें मालूम है कि **नटवरलाल** का क्या हश्र हुआ था। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी ने जिस शब्द का उपयोग किया है, उसे विलोपित किया जाये। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठ जाइए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह स्पष्ट कर दें कि इस शब्द का उपयोग करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह सभ्य समाज है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हुए हैं। जिस शब्द का उपयोग किया गया, उसे विलोपित किया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैं इसे दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मैंने कोई असंसदीय शब्द बोला है तो आप दिखवा लेना। मुझे मालूम है कि यह असंसदीय शब्द नहीं है। उखाड़ कर फेंक देंगे। तुमने कुछ उखाड़ा क्या हमारा 4 साल में? (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किस चीज को उखाड़ोगे। किस चीज को उखाड़ोगे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। कैसे असंसदीय हो गया ? (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुछ नहीं उखाड़ सकते। कुछ नहीं उखाड़ सकते।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, जो उखाड़ना है, उखाड़ लेना। (हंसी) (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी तुगलक बिन कासिम बैठे थे। अभी शुतुरमुर्ग बैठे हैं। जरा भैय्या, चिट फंड वालों का पैसा वापस दिलवायेंगे। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और उद्घाटन करने तुम ही जाते थे। फोटो तो तुम्हारा ही छपा था। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिटफंड कंपनी का उद्घाटन किसने किया था? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उद्घाटन करने कौन गया?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इनकी सरकार ने 15 साल में उद्घाटन किया है और अब दिलाने की बात आयी तो ये बड़ी-बड़ी बात करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप लोग शांत रहिए। अपना भाषण जारी रखें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप कितना कमीशन खाये? आपको कितना कमीशन मिला? कितना कमीशन मिला, यह बताइए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 12 लाख लोगों के आवेदन। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वो चिटफंड कंपनी का उद्घाटन आपने किया था। भैय्या, उद्घाटन में तुम्हारा ही फोटो छपा था। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपका चिटफंड कंपनी में कितना है? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- बृजमोहन जी एक बात भूल रहे हैं याद कराउं क्या? आप प्रियदर्शिनी बैंक का नाम भूल रहे हैं। प्रियदर्शिनी बैंक का नाम भी तो ले लीजिए। बड़ी कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, आप शांत रहे।

श्री अमरजीत भगत :- जब गुरू बृहस्पति बोले तो सुनना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, 12 लाख लोगों के आवेदन कलेक्टरों के ऑफिस में धूल खा रहे हैं। 32 करोड़ वसूल किया है। उनकी जमीनों को बेचा है। जरा, मुझे यह बता दें कि यह 32 करोड़ की जमीन किसने खरीदी है? कुछ लोग यहां पर भी बैठे हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी है। जो जमीन 100 करोड़ में बिक सकती है, वह 32 करोड़ में बिक गई। यही तुगलकीराज है। यही नटवरलाल का राज है। यही शुतुरमुर्गी राज है। क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश को लूटने का काम, पूरे प्रदेश को गर्त में डालने का काम हो रहा है। बड़ी-बड़ी बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- 20 मिनट हो गया। अब आप समाप्त करें। और भी सदस्य हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- उपाध्यक्ष जी। बृजमोहन भैय्या जी। प्रणाम करथव। 2 मिनट सुन लेवौ गा। थोड़ा से मोरो गोठ ला सून लेवौ भई। बइठ जावव, आराम कर लेवव।

श्री अमरजीत भगत :- ओखर कोई बात ला नई सुने। तही सुन ले भाई। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- एमन ला 15 साल मौका मिलिसे तो कुछू नहीं कर सकीस तो उही ला कहिथे, मरे में मेछा उपकाये हे। 15 साल में तो कुछू नहीं करिस, अब नहीं हे तो मेछा उपकावथे, तनक-तनक के। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अग्रवाल साहब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब बड़ी-बड़ी बात। जरा बताएं तो तुगलकी राजा, जरा बताए तो नटवरलाल, जरा बताए तो शुतुरमुर्ग, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा में देश में कौन से नंबर पर है? 36 राज्यों में 34वें नंबर पर है , 34 वें नम्बर पर (शेम शेम की आवाज़) । ज़रा बताएं तो नटवरलाल हायर एज्युकेशन में छत्तीसगढ़ कौन से नम्बर पर है ? 24वें नम्बर पर है । क्या इसी के लिए हमने बजट मांग रहे हैं ? बड़ी बड़ी बात, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे । हमने ऐसा किया, जितने का काम नहीं, उतने की होर्डिंग्स, उतने का विज्ञापन । ये मंत्री जी बैठे हैं, मैंने अभी एक प्रश्न पूछा था कि श्रमिकों को कितना पैसा दिया गया और विज्ञापन में कितना खर्च किया गया ? श्रमिकों को 2 करोड़ के उपकरण दिए गए और विज्ञापन में 8 करोड़ खर्च कर दिया गया । यही नटवरलाल की सरकार है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये असत्य बोलने में माहिर हैं ।अभी हमारे अध्यक्ष जी आए थे वे कहते हैं कि चील उड़ता है, यह तो भैंस को भी उड़ा देते हैं । देखो भैंस उड़ रही है बोलते हैं । ऐसा हाल है इनका, असत्य बोलने में तो पूरी तरह से माहिर हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- डहरिया जी, छत्तीसगढ़ में एक ठी हाना है । जतेक के मुर्गी नइ, ओखर ले जादा फुदकौनी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस विषय पर बात करेंगे, मैं बात करने को तैयार हूं । उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार करोड़ रूपए, मजदूरों का पैसा सरकार के पास जमा है । मजदूरों का पैसा खाने वाली सरकार, ये नटवर लाल की सरकार, ये तुगलकी सरकार, ये शुतुरमुर्ग की सरकार ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पैसा जमा है तो फिर खा कहां से गया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसका ब्याज खा रहे हो, गरीबों को नहीं दे रहे हो, मजदूरों को नहीं दे रहे हो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तुम्हारे जैसे फर्जी खरीदी नहीं करते । फर्जी खरीदी नहीं करते हम लोग ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम लोग मजदूरों के खाते में पैसा देते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 36 योजनाएं चलती थीं । आज एक योजना नहीं चल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, अरे बताओ संसदीय कार्य मंत्री नटवर लाल जी के मंत्री, तुगलकी सरकार के मंत्री, शुतुरमुर्ग सरकार के मंत्री, मैं 200 फूड पार्क खोज रहा हूं । इनके नेता बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जाओ, टमाटर बेचो, कैचअप बनाओ, पैसा लाओ, घर जाओ । कहां है फूड पार्क ? संसदीय कार्यमंत्री जी, अभी आपके दुर्ग जिले में 100 करोड़ के टमाटर सड़कों पर फेंके गए । आप बड़ी बड़ी बात करते हैं । आप तो कृषि मंत्री हैं । आपने तीन साल पहले भी योजना लाई थी कि जो अपने खेत में झाड़ लगाएगा उसको 10 हजार रूपए प्रति एकड़ तीन साल तक देंगे । ज़रा अपने बजट भाषण में बता देना कि कितने किसानों को दिया है ? वृक्ष सम्पदा योजना, नाम से अच्छा लगता है । जिस सरकार के पास गरीबों घर देने के लिए पैसा नहीं है वह बाकी कामों में पैसा खर्च कहां से करेगी ? अपना राज है, तुगलक राजा हैं, नटवरलाल हैं, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी गड़ाए हुए हैं । कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो । कोई समझने वाला नहीं है । अरे, हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और विपक्ष में ही रहना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, हुंकारू देवैया 70 जने हैं तो कुछ भी लिख दे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है, हम जहां पर भी रहें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बृजमोहन जी, आप ठीक बोल रहे हो लिखते जाओ । मेट्रो तक है, वो तो अच्छा है हरिकोटा से अंतरिक्ष यान उड़ाएंगे नहीं लिखे ।

श्री अरूण वोरा :- आप चिंता मत करिए, अगली बार वह भी उड़ा देंगे । वह भी उड़ेगा और आपको धरातल पर दिखेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो पक्का अंतरिक्ष यात्रा करने वाले हो 6 महीने बाद। आप अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे हम भी समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, वह उड़ेगा तो उसमें बैठकर आप ही जाएंगे ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- हरिकोटा का अंतरिक्ष यान भी कांग्रेस ने ही उड़ाया । 9 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ऐसा बोलकर, जो देश बेचने वाले लोग हैं ना, उन्होंने नहीं उड़ाया । हरिकोटा का अंतरिक्ष यान भी हम ने ही उड़ाया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको बनाने वाला ए.पी.जे.अब्दुल कलाम था । जो राष्ट्रपति था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मैं नहीं बोल रहा हूं । कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री 1008 मोहन मरकाम जी, कल इस सदन में बोलते हैं कि डी.एम.एफ. के 7 करोड़ में बंदरबाट हुआ है। यह रिकॉर्ड में है। यह 7 करोड़ तो एक प्रकरण का है, अगर पूरे छत्तीसगढ़ का निकाल लोगे तो 7 हजार करोड़ है।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसमें स्वीमिंग पुल भी शामिल है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 7 हजार करोड़ में साढ़े 3 हजार करोड़ रूपये की बंदरबाट हुई है। क्या यह छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं है ? क्या यह छत्तीसगढ़िया संस्कृति है ? छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बार-बार दुहाई देने वाले बड़ी-बड़ी बातें करने वाले यह पैसा किसका है ? राजा तुगलक का नहीं है, यह पैसा नटवरलाल का भी नहीं है, यह पैसा शतुरमुर्गी का भी नहीं है, यह पैसा छत्तीसगढ़ी जनता का है। यह पैसा छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान का है। भैया, कैम्पा में क्या हो रहा है ? कैम्पा में कितना प्रतिशत लगता है ? साढ़े तीन हजार करोड़ रूपए मिले हैं, अभी और मिल गये हैं। जरा एक जांच करवा लें। यह तो मंत्रियों की, कलेक्टरों की सत्ता पार्टी के विधायकों की पॉकेट मनी बन गयी है। जनता के पैसा का ऐसा बंदरबाट ? आखिर यह कब तक चलेगा ? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश की केन्द्रीय एजेंसियां कह रही हैं, यह ई.डी. कह रही है, यह इनकम टैक्स कह रहा है, यह आई.बी. कह रही है, यह सी.बी.आई. कह रही है। पकड़े जा रहे हैं। पैसे जप्त हो रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पांच-पांच आई.ए.एस. अफसरों से पूछताछ हों, उनके यहां छापे पड़ें, क्या यह छत्तीसगढ़ी संस्कृति है ? क्या यह छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अपमान नहीं है ?

श्री रामकुमार यादव :- क्या मिला ? अंडा बटे पराठा। कुछ नहीं मिला।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- भैया, कर्नाटक में भी एम.एल.ए. के बेटे के पास से 8 करोड़ मिला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ते अगले बार कर्नाटक जा के चुनाव लड़बे। (हंसी) ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- वहां तोर दादागिरी पूरा चलही।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आपको भी ले चलेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? खेल, खेल में भी खेला हो रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- गेड़ी चढ़े हस।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- में सब चढें हंव। तोर गेड़ी चढ़े से कुछु नई होय। मुख्यमंत्री के भौरा चलाय से कुछु नई होय, मुख्यमंत्री के खारून में डूबकी लगाय से कुछु नई होय, जोन दिन हमर बस्तर के जंगल में मांदर के थाप में आदिवासी नाचही वो दिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति जीवित रही। (मेजों की थपथपाहट) जोन दिन हमर गांव-गांव में...। (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नाचत हे।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- दादी भी मांदर बचा के तो नाचत हे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आदिवासी क्षेत्र में जा के ये कथय। में बता देहूं । जगह के नाम भी बता देहूं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ बहुत शांत दिखाई दे रहा था, जब से केन्द्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ है, तब से फिल्म चालू हो गया है। (व्यवधान) इसका क्या राज है बताईए।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- कम से कम करिश्मा कपूर को बुलाकर तो नहीं नाच रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदिवासी मन ला नाचे के परमिशन के थोड़ी जरूरत हे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां छत्तीसगढ़ कल्चर की बात आती है, वहां बहुत बड़ी संख्या हो जाती है।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक मिनट बोलना चाहता हूं। माननीय बृजमोहन भैया जी, आपने बस्तर के बारे में जिक्र किया, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ, पूरे विश्व के देशों ने भाग लिया था और छत्तीसगढ़ के उस आदिवासी नृत्य महोत्सव में हमारा बस्तर जीता है। उस प्रतियोगिता में बस्तर पहला स्थान प्राप्त किया है। 5 हजार रूपए जीते हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- बृजमोहन जी, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के लोग आये थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसे हे, ओमा भी खेला होथे, कोन कंपनी रहिस, जोन ये आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन करे रहिस। मोला मालूम हे। कोन कंपनी हे जो रामायण मेला के आयोजन करथे, कोन कंपनी ए जोन कौशिल्या महोत्सव के आयोजन करथे, 6 करोड़ के रामायण महोत्सव होथे। ओखर आयोजन में 15 करोड़ खर्चा होथे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय जी, का हे, हमर जो राज्य हे ओ छत्तीसगढ़िया राज्य हे, यहां करीना कपूर नई आय, यहां छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति उजागर होथे। सलमान खान, करीना कपूर, नई आय।

श्री रामकुमार यादव :- ओ सलमान खान हा चिरहा पैंट ला पहिन के आवय, अउ अइसे करके दो करोड़ ला ले के भाग जावय। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- टोका-टाकी ना करें, सबको मौका मिलेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एहा 2 करोड़ रूपये में करीना कपूर संग सेल्फी लेथे। एहा 2 करोड़ रूपये दे रीहिस हे।

श्री रामकुमार यादव :- एमन मौका में झगड़ा होए। एमन सेल्फी नहीं ले पाये करके झगड़ा होए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अइसने।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी पूछ लीजिए कि कौन-कौन करीना कपूर के साथ सेल्फी फोटो खींचवाये थे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- एमन सेल्फी ले बर झगड़ा होए।

श्री रामकुमार यादव :- एमन करीना कपूर ला बुलाये रीहिस।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओ समय तोर कर संस्कृति विभाग रीहिस हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृहस्पत जी, डहरिया जी, एला बता कि तै काखर संग सेल्फी खींचवाये रहे हस? बता न कि काखर संग खिचवाये रहे हस?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं तो अपन डोकरी संग सेल्फी संग सेल्फी संग सेल्फी खींचवा लेथो। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी मैं भऊजी ला इही ला भेजहुं कि तोला डोकरी कहात रीहिस करके। मैं अभी ऐला भऊजी ला भेजत हवौं, तोर घर मा घुसना वर्जित हो जाही। अभी मैं एला भऊजी इही रिकॉर्ड ला भेजत हवौं कि तोला डोकरी कहे हे कि के।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी कोफ्त होता है। माननीय मंत्री जी खड़े हुए। क्या गांव में ददरिया हो रहा है, कर्मा हो रहा है, भोजली हो रही है, सुआ हो रहा है ? गांव में ऐसी स्थिति नहीं है कि वह उत्सव मना पाये। गांव में ऐसी स्थिति नहीं है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति जीवित हो सके। छत्तीसगढ़ को काला यूरोप।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको आधा घण्टा से ज्यादा हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय :- आधा घण्टा से ज्यादा हो गया है। केवल 5 मिनट।

श्री संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े मंत्री हे, ए थोड़ा जमत नहीं हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बड़े नेता हैं। सफेद असत्य मत बोलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एला असत्य बोले के नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए। यदि असत्य बोले के नोबल पुरस्कार मिलही तो छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी ला मिलही। महामण्डेश्वर।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बॉबी देवल जी की फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। असत्य बोले कौंआ कांटे।

श्री रामकुमार यादव :- असत्य बोले कौंआ कांटे, बृजमोहन भैया से डरैहों।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने मैकाले का नाम सुना था। इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को काला यूरोप बनाने की कोशिश की है। यूरोप में तो गोरे अंग्रेज रहते हैं। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? कितना धर्मान्तरण हो रहा है ? आपके बुजुर्ग परेशान क्यों है ? श्मशान घाटों में काले यूरोपों को दफनाने पर रोक क्यों लगाई जा रही है ? क्यों ? धर्मान्तरण की आग में पूरा बस्तर क्यों जल रहा है ? पूरा छत्तीसगढ़ क्यों जल रहा है ? सरगुजा में वनवासी समाज, आदिवासी समाज धर्मान्तरण के विरोध में रैला क्यों निकाल रहा है ? यह तुगलकी राजा छत्तीसगढ़ को काला यूरोप बनाने में लगे हैं। यह नटवरलाल छत्तीसगढ़ को काला यूरोप बनाने में लगे हैं। यह शुतुरमुर्गी रेत में मुंडी डालकर सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है लेकिन इसको पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या दिल्ली की बात कर हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बड़ी-बड़ी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, राम वन गमन पथ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पर्यटन परिपथ। आप ठीक से बोला करिये। (हंसी)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप तो उस समय बनाये नहीं। आप उस समय कहां थे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यहु पर्यटन मंत्री रीहिस हे अऊ संस्कृति मंत्री भी रीहिस हे। खाली राम के नाम अऊ शाम को ढाई सौ ग्राम...। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- दिनभर खाली गोठ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दिनभर जय श्री राम अऊ शाम को ढाई सौ ग्राम।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है बृजमोहन जी, भगवान राम के नाम पर राम वन गमन पथ पर 2 करोड़ रूपये कालनेमी रूपी सरकार।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बड़ी-बड़ी बात करते हैं। 2 करोड़ रूपये, 2 करोड़ रूपये में क्या होगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- बोर्ड लगेगा, बोर्ड।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोमबत्ती जलेगी और उस 2 करोड़ रूपये में भी डेढ़ करोड़ रूपये भ्रष्टाचार में चला जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है ? अभी आप बात कर रहे थे। सिन्हा जी बोल रही थी, हमारे मंत्री जी बोल रहे थे। आपकी छत्तीसगढ़ से बनी हुई पूर्व सांसद, उनकी बेटी, उनकी कंपनी, उस कंपनी को अभी तक पर्यटन संस्कृति विभाग से 50 करोड़ रूपये इवेन्ट मैनेजमेंट के नाम पर दे दिया गया। (शेम-शेम की आवाज) बंदरबांट हो रही है। इसीलिए मैं इसे तुगलकी सरकार बोलता हूं और इसीलिए मैं नटवरलाल की सरकार बोलता हूं और इसीलिए मैं शुतुरमुर्गी सरकार बोलता हूं। आयोजन, भैया, मंत्री जी, विश्व आदिवासी दिवस में छत्तीसगढ़ के कितने आदिवासियों ने भाग लिया ? मैं भी वहां गया था। वहां पर छत्तीसगढ़ के 100 आदिवासी भी नहीं थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- थे, वहां पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी थे। मंत्री जी खुद नाचे थे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- भैय्या, 20 साल बाद किये थे न।

श्री राजमन वेंजाम :- वहां आदिवासी थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विश्व आदिवासी दिवस का अपमान मत करिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रेमसाय सिंट टेकाम जी ऊंहा नाचे रहीस हे अऊ कवासी लखमा जी भी ऊंहा नाचे रीहिस हे।

श्री राजमन वेंजाम :- मध्यप्रदेश में आपकी सरकार है। वहां तो आदिवासियों को छुट्टी नहीं देते हैं। इस बार पहली बार आदिवासी लोग बस्तर के बिहड़ जंगलों में विश्व आदिवासी दिवस मनाये हैं। जंगलों में अंदर रहते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाए हैं । हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये नटवरलाल की सरकार, ये शतुरमुर्गी सरकार, ये तुगलकी सरकार बोलते हैं-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ।

श्री गुलाब कमरो :- दिल्ली में इनकी सरकार है। उन्होंने कहा था कि मित्रों, दो करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, 15 लाख खाते में आएगा । दिल्ली में नटरवरलाल बैठे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट के पहले पैराग्राफ में लिखा है-"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" । छत्तीसगढ़ तो नहीं गढ़ा, पर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को अराजकता का गढ़ बना दिया । छत्तीसगढ़ को चाकूबाजी का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को हत्या का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को लूट का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को महिला

अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को बेरोजगारी का गढ़ बना दिया ।

श्री गुलाब कमरो :- उपाध्यक्ष महोदय, जो अपराध का गढ़ है, उसे आप देख लीजिए । पूरे देश में जहां-जहां भाजपा शासित प्रदेश है, वहां भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया । देश में हमारे प्रदेश का नम्बर 14-15 पर है । जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां-वहां भ्रष्टाचार है, चाहे हत्या, लूट, बलात्कार की बात हो, हमारा छत्तीसगढ़ 14-15 नम्बर पर हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आबादी के हिसाब से कौन से नम्बर पर है ? उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है । सामान्य बजट पर चर्चा मतलब सभी विभागों की चर्चा होती है । हमारे सदन की गरिमा बढ़नी चाहिए । पूरा अधिकारी दीर्घा खाली पड़ा हुआ है । संसदीय कार्यमंत्री जी, कुछ तो ध्यान दीजिए, कितने प्रमुख सचिव उपस्थित हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके भाषण से बोर होकर आदमी भागना शुरू कर दिया है, कोई कितना भाषण सुनेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार की स्थिति बताती है । यह तुगलकी सरकार है, ये नटवरलाल की सरकार है, ये शतुरमुर्गी सरकार है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, नये विधायकों को हंगामे का प्रशिक्षण दोगे तो इससे काम नहीं चलेगा । नये विधायकों को हमको संसदीय मर्यादाओं का, संसदीय परम्पराओं का, संसदीय सिस्टम का प्रशिक्षण देना चाहिए । यहां तो संसदीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी (सदस्यों को हाथ से उठने का इशारा करते हुए) करते हैं । यही नटवरलाल की सरकार है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि भागती हुए सेना लूटते हुए जाती है । भ्रष्टाचार की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो । आपकी सरकार के कार्यकाल का अब सिर्फ 9 माह बाकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको बोलते हुए 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं । समाप्त करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अब मुख्यमंत्री जी कितने बड़े नटवरलाल हैं, कितने बड़े तुगलक हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । माननीय सदस्य मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं । इसको विलोपित किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ का जी.डी.पी. 4 लाख, 57 हजार करोड़ है । देश का जी.डी.पी. 272 लाख करोड़ है । यहां से 50 गुना ज्यादा है । देश के बजट से तुलना करते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- केन्द्र सरकार में कांग्रेस के सरकार रहिस त 7.50 प्रतिशत जी.डी.पी. रहिस हवय । ये मन आए ह त 2 और 2.5 में जी.डी.पी. ला लुड़का दे हवय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसे टाटा, बिड़ला की तुलना, अम्बानी की तुलना एक पान डिब्बे वाले से की जाये । मजाक कर दिया है । तुलना कीजिए न, मैं आपको बताता हूं । हमारे समकक्ष राज्य हैं, जहां हमारे प्रदेश की जितनी आबादी है, वहां से तुलना करिए तो समझ में आता है । टाटा, बिड़ला की तुलना पान डिब्बे से करोगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है ?

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- भैया, आप पान खाते हो, पान वाले को सम्मान दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में जितने सदस्य हैं, उन सबसे ज्यादा पान मैं खाता हूं । छत्तीसगढ़ के 60 प्रतिशत पान डिब्बे वाले जानते हैं कि मैं कैसा पान खाता हूं । इसलिए उनके सम्मान की बात मुझसे मत करिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के अनुसार देश के आम आदमी की आय 1 लाख, 97 हजार रूपए है । आपके अनुसार 1 लाख, 33 हजार है । आपसे जुड़ा हुआ राज्य मध्यप्रदेश है, हम वहां से अलग होकर आये हैं । वहां की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख, 40 हजार रूपए है । नटवरलाल की सरकार यही करेगी क्या, तुगलक की सरकार यही करेगी क्या ? हर चीज में आंकड़े की बाजीगरी है । मैं तो यह चाहूंगा कि जरा एक-एक मंत्री खड़े होकर बताएं कि वे साल के अंत तक कितना पैसा खर्च कर देंगे। 5 अप्रैल तक बजट पारित होगा, मई-जून तक पैसा रिलीज होगा, विभाग को जायेगा, प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, टेण्डर होगा तो क्या कोई काम हो पायेगा ? खाली बड़ी-बड़ी बातें।

समय :

2.50 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो विधायक हैं, आप लोग जरा भुलावे में मत रहो। आखिरी बजट में कोई काम नहीं होता है। चाहे आपके यहां स्कूल खोलने की बात है, चाहे कालेज खोलने की बात है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारा अनुभव अच्छा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अनुभव के उदाहरण अभी भौजी ला डोकरी कहके बताय हस।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भाई डोकरी कहे हव यार, घरो मा भी लड़वाय के काम करथस। घरो में लड़वा देबे। तुमन के काम येही हावय।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री लोगों को अच्छा अनुभव है, इसमें दो मत नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- विधानसभा के बात घर मा चल दे हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- रिकार्ड कापी ला घर मा भेजवाहूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- छोकरी काला कहथे मालूम हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर ले ज्यादा कोन जानही ? मैं कैसे कह सकत हव।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अपन छोटे भाई के बाई ला छोकरी कहथे अउ जेकर शादी नहीं होय हे तेला छोकरी बोलथे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह कैरियर किलिंग की सरकार है। रोजगार की बड़ी-बड़ी बात, होर्डिंग में अलग, भाषण में अलग, राहुल जी को अलग। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि यह नटवरलाल की सरकार है, तुगलकी सरकार है। यह छत्तीसगढ़ के बच्चों का कैरियर किलिंग कर रही है। मैं आपको बताता हूं। 21 हजार लोगों की भर्ती अदालत में पेण्डिग है। सब इन्सपेक्टर के 900 पद, 75 लोगों की भर्ती सन् 2018 से पेण्डिग है। पी.एस.सी. के 171 पदों के परिणाम रोक दिए गए हैं। 211 पदों के वन सरंक्षकों के परिणाम रोक दिए गए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आरक्षण के कारण हे। आप मन आरक्षण ला पास नइ होन देवत हा, तेखर खातिर सब रूके हे।

एक माननीय सदस्य :- आरक्षण में तो साइन करवा दो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सी.जी.पी.एस.सी में 91 प्यून के पद लंबित हैं। पहली बार इस सरकार ने बड़ा कारनामा किया कि अब पी.एस.सी. चपरासियों की भर्ती करेगी। यही तो तुगलकी सरकार है। मंत्री जी, आप इतने भोले मत बनो। 91 पदों के लिए ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, बृजमाहन जी, वैसे भाषण-वाषण अच्छा दे लेते हैं। आपको रोजगार भर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। देश ने भी देखा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात जिन्होंने कहा था, आप कुछ बोलेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यहां के 2 करोड़ लोगों के बारे में आपके बजाय उन लोग कुछ बोलेंगे? आपने जिन 3 लोगों को दिल्ली भेजा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- देश जानना चाहता है, कुछ बोलेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है कि जिन 3 लोगों को राज्यसभा में भेजे हैं, वे छत्तीसगढ़ के हित के बारे में कुछ बोलेंगे क्या ? यह पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है।

श्री रविन्द्र चौबे :- 9 लोग भी लोकसभा में गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- 3 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि वे आखिर कर क्या रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो फिर आप ही बता दो। इसलिए आप रोजगार वगैरह के बारे में मत बोलो, बाकी भाषण-वाषण ठीक दे रहे हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आज ऐसी हालत है कि पूरे प्रदेश में कान्स्टीट्यूशनल ब्रेकडाऊन है। आप भी बस्तर से आते हैं। क्या बस्तर के नवजवान लड़के-लड़कियों की

भर्ती हो रही है ? वहां पर अनरेस्ट क्यों हो रहा है, वहां पर आंदोलन क्यों हो रहा है ? वहां पर नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, डाटा एन्ट्री आपरेटर, सहायक विस्तार अधिकारी के 250 पद, हास्टल वार्डन के 400 पद, अमीन पटवारी, मैंने कल मंत्री जी से जानकारी ली थी, 1200 पद सिंचाई विभाग में खाली हैं। यह तुगलकी सरकार नहीं है, यह नटवारलाल की सरकार नहीं है, झूठे सपने दिखाना, गुमराह करना, यह शुतुरमुर्ग की सरकार नहीं है तो क्या है ?

माननीय सभापति महोदय, 33 हजार पद हैं, आपने जिनका समायोजन कर दिया, लेकिन उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। पद खाली पड़े हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की हालत बद से बदतर हो रही है। हम लोग तो इस बात से परेशान हैं कि ये लोग 6 महीने बाद चले जायेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां चले जाओगे भाई ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोग चले जाओगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 6 महीने बाद ये चले जायेंगे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- 14 में एके दू बाचही, ज्यादा नई बाचय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अंधानुकरण मत करो, सबका भविष्य खतरे में है । यह [XX] की सरकार है, यह [XX] सरकार है, यह शुतुरमुर्गी सरकार है, अपने सर को रेत में गड़ाकर सोच रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है । सब हरा-हरा हो रहा है । क्या हुआ भईया, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है, खेल अलंकरण समारोह 4 साल से क्यों नहीं हो रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, आपकी खेल नीति कहां है...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, झूठ बोलना बंद करवाईये ।

सभापति महोदय :- आपका 50 मिनट हो गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा ये बता गा डहरिया जी, एति कहाथस झूठ बोलथस, तैं अभी विधान सभा म सब ले बड़े झूठ बोले हस । ऑन रिकार्ड हावय । बतांव काय झूठ बोले हस ? सब झन मोर बात ला स्वीकार करही । डोकरी बोले हस, वोहा डोकरी होगे हे का ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सबले बड़े झूठा बोले हस ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जेखर ले ज्यादा मया करथे, वोला डोकरी कथे गा प्यार से ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जवान हे भई, डोकरी नई ये ।

सभापति महोदय :- बैठिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, खेल ओलम्पिक की बात है, 11 एकादमी में कोच नहीं है, पैसा नहीं है । सभापति महोदय, आपने मुझे इंडिकेशन दिया है, मैं जल्दी समाप्त करूं ...।

सभापति महोदय :- एक घण्टे हो रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तुगलकी सरकार को, मैं प्रदेश की सभी जनता से आव्हान करूंगा, मैं सभी विधायक साथियों से आव्हान करूंगा, ऐसी सरकार जो सरकार, सभी किसानो का कर्जा माफ नहीं कर पाई, जो सरकार शराबबंदी नहीं कर पाई, जो घर-घर रोजगार नहीं दे पाई, जो सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं दे पाई, जो भूमिहीन परिवारों को घर, जमीन और बाड़ी नहीं दे पाई, जो भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा नहीं दे पाई, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, जो कर्मचारियों को क्रमोन्नति, पदोन्नति, चार स्तरीय वेतनमान नहीं दे पाई, जो कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर पाई, जो वृद्धावस्था, विधवा पेंशन को 1000 और 1500 नहीं कर पाई, जो स्व-सहायता समूहों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं कर पाई, जो सिंचाई योजना को दोगुना नहीं कर पाई, जो 200 फुड पार्क नहीं बना पाई, जो लोकपाल नहीं बना पाई, जो नक्सल समस्या को दूर नहीं कर पाई, नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1 करोड़ नहीं दे पाई, पत्रकार-वकील-डॉक्टर के लिये विशेष कानून नहीं बना पाई, गजराज योजना लागू नहीं कर पाई, पर्यटन स्थलों का विकास नहीं कर पाई, आऊटसोर्सिंग को बंद नहीं कर पाई, 10 लाख पदों पर भर्ती नहीं कर पाई, 9वी के बच्चों को पेपर में छपता है, लड़कों को भी मिलेगा, बजट में प्रोविजन हुआ है, जो बच्चों को साईकिल नहीं दे पाई, जो संपत्ति कर को आधा नहीं कर पाई, जो कॉलेज के छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा नहीं दे पाई, जो महतारी योजना का 500 रूपया नहीं दे पाई, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर वेतन नहीं दे पाई, जो सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित नहीं कर पाई, जो वृद्धावस्था पेंशन चालू नहीं कर पाई, जो सूपेबेड़ा में नल-जल योजना को प्रारंभ नहीं कर पाई, जो सातवें वेतनमान की बकाया राशि नहीं दे पाई, जो मितानिन का नियमितीकरण नहीं कर पाई, जो पुलिस कर्मियों का सामूहिक अवकाश नहीं दे पाई, जो चिटफण्ड का पूरा पैसा वापस नहीं दे पाई, ऐसी तुगलकी सरकार को....।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- कुछ कर नहीं पाये हैं, उसी को बोल रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र से मैं बोल रहा हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- पहले अपना घोषणा पत्र पढ़ लो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पढ़ेंगे, 6 महीने बाद हम अपना घोषणा पत्र पढ़ेंगे । जब हम सरकार में आयेंगे, इसलिये इस तुगलकी सरकार का, इस नटवरलाल की सरकार का, इस शुतुरमुर्गी सरकार का, जो छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में फरेब कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम कर रही है, ऐसे ठगू सरकार के बजट का मैं विरोध करता हूँ, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- माननीय सभापति जी, एक मिनट । आदरणीय बृजमोहन जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और 15 साल के अपने कार्यकाल के बारे में पूरा विस्तार से बताया, इसके लिये बहुत-बहुत बधाई ।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी ।

समय :

3.00 बजे

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का जो अंतिम बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका बहुत विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब इस विधान सभा की शुरूआत हुई, उसके पहले ही सरकार को नैतिक रूप से इस बात का अधिकार नहीं था कि महामहिम राज्यपाल को इस विधान सभा में बुलाकर वह अभिभाषण पढ़वाते क्योंकि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री, इन सभी लोगों ने एक आदिवासी महिला, जो कि इस प्रदेश की राज्यपाल थी, उनका जो संवैधानिक प्रमुख का जो पद था, उसका भी सम्मान नहीं किया और किसी आरक्षण के बिल के दस्तखत करने और नहीं करने को लेकर सारे मंत्रियों ने बयान दिया, कोई भी बाकी नहीं रहा। मैं एक बार समझ सकता हूं कि मंत्रियों ने भी राजभवन में शपथ ली है तो यह बोल लिये। आपके शहर में घूमने वाले अठन्नी, चवन्नी नेता भी राज्यपाल के खिलाफ बोल रहे थे। आपको उस वक्त चिंता नहीं सताई कि वह एक महिला राज्यपाल है, आदिवासी समाज की है। उनसे आपके भेद, मतभेद कुछ भी हो सकते हैं। आपका कोई भी चिल्हर छाप नेता उनके खिलाफ बयान दे रहा था। राज्यपाल को तो इस सरकार का अभिभाषण पढ़ने के लिये यहां आना भी नहीं चाहिए था। फिर आपने नये राज्यपाल को लाया। उनसे अंग्रेजी में भाषण दिलवाया। वह अंग्रेजी में भाषण कुछ पढ़े, हिन्दी में भाषण को कुछ और लिखा गया। मतलब जब यह सरकार राज्यपाल की गरीमा का भी ख्याल नहीं रख सकती तो यह सदन तो राज्यपाल के अभिभाषण और राज्यपाल के संरक्षण और नियंत्रण में चलता है।

सभापति महोदय, यह बजट बहुत ही असंतुलित बजट है। इसमें सिर्फ दुर्ग और रायपुर संभाग का वर्चस्व है। इसको इन लोगों ने इसलिये असंतुलित बना दिया है क्योंकि इनको चुनाव में जाना है। ये पहले अपनी गद्दी, अपना घर, अपना परिवार, अपना क्षेत्र सुरक्षित करना चाहते हैं। बाकी सारे लोग डर के मारे कि कहीं टिकट मत कट जाये, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यह बहुत ही असंतुलित बजट है। इस बजट में चाहे आपने 1 लाख 21 हजार करोड़ का प्रावधान कर भी दिया है। मैं चुनौती के संग कह रहा हूं कि आप इसमें कोई भी राशि खर्च नहीं कर पायेंगे। आपने जो आंगनबाड़ी के लोगों का पेमेंट बढ़ाया, वह बहुत अच्छा है, हमने भी उसकी मांग की थी। और भी जो पेंशन बढ़ाया, वह भी बहुत अच्छा है, हमने उसकी भी मांग की थी। लेकिन यह जो बाकी पुल-पुलिया, मेडिकल कॉलेज और जो दुनिया भर का हवाई अड्डे का प्रावधान किया है, वह कहीं भी कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि मैंने जो यहां 20 साल देखा है,

मैं उस अनुभव को बता रहा हूं। सन् 2022-23 के बजट में जो पैसा था। खुड़िया जाने के लिये एक पुल बनवाना था। उसकी फाइनेंसियल स्वीकृति ए.एस. तक इन लोगों ने नहीं दिया। ऐसी कई सड़कें हैं, जिनकी स्वीकृति नहीं मिली। इस बजट में बहुत बड़ा-बड़ा प्रावधान कर दिया गया है तो मैं नहीं समझता कि आपके लालफीताशाही और अफशरशाही के बीच में यह प्रावधान पारित होंगे और जनता तक पहुंचेंगे। यह पैसा जनता तक नहीं पहुंचेगा, कोई काम शुरू नहीं होगा। एक काम कोई शुरू करायेगा तो मुझे बताईयेगा। मैं बड़ा माला रखकर उसके स्वागत के लिये आऊंगा। आप दिग्भ्रमित कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर फोटो खिंचवा सकते हैं, आप वहां पर जाकर गुलाब की वर्षा करवा सकते हैं। आपके 5-10 लोग उसको प्रचारित कर सकते हैं। परंतु हर जनता यह समझ रही है कि 2 साल पहले जिस पुल और जिन सड़कों का बजट में प्रावधान था वह भी यहां पर खर्च नहीं हुआ है और आप चाहो तो मैं उदाहरण सहित बता देना चाहता हूं। लेकिन अभी बोलना है इसीलिये मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा।

सभापति महोदय, मेरे एक प्रश्न में माननीय गृहमंत्री जी ने अभी दो दिन पहले जवाब दिया। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि छत्तीसगढ़ में पुलिस बल कुल कितना है। उन्होंने बताया कि उनके विभिन्न ब्रांचेस मिलाकर 80 हजार पुलिस बल है। उसमें 17 हजार पद खाली है। 2.3 पुलिस 1 हजार जनता की रक्षा के लिये इस प्रदेश में है। यदि आप 1 लाख 21 हजार करोड़ के बजट को खर्च करना चाहते थे तो ये 17 हजार बच्चों की भर्ती कर देते तो 17 हजार बेरोजगारों को नौकरी मिलती। यह लिखने से क्या मतलब है कि मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, यह बनाऊंगा, वह बनाऊंगा। यह आपका Ornamental Budget है। शोभायमान बजट है, वह शोभा जरूर दे रहा है लेकिन आप वह खर्च नहीं कर पायेंगे। यदि आप पुलिस के इन जवानों की भर्ती करते तो यहां की कानून व्यवस्था ठीक होती, यहां के बेरोजगारों को नौकरी मिलती और वह आपका नाम भी लेते और वहां हमारे बच्चे काम में भी रहते।

माननीय सभापति महोदय, आपने आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को मदद की, यह बहुत अच्छी बात है। बजट में प्रावधान करने के बाद जो काम नहीं होता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ बजट में प्रावधान था और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ,जिसमें हम लोग भी गए थे विधान सभा भवन, मुख्यमंत्री जी का भवन, राज्यपाल महोदय जी का भवन और विधायकों के भी भवन बनने का प्रस्ताव था। उस उद्घाटन समारोह में एक लोकप्रिय सांसद महोदय मुख्य अतिथि थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्षता की। माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी का विशिष्ट अतिथि में नाम था। नया विधान सभा भवन कहां है ? अभी तक नया विधान सभा भवन कितना बना? हमारा नया विधान सभा भवन क्यों नहीं बना? जब दिल्ली में सेन्ट्रल विस्टा बन रहा था तो इन लोगों, इनके नेताओं ने उसका विरोध किया। चूंकि माननीय मोदी जी सेन्ट्रल विस्टा बनवा रहे हैं वहां पर पार्लियामेंट में उनके लोगों ने उसका विरोध किया तो उस विरोध स्वरूप में जब हम उस भवन का विरोध कर रहे हैं तो हम यहां विधान सभा भवन कैसे बनवायें ?आपने विधान सभा भवन नहीं बनवाया। इस छोटी सी विधान सभा में 20-22 साल तक चला लिया।

अगर वह विधान सभा भवन बनता तो आपका नाम पत्थर में रहता। छत्तीसगढ़ के और भी ज्यादा लोग दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा में आते, बैठते, देखते, सुनते, समझते। अभी तो छोटी सी जगह में विधान सभा चलाने में मारा-मारी होती है। हमारा नया विधान सभा भवन क्यों नहीं बना? लेकिन मुख्यमंत्री भवन बन गया, मंत्रियों के लिए भी पांच-पांच एकड़ में आलीशान भवन है, लॉन-वॉन, टेबल टेनिस सब खेलने का है। विधायकों ने क्या जुर्म किया था? आपने उनके लिए भवन क्यों नहीं बनवाया? विधायकों का भवन कहां है? उन्होंने 15 सालों में नहीं किया तो आपने इन 4 सालों में क्या कर लिया? आपने विधायकों के लिए कहां पर भवन बनवाया? आपने उनके लिए क्यों नहीं बनवाया? यह भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, यह भी वहां बाहर से आकर रहते हैं इनको भी अच्छे घर में रहने की पात्रता है। आपने अपने विधायकों का ख्याल नहीं किया। अभी भी मंत्रियों के आलीशन बंगले हैं। वह बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन विधायकों का रहने का कुछ प्रावधान नहीं है। यह अलग बात है कि विधान सभा से उनको 30 हजार रूपये का भत्ता या किराया मिलता है, लेकिन जब कोई कॉलोनी में ले जाते, जब बाहर के लोग आते हैं तो हमें अच्छा लगता।

माननीय सभापति महोदय, यहां अडानी बहुत अडानी का विरोध चल रहा है। आप विरोध करिये, हमारी अडानी से कौन सी रिश्तेदारी है ? हम तो इसी विधान सभा में अडानी के खिलाफ वर्ष 2021 में 29 जुलाई को एक घण्टे का भाषण दिया था। मैंने उसके हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक को निरस्त करने की मांग की थी। मैंने उसमें बताया था कि उससे 6 लाख से ज्यादा झाड़ कटेंगे। वहां वन्य प्राणी मारे जाएंगे। जो हसदेव बांगो डैम का केचमेंट एरिया है वह खत्म होगा। वहां बांध में पानी नहीं आएगा। वहां जो 6 लाख हेक्टेयर जो खेती होती है, वह सूखेगा। कोरबा के पॉवर प्लांट को बिजली पैदा करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर वहां पर अडानी ने एक रेल्वे लाईन जो खिंचा है उस रेल्वे लाईन के किनारे के खदानों को देने के लिए आपके ही बड़े नेताओं का निर्देश था और आपने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मण्डल के परसा कोल ब्लॉक को वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई। अगर अडानी का विरोध करना है तो उसे हिम्मत से निरस्त करिये। वहां लोग हड़ताल में बैठे हैं। वहां पर बिलासपुर में भी लोग हड़ताल में बैठे हैं और कई प्रदेश में बैठे हुए हैं। वह फेफड़ा है, वह छत्तीसगढ़ के सांस की धमनी है उसी से सांस आएगी। ऑक्सीजन का महत्व आप और हम सब समझते हैं। जब अडानी का इतना विरोध है तो आप एक तरफ तो अडानी को परमिशन देते हैं दूसरी तरफ कल जाकर ज्ञापन देकर फोटो छपवाते हैं। यह दोहरा मापदण्ड ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इसी विधान सभा में स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए तारीफ की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत अच्छा है और इससे हमारे बच्चें अंग्रेजी पढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई नियम है। आप आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोलिए, डी.एम.एफ. मद से या अपने मद से उसका स्कूल भवन बनवाईये। मंत्री जी कवर्धा में करपात्रे स्कूल है। शुरू-शुरू में जब आत्मानंद जी के स्कूल का

नाम आ रहा था तो करपात्रे जी का नाम भी गायब करने की कोशिश हुई थी। क्या आप करपात्रे जी को देखे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- हॉ, मैं देखा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बस, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न तो कर ही नहीं रहा हूं। करपात्रे जो को आप नहीं देखे हैं। हम लोग छोटे-छोटे थे, करपात्रे जी महाराज आते थे जो शंकराचार्य जी के गुरू थे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- एक मुट्ठी भर अन्न खाते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह ऐसे वाले नहीं, वह विद्यासागर जी हैं। मैं उनसे कल पोड़ी में मिलकर आया हूं। सभापति महोदय, करपात्रे जी के नाम से लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरे कहने का आशय यह था कि वह उतना ही अन्न ग्रहण कर रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसे वाले गुरू नहीं, वह ठीक से खाते थे। ये वाले गुरू विद्यासागर हैं। करपात्रे जी की के नाम से स्कूल था। वह भी गायब होने लगा। लोगों को गुस्सा आया। बाद में वह नाम बदलकर करपात्रे जी के नाम से रख दिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- धर्मजीत भैया, स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जहां भी स्कूल खोल रहे हैं जो उनके पुराने नाम हैं, चाहे किसी के भी नाम हो, उसको नहीं हटाया जा रहा है। वह नाम रहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। पर आप ही का थोड़ा सा एक-दो मांग और कर लूं। करपात्रे जी का नाम रह गया। यह मेरे पास एक दस्तावेज है। तखतपुर में जनकलाल, मोतीलाल पांडे हायर सेकेण्डरी हिन्दी मीडियम स्कूल चल रहा था। इसमें फोटो है, सन् 1964 में विनोबा भावे जी ने इसका उद्घाटन किया था। राजेन्द्र शुक्ल जी जो एम.एल.ए. भी नहीं थे, जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, वह वहां पर खड़े हैं। आपने उसका डायरस्कोट चेंज कर दिया, पूरा स्कूल का स्वरूप बदल दिया। आपने क्यों किया ? एक व्यक्ति जिसकी मौत होती है, जनकलाल जी की पत्नी रमादेवी 12 एकड़ जमीन देती हैं, स्कूल बनवाती हैं, आप उसका नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद जी के नाम से रखेंगे तो यह उचित नहीं है। स्वामी आत्मानंद जी का पूरा सम्मान है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोलिये। 2-4 करोड़ रुपये दे दीजिए और बनवाईये। लेकिन जनकलाल मोतीलाल पांडे के संग अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबंद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- जनकलाल स्कूल अभी भी अस्तित्व में है, आत्मानंद स्कूल की उसके पीछे नई बिल्डिंग बनी है। आत्मानंद स्कूल बिल्कुल अलग भवन में लगती है। जनकलाल मोतीलाल स्कूल अलग भवन में लगता है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसका कोई डॉयरस्कोट चेंज नहीं होगा और उनका नाम रहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं माननीय मंत्री जी से बात कर रहा हूं। डॉयरस्कोट चेंज कैसे हो गया ? वह स्कूल कहां गायब हो गया ? हिन्दी मीडियम स्कूल कहां लग रहा है, आप बताईयेगा। मैं एफ.आई.आर. कराऊं या आप करायेंगे। तो यह सब बात छोड़िये। इसको संज्ञान में लीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन वहां के लोगों ने लिखकर दिया है, अगर इस स्कूल का नाम बदलेगा तो ये वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप उसको हमको दे दीजिए। मैंने निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल जो पुराने नाम से था चाहे किसी का भी नाम हो, हमारे महापुरूषों का, उनका नाम रहेगा। यह जो पांडे जी का नाम बोल रहे हैं, उनका नाम भी रहेगा।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- इसी मसले पर यह भी चर्चा हो जाये कि जे.एन.पी. वर्मा को वापिस एस.बी.आर. कालेज करने के लिए जो नाम बदल दिया गया है, वह भी वापस एस.बी.आर. किया जाये। जिसके कारण पूरा विवाद आज पांडे जी भी कर रहे थे, हम भी और आप भी बिलासपुर के ही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो सरकार में शक्तिशाली मंत्री हैं। आप करवा दीजिए न। हम लोगों से क्यों बात कर रही हैं ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- नहीं, बांधी जी के टाईम में बदल दिये थे, जे.एन.पी. नाम हो गया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह नाम हो गया था तो आप बदलवा दो। आप तो सरकार में हैं। हम थोड़ी सरकार में हैं। हम तो महात्मा गांधी का महात्मा गांधी करो, कहेंगे तो आप लोग उसको नाथूराम गोड़से कर दोगे या जवाहर लाल नेहरू कर दोगे।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- हम लोग गोड़से वाले नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ तो बस ठीक है, आप करा लीजिए। आप शक्तिशाली लोग हैं, कराईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह सरकार से पूरा दादागिरी से करवा सकती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, एक प्रोफेसर खेरा थे। वह दिल्ली के कॉलेज में बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वह यहां आ करके लमनी के गांव में रहते थे। आप लोगों ने शायद सुना होगा। मुख्यमंत्री जी उनका बहुत सम्मान करते थे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं भी करता हूं। मैं उनसे मिला भी था और मैं स्कूल में भी गया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कैसे मिले थे और कैसा सम्मान करते हैं, मैं आगे बता रहा हूं न, आप बैठिये। मैं अभी आपको बताता हूं। प्रोफेसर खेरा साहब ने 25-30 गांव के बीच में छत्तीसगढ़ के अचानकमार के छपरवा गांव में अचानकमार शिक्षण समिति बनाये थे। उस शिक्षण समिति को कैसे भी करके वह इधर-उधर से चलाते थे। उनकी मृत्यु होने के बाद सरकार के समक्ष ये मामला आया कि वहां पर एक मात्र हाईस्कूल है, जहां पर छोटे-छोटे बच्चे हैं, गुरूजी पढ़ाते हैं। इनका शासकीयकरण करो।

शासकीयकरण में दिक्कत आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको अनुदान दे दो। आप बतायेंगे कि उनका अनुदान रीलिज हो गया? आपके फाईलों में कैद है। प्रोफेसर खेरा का कितना सम्मान कर रहे हैं, आप जरा पता करिये। अभी 15 दिन पहले तक के तो नहीं मिला है। यह लाल फीताशाही से जरा मुक्ति कराओ। वित्त विभाग से जाकर बता करो और पैसा दिलाओ। पैसा तो आपके पास है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है। लेकिन करना तो आप लोगों को है। आप लोग करते नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अकबर जी, स्कूल शिक्षा विभाग में जो सबसे अच्छा होता है, वह ट्रांसफर होता है और निरस्तर हो जाता है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, यह तो प्रक्रिया है। आप भी करते रहे होंगे। यह तो प्रक्रिया है। अभी तो बहुत निरस्त किए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब उसके बारे में भी बोल देता हूं। आप जब याद दिला दिये तो मैं बोल देता हूं। आपने कवर्धा जिले में 130 लोगों का ट्रांसफर किया और उसके बाद में उसको यह कह कर relieve नहीं किया जा रहा था कि वहां पर दूसरे गुरू जी नहीं आया है तो ट्रांसफर तो आप कर रहे थे न। दिमाग तो आप दौड़ाते कि 130 को ट्रांसफर कर रहा हूं तो कम से कम 100 तो भेजू। उनका क्या दोष था। एक लड़का मर गया जो relieve नहीं हुआ। वह वहां पर मर गया, तब जाकर आप लोगों ने कुछ का relieve किया और कुछ का ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर करने के पहले सोच लो कि 100 यहां से भेज रहा हूं तो कम से कम 90-100 वापस लाऊं। यह पावर हम लोगों को आपने कब से दे दिया। यह पावर तो आपके पास है। खेरा साहब जिस कुटीर में रहते थे। मैं उनके नाम से 10 लाख रूपये विधायक निधि से दिया था। फारेस्ट वाले उसको नहीं बनने दिये तो नहीं बनने दिये। उनके घर को ही मरम्मत कराकर कुटीर के रूप में रखना था। वह चाहे ताजमहल बनवा लें, लेकिन खेरा के नाम से नहीं बन पाया । उस पैसे को वापस मंगवाकर खुड़िया में मैंने 10- 20 लाख और मंगवाकर 20 लाख में प्रोफेसर खेरा के नाम से पर्यटन कुटीर बनवाया है, जिसका मैं 27 तारीख को उद्घाटन करूंगा। तो सम्मान देना तो सीखिये। जो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रह हैं, सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। वह बैठकर आदिवासी बच्चियों को नहलाता था, धुलाता था, कपड़ा सिलता था, चना खिलाता था, दवाई देता था। अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर जंगल में बिना पंखे के रहता था। वहां पर बिजली भी नहीं है। उनको नाम लेने में भी तकलीफ है। उनके स्कूल को राज्य संरक्षण देने में आपको तकलीफ है। इस पर विचार करियेगा। माननीय मंत्री जी, ए.टी.आर. की सड़क मरम्मत के लिए मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था। मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से प्रार्थना किया था। 30-40 किलोमीटर की सड़क को पता नहीं यहां पर अमेरिका का कानून लागू है या जापान का कानून लागू है। यहां के अधिकारी कौन सा कानून बताते हैं। मैं अभी आपके संग ही हैदराबाद गया था। मैं अपनी पत्नी को लेकर श्रीशैलम मल्लिकार्जुन गया था। ढाई सौ किलोमीटर दूर है और सिर्फ 50 किलोमीटर पहले तक तेलंगाना राज्य है, उसमें एक टाईगर रिजर्व है।

उसमें सैकड़ों गाड़िया रात को चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी। बहुत शानदार रोड है। तो वह कौन सा टाईगर रिजर्व है और यह कौन सा टाईगर रिजर्व है? मैं 35 साल से राजनीति कर रहा हूं। जहां आज तक शेर तो क्या शेर का पूंछ भी नहीं देखा हूं। इसको बनवा दीजिये। अभी भी वक्त है। आप तीन महीने में बनवा दीजिये। मैं तो आपको कई बार निमंत्रण दिया कि आप खुद चलिये, देख लीजिये, पर आप भी पता नहीं क्यों नहीं गये। आप हमसे नाराज तो नहीं हैं। मतलब आप उसको थोड़ा करा दीजिये। मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में पैरा 69 में छत्तीसगढ़ जन निवास भवन का आपने जो प्रावधान रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यह कहां बनेगा, इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं एक सलाह के रूप में यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ से पितृ पक्ष में अपने पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे ज्यादा जाने वाले गया जी के लोग होते हैं। मैं अपने माता-पिता के तर्पण के लिए अपने भाई एवं परिवार के साथ गया जी गया था तो मैंने खुद गया जी में देखा है कि वहां पर खड़े होने की जगह नहीं रहती है। बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है। 5-10 एकड़ जमीन मांग लीजिये और वहां पर इस पैसे का उपयोग करके वहां पर बनवा दीजिये। बालाजी भी जाते हैं। पूरी जी भी नजदीक हैं। वाराणसी और उत्तराखण्ड भी बहुत जाते हैं। यह मेरा सुझाव है कि आप अपनी क्षमता के मुताबिक इसमें जरूर कुछ न कुछ विचार करियेगा। शराब तो कामधेनु गाय है। हम जान रहे हैं, यह बंद होना नहीं है। लेकिन वाह सत्यनारायण भैया । इनके नेतृत्व में जो कमेटी बनाये हो, इतने सक्रिय लोग हैं कि 4 साल में एकाध- दो ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय, छत्तीसगढ़ के जितने सटोरिये हैं सरकार संरक्षित, वे सब दुबई भी जाते हैं वहां भी बनवाने के लिये आप बोलिये न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वे तो शुक्रवार की शाम को दुबई-बैंकाक भी जाते हैं और मंडे फ्लाईट में सुबह दुकान भी खोल लेते हैं तो शराब का ऐसा है कि शराब का तो हाल ही बेहाल है । आप बंद करो, न करो, आप जानो । आपकी घोषणा में था । आप करेंगे तो ठीक है लेकिन लॉकडाऊन में भयंकर शराब बिकी है । खुलेआम बिकी है । पुलिस के संरक्षण में बिकी है । बड़े-बड़े नेताओं के संरक्षण में वह शराब बिकी है । नाम बताउंगा तो कई बेनकाब हो जायेंगे इसलिए मैं इसको उचित नहीं समझता हूं । सत्यनारायण जी की दो कमेटी बनी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय, मैंने कल एक विषय उठाया था । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि पटल पर रख दें करके । आप अनुमति दिलवा दें, मैं पटल में वह पत्र रख देता हूं । मुख्यसचिव को एक आंदोलनकारी ने नामजद किया है कि इसके संरक्षण में छत्तीसगढ़ में यहां-यहां से आकर शराब बिकती है । मैं उसको पटल पर रख देता हूं, आप अनुमति दिलवा दीजिये । कल कहा था कि आप पटल पर रख दीजिये करके ।

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अभी आयेंगे न तो फिर उनको बोलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आप किसी से कम हैं ? आप इस सरकार के वलीहद हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पटल में रखने की अनुमति के साथ सदन से आपकी घोषणा आये कि हम इसमें कार्यवाही करवायेंगे । आप सक्षम व्यक्ति हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी आयेंगे न, अभी आने वाले हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने बोला न कि आप सरकार के वलीहद हैं, आप मुख्यमंत्री जी के वलीहद हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 2 कमेटी, 3 कमेटी की कौन-कौन सी कमेटी की जांच यही कर रहे हैं रिपोर्ट देने के लिये । वह स्काईलेब का मामला मैंने ही इस सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसी सरकार के कार्यकाल में उठाया था । मुझसे चौबे जी बोले कि आप क्या चाहते हैं, अगर आपको पॉवर मिलता तो आप क्या करते तो मैंने कहा कि मैं तो बोल देता कि विधानसभा में निकलने के बाद वहां पहुंचते तक उसको बुल्डोजर से उड़ा दो तो आप लोगों ने कमेटी बनायी है । 4 साल में यह तय नहीं कर पाये कि यह रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए । यह अच्छा है कि यह बुरा है ? कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ? कि इसमें शिष्टाचार हुआ है? आप 4 साल में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं । अब 6 महीने बाद जब जाना है तो सत्यनारायण जी अभी मीटिंग में बिहार गये थे जब रवानगी की बेला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है धर्मजीत भैया आपने जब उठाया था उस समय शिष्टाचार नहीं हुआ था । शायद बाद में कुछ शिष्टाचार हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त दुनियाभर की जो बात आ रही है । कभी मरकाम जी बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया । आप लोकायुक्त बना दो न, लोकआयोग नहीं, लोकायुक्त-लोकपाल जो भी उपयुक्त है पॉवरफुल कमेटी । लोकआयोग के बारे में रिपोर्ट लिखी गयी थी, उन्हीं के जस्टिस ने लिखा था कि यह दंतविहीन, नखविहीन संस्था है तो दंतविहीन-नखविहीन में बेचारा क्या करेगा ? तो नख वाली, दांत वाली संस्था बनाओ जो चाब ले, खा ले, चबा दे, मुर्गी के टाईप खा जाये, मुर्गी के टांग टाईप चबा जाये ऐसी संस्था बनाईये तो भ्रष्टाचार बंद होगा । टेग भी लगाये, मुर्गा टाईप खाये, जो करना है करे लेकिन डर तो पैदा करिए । पर्यटन मंत्री जी हमारे मोहले जी को और हमको बताये कि मुंगेली में दो रूपये नहीं दिये हैं करके । आपने क्यों नहीं दिया भैया ? हम लोगों ने क्या गलती कर दी है तो चलिये, हमको मत दो।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन । मैं पर्यटन के बारे में क्या बोलूं ? चिरमिरी, एक बहुत रमणिक जगह है, बहुत खूबसूरत है । एक बार भूपेश बघेल जी, हम लोग सब साथ में न्यूजीलेण्ड और ऑस्ट्रेलिया गये थे तो वहां पर क्वींस टाऊन शहर जब हमने देखा तो मुझे लगा कि यह चिरमिरी से मिलता-जुलता है वैसे ही पहाड़ी में रात को लाईट दिखे, इधर-उधर पहाड़ । बहुत सुंदर है, आप लोग नहीं

गये हैं तो विनय को बोल दीजिये कि कम से कम सम्मानपूर्वक घूमा दे । वहां पर कोयले का खदान सबसे पुराना है । वह बंद हो गया, अब वहां पर जनसंख्या जब वहां नगरपालिका बनी थी तो 1 लाख 25 हजार जनसंख्या थी । अब वहां 70 हजार की आबादी हो गयी है, उनको बचाईये । उस उजड़ते हुए शहर को बचाईये । वहां स्पोर्ट्स गेम का आयोजन करिये । वहां वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन करिए। वहां टूरिज्म बनवाइए। वहां पर मोटल के लिए जगह दीजिए। वहां रेस्ट हाउस बनवाइए। कुल्लू-मनाली सरीखे छोटा सा एरिया बहुत सुंदर दिखेगा। उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां की जो आबादी खत्म हो रही है, वह बढ़ेगी। जो शहर एक जमाने में समृद्ध, शानदार था, वह मरणासन स्थिति में जा रहा है। उसको बचाने का काम कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ के लोग चिरमिरी में एक ही जगह जियोलॉजी पढ़ने जाते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, लाहड़ी कॉलेज। स्पोर्ट्स मंत्री जी हैं। इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- किनका?

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी का।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन से वाले?

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हमारे नंद कुमार जी, हमारे नेता के आप सुपुत्र हैं। आपका बहुत आदर है। बिलासपुर में बहतराई में एक स्टेडियम है। आप जानते होंगे। आप गये भी होंगे। यह भा.ज.पा. के शासनकाल में बना है। एस्ट्रोटर्फ वगैरह भी बाद में कोई लगवाया है, क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं वहां 2 प्रोग्राम में गया था।

सभापति महोदय :- और कितना समय लेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, 5 मिनट। बहतराई स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत बड़ा इंडोर हॉल इस विधान सभा के हाल से 3 गुना बड़ा इंडोर हाल है। एयर कंडीशंड और वहां हाल क्या है साहब, पोताई नहीं हो रही है। झाड़ में सांप निकलता है। वहीं लड़के-लड़कियां रहते हैं। कभी भी सांप काट ले, बिच्छू काट ले, हाल बेहाल है। इतना बड़ा आपके पास establishment है तो उसकी हिफाजत करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है क्या? आप क्यों नहीं करते? हम दिखाने के लिए ले जाते हैं, लोग देखकर भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बदरंग तरीके से है। देखने में घिन-घिन लगता है। उसको ठीक करा दीजिए। मंत्री जी, हमारे मित्र और इस सरकार के बहुत दमदार मंत्री अकबर साहब, 19 गांव के कोर एरिया के 3 गांवों को हटाने के लिए मेरे प्रश्न के उत्तर में 3 दिन पहले आपने बताया। 1 तो उसमें आपका जो आंकड़ा था कि इतने परिवार के लिए इतना हेक्टेयर, वह बहुत विसंगति है। जरा, एक बार अपने अधिकारियों को बोलकर पढ़वाइएगा, लेकिन आपने अंततः यह कह दिया कि अभी तक के वहां पर एक रूपया केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया है। आपका ही जवाब है। मैं मान लिया। तो जब आयेगा, तब आप उसे हटायेंगे, मैं यह भी मान लेता हूं, लेकिन कृपापूर्वक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वे गांव वाले

सिर्फ यह जानते हैं कि हमको हटाना है या ये हटायेंगे। उनको यह नहीं मालूम है कि केन्द्र की सरकार का 2 रूपया भी नहीं आया है और आप बिल्कुल नहीं हटा पायेंगे। तो आपके जो अधिकारी जाते हैं, अचानकमार के रेस्ट हाउस में लंच करते हैं, आने के बाद बढिया बयान देते हैं, ये सब गांव हटा दिये जायेंगे। भय पैदा कर देते हैं। तो भय पैदा करने की प्रवृत्ति को जरा रूकवाइए। उनमें भय पैदा मत करिए। वे सबसे निरीह और बेबस लोग हैं। न उन्हें आप एक काम देते हैं। मैं चुनौती से कह रहा हूं कि सदन का कोई भी विधायक जाकर अचानकमार टाइगर रिजर्व के किसी गांव में दिनभर बैठे और अगर वह 20 रूपये का कोई काम कर लेगा, मेहनत करके 20 रूपये पाने की योग्यता अगर पैदा कर लेगा तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। सभापति महोदय, उनके बच्चे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी भी एक बार इस्तीफा दे रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जाओ न। ले लेना। मैं दूंगा नहीं दूंगा, बता दूंगा। सभापति महोदय, मैं एक बार लॉकडाउन के बाद उनके बीच गया था। वहां मैं एक गांव में रूका। मैंने पूछा कि आप लोगों को चावल सरकार का मिलता है तो बोले कि हां मिलता है। तो क्या-क्या खाते हो तो बोले कुछ नहीं खाते। चावल बनाते हैं और टमाटर को उबालकर पानी में नमक डालकर उसी में मिलाकर खाते हैं। बोले कि हमारे पास तेल के लिए भी पैसा नहीं है माननीय मंत्री जी। मंत्री जी, मेरा कहने का सिर्फ आशय यह है कि आप तो बहुत ही बारीकी में चलने वाले आदमी हैं। किसी की तकलीफ को हल करने के लिए आप दिल में इच्छा भी रखते हैं तो उनके गांव में छोटे-मोटे काम कम से कम वन विभाग का करवा दीजिए न। सभापति महोदय, मैं बहुत सालों से वहां जा रहा हूं। पिछले 4 साल में एक भी वनग्राम, फॉरेस्ट, वीलेज टू फॉरेस्ट, वीलेज कनेक्ट करने के लिए जो गांव होता है मिट्टी का, वह तक आप लोगों ने नहीं बनवाया है। तो काम मिले कहां से और जब काम नहीं मिलेगा तो नमक कहां से लायेंगे? तेल कहां से लायेंगे? बच्चे के लिए बिस्किट कहां से लायेंगे? कैसे जीयेंगे? उनके बच्चों के लिए सड़क भी बंद कर दिये थे। मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से सड़क खुलवाया । इस तरह से उनको नारकीया जीवन मत जीने दीजिए । आप हटाइए, हम आपके हटाने में सहयोग करेंगे लेकिन जैसा नियम, मापदंड आपने विधान सभा में दिया है, उस नियम के तहत् हटाकर बसाइए । जब तक आप नहीं हटाते हैं, तब तक उनकी ज़िंदगी की हिफ़ाजत करना आपका काम है माननीय मंत्री जी ।

सभापति महोदय :- पांच मिनट से अधिक हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 मिनट सर । सिंचाई, बोधघाट परियोजना का क्या हुआ? कहां तक मामला पहुंचा वही बता दीजिए ? भैंसाझार परियोजना 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई का प्रोजेक्ट है और वह टर्न-की जैसा है, वही प्रोजेक्ट बनाएगा, वही बांध बनाएगा, वही नहर बनाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोधघाट की बात उठाओगे इसीलिए सिंचाई मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों सदन से बाहर हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिर्फ साढ़े 12 हेक्टेयर सिंचाई हो रही है । उसका ड्राइंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है और उस ठेकेदार को बड़े बड़े शक्तिशाली नेता संरक्षण दे रहे हैं । जनता के पैसे से, जनता के लिए बनाए गए सिंचाई बांध को एक ठेकेदार की मुट्ठी में आपने कैद कर दिया । जनता की ज़िदगी और किसानों की जिंदगी एक ठेकेदार अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा । अभी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शैलेश पाण्डे जी की मांग पर बिलासपुर में दो-दो एनीकट बन रहे हैं । इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है वहां पर, घटिया एनीकट बन रहा है कि उसका कोई हद नहीं । वही ठेकेदार भैंसाझार में था । सभापति महोदय, मान लो वह एनीकट बन भी गया, पानी भर भी गया तो बिलासपुर की नालियों का पानी जो जा रहा है वह तो सीवरेज का बड़ा टैंक बनेगा, जलकुंभी फैलेगी, जिसकी हमने कल्पना की हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि वहां पर बढ़िया बोटिंग होगी, बच्चे नहाएंगे, घूमेंगे, शहर के लोग आएंगे । वहां तो बदबू मारेगा तो लोग नाक दबाकर गाड़ी में बैठकर भाग जाएंगे । वहां पर नालियों के निर्माण के लिए बजट में, सीवरेज पम्पिंग प्लांट के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए । स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कोई लोकल नेता..।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट साहब । विधायक को रखा ही नहीं गया है । जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं । मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं । मैं नाम लेकर उस नेता को अपमानित नहीं करना चाहता और न मैं बदनाम करके आपके गुस्से का शिकार होने देना चाहता । जब आप हैलीपैड में गए थे तो एक रस्सी लगाकर, रस्सी के इस तरफ एक बहुत बड़ा नेता और रस्सी के उस तरफ मुख्यमंत्री जी । अधिकारियों को यह नहीं लगता कि प्रोटोकॉल में वह एम.एल.ए. है, मंत्री है, महापौर है या कोई बड़ा पदाधिकारी है, निर्वाचित अधिकारी है । उसको रस्सी के बाहर, जनता कोटा में । यह असम्मान ज़रा बंद कराइए । हम लोगों को तो बुलाते नहीं, अब 4 महीने के लिए क्या शिकायत करें । यंत्र बांटना है, जंत्र बांटना है, साइकिल बांटना है, उसमें बुला लेते हैं, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

सभापति महोदय, सीवरेज में पानी जाएगा नहीं और अमृत मिशन में पानी आएगा नहीं । यह बात मैंने 4 साल पहले बोला है और आज भी बोल रहा हूं । अगर 6 महीने बाद बिदाई सत्र में मौका मिला तो..।

श्री शिवरतन शर्मा :- सीवरेज के एक्सपर्ट और अमृत मिशन के एक्सपर्ट दोनों बैठे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक बात और । सूदखारों का, ब्याजखोरों का बहुत बड़ा आतंक है । यहां सत्ता के संरक्षण पाए हुए नेता ब्याज पर अंधाधुंध पैसा देते हैं और मनमाने तरीके से ब्याज वसूलते हैं, इसके चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आई.जी. और एस.पी. को डायरेक्शन दें कि वे ऐसे तत्वों को सख्ती से कुचल

कर रख दें । ऐसे लोग जो ब्याजखोरी करके गरीब लोगों के मकान, दुकान, गहना सब रखवाते हैं । ऐसे लोगों को कुचल दीजिए, पूरे प्रदेश में आपका नाम होगा ।

श्री पुन्नूलाल माहले :- सभापति जी, आप कहते हैं कि कुचल कर रख दीजिए। ये लोग तो पंडरिया के भाजपा को कुचल रहे हैं । बाकी नहीं कुचल सकते ।

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बस अब खत्म कर रहा हूं । पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मैं कोई सड़क की बात नहीं कह रहा हूं । लेकिन ध्यान दिला रहा हूं पटेल जी बता देना।

श्री अजय चंद्राकर :- पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री अपना अनुदान मांग शुरू होगा करके सुबह से टेंशन में हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं क्यों टेंशन में हैं। आप जो बोलोगे हम मानेंगे, यहां से अमेरिका के लिए रोड बना है, हां बोल देंगे। आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। कोई टेंशन मत पालिए। मैं दो तीन बात बताना चाहता हूं। यह जितना छोटा-छोटा पुल पुलिया है, उसका कहीं आधा दीवार टूटा है, कहीं और टूटा है, पता चला एकात गाड़ी गप से अंदल चला जाए। उसको तो बनवा दीजिए, उसमें थोड़ी पैसा लगता है, ना उसका कोई बजट प्रावधान करना पड़ता है, वह तो एनुअल रिपेयर में होता है, चूने में थोड़ा पुतवा दो, पर नहीं टूटा रहेगा। गांवों के नाम लिखने का ठेका किसको दिए हैं पता नहीं, जो सहसपुर गांव है उसको सहजपुर लिख दिए हैं। पोड़ी को पाड़ा लिख दिए हैं। पता नहीं उसको देखते भी है या नहीं देखते हैं। बड़ा बुरा लगता है। यह सब थोड़ा क्वेरी कराना चाहिए और उसको व्यवस्थित करना चाहिए।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। साहब दो मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद यहां भाषण वगैरह नहीं होना है, अब जन-गण-मन बजेगा और हम लोग घर जाएंगे। (हंसी) मैं बिलासपुर के लिए मांग करता हूं कि दो महापौर नगर निगम बनाया जाना चाहिए। बिलासपुर के नदी के उस तरफ उत्तर और बिलासपुर के इस तरफ दक्षिण हो। दो महापौर बनाईए, बहुत बड़ा है, पैसा कम आता है तो दो में पैसा आएगा। दो जगह की नेतागिरी बढ़िया चलेगी। हमारी लोरमी को नगर पंचायत, नगर पालिका का दर्जा मांग रहा हूं और लालपुर थाने में जहां पर सतनामी समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां कॉलेज की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, कम मेरी तबियत के बारे में भी यहां आगे से पीछे से किधर से प्रश्न उठा। मैं बोल नहीं पाया था। सभापति महोदय, हां, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। बाम्बे के एशियन हॉस्पिटल में हुआ है। लेकिन मैं वहां ईलाज कराकर स्वस्थ हो गया हूं। जो लोग अपने को लोहे के लंगड़ का आदमी समझते होंगे, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। किसी की तकलीफ में किसी की तबीयत में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जितनी जिंदगी भगवान ने दी है, वह तो मैं जीऊंगा ही, मुझसे वह जिंदगी कोई छीन

नहीं सकता है। लेकिन बीमार तो सब पड़ते हैं। इस तरीके का मजाक उड़ा करके कोई बोले कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो बहुतों को हार्ट का आपरेशन हुआ है। मनमोहन सिंह का भी हुआ है और अभी कई लोगों का होगा। यह हल्की बात नहीं करना चाहिए। इधर तो इनको बहुत गुस्सा है, मंत्री जी लोगों को गुस्सा हो तो समझ में आता है। आप लोगों को हर बात में बहुत गुस्सा रहता है। कोई यहां नहीं आ सकता, कोई वहां नहीं जा सकता, उसके यहां क्यों आया, उसके यहां क्यों गया, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको निपटा दूंगा। इस टाईप की बात करने वाले लोगो के लिए मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- भैया, उसके बारे में मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। वह हास्य पद मैंने ही कहा था, अगर बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। माननीय धर्मजीत भैया।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आपने तो यहां कहा ना। कई तो विधान सभा के बाहर भी बोले हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अगर कल की बात कह रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बाहर की भी बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मैं तो हाड़ मांस का आदमी हूं, जो लोग लोहे के हैं, वे लोग घमंड करें। माननीय सभापति महोदय, यह जो गुस्सा है ना, उसके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक श्लोक कहा था।

क्रोधाद्ध्वति संमोह: संमोहात्स्मृतिविभ्रम:।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति

सभापति महोदय, इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ है, यह कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस क्रोध को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। (मेजों की थपथपाहट) छोटी सी जिंदगी है। इसमें ईर्ष्या दिखाने और नफरत करने और किसी को नीचा दिखाने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी लकीर खींचो। किसी की लकीर मिटा देने से कोई बड़ा नहीं होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और हमको जहां जाना होगा वहां जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। हम यहां जनता की सेवा के लिए जनता की बात यहां कर रहे हैं और इस बात को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम सब धर्मजीत जी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हैं। यदि किसी के बोलने से उनको कोई कष्ट हुआ होगा तो मैं सबकी तरफ से उनसे

क्षमा चाहता हूं। वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, लंबा जीवन जीये और हम सब के साथ में लंबे समय तक चले। मैं प्रभु से यही कामना करता हूं और मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं, आदरणीय बृजमोहन भैय्या जी की बात का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, आप बैठिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक मिनट की बात है। वैसे भी हम सभी को आदरणीय धर्मजीत भैया बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वह बहुत अच्छे नेता हैं। यदि वह कभी कुछ बोल देते हैं तो हमें उनकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बृजमोहन भैया भी बहुत सीनियर हैं, वह बहुत सारी बातें बोलते हैं। चंद्राकर जी भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं लेकिन इस सदन में सबको अच्छे से रहना चाहिए। इस तरह व्यक्तिगत रूप से किसी के जीवन पर नहीं बोलना चाहिए। मैं भी चाह रहा हूं कि आदरणीय धर्मजीत भैया और उनका परिवार बहुत सुखी रहे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, धर्मजीत भैया हम सबके आदरणीय हैं। वह हमारे गार्जियन जैसे हैं और हम हर समय उनके साथ हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं धर्मजीत जी को धन्यवाद देता हूं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर आदमी को बीमार पड़ना है। हर आदमी के घर में घटना होती है। जिसके घर में घटना होती है उसको मालूम है कि उस पर क्या दु:ख बितती है।

सभापति महोदय :- चलिये, शुरू करिये।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय सभापति महोदय, आज हमर प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी हा वर्ष 2023-2024 के 1 लाख, 12 हजार, 708 करोड़ रूपये के जो बजट ला हे, ओखर समर्थन में मैं खड़े हो। मैं वर्ष 2018 में प्रदेश के पूरा जनता ला भारतीय जनता पार्टी हा जो बोले गिस हाबे, पहली ओखर एक छोटे से दोहा के रूप में बोलना चाहहुं।

वादाखिलाफी, असत्य, लबारी
तैं झन आबे मोर दुआरी
2100 के फांसा अऊ 300 के झांसा
अऊ नहीं चलही अब के बारी,
तैं झन आबे मोर दुआरी।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2018 में जब चुनाव होइस तो पूरा प्रदेश के जनता 3 बार एमन ला मौका दीस हे अऊ जब ए मन ला 3 बार मौका दीस हे अऊ एमन हा किसान मन से अऊ अन्नदाता मन से वादा करे रीहिस हे कि 2100 रूपया समर्थन मूल्य अऊ 300 रूपया बोनस देबो। पूरा प्रदेश के जनता पूरा विश्वास करके एमन ला 3 बार अवसर दीस हाबे अऊ 3 बार अवसर दे के बाद भी भारतीय

जनता पार्टी के मन अन्नदाता के साथ जो वादाखिलाफी करीस अऊ ओ भी 3 बार अवसर दे के बाद जब वर्ष 2018 में इही बात ला अन्नदाता मन हा बोलीस हे।

माननीय सभापति महोदय, जेन वादा प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी करिस, हम सब जाके अऊ हमर पूरा कार्यकर्ता जाके पूरा प्रदेश के जनता के पास निवेदन और आग्रह करिस कि यदि हमर कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाहुं, किसान के सरकार बनाहुं तो किसान के कर्जा माफ भी होही अऊ किसान के ऊपज के भी कीमत ला हमन देबो। ए पूरा विश्वास करके तीन तिहाई के बहुमत देके पूरा प्रदेश के जनता हा हमन ला इहा भेजीस हे। आज प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी हा जइसे मुख्यमंत्री पद के शपथ लीसे अऊ सबसे पहले जो काम करीस तो ओ अन्नदाता के लिए, किसान के कर्जा माफी के लिए जो कलम चलइस हे अऊ पूरा प्रदेश के अन्नदाता के कर्जा माफी के लिए जो काम करीस हाबे, ओ बहुत ही अच्छा काम हे।

माननीय सभापति महोदय, ओखर साथ आज पूरा भारत देश में छत्तीसगढ़ पहिली राज्य हे, जिहा किसान, अन्नदाता मन के समर्थन मूल्य के मान अऊ सम्मान रखते हुए, अन्नदाता हा खून-पसीना एक करके जो अन्न ला उगाथे, ओखर सही कीमत देने वाला हे तो कांग्रेस के सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार हे । आज किसान के रोटी अउ किसान के पगड़ी ला जो बनाए रखे हे तो कांग्रेस के सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी बनाए रखे हे । निश्चित रूप से 2017 में जब राजनांदगांव जिला में बहुत घोर अकाल पड़िस तो हजारों किसान सड़क मा उतरे रिहीसे कि किसान के कर्ज ला माफ कर दव । ओ समय मोर गृह जिला के विधायक डॉ. रमन सिंह जी ह मुख्यमंत्री रिहीसे । पूरा किसान सड़क में उतर के अपन अधिकार के लड़ाई लड़िस हे अउ मांग करिस कि किसान के कर्जा माफ हो जाए, बीमा मिल जाये, ए बात का पूरा बोलिस हवय । लेकिन दुर्भाग्य कहे जाये कि ये मन सदन में बनावटी आंसू बहाथे । बोलथे कि आज इतना अत्याचार होवथे, जेल में भेजे के काम करथे । मैं याद दिलाना चाहहूं कि ओ समय 12 बजे रात में किसान ला बिस्तर से उठाके जेल में डाले के काम करे हे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार रिहीसे, तेमन करे हे । साथ-ही-साथ वन अधिकार पट्टा देके बात ला भी बोलिस, लेकिन ये मन ह अईसे जूता, मोजा, चप्पल दे रिहीसे, जेकर जोड़ी घलो नहीं रिहीसे । जब भी हमन चप्पल लेथन त जोड़ी में लेथन, ए मन ह कोई ला 7 नम्बर के चप्पल, त कोई ला 6 नम्बर के एकड़ा, एकड़ा चप्पल दे के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ह करिस हे ।

सभापति महोदय, ये सदन के माध्यम से अउ खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के जनता के तरफ से मैं प्रदेश के मुखिया ला धन्यवाद देना चाहहूं, जेन ह आज अन्नदाता के मान अउ सम्मान करिन हे, ओकर साथ महिला के मान अउ सम्मान करिस हे । आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन ला, हर व्यक्ति ला धरना प्रदर्शन करे के अधिकार हे । प्रदेश में हर व्यक्ति ला अधिकार हे कि अपन अधिकार मांगना चाहिए, प्रदेश में धरना प्रदर्शन करना चाहिए । आज हमर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन, हमर सहायिका मन,

रसोइया मन बहुत ही अच्छा ढंग से होली के त्यौहार मनईस हे और आज ये बात प्रदेश के मुखिया बोलिस हे, ओ मन ला साढ़े 6 से लेकर 10 हजार रूपया देके काम करे हवय तो कांग्रेस पार्टी के सरकार, हमर भूपेश बघेल जी करे हवय ।

सभापति महोदय, मैं गोधन न्याय योजना के बात करना चाहहूं । विपक्ष के मन पहिली गोबर, गोबर के बात करयं, लेकिन कोई दुनिया नहीं सोचे रिहीसे कि दो रूपया किलो में गोबर खरीदी होही, लेकिन आज दो रूपए किलो में गोबर खरीदी होवत हवय और गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमर महिला समूह के बहिनी मन बहुत ही अच्छा ढंग से काम करथे और ओ काम करके अपना घर, परिवार ला आर्थिक रूप से मजबूत करे के काम करत हवय । ओकर श्रेय जाथे तो सबसे पहिली भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के सरकार ला श्रेय जाथे ।

सभापति महोदय, आज प्रदेश में रिकार्ड तोड़ धान खरीदी केन्द्र हे और जो धान खरीदी करे हे, वह बहुत ही रिकार्ड तोड़ हे । पहिली मैं देखत रेहेंव कि 2016-17 में मात्र 14 लाख किसान मन पंजीकृत रिहीसे, लेकिन आज कांग्रेस के सरकार में लगभग 24 लाख किसान मन पंजीकृत रिहीसे और आज किसान मन ह धान बेचिस हवय । हमर प्रदेश के बात हे, पर मैं खुज्जी विधान सभा के बात बताना चाहहूं । 15 साल के कार्यकाल में खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक धान खरीदी केन्द्र, वह भी उपकेन्द्र रिहीसे । हमर 4 साल के कार्यकाल में खुज्जी विधान सभा में 9 धान खरीदी केन्द्र खोले हे तो वह कांग्रेस पार्टी के देन हे । ए उपलब्धि हमर कांग्रेस सरकार के हवय । हमर मुखिया के मंशा हवय कि छोटे-छोटे धान खरीदी केन्द्र होही, जेमे बड़े-बड़े सोसायटी रहिथे और किसान मन ला जाके एक से दो दिन तक रूके ला पड़य, लेकिन आज हमन देखथन कि कोई भी किसान ला एक से दो दिन पानी-पसीया धरके बैठे के जरूरत नहीं पड़य। किसान सुबह धान लेकर जाथे अउ शाम तक कांटा हो जाथे । ये उपलब्धि हमर कांग्रेस पार्टी के हवय । आज हमन देखथन कि हमर प्रदेश के मुखिया ह 1 करोड़, 7 लाख टन धान के खरीदी करे हवय, ये रिकार्ड तोड़ अउ बहुत ही अच्छा काम करे हवय। पूर्व के सरकार में बोनस तिहार मानस, बिजली तिहार मानय अउ अनेक प्रकार के तिहार मनाके जो मूलभूत सुविधा हमर सरपंच मन ला मिलथे, ओ पईसा मा खर्च करे के काम भारतीय जनता पार्टी के हमर नेता मन करे हें ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहहूं कि मोर खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में कईसे रोड़ हवय । जेन समय जोगी जी के सरकार रिहसे त रोड़ के निर्माण होए रिहीसे और इकर मन के 15 साल के सरकार में गड्डा ला भी पाटे के काम नहीं करे हे । आज तो प्रदेश के मुखिया, कांग्रेस के सरकार ला धन्यवाद देना चाहहूं । जब कांग्रेस के सरकार रिहीसे, ओ समय सड़क बने रिहीसे अउ आज फिर से कांग्रेस के सरकार बनिस तो वही 13 करोड़ रूपए के स्वीकृति सड़क बर मिले हे । मैं एक गांव मा गैव, बी.जे.पी. के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहिस, ओ हा रोड ला बना दे, रोड ला बना दे, मांगत-मांगत थर्रा गय

रहिस। ओ हा आखिरी में गमछा ला बदल दिस, बोलिस कि मोर सरकार के रहत ले मैं रोड ला मांगेव, लेकिन नइ मिलिस। मैं आज गमछा ला उतरत हव, आज कांग्रेस के सरकार मा ये रोड हा बनिस। तो सभापति महोदय, ये मन चाह के भी नइ बोल सकत हे। चाहत जरूर हे अउ कहत भी हे कि आज सबसे ज्यादा काम होवत हे तो कांग्रेस के सरकार मा होवत हे। इकर सरकार के बारे मा आप ला बताना चाहूं कि राजनांदगांव रमन सिंह के गृह जिला रहिस हे अउ ओ समय मुख्यमंत्री रहिस। वहां एक-एक कोना विकास से नहीं बचतीस। मोर खुज्जी विधानसभा मा एक ऐसे गांव हे, जो अबूझमाड़ जैसे हे। वहां आज ना आंगनबाड़ी हे, ना स्कूल हे, ना चले के रास्ता हे ना पुल-पुलिया हे। लेकिन आज बजट में पुलिया स्वीकृति मिले हे अउ बहुत अच्छा ढंग से स्वीकृति दिलाही, यही उम्मीद और विश्वास भी करन चाहूं।

माननीय सभापति महोदय, एखर साथ-साथ अनेक प्रकार के योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मा शुरूआत मा 15 हजार रूपया मिलत रहिस हे। हमर आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व मा 25 हजार रूपया करिस ओखर बाद अभी 50 हजार रूपया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करे गय हे। चाहे गोधन के बात हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन के बात हो, जो अनेक काम करे गय हे तो हमर भूपेश बघेल जी की सरकार मा करे गय हे। निश्चित रूप से ऐसन काम होते रहना चाहिए अउ होवत भी हावय। ओखर साथ-साथ चाहे सहायिका के बात हो, चाहे गांव के कोटावार के बात हो, चाहे गांव के पटेल के बात हो, जेमा गांव के मुखिया के रूप में पटेल ला चुने जाथे। उनखरों मन के मान अउ सम्मान करे के काम करे गय हे तो हमर कांग्रेस के सरकार मा करे गय हावय।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही अच्छा ढंग से "नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी" जेमा कई किसान पैरा दान करत हावय। पहली पैरा ला जला देत रहिस हे। नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी गांव मा बहुत ही अच्छा ढंग से संचालित होवत हे, जेमा बिहान के बहिनी मन अनेक प्रकार के, जैसे एक मिनी उद्योग लगाय हे, जेमा, मिर्ची, मसाला अउ अनेक प्रकार के काम हमर महिला बहिनी मन ला मिलत हावय तो निश्चित रूप से ये मंच के माध्यम से, ये सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहू। ओखर साथ-साथ हमर खुज्जी विधानसभा मा बहुत पुराना मांग रहिस हे कि कुमरदा ला तहसील के दर्जा दिए जाय। वहां जा-जाके, वहां बैठ के मांग करत रहेन। ओ समय अभिषेक सिंह सांसद रहिस हे, ओ रहिस तेन घोषणा करे के काम करिस, लेकिन ओ काम ला भी पूर्ववर्ती सरकार नइ कर पाइस। आदरणीय भूपेश बघेल जी भेंट-मुलाकात मा गइस अउ वहां तहसील के दर्जा के घोषणा करसि अउ बजट मा स्थान दे के काम आदरणीय भूपेश बघेल जी करे हावय।

माननीय सभापति महोदय, ओखर साथ-साथ हमर खुज्जी विधानसभा महाराष्ट्र बार्डर से लगे हुए हे। हमन आज तक मांगत रहेन कि महाविद्यालय मिल जातिस। लेकिन दुर्भाग्य कहे जाय कि 15 साल के कार्यकाल में एक भी महाविद्यालय, ना एक भी तहसील या उप केन्द्र खोले गय हे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय सभापति महोदय, हमन ला बहुत कम बोले के समय मिलथे।

सभापति महोदय :- अभी बहुत लोग है। 14 लोग और बचे हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- सभापति महोदय, हमन चिल्हाटी मा भेंट-मुलाकात के समय आदरणीय भूपेश बघेल जी गइस तो ओ समय बहुत ही सुन्दर ढंग से महाविद्यालय के घोषणा करिस हे। ओ क्षेत्र के बच्चा मन के भविष्य के संवारे बर शिक्षा के क्षेत्र मा बहुत ही अच्छा निर्णय आदरणीय भूपेश बघेल लीस हावय। ओखर साथ-साथ देखथन कि शिक्षा के क्षेत्र मा आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल , जेमा गरीब, मजदूर, किसान के लइका मन शिक्षा अध्ययन करत हे। किसान मन के भी मंशा रहिस कि मोरो लइका आई.ए.एस. अधिकारी बनय, आई.पी.एस. अधिकारी बनय, वही सपना ला साकार करे बर आदरणीय भूपेश बघेल जी हा आज आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हावय।

माननीय सभापति महोदय, ओखर साथ-साथ भूमिहीन कृषक, कोई दुनिया नइ सोचे रहिस हे कि जेखर पास एक डिसमिल जमीन नइ हे, ओला भी सरकार योजना के लाभ मिलय। ओखर बारे मा भी बहुत अच्छा ढंग से योजना निकाले गय हे, जो भूमिहीन ग्रामीण कृषक हावय, ओ मन ला 7 हजार रूपया दे के घोषणा बहुत ऐतिहासिक निर्णय हे, मैं ओखर लिए भी प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेली जी ला धन्यवाद देना चाहूं। सभापति महोदय, आप मोला बोले के अवसर दे, ओखर लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्यय पर चर्चा करने के लिये खड़ी हुई हूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूंगी । हमारे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी ने कहा था कि मैं दबे कुचले समाज को जिल्लत भरी जिंदगी से निकालकर मान-सम्मान वाली जिंदगी जीने के लिये उनको पैरों में खड़ा देखना चाहता हूँ । सम्माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ सरकार वर्ष 2023-2024 के बजट की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने इतने बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाये थे, इतने बड़े-बड़े पोस्टर लगवाये, अखबार में यह लिखा गया कि भरोसे का बजट । इसका इतना प्रचार-प्रसार किया गया कि हम लोगों को भी लगा कि शायद इस बार छत्तीसगढ़ सरकार अपने पिटारे से कुछ न कुछ तो करेगी ही । माननीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ दिखाने के लिये है और करने की उनकी कुछ नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भरोसे के बजट के नाम पर इतना ढिंढोरा पिटा कि हर जिले में एलईडी के माध्यम से लोगों को बताने के लिये इस बजट भाषण में सब को दिखाने के लिये, लोगों को जताने के लिये टी.वी. लगाया गया, लेकिन जो भरोसे का बजट है, उस भरोसे पर जो छत्तीसगढ़ सरकार की उम्मीद टिकी हुई थी, उस भरोसे पर छततीसगढ़ की सरकार उतर नहीं पाई है । छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित में नहीं है, वह केवल भ्रष्ट्राचार के लिये ही बनाया गया है । सम्माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार

शिक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है । सम्माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला है, इसके लिये बधाई के पात्र हैं । छत्तीसगढ़ मे ऐसे जर्जर विद्यालय हैं, ऐसे भवनविहीन विद्यालय हैं, जहां आज की स्थिति में हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं । ऐसे छोटे-छोटे कस्बे हैं, छोटे-छोटे गांव है, जहां हम लोगों ने पत्र के माध्यम से बजट में जोड़ने के लिए, उन्नयन के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को आवेदन दिया था, लेकिन बजट में शामिल नहीं है । इससे छोटे-छोटे कस्बे जहां पर बेटियां पढ़ने के लिये, दूसरे गांव जाने के लिये हमारे बेटियों को परमिशन नहीं मिलता है । वह स्कूल मीलों दूर रहती है, गांव में इतनी सुविधा नहीं होती है, आये दिन हमारी बेटियों के साथ जो घटना होती है, उससे परिजन भयभीत रहते हैं । मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, जिसका उन्नयन करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारी बेटियों को शिक्षा प्राप्त हो । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि पामगढ़ क्षेत्र में बजट में शामिल करने के लिये, उन्नयन करने के लिये जो दिया है, उसको प्रशासकीय स्वीकृति दें । सम्माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास के बारे में अपने भाषण में कहा कि 1 अप्रैल से सर्वे कराकर हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उसको आवास दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे । सभापति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में यही रहता है कि केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन विपक्ष के साथी बताते हैं कि राज्य सरकार इसमें जो 40 परशेंट का जो रेशो होता है, वह जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में छत्तीसगढ़ की जो भोली-भाली जनता है, जिनके पास रहने के लिये छत नहीं है, कमाने-खाने के लिये बाहर के प्रदेशों में पलायन करते हैं, उनकी उम्मीद है कि हमको आवास मिले, ऐसे लिस्ट में सबका नाम है। राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है कि केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, यही लोग जानें, इस चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जो जनता है, वह पिस रही है । माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वह ऐसे बजट का प्रावधान करे, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनको आवास मिले और दर-दर भटकने की उन्हें आवश्यकता न पड़े ।

समय
3.59 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुये)

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं जल जीवन मिशन के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी । छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार के अरबों रूपये की राशि जो जल जीवन मिशन के तहत प्राप्त हुई है, उसमें जनता को ठगा जा रहा है । भ्रष्ट्राचार हो रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, कहीं

पाईप फटा हुआ है, किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, केवल दिखाने के लिये इसको लाया गया है । आम जनता को इसका सही उपयोग जो मिलना चाहिये, वह नही हो रहा है । इसमें केवल पैसों का दुरूपयोग किया जा रहा है । जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किये गये हैं, एक भी सफल नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि बिजली के लिये इन्होंने ढिंढोरा पिटा है, बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा जा रहा है, उपभोक्ताओं को डराया, धमकाया जा रहा है कि आपको जेल के अंदर डाल देंगे और डर से उपभोक्तागण पैसे को पटा रहे हैं ।

समय :

4.00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कथनी और करनी में अंतर होता है, तो केवल कहे ही नहीं बल्कि करके भी दिखाएं। छत्तीसगढ़ के लोग, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वह बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। जब भरोसे का बजट आया तो हमें भी यह लगा था कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो महंगाई है, जो गरीबी है, वह कम होगी। हमें यह उम्मीद थी कि केन्द्र सरकार ने भले ही गैस को 1250 रूपये बढ़ा दिया है, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार से हमें यह उम्मीद थी कि राजस्थान में जो नीति अपनाई गई है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार वह नीति अपनायेगी। लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि केवल हवा-हवाई में ही बातें हो रही है कि भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन धरातल में आम जनता का यह भरोसा, भूपेश बघेल जी के प्रति टूट चुका है। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्योंकि वह बार-बार उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं। यदि वे चाहते तो गैस की कीमत 500 रूपये कर देते, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने की है। क्योंकि वहां पर भी इनकी ही सरकार है। यदि वह चाहते तो यह कर सकते थे और आम जनता को गरीबी से बचा सकते थे। लेकिन इनकी मंशा आम जनता को सुरक्षित रखने की, गरीबी को कम करने की नहीं है। यही कारण है कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनका छत्तीसगढ़ सरकार पर जो भरोसा था, वह उठ चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी बहुत जोर-शोर से भाषण दे रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा है। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र है कि आपने हमारी बहनों का सम्मान किया लेकिन आपने भीख के रूप में रसोई कर्मचारियों के लिये क्या किया। वह बेचारे दिन भर अपने घर के कामकाज को छोड़कर पूरा दिन भर स्कूल में लगे रहते हैं और आप भीख के रूप में उनका 300 रूपये बढ़ा रहे हैं। यदि आपकी नियति सही होती, आप सही मायने में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते, तो आप उनकी भी कीमत 3 हजार, 4 हजार रूपये बढ़ाते। मैं आपके माध्यम से इसे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं। हमें पूरी उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने चार सालों में शराबबंदी का जो काम नहीं किया। जिसे पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं, हमारी बहनें एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी

कि इन्होंने भले ही चार साल में नहीं किया लेकिन जो आखिरी बजट में उसमें कुछ करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें भी कोई पहल नहीं की। मैं आपके माध्यम से इस सदन को और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता, जो हमारी बहनें हैं, इस बार अपने पल्लू में गांठ बांध लिये हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं लायेंगे क्योंकि वह झूठ की, ठगी की सरकार है। वह केवल भ्रष्टाचार और हमारी बहन, बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार ही कर सकती है।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बड़े-बड़े पोस्टर लगवाये जा रहे हैं। लेकिन यदि बेरोजगारी को सही मायने में देखना है तो आप गांव स्तर पर देखकर उनकी जनगणना करवाईये। अभी हमारे बच्चे 11वीं, 12वीं पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे और हमारे युवा भाई पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसके बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर यह बोलती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत कम हो गया है। कहां से कम हो गयी है। यदि आप सही मायने में प्रतिशत का आंकड़ा देखना चाहते हैं तो उन गांव-गांव में छोटे-छोटे कस्बों में जनगणना करवाईये, तब आपको सही स्थिति मालूम पड़ेगी। केवल बातें करने में यह वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नौकरी देने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून लाद दिये हैं, जिसमें लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आयेंगे। ये केवल कहने की बात कर रहे हैं। इनकी मंशा बेरोजगारी खत्म करने की नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि लोकतंत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कानूनी अपराध है। चाहे हमारी बहन-बेटियों के साथ देखा जाये, हर दिन उनके साथ शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। न तो हमारी 12 साल की बेटियां सुरक्षित है, न तो हमारी 8 साल की बेटियां सुरक्षित है, यहां तक मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी गंदी कानूनी व्यवस्था है कि इस प्रदेश में हमारी 72 साल की माता भी सुरक्षित नहीं है। हम पेपर या टी.व्ही. के माध्यम से देखते हैं, लेकिन यह केवल कानूनी अपराध को बताते हैं, उनका आंकड़ा पेश करते हैं, जो इनके नॉलेज में है। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं, जिसमें हमारी बेटियां समाज के डर से, प्रताड़ना के डर से और कहीं हमें कुछ हो न जाये, इस डर से अपने साथ हुए अपराधों को कानून के पास जाकर नहीं बताते। इनके पास अपराध का जो आंकड़ा है वह बहुत कम है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। इनका केवल एक ही काम रह गया है कि शराब के नाम पर जो भी मिले उसको पकड़ो और उससे पैसा वसूली करो। उसी तरह से अभी हमारे शैलेश जी नहीं है, उन्होंने जो बात कही कि हमारे थानाओं में रेट लिस्ट टंगी होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। शैलेश जी सामने बैठे हैं, मैं इधर देख रही थी । शैलेश जी, आपने जो बोला था, वह बिल्कुल सही है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपकी चर्चा हो रही है। आपने थाने में रेट लिस्ट की बात की थी।

श्रीमती इंदू बंजारे :- वह बिल्कुल सही है कि थाने में रेट लिस्ट टंगी हुई है कि चोरी, शराब, मारपीट के नाम पर कितना पैसा लेना चाहिए ? यह केवल वसूली की जा रही है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अब माननीय पाण्डे जी की दोस्ती पुलिस वाला करा होगे हे। काबर की अपन उद्बोधन में कहिन हावए कि केशव तोर घर चोरी होए हे तेला पुलिस वाले मन पकड़ डारही। अब मित्रता होगे हे। अब रेट लिस्ट ले ऊपर होगे।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के सांठ-गांठ लगेच रही भईया, लेकिन विपक्ष के मन ओ चीज के भुगतना ला भुगतत हन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ विधान सभा के अंतर्गत शिवरीनारायण नगर पंचायत है जहां पूर्व में सड़क निर्माण हुआ था जो आज भी अधूरा है, लेकिन जो प्रभावित किसान थे, उनको मुआवजा नहीं मिला है। मैंने उसके संबंध में ध्यानाकर्षण भी दिया है तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जो प्रभावित किसान हैं क्योंकि वह अधिकारी और कुछ किसानों की सांठ-गांठ की वजह से पैसे का स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया गया है। जो किसान हैं जिनकी जमीन नंबरी जमीन उसमें फंसी है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। इसके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो। जो किसान हैं, उनको मुआवजा मिले। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा निवेदन करना चाहूंगी। सम्माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहती हूँ कि मैंने सम्माननीय कृषि मंत्री जी के विभाग में एक प्रश्न लगाया था कि फुलगांव में जो जमुनी नाला है पिछले बजट सत्र में वहां उन्होनें निर्माण की गुणवत्ता के लिए जांच के आदेश दिये थे। पिछले बजट सत्र से आज तक हो गया, न तो कोई जांच की गई और न तो वहां पर कोई कार्यवाही की गई। मतलब इतने बड़े माननीय सम्माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं और उनके अधिकारी लोग उनकी बातों की अवेहलना करते हैं । उनके सदन में घोषणा करने के बावजूद भी आज तक उसका तत्परतापूर्वक निरीक्षण नहीं किया गया, उसकी जांच नहीं की गई। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार और उनके अधिकारी के कारनामे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका समय हो चुका है।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जिस तत्परता से हमारी आंगनबाड़ी बहनों, सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी की बहनों का वेतन बढ़ाया, इसके लिए आपको

बधाई देना चाहूंगी, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हमारे सहायक शिक्षक हैं, उनकी भी मांग है, आप उनकी मांगों को भी पूर्ण करें। मैं आपसे ऐसा निवेदन करना चाहूंगी। इसके साथ-साथ जो हमारे अतिथि प्रोफेसर हैं जिनकी वेतन में अनियमितता बढ़ती जाती है आपसे उसके भी संबंध में निवेदन करना चाहूंगी कि प्रोफेसरों का मानदेय उनके कार्यों के अनुरूप बढ़ायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत सारी बहनों ने महिला सशक्तिकरण के लिए कहा तो अगर सही मायने में हम महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो हमारी बहनें जो अनुकम्पा नियुक्ति के लिए धरना-आन्दोलन में बैठी हैं छत्तीसगढ़ सरकार का उनकी ओर भी ध्यान जाना चाहिए। उनके लिए भी यह ठोस कदम उठाये। मैं आपके माध्यम से ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनियमित कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा पत्र में उनके लिए भी बोला था कि हम उनको नियमित करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए भी कदम नहीं उठाया तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए कोई कदम उठायें। इसके साथ-साथ हमारे जो सरकारी वाहन चालक हैं हमें उनकी भी पीड़ा सुनने को मिलती है सत्तापक्ष के लोग तो बोल नहीं पाते क्योंकि यहां पर केवल मूर्ति के समान बैठे हैं, लेकिन वह अपने हक अधिकार के बारे में बोल नहीं पाते। इसलिए वह हम लोगों को अपनी पीड़ा बताते हैं। जितने भी हमारे सरकारी वाहन चालक भाई हैं छत्तीसगढ़ सरकार उनका भी वेतन बढ़ाये, चूंकि दिन-रात वह लोग हमारे साथ लगे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है क्या तीज, त्यौहार, क्या होली, दिवाली, उनको देखने को नहीं मिलता। वह दिन-रात हमारे साथ लगे रहते हैं मैं आपके माध्यम से उनका भी वेतन बढ़ाने के लिए निवेदन करना चाहूंगी। यहां कहने को तो बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कार्यों में विफल रही। अगर छत्तीसगढ़ सरकार की नीति ऐसे ही चलती रही तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा कहकर, मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्.।

जब इस प्रदेश का बजट लाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बातों से अपने विषयों की शुरूआत की। प्रदेश की जनता के स्नेह और आर्शीवाद से चार वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सच में जनता को इस सरकार से बहुत अपेक्षाये रहीं और वास्तविक रूप से बहुत बड़ा जनादेश इस कांग्रेस की सरकार को मिला। उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता लेकिन जो सत्य जान गया, उसको अहंकार कभी नहीं होता। लेकिन इस सरकार ने 04 सालों में अभी तक सत्य को समझा ही नहीं, सत्य को जाना ही नहीं। अभी भी वह इस

अहंकार में जी रहे हैं कि हमने सरकार अच्छे से चला जी। यह अहंकार आज भी इनको है। इस प्रदेश की स्थिति ये है। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है या जाना जाता है, छत्तीसगढ़ को जाना जाता है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहां होता है तो आप छत्तीसगढ़ में जाकर देख लीजिए। अवैध वसूली कहां पर होती है तो छत्तीसगढ़ को जाकर देख लीजिए। सबसे अधिक अपराध कहां पर होते हैं तो छत्तीसगढ़ को जाकर देख लीजिए। सबसे ज्यादा कमीशनखोरी कहां पर होती है तो छत्तीसगढ़ को जाकर देख लीजिए। सबसे अधिक चरस, गांजा जैसे तत्व, ऐसी चीजें जो समाज के लिए नासूर बन गई है, वह सबसे अधिक कहीं पर मिलती है तो वह छत्तीसगढ़ में मिलती है। अवैध करोबार का गढ़ प्रदेश सरकार के सरंक्षण में कहीं पर चल रहा है तो वह छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सबसे अधिक अपराध यहां पर हो रहे हैं। भू-माफियाओं का गढ़ कोई बना है तो वह छत्तीसगढ़ प्रदेश है। आज सरकार फिर इसी सोच में है कि 71 का जनादेश मिला है, लेकिन 71 कब उल्टा हो जायेगा, इस सरकार को समझ में नहीं आयेगा। वह 17 बन जायेगा और 17 होकर वह इधर बैठेंगे। वह इस तरह से न सोचें कि हमने 04 सालों में जनता से किये वादे पूरे किये हैं। यह लिखा हुआ बजट केवल लिखावटी बजट है। इसमें एक भी ऐसे शब्द नहीं हैं, एक भी ऐसी चीजें नहीं हैं जिसे सरकार ने पूरा करने के लिए अपना 100 प्रतिशत लगाया हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार को यह टाइटल दे दिया जाये कि हमेशा तो यह इस बात को कहते आये कि हमने जनता के लिए ये किया, वह किया, लेकिन आपने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। केवल और केवल आपकी बातें रह गईं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सार्वजनिक मंचों में जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। वह सीधे-सीधे जनता से ही असत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज लिया ही नहीं और कुछ ऐसे वर्ष हैं जिनमें हमने कर्ज लिया ही नहीं। कहा जाता है कि आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आज इस सरकार ने जो गुनाह किया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता उसकी कीमत चुका रही है। कर्जदार प्रदेश की जनता बनी है। कर्ज ये लेकर बैठे हैं। यह अपने घरों को भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का भला नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सरासर असत्य बोलते हैं। इन्होंने जो बजट लाया है, 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का बजट है और 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये खुद इनका कर्ज है। ये सरकार प्रतिमाह 500 करोड़ रुपये का ब्याज चुका रही है। आप कर क्या रहे हैं, ये सरकार की समझ से बाहर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं यह बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ऋण लिया और विश्व बैंक से ऋण लिया। बैंक से ऋण लिया, जी.एस.टी. ऋण और अन्य ऋण लिया। जब से यह सरकार बनी है तब से केवल और केवल प्रतिवर्ष ऋण लेते आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरेआम असत्य बोलते हैं। इन्होंने जनवरी से मार्च 2019 को 10,762 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया, 2019-

20 में 12,928 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। वर्ष 2021 में इन्होंने फिर से 17,555 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। वर्ष 2021-22 में फिर इस सरकार ने 10,880 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। मुख्यमंत्री जी अभी, जब यह बजट सत्र चल रहा था, वह एक सार्वजनिक मंच में गये और उन्होंने कहा कि हमने इस वर्ष तो कर्ज लिया ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022-23 में इन सरकार ने 2,364 करोड रुपये का कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री जी, सीधे-सीधे असत्य बोलते हैं। आप किसी और की बात करें तो समझ में आता है, आप जनता से असत्य बोतले हैं। आप सार्वजनिक मंचों पर असत्य बोलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने छत्तीसगढ़िया खेल का आयोजन करवाया। कोई नीति, नियम, कानून नहीं, किसी फर्स्ट-एड की व्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, उस खेल मे कई लोग मरे भी हैं। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। बाहर जाकर जो लोग मरते हैं, उनके लिए पैसा बांटते हैं। इनको अपने प्रदेश की चिंता नहीं है। न तो इनको किसी प्रकार का उपहार दिया गया कि कहीं खेल-खूद में कहीं जीत गये तो छोटा-मोटा उपहार की व्यवस्था कर देते। बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि जोन स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर यह जो छोटे-छोटे खेल का आयोजन करते हैं, उसकी वसूली सरपंचों से की जा रही है। सरपंच और सचिव पर इनके अधिकारी दबाव बनाते हैं। 10-20 हजार आप पैसा लाईये, तब हम सरकार के निर्देश का पालन करेंगे और हम खेल की व्यवस्था करेंगे। रामायण करने की इनकी बखत नहीं है तो क्यों यह रामायाण करवाते हैं। रामायण करवाकर पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पिटते हैं और 5 हजार, 10 हजार की वसूली सरपंचों से करते हैं। इनको रामायण करन। पूरे रामायण की व्यवस्था सरपंच करते हैं। सरपंच कहां से पैसे लायेगा। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आप इस तरह का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने निराश्रित बुजुर्ग, दिव्यागों को परित्यक्ता पेंशन 350 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया। अब आप जरा घोषणापत्र को झांक कर देख लें कि इन्होंने 1000 और 1500 कहा था। 500 रूपये से काम चलेगा क्या? आपको इनका पैसा बढ़ाना पड़ेगा। इतने में काम नहीं चलेगा। आप दिखावटी बजट का काम मत करिये। इन्होंने कहा कि हम 25 रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने कहा कि इस प्रदेश में 0.4 प्रतिशत बेरोजगारी है। यदि बेरोजगारी इतनी कम है तो यदि यह सभी बेरोजगारों को भत्ता देंगे तो सरकार पर कोई बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। यह केवल दो वर्षों का दे रहे हैं। आप पिछले चार वर्षों का बेराजगारी भत्ता दीजिये न। आपको किसने मना किया है। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए जो नीति-नियम, जो बान्डेशन लेकर यह आए हैं और जितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, उसमें 10 प्रतिशत भी लोग ऐसे नहीं हैं, जिनको यह लोग बेराजगारी भत्ता दे पायेंगे, क्योंकि इन्होंने तो इतने नियम लगा दिये। अब यह घर में एक-दूसरे को लड़वाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने नियम निकलवा दिये कि यदि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो परिवार के एक सदस्य को देंगे। यदि परिवार में तीन भाई हैं और तीनों भाई बेरोजगार हैं तो क्या आप घर में लड़वाई नहीं करवा रहे हैं। एक

भाई को मिले, एक नौजवान साथी को मिलेगा और फिर दो नौजवान साथी क्या करेंगे? आप घर में लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं। एक घर में जितने बेरोजगार हैं, आप सभी को बेरोजगारी भत्ता दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, बहुत इस विधानसभा में गोबर खरीदी के संबंध में बहुत सारी बातें चलीं और बहुत अच्छे-अच्छे विषय भी आयें। उन्होंने जिस तरह गोबर खरीदी की बात कही । अब उन्होंने कहा कि हमने गोबर खरीदी के लिए समूह बनया। समूह में एक अध्यक्ष बनाये, अध्यक्ष के साथ- साथ बहुत सारे सदस्य बनाये। सरकार जब उनका 750 रूपये, 300 कुछ रूपये मानदेय तय कर रही है। अध्यक्ष और कुछ समितियों के सदस्यों का यदि मानदेय तय कर रही है तो सरकार के खजाने से उनके लिए पैसा जा रहा है। क्या उस समूह के ऑडिट होने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था की है? उनकी नियुक्ति कैसे हुई है? उन्होंने कहा कि जितने ग्राम सभा होंगे। ग्राम सभा से जो नाम अनुमोदित होकर आयेगा, उस नाम को फाइनल किया जायेगा, लेकिन ग्राम सभा से नाम नहीं आया । कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यालय से नाम आया है। उन्होंने सीधे-सीधे अपने लोगों को उस समूह में भेजा है और सरकार सीधे-सीधे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष और समिति का सदस्य बनाकर पैसे का बंदरबांट कर रही है। हर काम में सरकार केवल ऐसा ही कर रही है। कब उनकी सदस्यों की नियुक्ति कर दी। कहां से नाम आया। आपने कहा था, ग्राम सभा से नाम आयेगा। कहां से ग्राम सभा से नाम आया? आपने तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बैठकर अध्यक्ष और सदस्यों का नाम तय किया है। अब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि सभी पदाधिकारी सदस्यों को पैसा दिया जायेगा। तो यह पैसे का सीधा-सीधा बंदरबांट हो रहा है। वैसे ही आपने राजीव मितान क्लब बनाया। केवल और केवल पैसे का बंदरबांट करने के लिए, सरकार के पैसे से अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरने का काम यह सरकार कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सरकार बजट लेकर आती है। यह प्रदेश का बजट है, प्रदेश की जनता के लिए बजट होता है। बहुत गंभीरता से यह बजट बनते हैं। बहुत मेहनत से, बहुत समय लगाकर, बहुत पैसे से इस बजट की पुस्तक को तैयार किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट को खुद कहते हैं, लेकिन इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बजट को गंभीरता से नहीं लेते। एक ही विभाग का बजट बार-बार लगातार तीन सालों से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि इस सरकार ने सुगम सड़क योजना लेकर आई। अभी फिर इस बार इन्होंने 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। पिछले समय 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। आवेदन मंगवाये जाते हैं । वास्तविक रूप से होता यह है कि जब कार्य प्रारंभ करना होता है तब मंत्री को पता चलता है कि हमारे मद में तो पैसा ही नहीं भेजा गया है तो इसका पैसा जाता कहां है ? आपने बजट में उसकी स्वीकृति रखी है, 150 करोड़ का पैसा आपने रखा है लेकिन यह पैसा गया कहां ? कहां पर यह पैसे खर्च हुए ? यह जांच का विषय है । किसी असत्य से बजट नहीं बनता, इतना महत्वपूर्ण बजट है । इसको

सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और एक ही बजट के लिये, आखिर वह पैसा कहां गया ? समग्र विकास के लिये पिछले समय भी पैसे रखे गये थे, इस समय भी पैसा रखा गया है लेकिन मंत्री जी को ही नहीं पता । वे कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं है । माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि जो सुगम सड़क के लिये, समग्र विकास के लिये जो पैसा रखा गया वह तो मंत्री जी के पास आया ही नहीं । हमारे मद में तो पैसा है ही नहीं तो वह पैसा गया कहां ? यह इतना महत्वपूर्ण विषय है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 सालों तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह सब असत्य था ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय सदस्य से पूछिए । माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रही हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आपकी आवाज बहुत धीमी हो गयी है । (हंसी) (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने इतना ज्यादा ट्रेलर दे दिया है कि उनकी आवाज धीमी हो गयी है । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपके लिये बोल रहे हैं कि सुगम सड़क का पैसा, उसका बजट कहां गया ? सुनो, अच्छे से समझो और नेता जी से पूछना कि कहां गया करके ? (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समग्र विकास के लिये पिछले समय भी 500 करोड़ रूपये का बजट रखा गया था और अभी भी 500 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है । माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी को यह पता नहीं था, जब यह पंचायत विभाग उनके पास थे । वे कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम आपको क्या दें ? पंचायत प्रतिनिधियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । एक भी काम, ग्रामीण स्तर तक कोई काम नहीं है और जितने पंचायत प्रतिनिधि बने हैं वे सब खाली बैठे हुए हैं क्योंकि अभी तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एक पैसा इन 4 वर्षों में अभी तक नहीं दिया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां तक कि 14वें वित्त, 15वें वित्त के जो पैसे होते हैं, मूलभूत का जो पैसा है । ये सरपंचों पर दबाव बनाते हैं कि आपको काम करना है तो आप नरवा-गरूआ, घुरवा-बाड़ी बस इतना ही काम करिये । इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी यहां पर इस विषय का उल्लेख करना बहुत आवश्यक समझती हूं । माननीय मंत्री जी जब प्रथम बार इस सदन में आये थे, उनका भाषण मैंने सुना था कि वे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेकर आयेंगे लेकिन 4 वर्ष हो गये हैं, हमारी आंखें भी तरस गयी हैं और हमारे कान भी तरस गये हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम

कब आयेगी ? अब तो यह सरकार का अंतिम बजट है, 1 रूपए का बजट इनके विभाग के लिये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के लिये नहीं गया और तो और जो आयुष्मान योजना चल रही थी उसमें भी 150 प्रकार की बीमारियों को इन्होंने बंद कर दिया तो लोग कहां जायें ? अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता यदि लोगों को है तो वे फिर कहां पर जायेंगे ? आप तो अच्छी-अच्छी योजनाओं को बंद करने के पीछे पड़े हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धरसा विकास प्राधिकरण इस योजना की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने बजट में, अपने बजट की चर्चा में इस विषय को लाया था कि धरसा विकास योजना की शुरूआत की जायेगी लेकिन आज 4 वर्ष हो गये हैं कहीं पर भी इस योजना का उल्लेख अभी तक नहीं है । क्या ये ऐसे ही जनता को बताना चाह रहे हैं, ये इस योजना को क्यों लाना चाह रहे थे, इन्होंने इसे भी स्पष्ट नहीं किया है और अभी तक इस योजना की शुरूआत इन्होंने नहीं की है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई कर माफ करने की बात इस सरकार ने कही थी और मैंने जब प्रश्न लगाया । मेरा प्रश्न था कि सिंचाई कर कितने किसानों का आपने माफ किया है तो इन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो आपने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहा ही क्यों था जब आपके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, रंजना जी आपका समय समाप्त होने वाला है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल और केवल असत्य पर बनी हुई यह सरकार है । केवल और केवल हमको असत्य बोलती रही । मैं धमतरी का एक-दो विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हमारे यहां सबसे ज्यादा लो-वोल्टेज की समस्या है । हमारे यहां 80 से 85 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिन्होंने आज भी धान की फसल ली है । हमारे 4 डेम हैं और चारों डेम भरे हुए हैं लेकिन यह सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है । वे कब से पानी की मांग कर रहे हैं कि डेम से पानी छोड़ दिया जाये । हमारे रूद्री-बैराज से अभनपुर और रायपुर को पानी मिल रहा है लेकिन हमारे धमतरी के किसान आज भी पानी के लिये तरस रहे हैं । हमारी सबसे अधिक समस्या लो-वोल्टेज की है और इसका कारण यह है कि धमतरी विधानसभा में एक भी सब-स्टेशन वहां पर नहीं है और इस सरकार ने इतना सब जानने के बाद एक रूपये बजट का प्रावधान धमतरी विधानसभा के सब-स्टेशन के लिये नहीं किया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और यहां पर स्थिति यह है कि विगत कुछ वर्षों से अभी तक स्थायी पंप कनेक्शन हमारे किसानों को नहीं मिले हैं। जो टी.सी. कनेक्शन मिले हैं, टी.सी. कनेक्शन की क्षमता इतनी नहीं है कि ट्रांसफार्मर उस कनेक्शन की क्षमता को उठा सके और जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो महीनों तक ये ट्रांसफार्मर नहीं बदलते।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, 2 मिनट में समाप्त करिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, भा.ज.पा. सरकार रही तो विभाग में कितने ही ट्रांसफार्मर, 5-10 ट्रांसफार्मर ऐसे पड़े होते और इनके यहां यदि एक ट्रांसफार्मर यदि हमारे यहां खराब हो जाता है तो ये अपने 5 कर्मचारी को 5 दिन तक रायपुर में छोड़ देते हैं कि जाओ ट्रांसफार्मर लेकर आओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये सब प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है और ये केवल लगातार हमसे असत्य वादे करते गये।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- रंजना जी, कितना लाइट बंद होता था भा.ज.पा. शासन में हम लोग भी जानते हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- विधायक जो हैं वे ट्रांसफार्मर निकलवाकर अपने फार्म हाउस में लगवाते थे। हमारे विधान सभा में।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप देखने गये थे क्या? आपकी आवाज धीमी हो गई ।

डॉ. विनय जायसवाल :- देखा। आप चलिए। मैं आपको दिखाता हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आपकी आवाज धीमी हो गई है। थोड़ा जोर से बोलो।

डॉ. विनय जायसवाल :- बिल्कुल आपको दिखाता हूं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप जोर से बोलिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपस में बात न करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये बार-बार प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप समाप्त करें। रामकुमार जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- हमारे ए.एच.पी. के 480 मकान हैं जो आज भी अधूरे पड़े हैं। ये सरकार कहती है कि हमने प्रधानमंत्री आवास शहरी में भी पैसा दिया है तो हमारे धमतरी निगम में ये 480 मकान जो 4 साल से अधूरे हैं, क्यों इन्होंने धमतरी में पैसा नहीं दिया? यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारे गोकुल नगर हाईटेक बस स्टैण्ड, ट्रांसपोर्ट नगर और शहर की 3 प्रमुख ऐसे रास्ते हैं, जिनका चौड़ीकरण होना नितांत आवश्यक है और पिछले 4 वर्षों से मैंने 4 बार विभाग को अवगत कराया। माननीय मंत्री जी यहां बैठे थे, मैंने बार-बार उन्हें अवगत कराया कि हमारे धमतरी में यह समस्या है, लेकिन एक रूपया उन्होंने धमतरी के विकास के लिए, 1 रूपए इन 4 वर्षों में नहीं दिया। हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे धमतरी नगर-निगम का विकास अभी भी अधूरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ट्रांसपोर्ट नगर की यदि मैं बात करती हूं, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं। हमने काफी समय से ट्रांसपोर्ट नगर मांगा, लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट नगर न मिलने के कारण जो बड़ी गाडियां हैं, वह रोड के किनारे खड़ी रहती हैं। अब इनकी अवैध वसूली शुरू हो गई है। आर.टी.ओ. है, ट्रांसपोर्ट है, पुलिस विभाग है, तीनों की मिली-भगत से 5 हजार से 7

हजार रूपये का इनका महीना बंधा हुआ है। एक गाड़ी जिस जिले से गुजरती है, हर जिले में उनको पैसा देना पड़ता है। बस्तर की जो गाड़ियां ये तेन्दुपत्ता लेकर आती है, वह गाडियां जितने जिले से गुजरती हैं, हर जिले से उनको पैसा देना पड़ता है। हमारे यहां राइस मिल अधिक हैं। हमारे यहां भूसे का उठाव अधिक है। हमसे भूसा लेकर जिस जिले को ये लोग जाते हैं, हर जिले में उन्हें कमीशन और पैसा उन्हें देना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या है और हर जिले में ये तीनों विभाग मिलकर जो कमीशनखोरी मांग कर रहे हैं, ये लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, लगातार हमने कोई न कोई मांग अपने क्षेत्र के लिए की है। हमारे यहां 5 गांव हैं, जिसमें विरेतरा, डाही, अंगारा, सेंचुआ, सेमरा जो कुरूद थाने में हैं और लगातार मैंने इसमें मांग की कि इन्हें भखारा थाने से जोड़ा जाये, क्योंकि तहसील भखारा है। जिला इधर है। आप तहसील अलग बना रहे हैं। थाना अलग दे रहे हैं तो बेवजह लोग यहां पर परेशान होते जा रहे हैं। मैंने विभाग को बार-बार अवगत कराया था। इनके मंत्री को बार-बार अवगत कराया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहां नगर पंचायत आमदी और छाती दो ऐसे गांव हैं, एक नगर-पंचायत और एक गांव, जहां पर चौकी खोलना बहुत आवश्यक है। असामाजिक तत्व बार-बार वहां के महिला वर्ग को परेशान करते हैं। वहां पर अवैध वसूली करते हैं। जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, वहां पर ये रंगदारी, वहां पर वसूली करते हैं। वहां पर चौकी होना आवश्यक है ताकि वहां जो गुनाह हो रहे हैं, वहां जो अपराध हो रहे हैं, ऐसे अपराधों पर दबाव पुलिस विभाग का बन सके, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 4 वर्षों से लगातार मैंने मेडिकल कॉलेज की मांग की, क्योंकि धमतरी सेंटर है। इधर आपको जगदलपुर आना पड़ता है। इधर आपको रायपुर आना पड़ता है। आस-पास के और जो जिले हैं, आस-पास के जो बच्चे हैं, उनको हमारे यहां रायपुर आना पड़ता है। तो यदि धमतरी विधान सभा में, धमतरी जिले में यदि मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो यह हम सबके लिए बहुत सुविधा होगी। हमारे धमतरी में ऑडिटोरियम है। वाटर ट्रिटमेंट प्लांट है, एकलव्य खेल परिसर है। बालक चौक शॉप में काम्प्लेक्स है। सीवरेज प्लांट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये सारे काम प्रारंभ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये काम स्वीकृत हुए थे और ये कार्य प्रारंभ भी हो चुके। आज 4 सालों बाद भी ये कार्य अधूरे पड़े हैं। इसका कारण यह है कि नगर-निगम को एक भी पैसा ये स्वीकृत कार्य, ये अधूरे कार्य को पूरे करने के लिए आज तक धमतरी को एक भी पैसा नहीं मिला है और इसके चलते आज भी ये कार्य अधूरे पड़े हैं। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका 20 मिनट समाप्त हो चुका है । रामकुमार यादव जी अपनी बात रखें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष जी, चार लाईनें कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं - संसार जरूरत के नियम पर चलता है, जिस प्रकार सर्दी में सूरज का इंतजार होता है, उसी प्रकार गर्मियों में सूरज का तिरस्कार किया जाता है । कांग्रेस पार्टी का इनकी सरकार का तिरस्कार जनता करती है ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करे हे । ओकर भूरि-भूरि प्रशंसा करे बर, अतेक सुंदर बजट पेश करे हे ओला मैं धन्यवाद् दे बर खड़े होए हौं । एक महापुरूष कहे हे छत्तीसगढ़ मा जनम ले हमर शिरोमणि गुरू घासीदास जी कहे हे वो ही बात ले मैं शुरूआत करना चाहत हौं । गुरू घासीदास जी कहे हे रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों हे सतलोक समान । आज गुरू घासी दास जी के सपना ला पूरा करे बर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, मोर सरकार आज ए बजट ला पेश करे हे । उपाध्यक्ष जी, 15 साल ले एमन जो सरकार ला चलात रहिस हे एमन मन से हार गे रिहिस हे । तेखरी खातिर मैं अउ कहत हौं कि मन के हारे हार हे अउ मन के जीते जीत । जब ले मुख्यमंत्री जी हा छत्तीसगढ़ के बागडोर संभालिस । ए वही प्रदेश हे जो 15 साल तक इहां के गरीब आदमी अउ गरीब होत जात रहिस, अमीर अउ अमीर होत जात रहिस । साइकिल मा चलने वाला, मोटर साइकल मा चलने वाला पेट्रोल नइ डला सकत रहिस हे । अउ हवाई जहाज उड़ाने वाला मन हवाई जहाल लेवत रहिन हे । अइसे प्रदेश के दशा ला बना के रखे रहिस हे । उपाध्यक्ष जी, बहुत बात हे अउ समय कम हे । तेखर खातिर मैं कुछ गरीब के बात कहना चाहत हौं । चूंकि मैं गरीब घर के हौं । मैं देखत रहेंव ए सब मन बजट मा अइसे बुरई करत हे, अइसे बात करत हे जब जब भी गरीब ला कुछ मिले हे तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होत हे । जइसे कि राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना, 15 साल ले एमन ला गरीब के खाता मा पइसा डाले ले कौन रोके रहिस हे । आज अइसे गरीब आदमी जेखर गांव मा घर नइ हे, अउ खार मा खेत नइ हे । एक डिसमिल जमीन नइ हे, ओमन कनी, पटवारी कनी कोई लिखा पढ़ी नइ हे । काबर महू आइसने घर के व्यक्ति हंव । मुख्यमंत्री जी मोला विधायक बना दिस, आज आप मन के आशीर्वाद से वेतन भत्ता अलग हो गिस लेकिन मोर एक डिसमिल जमीन नइ हे । मैं गरीब के दर्द ला समझथौं । वो गरीब आदमी ला साल के 7 हजार रूपया मिलत हे, भारतीय जनता पार्टी के मन कथे, 7 हजार रूपया का होही, तैं 15 साल ले राज करे, अरे 7 हजार रूपया ला छोड़ दे, 7 रूपया तैं देहे का । उपाध्यक्ष जी, हजार रूपया कम नइ हे । मैं जानथौं गरीब आदमी जै दिन में जा के खेत मा काम करते तो 200 रूपया ला पाथे । कतका दिन ला दू दू सौ रूपया ला जोड़ही तो सात हजार रूपया हो ही । वो 7 हजार रूपया ला गरीब आदमी पाही तो साल के मोर गरीबनिन दाई कम से कम 2 जोड़ा लुगरा ला बिसा लिही । वो गरीब मोर ददा जेन जंगल मा रथे वो आदमी कम से कम 2 जोड़ी धोती ला ता बिसा डारही । एखर खातिर गरीब मन बर व्यवस्था किये गे हे । अउ आज भारतीय जनता पार्टी वो गरीब के विरोध करथे । मैं बात करना चाहत हौं, एमन बात करथे प्रधानमंत्री आवास के । हमन जब लइका रहे हन, मैं खुद जोन घर मा रथौं वो प्रधानमंत्री आवास

हे । मैं प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास में रथौं । हमन वो समय घर बने तो इंदिरा आवास, इंदिरा आवास कहन, जब दिल्ली मा सरकार बनिस, जेला नरेन्द्र मोदी जी के, ओला कइ जन फेंकू से भी सम्बोधन करथे । खैर मैं नइ कहत हौं, मैं कथे तेला बतात हौं । तो वो मन के सरकार बनिस तो इंदिरा आवास ला पलटकर पी.एम. कर दिस । मैं तो ज्यादा इंग्लिश पढ़े नइ हौं । लेकिन पी.एम. के मतलब होथे, प्रधानमंत्री आवास । पहिली 80 परसेंट पइसा दिल्ली के रहय, मात्र 10 परसेंअ हमर छत्तीसगढ़ या कोई प्रदेश के रहय, मात्र 10 प्रतिशत छत्तीसगढ के कोई प्रदेश के रहाय। अब छत्तीसगढी में एक कहावत हे, पर के मुड़ में नऊ सियान। हमर मन के पईसा मे ओमन सियानी करबो कथे। भई, मोर मुड़ ए, मैं ओला छोटे राखिहा कि मुंडा होवईहां कि मैं मिथुन कट राखिहा, ओ मोर मन तोय । भारतीय जनता पार्टी वाला मन हा पर के मुड मा सियानी करबो कथय। आज ये मन ओला आधा-आधा कर दिस। प्रधानमंत्री आवास बर मोरो घर ला ए भारतीय जनता पार्टी के बड़का बड़का नेता मन घेरे ला गे रहिन हे। इंदिरा आवास मे रहने वाला घर ला घेरे बर गे रहिन हे। मैं तो भात साग घलो रांधे रईहा, आवा खईहा करके। आज मे बता देना चाहत हंव, हमर सरकार प्रधानमंत्री आवास में 8 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण कर चुके हन, अऊ अभी के बजट में 2 लाख 30 हजार फिर से प्रावधान रखे हावन। एमन सिर्फ गरीब के बात करथय लेकिन मोर भूपेश बघेल जी के सरकार मोर छत्तीसगढ़ के सरकार गरीब मन के लिए करके दिखाथे। सम्मानीय उपाध्यक्ष जी, ये मन काय बात करथे, मैं देखत रहेव बृजमोहन अग्रवाल जी, कल के बात करत रहिन, काकर, ओ गरीब के बेटी के शादी के बाद करत रहिन। पहली ए मन 15 हजार रूपया देवत रहिन हे, उहू 15 हजार रूपया हा, लोग लईका हो करके लोग लईका के खेले के लायक हो जाय तभो ले पईसा नई आय रहाय। शादी होय के बाद लोग लईका हो जाय, लोग लईका हा कहाय, पापा आप लोग शादी किए हो तो 15 हजार रूपए मिलता है वह कब मिला करके । तभो ले नई पाय रहाय। लेकिन हमर सरकार ओ 15 हजार ला बढ़ा करके सीधा 50 हजार करिस। ए मन का जानही ओ बात ला। ओ गरीब ला पूछ के देखा, जेखर घर में बेटी बाढ़े रथय, ओखर मा बाप ला चिंता रथे कि कुछु करके मोर बेटी के हांड़ा में मैं हल्दी ला रचा डारथय, ओ बेटा के चिंता रथय, ओ बाप के चिंता रथय की मोर बेटा के कहूं मेर कानी खोरी कहूं मेर ले बिहा डारथय। ऐ चिंता रथय। ओ चिंता ला दूर करे बर हमर सरकार आज 50 हजार रूपया के सप्रेम भेंट दे के ओ शादी करत हावय। उहू में ऐ मन ला दर्द होथे। कम से कम तुमन तो कुछु करे नई सकव कम से कम जे करत हे, तेखर बर उल्टा सीधा आप ला बात नई करना चाहिए। ऐ मन पेंशन के बात करथय, मोरे दाई हा पेंशन पाय। मैं जानत हंव, शिवरतन शर्मा जी के दाई हा पेंशन नई पावत होही काबर ओ हा उद्योगपति घर के हरे, कई ठन राईस मिल हे, मोर दाई हा गरीब घर के, आज मोर दाई ए संसार में नई हे लेकिन मैं जानत हंव, मोर दाई हा पेंशन ला अगोरत रहाय, कब पेंशन पातेन ते एको किलो पाताल पिसातेन। तेल पिसातेन, ये समझ के।

श्री शिवरतन शर्मा :- रामकुमार जी, मोर नाम के उपयोग करेस, सुन ले। मोर के ठन राईस मिल हे भाई, एकात ठन खोज के मोला कब्जा दिला दे।

श्री रामकुमार यादव :- हमन तुंहर बोरा के पुरतन नई हन। हमन तुंहर बदरा के पुरतन नई हन। मैं जानत हंव पूरा ट्रक हा तुंहरेज हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- तैं अभी बोलेस ना शिवरतन के के ठन राईस मिल हे। एकात ठन खोज के बता, मैं तोर से अतके निवेदन करत हंव।

श्री रामकुमार यादव :- ओ छापा हा तुंहरे घर पड़ना चाहिए तेला मोर घर भेज देवत हव। (हंसी) आज में ये बात ला कहना चाहत हंव पेंशन के साढ़े तीन सौ रूपया लो ओ डोकरी दाई मन इंतजार करत रथय, कब पाबो, आज ओला मोर सरकार बढ़ा के पांच सौ रूपया कर दिस तो गरीब ला जब जब भी मिले हे, ए मन ला तकलीफ होय हे। अउ दिल्ली में जो नरेन्द्र मोदी जी बइठे हावय हो कथय, मैं गरीब घर का हूं। आज दिल्ली के सरकार सिर्फ दिखावा करने वाला हरे। कोई गरीब के काम नई करय। लेकिन मोर सरकार मोर भूपेश बघेल के सरकार गरीब के लिए काम करथय। ए मन का बात करथय। मैं बात करना चाहत हंव, सरकार के मतलब होथे, उपाध्यक्ष जी, तुमन अइसने खुजयाहा ता जानत हंव मोला कुछु कइहा। लेकिन मैं तुमन ला हाथ जोड़त हंव, तहूं गरीब घर के बेटा अस भले उपाध्यक्ष बन गेहा। आज गरीब के बात होत हे, आज गरीब के गोठ ला सुना, महोदय जी, ए मन सुने के साहस रखय। आज मैं बताना चाहत हंव, जब ऐ छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग होईस ओमे कई ठन भावना जुड़े रहिस हावय। मध्यप्रदेश रहिस हावय, भिंड, मुरैना, जबलपुर के बड़े-बड़े मेछा वाला मन टेबल ला ठोक के जब धन ला ओली मा रख लेवय, लेकिन हमर छत्तीसगढ़ के खूबचंद बघेल जी, अऊ हमर तमाम महापुरूष मन सपना देखिस कि छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए तो छत्तीसगढ़ अलग होये के साथ इहां के खाना पीना, इहां के खेलकूद, इहां के रितिरिवाज, ऐ सब के विकास होवय, एखर खातिर छत्तीसगढ़ ला अलग करे रहिन हे। एमन 15 साल ले सरकार में रहिन ता का के विकास करिस। बाहर-बाहर ले हीरो हिरवईन ला लावय, अउ उही मन ला नचवा करके माई पिला मन बईठ के देखत रहाय, अउ छत्तीसगढ़ के आदमी मन ला भुला गिस। लेकिन वाह मोर सरकार आज खेल तो बहुत सारा खेल हे, लेकिन खेल में कोई राजा खेल हे तो ओ खेल कबड्डी हे। ओ हमर छत्तीसगढ़िया खेल हे। मैं विश्वास के साथ काहत हो कि ए कबड्डी खेल ला 3 दिन के बासी खाने वाला हा खेल सकथे, एला काजू-बादाम खाने वाला नहीं खेल सके। काजू-बादाम खाने वाला हा कबड्डी ला नहीं खेल सके। का शिवरतन शर्मा जी हा कबड्डी ला खेल सकही? चल तो दोनों झन खेलबो। का आज ओहा गिल्ली-डंडा खेलन सकही?

श्री शिवरतन शर्मा :- चल न। चल, चल अभी खेलबो। चल अभी खेलबो का?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- चल, दउड़ जा।

श्री रामकुमार यादव :- आज मैं कहना चाहत हो। महाराज, पांव लागही। तुहर लबारी ला देखकर मोर...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कबड्डी खेलबो, कुश्ती खेलबो।... मैं सब में तैयार हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- चल, तोर संग मैं खेल लेथो।

श्री रामकुमार यादव :- बबा, ए तोर बर नो हरे, ते बइठ। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- ते एखरे संग खेल के बता।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- रामकुमार जी, हमर बबा घलो कबड्डी खेलथे। उपाध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, क्या आप मोहले जी जैसे खेल पाएंगे ?

श्री कवासी लखमा :- शिवरतन जी, आप और क्या-क्या चढ़ते हो ? आप और दूसरा क्या चढ़ते हो ?

श्री रामकुमार यादव :- मोर बबा हा भइसी भर मा चढ़ाए हवे। मोर बबा के चक्कर में नहीं रहना, ओ मोला भइसी में चढ़ाए हवे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बबा के साथ टक्कर मत लेना।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है कि मैं गेड़ी, भांवरा और तैरना, तीनों में मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को चुनौती देता हूं। तीनों में।

श्री रामकुमार यादव :- सुनौ तो, एमन हमर मुख्यमंत्री जी के भांवरा चलई...। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यादव जी, आप शर्मा जी करा भले खेल लिहौं लेकिन मोहले जी करा खेले के कोशिश मत करिहौं, नहीं तो आप चीत पड़ जाहौं। (हंसी)

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- रामकुमार भाई, सुनना, ते मोहले जी ला अपन गुरू नहीं बनात हस तेखरे कारण तोर बिहाव नहीं हो पावत हे। ते ओला गुरू बना ले।

श्री रामकुमार यादव :- हमर मुख्यमंत्री जी हा भांवरा खेलिस अऊ भांवरा ला लेकर के ओला हाथ में उठा के देखिस तो छत्तीसगढ़ के हमर विपक्ष के नेता मन हा 5 दिन ले नहीं सुतीस कि मुख्यमंत्री जी हा भांवरा ला कइसे हाथ मा चला दीस करके। ए कइसे होगे ? ए मन ला चिंता होगे रीहिस कि हमन भांवरा, बांटी ला भुइंया मा चलात देखे हन, ओहा हाथ में कइसे चलत हे ? आज मैं कहना चाहत हो अऊ धन्यवाद दिहौं कि एमन बजट में प्रावधान रखे हे कि आज छत्तीसगढ़ में फिल्म घलो बनही। फिल्म बनत हे। जइसे हमन टी.वी. ला खोलथन तो आंध्रप्रदेश के फिल्म चलथे, ओमा नीचे में अनुवाद दिखथे, ओ तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश के आने भाषा हे, लेकिन मैं धन्यवाद देहौं कि आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनत हे। आज मोर छत्तीसगढ़ के गरीब समाज के मन, मोर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के बेटी-बेटा मन भी इहा के फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती अऊ श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन बनही। काबर कि छत्तीसगढ़ के भाषा ला अऊ छत्तीसगढ़ के रिवाज ला हमन जानबो अऊ हमन हीरो बने बर इहा ले बंबई थोड़ी न जा

सकबो, लेकिन छततीसगढ़ में मोर गरीब समाज के मन मोर अमरजीत भगत जी के चलते यहां पास ओमन जरूर हीरो-हीरोइन बनही।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहले जी भी हीरो का रोल करने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यादव जी, तो सुन न, आत्मानंद स्कूल ला बंद कर दे। हीरो-हीरोइन के स्कूल खोल।

श्री रामकुमार यादव :- बस, एक मिनट। मोहले जी, हमन खेल-कूद के बात करथन। जिस प्रकार से आज एक झन मोर डोकरी दाई हा फुगड़ी खेलिस, मैं विश्वास के साथ कहात हो कि यदि रंजना बहिनी ओखर से जीत जाही तो मैं ओला विधान सभा में चैलेंज करत हो। (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं खेल दुहुं। मैं चैलेंज स्वीकार करत हो। रामकुमार यादव जी, महुं किसान के बेटी हो। मैं तोरो संग फुगड़ी खेल दुहुं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ओ डोकरी दाई हा फुगड़ी खेले हे। एमन तो हो गेहे...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- फुगड़ी वही खेल सकथे। काबर कि मोर रंजना दीदी हा काजू-बादाम वाली हो गेहे। (हंसी) आज मैं कहना चाहत हो उहु मा ओ मन ला तकलीफ हे। एमन काला फुगड़ी कथे, काला गिल्ली-डंडा कथे अऊ काला रस्सी खींच कथे, मैं कहात हो कि ए भाजपा के 20 झन नेता मन हो जाए अऊ मोर गांव के, मोर बस्तर के, दंतेवाड़ा के हमर आदिवासी समाज के 5 झन हो जाए अऊ रस्सी ला खींचे। ऐमन ला झींक के फेंक दीही। ऐ होथे हमर रस्सी खींच।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं एनीकट के बात करना चाहत हो। अभी एमे हमर बर प्रावधान हे। धन्य हे हमर रविन्द्र चौबे महाराज जी हा ए मेर हवैं। एहा अभी कई ठोक एनीकट भी जोड़े हे। वृहत सिंचाई योजना 218, एनीकट 598, बाढ़ नियंत्रण 256 के अभी प्रावधान में रखे हे। काबर कि एनीकट के भुगतना ला मैं भुगते हो। ए मन एनीकट बनइस, बांध बनइस लेकिन कहां बनइस ? महानदी में बनइस। गरीब के लिए नहीं बनइस ता काखर बर बनइस, ओ बड़े-बड़े इंग्लैण्ड, जर्मनी, ईटली, रूस, फ्रांस से जतका कंपनी आहे, तेमन ला पानी देबर एमन हा एनीकट, बांधी बनइस अऊ आज हमर मन के जो एनीकट बनत हे, तेन काखर बर हे ? गरीब के खेत ला पानी दे बर बनत हे। यही अंतर होथे। काखर जेब में कतका कन पइसा हे, तेन बड़ी बात नहीं होए बल्कि ओ पइसा के उपयोग कहां पर किये जाथे, ए हर बड़ी बात होथे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

सम्मानीय साथियों, आज पूरा सदन देखत होही कि ए उही छत्तीसगढ़ हे जेला 15 साल तक आप मन कुछ नहीं कर सकेव लेकिन मोर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रेत में तेल निकालने वाला हे। वही छत्तीसगढ़ के पइसा से आज पूरा प्रदेश में विकास करने वाला हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये बात बिल्कुल सही बोलेस कि रेत से तेल निकाल दिही।

श्री रामकुमार यादव :- हां, हमन रेत में तेल निकालथन । तुमन छत्तीसगढ़ में सूखा बनाके रखे रहाव, जेनला आज अतके कन बड़े कर दिस । आज मैं आपसे कहना चाहथौं कि एमन एनीकट 15 साल में बनाए हे, मैं जब भी रविन्द्र चौबे जी कर, सचिव मन करा ओकर मुआवजा बर जाथव । ऐमन एक रूपिया मुआवजा नहीं दिस। आज ओ क्षेत्र में जाथव तो सिर्फ मुआवजा के मांग होथे । अभी भी बहुत सारा मुआवजा बचे हे, ओकरो खातिर मैं आथौं । कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहथौं कि जब तक धरती चंदा रहिही, तब तक ये बजट ला याद करहि । काबर कि एमा सबके समाहित हे । किसान, गरीब, नौजवान, आदिवासी, पिछड़ा, अगड़ा, ए बजट मा सबला लेके चले हे । मितानीन ह रात-रात भर दूसर के लईका मन ला छट्टी करवाए बर जाथे, वइसने मन के पईसा बढ़ाए के काम करे हे । ए मन ला तकलीफ होथे काबर कि ये मन गरीब के दुख ला नहीं जानय, भाजपा वाला मन तो बड़का-बड़का घर के । ओ मन के बहु बेटी ह फाईव स्टार हॉस्पिटल में जाथे, लेकिन गरीब के बेटी ओ हॉस्पिटल में जाथे अउ ओकर जाग के सेवा करने वाला मितानीन के सम्मान कोई करिस तो मोर भूपेश बघेल के सरकार, पंजा छाप के सरकार करे हे । उहूं मा एमन ल तकलीफ हे । पुन्नू बबा, आपसे प्रार्थना हे, तै सियान आदमी हस । सिरतोन ला गोठियाबे । काबर कि ये दुनिया में कोई अमर खाके नहीं ए, तै बजट मा लबारी मारबे, तोला अभी क्षेत्र में जाए बर हे अउ तोर हाथ ला घर दिही ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तै ओला गुरू अउ बबा बना ले न, कई मामला मा तोला सहयोग करही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, समाप्त करिए ।

श्री रामकुमार यादव :- दो मिनट में समाप्त करथव । ये मन ला 15 साल में मौका मिलिस त कुछू नहीं कर सकिन । ए मन ला मौका मिलिस त ए मन आने काम करिस । एक ठी कहावत हे कि मरे में मेछा उपकाए, 15 साल ले एमन बढ़िया रहीन हे, मौका रिहीसे त कुछ नहीं करिन । अब बुलक गे त हाथ ला सकेलथे कि मैं ह अइसे कर देहवं, अइसे कर देहवं । 15 साल ले काए करेव ? ओकरे खातिर मैं अपन सरकार ला धन्यवाद देवथौं अउ हमन जब भी कहिथन त छोटे-मोटे आशीर्वाद नहीं देवन, छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड़ जनता डहार ले मैं कहना चाहथौं, जेन ला ओमन कहिथे । जइसे मालिक लेहे देहे, अउ तइसन झोकिहव सीसो, अउ अन्ने-धन्ने घर बरे, जुग जीहो लाग बरिसो । जब अइसे सरकार बने हे त लाख-लाख बरस जीही। ए दारी त 14 ठन कुर्सी मा हवय, मोला लगही कि एमन खिया जही, एमन बहुत कोशिश करथे, धर्म के राजनीति, दुनिया भर के राजनीति करथे, लेकिन मोर छत्तीसगढ़ के जनता पूरा जानथे । पूरा देश में कहीं एक नम्बर के जनता हे तो छत्तीसगढ़ के जनता ए मन के बात में नहीं आवय । मैं पुन: एक बार रविन्द्र चौबे महाराज जी से कहिहौं कि मोर क्षेत्र में जो मुआवजा के समस्या हे, तेहा देख लिहव महाराज अउ एमन एनीकट खोले हे, ओमा मैं बढ़ दुख पावथौं । कुछ-कुछ समस्या हे, ओला देख लिहौ । आप मन मोला बोले के मौका दे हव, ओकर बर धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मंत्री जी ह नहीं सुनथे ।

श्री रामकुमार यादव :- सुन डरे हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं सुने हे, नहीं सुने हे ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन सुन के नहीं जानव, हमर महाराज ह किसान के समस्या ला सुन डरे हे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 के बजट मा चर्चा करेबर मैं खड़े होए हव । मैं पूर्व मा भी ये सदन में कहे हवव कि ये सरकार के बजट केवल कागज के पुलिंदा हे ।

श्री अमरजीत भगत :- बजट कागज में ही बना है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कागज में बनथे, मंत्री जी, कागज के उपयोग बहुत अकन होथे। कई जगह चना बांधे के काम आथे, कई जगह भजिया बांधे के काम आथे अउ कई जगह बहुत अच्छा काम आथे अउ ये जो तुमन बजट बनाए हवव, ए चना के दुकानदार करा केवल चना के पोगड़ी बनाए के काम आवथे । ये तुहर मन के 5वां बजट ए, 4 बजट के का होईस ? बजट के अनुमान लगाए हव, कतका अकन के स्वीकृति दे हवव, कतका अकन सड़क बनाए हवव, कतका अकन पुल-पुलिया बनाए हवव, कतका अकन एनीकट बनाए हवव । बजट में अईस त तुहू मन माला पहिने हव, हमु मन माला पहीने हन । आज जनता पूछथे, 2 साल मा बजट ले बाहिर होगे। इकरे बर कहात हवव कि ए बजट केवल कागज के पुलिंदा हे । आज रामकुमार जी कहात रिहीन हे कि ये बजट गरीब के । गरीब के आवाज हे, यह सरकार ह गरीब बर चिन्ता करथे । साढ़े चार साल में गरीब के काबर सुरता करिस । साढ़े चार पहिली गरीब नहीं रिहीन हे । ओल्ड पेंशन, पुराना पेंशन, एक-दो लाख तनख्वाह पावथे, तेहर पेंशन के चिन्ता होगे, लेकिन गांव के ओ गरीब साढ़े तीन सौ रूपया पेंशन मा सियान-सियानीन, दिव्यांग अउ विधवा बहिनी, साढ़े तीन सौ रूपया पेंशन मा जीवन चलात रहिस हे, ओखर चिंता साढ़े चार साल बाद आइस हे। कैसे ? 1500 रूपया के घोषणा करे हावा, 1500 रूपया के वादा करके वोट लेकर जीते हा अउ कतका देया ? 500 रूपया देहा, डेढ़ सौ अउ तहूं ले ले, चना, मुर्रा, चुटुर खाबे। माननीय सभापति महोदय, केवल चुनावी बजट हे। कतको के बजट रहय, कई लाख करोड़ रूपया के बजट रहय, का काम के ? बजट मा पूंजीगत व्यय कतेक कन हावय ?

श्री अमरजीत भगत :- केशव भाई, राशनकार्ड वगैरह तो बन गय हे ना ? राशन बन गय हे ना, राशन मिलत हे ना। तोर इहां धान खरीदी केन्द्र भी खोल दे हंव। ओ समय तो धन्यवाद देथव, बाद मा क्रिटिसाइज करथव।

श्री केशव चन्द्रा :- सभापति महोदय, जतका बढ़िया बुता करे हावा, तेखर बर धन्यवाद दे हन। लेकिन नीयत हा साफ नइ हे न। नीयत साथ नहीं रहय तो जनता ओला समझ जाथे। अतका दिन बाद

काबर सुरता करा, हर दारी चिल्लात रहेन तो सुरता नहीं रहत रहीस हावय, तो नीयत साफ नही हावय। ओ पढ़े-लिखे तनख्वाह पावत हे, तेमन ला होशियार समझत हाववं, ओ मन ला बुद्धिमान समझत हाववं, ओ मन ला पैसा वाला समझत हावा, ओमन समझत हाव कि सरकार गिराय के ताकत रखथे, सरकार बनाय के ताकत रखथे, तेखर बर ओ मन के पुराना पेंशन के चिंता करा। लेकिन गरीब के चिंता नहीं करा। लेकिन मंत्री जी, मैं बता देना चाहत हव कि एक गांव मा मुश्किल से 2-4 झन नौकरी वाला होही, लेकिन एक गांव मा तीन सौ, चार सौ पेंशनधारी हे अउ तीन सौ, चार सौ पेंशनधारी के आह लग जाही तो लाख कोशिश करिहा तभो सरकार मा नहीं आहा।

माननीय सभापति महोदय, एमन मितानीन के बात करिन। आंगनबाड़ी के बात करिन अउ रसाइया के तीन सौ रूपया बढ़ाइन। सफाई कर्मचारी के केवल तीन सौ रूपया बढ़ाइन। आदमी तो ओहिच हावय, दिन भर बुता करत हावय, भले पार्ट टाइम कहत हावा। एक स्कूल में डेढ़ सौ लइका के खाना बनाही, बिहनिया ले तैयारी करही, देखरेख करही। लेकिन आप सचिव के चिंता नहीं करा। ग्राम पंचायत मा जो सचिव हे, ओमन के बात नहीं करा। मनरेगा के रोजगार सहायक हे, काम चलात हे, सब ला रोजगार दिलात हे, ओखर कोई बात नहीं होइस। आप जो वादा करे रेहा कि अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ऐखर लिए बजट मा कोई प्रावधान नहीं करा। एखर बर बजट बनाय के अवसर आप मन ला ये कार्यकाल मा तो नहीं मिलय। हां, अगर जनता हा पुन: आशीर्वाद दे देही तो अगले कार्यकाल मा भले दे दिहा, लेकिन ये कार्यकाल मा पुन: बजट बनाय के बात नहीं करा। आप मन अब्बड़ विकास के बात करत हा। हमर शिक्षा मंत्री जी हा बइठे हे। 5 बार घर गय हव, हाथ जोड़े हाववं। तांदुलडीह एक आदिवासी गांव हे, शत-प्रतिशत आदिवासी गांव हे माननीय मंत्री जी, वहां प्राथमिक विद्यालय ही नहीं है, 3 किलोमीटर दूर जाथे। मैं 5 साल तक बात ला रखेव, लेकिन मोर क्षेत्र के ओ आदिवासी तांदुलडीह गांव मा स्कूल नहीं खुल पाइस। उल्टा मोला मंत्री जी पूछथे कि प्राथमिक शाला कैसे मा खुलथे। मंत्री जी, आदिवासी के बात करथा, 34 प्रतिशत आबादी हे, आरक्षण के बात करथा, लेकिन स्कूल नहीं खोलिहा तो बच्चा पढ़के कहां ले आरक्षण के लाभ लेही।

श्री राजमन बेंजाम :- चन्द्रा भईया, हमारे बस्तर जिले में 15 साल में 3 हजार स्कूल बंद किये थे। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल ने 3 हजार स्कूल खोलने का काम किया है।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, तांदुलडीह विकासखण्ड जैजेपुर। रामकुमार जी गोठयात रहिस हे कि 30 किलोमीटर के सड़क नहर के रास्ता मा जोड़वाय हे। ओ हा काबर धन्यवाद नहीं देही। लेकिन जे गांव पहुंचविहीन हे, जे हा केवल पगडंडी मा चलत हावय, ओ डेढ़ किलोमीटर के सड़क भी बजट मा आ गय रहिस हे, ओला भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलिस। माननीय रामकुमार जी, ये सरकार के नीयत हे, ये सरकार के दुर्भावना हे।

श्री रामकुमार यादव :- केशव चन्द्रा जी, 20 किलोमीटर के सड़क बने हे, सित्तो मा बताहा। 20 किलोमीटर गोबरा से जैजेपुर के सड़क भा.ज.पा. वाला करा मांगत-मांगत थक गया, कोन बनाइस हे, सही बतावा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मोर क्षेत्र के बरभाठा, चामनडीह, स्वीकृत कब होय हे बतावव । बता दव ईमानदारी से । एमन के सरकार मा स्वीकृत होय हे ।

श्री रामकुमार यादव :- एडीबी के हमर में होईसे ।

श्री अमरजीत भगत :- काम काबर नई होवय हमन समझ गेन । कभु उते जाथस, कभु उते आथस । अइसे-अइसे ढुलमुल ढुलमुल होवत रथस तैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं एक झन हांवव, जेन हा सच्चाई ला गोठियाथंव । तुंहर दूनो झन के कपड़ा ला उतारे के काम करथंव । तुमन केवल वोट के राजनीति करथव । तुमन क्षेत्र के आम जनता के राजनीति नई करव । तुमन वोखर सुख-दुख के साथी नो हावव । सुख ला भी वोट के नजर से देखथव, दुख ला भी वोट के नजर से देखथव, लेकिन हम सुख और दुख ला वोट के नजर से नई बल्कि आम जनता के हित के नजर से देखथन ।

श्री अमरजीत भगत :- पुन्नूलाल मोहले से बात करव 15 साल में काय करे हे तेन ला ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम तो सब करे हन ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बरभाठा गांव हे, सड़क नई हे, बजट म आय रहिसे, नी बन पाईस । मैं विरोधी विधायक अंव त मोला प्रशासकीय स्वीकृति नई मिलिस । कतका लंबाई डेढ़ किलोमीटर, करमनडीह डेढ़ किलोमीटर, अधिकारी मन कना कतका कन दरबारी बनेन, लेकिन वोमन कहिस हाऊस ले निर्देश आही डेढ़ किलोमीटर के । हाऊस कहि त वोमन ला सड़क चले के रास्ता मिलही रामकुमार यादव जी । सेमराडीह, छिर्राडीह, सबगांवगेहावा, डोमाडीह, जुनवानी कतका दुर्गम गांव ए, आज आपके उंहा न एम्बुलेंस जा सकै, बरसात के दिन मा बिन खाट के आदमी उहां नई निकल सकै, ऐसे पहुंचविहीन गांव ला डेढ़ किलोमीटर-दू किलोमीटर नई जोड़ पाय हावव, विधान सभा प्रश्न लगाय रेहेव, माननीय मंत्री जी आगिन, पी.डब्लू.डी.मंत्री जी आगिन, जब स्वीकृत नई करे हे त बजट में जोड़े के काय मतलब हे, 2014 प्रशासकीय स्वीकृति होगे हे, वो भी सड़क स्वीकृत नई होवथे, एक सरकार चल दिस, दूसरा सरकार के कार्यकाल मा भी वो सड़क नई बन पावथे, बजट के बात करथव, गरीब के बात करथव, गांव के बात करथव, केवल बांटी-भौंरा गेड़ी चढ़े ले कोई छत्तीसगढ़ के संस्कृति नई बढ़ जाये । गेड़ी, भौंरा, बाटी, आज छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनिसे त नई खेलथें, ये हमर पुरखा के संस्कृति ए, ऐला कोई मुख्यमंत्री नई सिखाय हे, मुख्यमंत्री हर बासी खाय बर नई सिखाय हे, बल्कि ए हमर पुरखा के संस्कृति ए । आज देश कहां जाथे ।

श्री कवासी लखमा :- इधर वाले सब भूल गये थे । याद दिलाना पड़ेगा ना ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपको याद था ना । माननीय मंत्री जी, आज देश कहां जाथे, आज हमर लईका कम्प्यूटर के की-पैड में खेलथे, आज बाटी खेला के वोला लाचार अऊ बेबस बनाना चाहथव, केवल गेड़ी चढ़ाके वोला लाचार बनाना चाहथव । आज हमर बेटी हवाई जहाज चलाना चाहथे, लेकिन गेड़ी भौरा खेलके ए छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाम से छत्तीसगढ़ के गांव के रहने वाला गरीब आदमी ला आप पंगु बनाना चाहथव ।

डॉ. विनय जायसवाल:- माननीय चन्द्रा जी । कलारी फायटिंग जानते हैं, क्या होता है । कलारी फायटिंग नाम सुने हो । सुने हो कि नई सुने हो । केरल का बेसिक सांस्कृतिक खेल है । जैसा कि आप बोल रहे हो ना भौंरा, बाटी, इससे कोई आसमान में नई चढ़ेगा, फाईटर प्लेन नहीं चलायेगा, इससे इसका कोई संबंध नहीं है । आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है । केरल का वहां खेल है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपस में चर्चा न करें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आजादी के बाद ले त तूंहरे च सरकार हे । कोन से नया सरकार बनगिस ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में संवाद करें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कि 1947 ले पहली बार सरकार म बने हावव । अगर संस्कृति ला खतम करे रेहेव त तुईमन खतम करे रेहेव । आज संस्कृति ला जिंदा करे के बात आवथे त तुई मन संस्कृति ला खतम करे हावव । केन्द्र मा तुंहर सरकार, राज्य म तुंहर सरकार, 15 साल ला छोड़ दव, बाकी दिन का करथ रेहेव ।

श्री रामकुमार यादव :- जेन स्कूल मा पढ़े हव ना, तेला यही सरकार हा बनाये हे । जेन तुंहर कुला म सूजी देवाय रहिसे वोला हमरे डाक्टर दे हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- रामकुमार जी, अऊ कतका दुर्भावना ए सरकार के होही, जैजेपुर अनुविभागीय कार्यालय के प्रारंभिक प्रकाशन दावा आपत्ति के बाद न बजट में आइस, न वोखर स्वीकृति मिलिस, काबर कि बगल के कांग्रेस के विधायक के यहां खोलना जरूरी रहिसे, लेकिन विपक्ष के विधायक के यहां खोलना जरूरी नई रहिसे । सरकार के ये दुर्भावना हे ।

<u>सदन की सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था लाबी स्थिति कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें ।

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- लखमा जी के बारे में बाते नई करना हे । काबर उ कदे हे, मोर बारे म तै बातचीत मत करबे, नइ त तोल ठीक कर दुहूं । बाबू ए भुला जा कहे हे, भले हमन घोषणा कर दे हन, लेकिन दारू बंद होने वाला नई ए करके वोखर विशेष रूप से निर्देश हे । दारू बंद करे के बात मत करबे । लखमा जी, मैं बिल्कुल दारू बंद करे के बात नई करंव । काबर कि मैं आपके नीयत ला जान डारे हावंव । अऊ मैं कइहा भी तो ओला आप नोट नहीं करा।

समय :

5.00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी शैलेश पाण्डे जी कहिन। जब यह भाषण के शुरूआत करिस तो कांग्रेस की तरफ से बजट मा माननीय शैलेश पाण्डे जी शुरूआत करही। एक जिक्र मोर भी करिन कि तोर घर मा चोरी होये हे अऊ जल्दी चोर पकड़ा जाही। ऐसा लागिस कि पाण्डे जी अब पुलिस के प्रवक्ता हो गे हे। चोर ला पुलिस मन पकड़ डारे हे अऊ वो घोषणा करने वाले हे।

श्री रामकुमार यादव :- वह ई.डी. के प्रवक्ता है। (विपक्ष के माननीय सदस्य की ओर इशारा करते हुए)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक के घर चोरी होवत हे। थानेदार के थाने में हत्या होथे, तब पुलिस काम नहीं कर पाथे तो एक आम आदमी, एक आम जनता के हित मा का काम करत होही। यह प्रदेश के दुर्भाग्य के बात हे कि ये कानून व्यवस्था है। केवल शराब पकड़ना, सेटिंग करना। शराब पकड़ के काम भी नहीं करना, सेटिंग करना अऊ सेटिंग नहीं होही तब जेल भेजना, यह छत्तीसगढ़ पुलिस अऊ आबकारी, दोनों विभाग के कानून व्यवस्था में काम रह गये हवय। हमर माननीय पर्यावरण मंत्री जी हे, माननीय मंत्री जी, मोर क्षेत्र में एक ही ठन छीता पंडरिया के जंगल है। वहां बहुत अकन जंगली जानवर रहिथे, जंगली सुअर, खरगोश। वहां पर पूरा डोलोमाइट वाला अगल बगल मा खदान बना ले हे। कहां लेर आये हे। एक बालाजी वाला झारखण्ड ले आये हे। वह वहां खदान बनाये हे, आप 45 एकड़ दे भी दे हव लेकिन 45 एकड़ में ओकर पेट नहीं भरथे अऊ 10 एकड़ ला कब्जा करे हे। लेकिन दुर्भाग्य ये हवय कि तहसीलदार जाकर नापिस कि तोर अतका हे, अवैध अतिक्रमण है तो ओ मे डिप्टी कलेक्टर हा स्टे दे दिस, नहीं हे। क्रेशर हा लगै रहे, भण्डारण करत रहै। ओकर परिणाम ला हमन भोगथन। वहां ब्लास्टिंग होथे, वहां क्रेशर चलथे, वहां प्रदूषण फैलथे, वहां पेड़ कटथे। तो जंगल के जानवर हमर खेत की तरफ जात हवय। आये दिन आदमी के ऊपर हमला होथे। हमर फसल के नुकसान होत हवय। रामकुमार यादव जी, आपकी और आपकी सरकार की यह व्यवस्था हे। एक डिप्टी कलेक्टर स्टे देथे। कौन ला ? उद्योगपति ला। आप उद्योगपति के बात करै ना कि भाजपा के उद्योगपति हे। आपकी

सरकार उद्योगपति ला संरक्षण देथे, आपकी सरकार गलत काम करने वाला ला संरक्षण देथे। आप तो वो क्षेत्र में रहथे जहां बहुत अकन पॉवर प्लांट हे। रोज का एक गाड़ी राखड़ निकलथे। लेकिन वो राखड़ हा कहां जात हे। यदि पॉवर प्लांट हा अनुमति दिस होही तो राखड़ की व्यवस्था के भी प्रावधान रखे गे रिहीस होही। लेकिन कहां आथे मोर क्षेत्र के ..। मनरेगा मा तालाब खोदाये हे तेमा राखड़ पाटे जाथे। पर्यावरण अनुमति देहे तालाब मा राखड़ पाटे के। छपोरा, जहां आम निस्तारी के तालाब हे, पर्यावरण ओला पाटे के अनुमति दे हवय। देवगांव के डोमा के बीच किसान मन के खेत मा 12 फीट ऊपर वो राखड़ ला बांध दे हे कहिथे किसान अपन खेत मा राखड़ डलवाना चाहत हे। किसान ता अपन खेत मा राखड़ डलवा दिस, आज पानी गिरही, हवा चलही। वो राखड़ हा कहां जाही, वह बगल के खेत मा जाही, आज गरीब आदमी विरोध करै की स्थिति मा नहीं हे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये होगे हे कि आज यदि हमर जैसे विधायक वह राखड़ डालने वाले का, ट्रक वाले का विरोध करै ता ऊ दू-चार चक्का के ट्रक नो हे, 10 चक्का, 20 चक्का के ट्रक हे। कतका बेर हम ला कुचल के निकल जाही ओकर पता नहीं हे। यहां आतंक के प्रशासन चलत हे, इहां दबाव के प्रशासन चलत हे, अऊ एकर परिणाम कल हमारा आने वाला पीढ़ी, निश्चित रूप से ये बात ला झेलही, प्रदूषण फैलही, वायु प्रदूषण फैलही, जल प्रदूषण फैलही, अऊ हम सब ओकर शिकार होबो।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये आपका समय लगभग खत्म हो रहा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, आपके बारे में चंद्राकर जी हमेशा कहिथे कि आप सक्षम हा। मोर निवेदन हे वो पर्यावरण विभाग ला दिखवावा। तालाब मा काबर अनुमति दिस। जब हम शिकायत करे तो भेज दिस। 500 ट्रक राखड़ पाटे रहिस, 100 ट्रक राखड़ ला उठा दिस। ट्रांसपोर्टर आकर मोला कहिथे कि विधायक जी ओमा ऊपर मा मिट्टी डलवा देथन। तो सरकार हा तालाब काबर खोदाये हे ? 7 लाख रूपये के स्वीकृति देकर सरकार हा तालाब खोदवाइस अऊ ओमा राखड़ पाट कर के ओ तालाब हा बराबर कर देहे। माननीय रामकुमार यादव जी, यही काम होवथे, आपके भी नॉलेज मे हे। मोर ले ज्यादा तो आप भुगतत हवव। लेकिन आप बोल नइ सका। आप पीड़ा ला व्यक्त नइ कर सका। मैं कम से कम यहां पीड़ा ला व्यक्त करके अपन आप ला हल्का तो महसूस करिहा। कल बने बटकी मा बासी ला खाये हे, चल भई मोर मन के जो गुबार रहिसे तेला निकाल लेहा, अब तै तो प्रशंसा ही करिहा।

श्री अमरजीत भगत :- आप बीच-बीच में लखमा जी से मिल लिया कीजिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में होली के दिन कतका खोजेव। माईक में तीन बार एलाऊंसमेंट करेव। बिना लखमा जी के होली मिलन अधूरा हे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी भी रिहिन। में तीन बार माईक में एलाऊंसमेंट करेव, लेकिन अब ओला जनता मन के कहां ख्याल हे। खाद्य मंत्री जी काय हे कि आप खाता-पीता मंत्री बन गे हौ। वह पीता-पाता मंत्री बन गिन, लेकिन बने

के काकरो ख्याल नइ हे। मंत्री बने के पहिली कतका बढ़िया पूछव कि केशव का हाल-चाल हे, लेकिन जे दिन ले खाता-पीता मंत्री बनेव एको दिन पूछेव कि केशव का हाल-चाल हे ? तहूं ला नइ मिलत हो ही चऊंर, में बीस-पचीस किलो के राशन कार्ड बनवा दूंहूं । तहूं ला कुछ कार्यक्रम नइ मिलत हो ही। बड़े-बड़े कलाकार के कार्यक्रम करवा दूंहूं। मंत्री बने के बाद में कहात हौं।

श्री शैलेश पाण्डे :- इनके घर में चोरी अलग से हो गई है।

श्री अमरजीत भगत :- यहां यूनिवर्सल पी.डी.एस. सिस्टम लागू है। यहां सब झन के लिए राशन कार्ड है। पूरा 100 प्रतिशत है कहीं भी कमी होगी तो आप बतायेंगे तो तुरंत मैं बनाऊंगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बोलव के मौका दे हो, तेखर लिए धन्यवाद्।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये बजट का विरोध करते हुए, अपनी बात शुरू करता हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- का चीज से शुरू करबे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तोर संस्कृति विभाग ले शुरू करहूं। (हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट है या गजट है ? अब बजट कैसे है और गजट कैसे है, मैं यह बता देता हूँ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मोहले जी, ए बजट ए न गजट हे। ए कागज के पुलिंदा हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- भई गजट मतलब पेपरबाजी। सरकार हे...।

श्री कवासी लखमा :- माननीय पुन्नूलाल मोहले जी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। चन्द्रा जी, पिछले 5 सालों में आपको विधायक निधि 1 करोड़ रूपये मिलती थी। अभी 4 करोड़ रूपये मिला है, आपने उसके लिए कभी बधाई दी ? ऐसा काम किया तो आपने बधाई दी। दिल्ली से सांसद को 5 करोड़ रूपये मिल रहा है और पहली बार छत्तीसगढ़ में विधायक को 4 करोड़ रूपये मिल रहा है। आप इसको नहीं बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई नहीं देंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, अब आप भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ बना तो आपकी सरकार बनी । आपको कितनी विधायक निधि मिलती थी, आप बता दें ? उस समय आपकी सरकार थी आपको कितनी विधायक निधि मिलती थी

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट है या गजट ? अब दोनों बातें हैं। बजट मतलब पेपरबाजी, टी.वी. बाजी और सब समाचारपत्रों में देना। अब मैं नशाबंदी के बारे में कहूंगा । नशा कुल का उल्टा है शान । शानबाजी सरकार है। अब यह कहते हैं कि हम नशाबंदी करेंगे या शराबबंदी करेंगे। इन्होंने किसमें कसम खायी थी ? हाथ में कसम खायी थी। इनका छाप भी हाथ है और हाथ में किसकी कसम खाये थे ? गंगाजल की कसम खाये थे। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी

भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि हमने यह कसम नहीं खायी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें। जब उस समय इनकी सरकार नहीं थी तो इनके बड़े नेता आये थे, वह घोषणापत्र में कौन-कौन सी कसम खाये थे ? आप तो नशा मंत्री हैं, आप क्या बात करेंगे ? शराब सबके दिल को मत करो खराब।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको 2600 रूपये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आप तो [XX][10] हो। अब आप नशाबंदी नहीं कर पायें।

श्री रामकुमार यादव :- तें आने के ताने कहात हस । तैं होगेस आएं-बायं-सायं। राजस्थान में चलथे तेला कथे ऊंट बबा तें झन ज्यादा बोलबे असत्य।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैंने पिछले साल भी बोला था। आप नशाबंदी नहीं कर पाये। जब कोई आदमी के अपने कसम, वायदे या जुबान की कीमत नहीं है तो फिर बात और इंसानियत की क्या कीमत है ? यह संवेदनशील सरकार है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय पुन्नूलाल साहब, दिल्ली वाले बोले थे कि हम सबको 15-15 लाख रूपये देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ ? आप उसको भी थोड़ा बताईये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात करव दिल्ली। आपके पार्टी वाले मारत हावए किल्ली। जो क्या बात करते हो दिल्ली। यह आपको सोचना है। आप लोग कहते हो कि आपने 15 सालों में क्या किया ? हमने उन 15 सालों में जो किया नहीं किया, आप जानते हो, उस समय आप भी थे, लेकिन इन 15 सालों में आपकी 36 प्रकार की घोषणाओं ने हमें इधर ला दिया। अपने ऐसी मनमोहनी घोषणा की जिससे आप लोग उधर हो गए और हम आऊट हो गए। यह आपको सोचने की बात है आप 15 सालों की बात करते हो तो आप 15 सालों की बात छोड़िए। आपके 4 साल में आप क्या हो गए, यह आपके सोचने की बात है। आप तो इन 4 साल ही रहे, आपने किन-किन घोषणाओं का पालन किया ? क्योंकि 36 घोषणाओं में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों से आज की स्थिति में 14 सीटों में आ गई।

श्री अमरजीत भगत :- पूर्व खाद्य मंत्री जी थोडा सा सुन लीजिए। आप ये बताईये, बाकी बात तो ठीक है लेकिन सी.एम. हॉउस में आपका प्रवेश क्यों बंद करा दिया गया था?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह आप ही के कारण था। (हंसी)

---

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आदरणीय का प्रवेश विधान सभा में भी बंद कराना चाहिए। नये विधायकों को गलत-गलत ट्रेनिंग देकर बिगाड़ते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सब मेरे पास आते हैं। मैं उनको ट्रेनिंग देकर क्या करूंगा ? मैं तो अपने आप में ट्रेनिंग नहीं देता। ये खुद ट्रेनिंग नहीं लेते, मेरे पास ट्रेनिंग लेकर चले जायें। ये कितने बिगड़े हैं, खुद जानें।

श्री शैलेश पांडे :- आपके सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वाले छात्र यहीं हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मैं हूं।

श्री अरूण वोरा :- मैं इसीलिए तो इनकी प्रशंसा करता हूं कि उनको कभी न निकाला जाये। आप तो बिगड़े हुए को सुधार रहे हैं।

श्री शैलेश पांडे :- इस बात से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नशाबंदी क्यों नहीं करते हैं ? क्योंकि सरकार को इससे 6 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिल रहा है, उसके बाद भी ये लोग कर्ज ले रहे हैं। हमारे सहित पूर्ववक्ताओं ने बोला कि सरकार 1 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है, और नहीं पा रहे हैं दर्जा और ले रहे हैं कर्जा। कर्ज लेने के बाद भी इन लोगों ने नशाबंदी नहीं की। अगर मैं दूसरी बात कहूं कि आप किसानों का धान खरीदते हैं। आप किसानों को 04 किश्तों में पैसा देने के कारण किसानों को परेशान कर रहे हैं और किसानों का जरूर लेते हैं धान, पर करते हैं 04 किश्त में भुगतान। कैसी है आपकी जबान। यह आपको सोचना पड़ेगा।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- उपाध्यक्ष जी, आप खाद्य मंत्री थे। 2021 में हम लोग पहली बार 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे थे, आपकी दिल्ली की सरकार ने क्यों बंद किया ? आप उनको बताईये कि क्यों बंद किये ? आप उधर नहीं बोलेंगे। इसलिए 04 किशतों में दे रहे हैं। आपकी केन्द्र सरकार ने बंद किया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप दिल्ली की बात छोड़िये, यहां की बात करिये। चलो न, हम आपको दिल्ली ले जाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह शराब की बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए न। आप इधर-उधर क्यों कर रहे हैं ? आपके विभाग का शराब का जवाब दो।

श्री कवासी लखमा :- आपकी केन्द्र सरकार के कारण 04 कश्ति में भुगतान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग टोकाटाकी न करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप शराबबंदी करायेंगे या नहीं करायेंगे ? आप खड़े होकर बोलिये न। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप बताईये, शराबबंदी करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- इधर आईये, आपको बता देता हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं क्यों इधर आऊं। आपकी जबान बंद हो गई। अब आप 06 महीने में क्या करोगे ? आप हमारे जैसा ऑउट हो जाओगे, जैसे हम ऑउट हो गये न, आप भी ऑउट हो जाओगे। आपके पास अभी भी टाइम है कि आप शराबबंदी लागू करें। शराबबंदी करेंगे तो अच्छा होगा। आप 04 किश्त में किसानों को पैसा देते हैं, 01 किश्त में किसानों को पैसा दीजिए। आपने धान लेना शुरू किया है, आप इस की शान मारते हैं तो आप जो किसानों को 04 किश्त में पैसा देते हैं, उसको 01 किश्त में किसानों को भुगतान कीजिए। मेरा यह कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में कहना चाहता हूं। आपके घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को 250 रुपये देने की बात है। पर यह नहीं कहा है कि रजिस्ट्रेशन वालों को देंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- बाबा, वह 250 रुपये नहीं है, वह 2500 रुपये है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं क्या पढ़ रहा हूं, आप मेरी बात को सुने ही नहीं हैं।

श्री उमेश पटेल :- गलती से 250 रुपये बोल देहे रहेव।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 2500 रुपये, भूल गया था। आपने बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- तैं एला बबा कैसे कह देहेस। अभी जवान आदमी गा हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- बबा, मानथे हें।

श्री कवासी लखमा :- जिनके पास 12 बच्चे हैं, उनको बाबा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ? आपके पास कितने बच्चे हैं ? इसलिए आपको बाबा नहीं बोल रहे हैं। आपके भी 12 बच्चे होंगे तो आपको भी बाबा बोलेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं तो बबा हूं जी। आपने ये घोषणा नहीं की थी कि हम इतने लोगों को देंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन वालों को देंगे, आपने उम्र का उल्लेख नहीं किया है। उसमें आपने ये डिवाइड नहीं किया था कि इतनी उनकी आमदनी होगी। इस बात के कारण आप लंदी-फंदी हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप धोखा दे रहे हैं। अगर आप शिक्षित बेरोजगारों को राशि दे रहे हैं तो जितने शिक्षित बेरोजगार हैं, सभी लोगों को दें। आपने ये नहीं कहा था कि आयु ज्यादा होगी तो उसको नहीं लेंगे। जब आपने 04 साल पहले घोषणा की थी, उस समय जो शिक्षित बेरोजगार थे उस समय उनकी उम्र क्या थी ? मान लीजिए उनकी उम्र 35 वर्ष की रही होगी, आज वह 39 वर्ष के हो गये हैं। आप उनके बारे में क्या सोचेंगे ? यह आपका विषय है। आप इन सब बातों का मतलब बता दीजिए, आप यह कहते हैं कि पंजीकृत हैं, वह भी 03 साल के हैं। आप मेरी बात को तो पूरी होने दीजिए। आपको क्यों लग रहा है, आप इनको पूरे वर्ष का पैसा दे दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उमेश पटेल :- बबा, तैं हर बार-बार माईक ला बंद-चालू मत करबे। ओ काहे कि येति के मन चालू करथे तहां तैं फेर बंद कर देथस। फेर चालू कर देथे तहां फेर बंद कर देथस। अब छूबे झन। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तो मैं कैसे करूं?

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी बार-बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। शर्मा जी, उनको बार-बार तंग मत करिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, भाषण जारी रखिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब मैंने बेरोजगारों की बात कही कि आप बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं तो सभी बेरोजगार हैं। चाहे उनका 35, 36 या 37 है, अनुसूचित जाति, जनताति का 40 वर्ष तक आयु सीमा है। इन सबको बेराजगारी भत्ता देंगे, यह मैं सरकार से आशा करता हूं।

श्री उमेश पटेल :- बबा, बंद-चालू मत करना। चालू भर मत करबे तैं हर।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- बोलने के लिए तो चालू करूंगा, तब तो आप सुनेंगे, नहीं तो आप क्या सुनेंगे।

श्री उमेश पटेल :- शर्मा जी, आप उनका हाथ बांधिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- का हे कि असल में श्यान के मसके के आदत हे। (हंसी)

श्री बृहस्तप सिंह :- यह कहा कि 80 साल का युवा है भाई।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब भर्ती में अनुसूचित जाति और जनाजाति का लगभग 35 पद रिक्त है। उसके बारे में आपका ख्याल नहीं है। उसके बारे में अनेक पदों के लिए विज्ञापन भी हुआ और विज्ञापन में भर्ती की प्रक्रिया है, पर आप हाईकोर्ट का बहाना बनाकर भर्ती नहीं कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है तो जो हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन का सरकार को पालन करते हुए रिक्त पदों की भर्ती करें, क्योंकि यदि मार्च में एक साल के बाद पद समाप्त हो जाता है और जितने विज्ञापन हैं और निकाला गया है, उनको आप ध्यान देंगे, ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूं। अब मैं यदि आवास की बात करूं। आपने आवास देने की बात की थी कि हम सभी को आवास देंगे, पर 14 लाख लोगों को आवास नहीं दिये हैं। इस बजट में प्रावधान नहीं किये हैं। सिर्फ यह कहा है कि हम भारत सरकार के गाइडलाईन के अनुसार आवास दे रहे हैं। भारत सरकार का गाइडलाईन है, पर आपका माइंडलाईन क्या है? आपका घोषणापत्र क्या है? आपने सभी आवसहीनों को आवास देने की बात की है। आप कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाता है और क्या कहते हैं कि सर्वे करायें। आपका कार्यकाल तो समाप्ति की ओर है। आप सर्वे कब करवायेंगे? सर्वे का रिपोर्ट कब आयेगा? आवास प्लस टू हमारी सरकार में पास हुआ है। आवास प्लस टू मिलाकर आप काम करेंगे। अधिकतर लोगों को पिछले समय में हमारी सरकार ने सर्वे कराई थी, जिसको आवास प्लस टू के नाम से है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरा आधा टाईम से ऐसी ले लिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट और बोलिये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- मोहले जी, कन्या विवाह योजना में 25 हजार की जगह 50 हजार कर दिया गया है, यह आपको मालूम है न?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हाँ, मालूम है।

श्री अरमजीत भगत :- सरकार को धन्यवाद दीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपके लिए ही तो है। सब मूल विवाह आप करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब मूल परिस्थिति में आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत मंत्री हैं। पंचायत मंत्री के समय में मैं कहना चाहूंगा कि पंचायतों के सरपंच के लिए राशि का मतलब चार साल निकल गया। समग्र योजना, अन्न योजना में पंचायतकर्मी इधर-उधर भटक रहे हैं। सचिव लोग भटक रहे हैं। उनको समान वेतन नहीं मिल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- कहां भटकथे?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपके पास आवेदन करने नहीं आयेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- ओहर भटकना होथे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तो भटकना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उनको पटकनी दे रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वह तो भटक रहे हैं । उसको आप किनारे ही लाने दे रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- बबा, माईक ला बंद-चालू मत कर न।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पिछले साल भी आपने समग्र योजना का राशि नहीं दिया। अनदेखा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इधर वाले को छोड़िये। आप देख-दाख कर रेवड़ी बांटते हैं। चाहे पिछड़े वर्ग के विभाग का है, चाहे अनुसूचित जाति प्राधिकरण का पैसा है। पैसे इधर नहीं देते। हम लोगों का चेहरे ही नहीं देखते। बोलते हैं तो ऐसे मुंह टेढ़ा कर देते हैं। आपने इसलिए अनदेखा किया कि आपने ज्यादा बहुमत पा लिया है। आप इतरा रहे हैं। आप ज्यादा घमंड न करें। लोगों को सम्मान की दृष्टिकोण से, भाईचारा की दृष्टिकोण से व्यवहार करें। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। मैं आपको अन्न योजना में जिला मुंगेली की बात कहूं। जिला मुंगेली में माननीय डहरिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री गये थे। मुंगेली जिला में 4 साल पहले वहां शिलान्यास किये । किसका ? जलप्रदाय योजना का, खुडिया बांध के पानी को पाईपलाईन द्वारा नगरपालिका मुंगेली में पूरे...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बबा, 4 साल पहिली तें हा काय करे रहे तेला बताना भैया ? 4 साल पहिली काय करे रहे ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 4 पहले हमने पास किया था, आपने शिलान्यास किया था और मुख्यमंत्री जी गये उसके बाद कहां हुआ ? वह अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस

योजना को बढ़ायें, पैसा दें जिससे पूरे नगरपालिका को पानी मिले । वहां सिटी स्कैन मशीन जिला चिकित्सालय के लिये कहा गया था लेकिन वहां सिटी स्कैन मशीन का न तो आज तक स्कैन हो रहा है और सिटी का कुछ पता ही नहीं है । अगर मैं फिर कहूं कि बिलासपुर से मंडला रेल्वे लाईन पास हुआ । यहां की कैबिनेट ने, पिछली सरकार ने पास किया । अपना परसेंट देंगे, 49 परसेंट का था । रेल्वे लाईन पास हुआ, प्रशासकीय सवीकृति भी मिल गयी लेकिन यहां की सरकार ने उसे रोक दिया । वह डोंगरगढ़ तक बनने का था । लाखों लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलता उसको भी बंद कर दिया गया, यह सोचने की बात है । मैं एक और बताउं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गिरौधपुरी के पास मड़वा में गये थे, वहां पर गुरू घासीदास बाबा जी की जन्मस्थली है, वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि हम गुरू घासीदास जी गुरूकुल संस्थान बनायेंगे । 4 साल पहले नहीं बना, सतनामी समाज ने मड़वा में मांग की, वहां सतनाम सदन के उद्घाटन में गये थे । सरकार की क्या मंशा है ? अंग्रेजी आत्मानंद स्कूल खोलने की बात है, अगर वहां के बच्चे आई.पी.एस. होते, आई.ए.एस. होते, इंग्लिश की पढ़ाई करते तो घासीदास गुरूकुल की बात नहीं करते । मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये । श्री राजमन बेंजाम जी ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और है वहां कॉलेज खुलना था । जरहा गांव में कॉलेज नहीं है क्योंकि वहां पर अनुसूचित जाति क्षेत्र है । जरहा गांव बाहुल्य है । वहां कॉलेज भी खोलें ऐसी आशा करता हूं । वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात थी, वहां भी नहीं खोला गया । खोलेंगे ऐसी आशा करता हूं और सरकार से यह चाहता हूं कि इन बातों पर ध्यान दें क्योंकि सरकार की योजना है । माननीय कृषि मंत्री जी चले गये हैं । 2 रूपये का गोबर कितने में बेच रहे हैं, उसको 10 रूपये में बेच रहे हैं यानी 5 गुना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, लगभग आपकी सब बातें आ गयीं हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आ गयीं न । इसीलिये तो नोट करा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका पूरा नोट हो गया ।(व्यवधान) लगभग-लगभग आपकी पूरी बात आ गयी । 5.30 बजने वाले हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5.30 बजने वाले हैं तो इस बात को लें । (व्यवधान) लोगों को अच्छा वर्मी खाद मिले । (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- राजमन बेंजाम जी । आप सब लोग सहयोग करिये ।

श्री राजमन बेंजाम (चित्रकोट) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बजट हमारी छत्तीसगढ़ महतारी के लिये एक खुशहाली का बजट है । यह बजट हमारे छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में निवास करने वाले आदिवासियों के लिये

खुशहाली का बजट है । यह बजट हमारे राज्य के बेरोजगार युवा-युवतियां उनकी खुशहाली के लिये हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का बजट है । मैं बस्तर से आता हूं, मैं पहले बस्तर की बात रखता हूं । हमारे माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी ने हमारे बस्तर में जो सामाजिक भवनों का निर्माण कराया है, यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । अकेले बस्तर जिले में लगभग 19 समाजों का जिला मुख्यालय में भवन बनाया है जिसमें हमारे कोया समाज का, कोया समाज बस्तर संभाग में 60 से 65 प्रतिशत निवास करते हैं वहां उनके लिये हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने 6 करोड़ 5 लाख रूपये दिये हैं । हमारे बस्तर जिले का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है । बस्तर में, गांव में निवास करने वाले लोगों की आस्था का केंद्र है । गांव के सभी लोग समर्पित भाव से उस देवगुड़ी की सेवा करते हैं, उस देवगुड़ी के लिये हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने 5-5 लाख रूपये देने का काम किया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नारायणपुर जिले में जो अबूझमाड़ क्षेत्र आता है । वहां की अबूझमाड़िया हमारी जनजाति है । उनके आस्था का केंद्र गोटुल है। गोटुल के लिये भी हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने 10-10 लाख रूपये देने का काम किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चांउर बाबा के 14 असत्यवादी शेर लोग जो कह रहे थे कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की जो घोषणा किये हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इतलकुडुम एक गांव है। नारायणपुर जिले के लोग भी आते हैं। बीजापुर जिले के लोग भी आते हैं। हमारे बस्तर जिले के लोग भी जाते हैं। उस इतलखुडुम गांव में आम आदमी का जाना तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इस वर्ष उस इतलखुडूम में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान किया है। अगर पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान हुआ है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में सम्मान हुआ है, जिन्होंने पंच के लिए 200 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए किया। सरपंच को 5000 रूपये देने का का किया। जनपद सदस्य को 6 हजार रूपये देने का किया। जनपद अध्यक्ष को 10 हजार रूपये मानदेय देने का काम किया और जिला पंचायत सदस्य को 10 हजार रूपये मानदेय देने का काम किया और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया है। मैं इसलिए पंचायतों के सम्मान की बात करता हूं, क्योंकि मैं 20 वर्ष पंचायत जनपद में रहा। मैंने इनके शासनकाल में लगभग वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अगर पंचायत का अपमान हुआ है तो 15 साल में बी.जे.पी. के शासनकाल में हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बस्तर से आते हैं। बस्तर में शैक्षणिक व्यवस्था की जो पद्धति है, वह आश्रम पद्धति है। आश्रम पद्धति में जो शिक्षा हमारे गांव, देहात के जो आदिवासी बच्चे को मिलती है, जो नक्सली पीड़ित हैं, जिनके मां-बाप नहीं होते हैं, वे लोग आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आश्रम शाला में पढ़ रहे बच्चों के

लिए 750 रूपए से बढ़ाकर 1200 रूपये किया और जिन बच्चों को 1000 रूपये मिलता था, उनको 1500 रूपये पढ़ने के लिए, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करने का काम किया तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। 15 साल तक इन लोगों ने बच्चों की शिक्षा की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। इन लोगों ने कभी आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चिंता नहीं की और इन लोगों ने 15 साल में स्कूल बंद करने का काम किया है। बी.जे.पी. की सरकार ने शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का काम कहां किया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल खिलाड़ी भी रहा और खेल की भावना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय हमारे भूपेश बघेल जी ने धन्यवाद देना चाहता हूं। चूंकि बस्तर में तीरंदाज की प्रतिभाएं हैं, वे आदिवासियों में कूट-कूट कर भरी हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1996 में जब लिंबाराम कटरनी इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में वहां ओलंपिक होने के लिए चल रहा था, एक मासोराम गावड़ेकर के लिंबाराम के साथ ट्रेनिंग दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने बस्तर में तीरंदाजी एकेडमी खोलने का घोषणा की है। इसके साथ-साथ हमारे नारायणपुर में मलखम्ब एकेडमी खोलने का निर्णय हमारे माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने लिया है। ये हमारे बस्तरवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी साहब।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार बोलने को मिल रहा है। थोड़ा सा और बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विश्व आदिवासी दिवस की बात कर रहे थे। हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया और इसमें विदेश के लोग भी हमारे यहां भाग लिये और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी भाग लिये। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण के लिए जो आयोजन किया है और आदिवासियों को जो प्लेटफार्म दिया है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है । मैं सदन को बताना भी चाहता हूं कि जिस विश्व आदिवासी प्रतियोगिता में विदेशों से खिलाड़ी आए थे, उनमें से मेरे बस्तर और मेरे विधान सभा के लोगों ने पहला स्थान प्राप्त किया था । उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जंगलों में रहते हैं और जंगल में निवास करते हैं । वहां वर्षों से वन अधिकार पत्रक नहीं दिया जाता था । फॉरेस्ट के अधिकारी आते थे और उनका घर उजाड़ते थे, घर जलाते थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने उनको वन अधिकार पत्रक देने का काम किया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री राजमन बेंजाम :- एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों की सबसे बड़ी पूंजी सहकारी वनोपज है । सहकारी वनोपज से हमारे आदिवासियों को आय होती है वह उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है । मैं धन्यवाद् देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 7 प्रकार के वनोपज को बढ़ाकर अब 65 प्रकरण के वनोपजों को खरीदने का काम किया है । उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हमारे आदिवासियों से 2 रूपए किलो में महुआ खरीदते थे। मैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद् देना चाहूंगा जिन्होंने महुआ बोर्ड का भी गठन किया है । यह हमारे आदिवासियों और हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है । आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

श्री रामकुमार यादव :- डॉक्टर साहब सही सही ला कहियो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- ठीक हे रामकुमार, बताबे बीच-बीच में । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके विरोध में बात करता हूं । यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जादूगरी बजट है, जो दिखता है लेकिन होता नहीं है । इस बात की कल्पना की गई कि गढबो नया छत्तीसगढ़, बोरबो नया छत्तीसगढ़ । किस तरीके से होता है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ियों के साथ कपट किया गया, छल किया गया, उनको कैसे भेदने का काम किया गया, मैं एक-एक प्वाइंट पर बात रखता हूं । माननीय अजय चंद्राकर, बृजमोहन जी, शिवरतन जी ने बहुत सारे आंकडों के साथ तथ्यों को रखा । लेकिन जिस पहलू से छत्तीसगढ़ के लाखों लोग प्रभावित होते हैं उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, मैं सरकार को आईना दिखाने का काम करता हूं । पहला पलायन, छत्तीसगढ़ से कितने लोग पलायन करते हैं और आपने उनके लिए इस बजट में आपकी क्या कल्पना है । क्या आपने कभी इस बात का अध्ययन किया है कि छत्तीसगढ़ से जो लोग पलायन करते हैं, इन पलायन करने वालों को हम कैसे स्किल्ड करें, इनका सम्मान, इनका गौरव कैसे बचाएं और हम उन्हें छत्तीसगढ़ में ही अवसर कैसे दें । क्योंकि पलायन ही एक ऐसा आंकड़ा है जो कांग्रेस सरकार की योजनाओं की पोल खोलती है । उपाध्यक्ष महोदय, पलायन क्यों हो रहा है ? मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में पिछले साल 70 हजार और अभी एक लाख लोगों ने पलायन किया है । प्रतिवर्ष एक लाख लोग पलायन करते हैं ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- डॉक्टर साहब, पिछले साल तो कोरोना रहिस, सब लोग घर में रहिन तो कइसे कहत हस तैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हर विधान सभा क्षेत्र से लोग पलायन करते हैं । क्या उन गरीब लोगों के लिए यह बात करते हैं । कभी इन्होंने जाकर देखा पलायन करने वाले गरीब लोगों को । वे लोग इनको आईना दिखा देंगे ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल तो कोरोना रहिस, आदमी घर ले बाहर नइ निकले ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जब तक इन गरीब आदमियों के लिए आप गढ़ने का काम नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ गढ़ेगा कैसे । क्या कल्पना है आपकी बताइएगा अगर कोई बात होगी तो ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप शर्मा जी के दबाव में भाषण दे रहे हैं, स्वतंत्र भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब जी, आप साईंस के कॉलेज के स्टूडेंट अव, (व्यवधान) मोला ए बतावव, कोरोनाकाल में सूजी दे ले कोरोना भागथे कि थाली पिटे ले भागथय मोला बतावव।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- डॉ. साहब हमर इंहा छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लागू होय हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, टोकाटाकी ना करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में हम गढ़ने की बात करते हैं चाहे हमारा जो बजट है, वह केन्द्र परिवर्तित हो या राज्य परिवर्तित हो। हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा है। लेकिन जहां-जहां पर कपटपूर्ण वैचारिक रहता है, आपकी दूरदृष्टा रहती है तब-तब आपने उन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जिसमें लोगों को फायदा पहुंचे। केन्द्र परिवर्तित योजना का लाभ से वंचित रखने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह कपटपूर्ण व्यवहार है। कैसे है? अभी जितने भी किसान सम्मान निधि वाला मामला है, किसान को उसमें लाभ मिल जाना चाहिए, उसमें आंकड़े हैं, उसकी जानकारी है, प्रस्तुत करें, आपके ही किसान हैं और ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाता, क्या फर्क पड़ता। लेकिन नहीं है। तीसरी बात, जल जीवन मिशन का है। अगर यह काम हो जाता है तो लोगों को घर पहुंचकर पानी की व्यवस्था बन जाती, यह सुनिश्चित है, ठेकेदारों पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। अगर यह मिल जाता, जल जीवन मिशन का काम हो जाता तो यह किसका काम होता, छत्तीसगढ़ के लोगों का काम होता। क्या इसमें प्रगति नहीं होनी चाहिए ? आज जिस तरीके से ठेकेदार गांव के लोगों को धमकाकर जो सी.सी. रोड बना हुआ है, उसको तोड़ रहे हैं। उसको ठीक करने का काम नहीं नहीं कर रहे हैं। खपट रहे हैं जो भी कर रहे हैं। दूसरा, जहां पाय तहां खोद करके रखे हुए हैं। जिस क्वालिटी का है, उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। कुल मिला करके वहां पर ठेकेदारों के द्वारा मनमानी चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास की तो जगजाहिर चर्चा है कि किस तरीके से है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की है। अनुसूचित जाति के जितने प्रभावित गांव हैं, जनसंख्या वाले गांव हैं, जिसको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लेकर उस गांव का विकास करके लगभग एकात करोड़ रूपया प्रत्येक एस.सी. गांव को दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- स्मार्टसीटी घलो बनाबो कहे रहिस हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उस गांव की प्रगति के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा है, इसमें प्रशासन मौन क्यों बैठी है। इसका काम हो जाए तो किसका काम होगा, छत्तीसगढ़ के लोगों का काम होगा लेकिन आपका विचार कपटपूर्ण है, वह होने नहीं दे रहा है। क्योंकि आपकी दूरदृष्टा उसमें नहीं है। दूसरी बात, अतिरिक्त चावल देने की है। एडिशलन चावल है, गरीब लोगों के लिए है। अब यह गरीब लोगों को चावल देने के लिए है, क्या आपने उसको दिया ? उसके लिए सिस्टम बनाया, अभी भी गरीब लोगों को चावल देने की बातचीत है। गरीबों के साथ खिलवाड़, चावल से, पानी से, मकान से, उसका सब चीज लूटने का काम कर रहे हैं। इसमें आपकी कौन सी दूरदृष्टा है। केवल कपट के अलावा और कोई बात नहीं है। छल करना, आपके द्वारा छल किया जा रहा है, वादाखिलाफी किया जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- बांधी जी, जब से कोरोना आया था, तब से हम फ्री में चावल दे रहे हैं, किसको-किसको नहीं मिला है, लिस्ट दे दीजिए, हम दिला देंगे।

श्री उमेश पटेल :- क्या है, बोलने के लिए शायद बोल दिए, उनको भी पता नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप उसका हिसाब कर लीजिए, उसकी भी जानकारी दी गयी है।

श्री अमरजीत भगत :- वह भाषण आपको किसने लिखकर दिया है ?

श्री उमेश पटेल :- कौन ऐसा लिखकर दिया है, उसको पकड़िए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- छल, कपट वादाखिलाफी का क्या है। आपने छल, कपट और वादाखिलाफी किया। कैसे छल किया ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- लिखने वाले केवल आपकी तरफ थोड़ी हैं, इधर भी लिखने वाले हैं।

श्री उमेश पटेल :- गलत लिख दिया है, छल कपट उसने किया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने महिला सशक्तिकरण के नाम पर, आर्थिक स्वावलंबन के नाम पर उनको धोखा दिया है, उनके साथ छल किया। वे जो रेडी टू ईट बनाते थे, आपने उसको लूट लिया। वह कौन महिला है ? छत्तीसगढ़ की महिला जो स्वरोजगार से जुड़ी हुई थी, जो आर्थिक स्वावलंबन की ओर जाते थे, आपने उसको लूटने का काम किया है। यह जितने विधायक लोग हैं, उसके लूटे हुए पर वाहवाही दे रहे हैं। आने वाले समय में जो रेडी टू ईट का लूट किए हैं, वह समझ में आ जाएगा। (व्यवधान) उसका ठेका किसको दिए हैं, सब जगजाहिर है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- रेडी टू ईट खराब है करके आप ही लोग बदनाम करते थे। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- रेडी टू ई की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप उसको देखिए ना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जो बहनें रसोईयां की बातचीत करते थे, खाना बनाते थे, आपने उनको आश्वासन दिया।

श्री देवेन्द्र यादव :- डॉ. साहब, वह गांजा वाला बात भी बता दीजिए। (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या आपने अपने बजट में उनके आश्वासनों को पूरा किया ? वह रसोईयां भी आपको इस बार ज्यादा मिर्च डालकर खिलायेंगे। आपने जो रसोईयों को वादा किया, जो आश्वासन दिया, आपने उम्मीद की, आपके प्रति विश्वास किया। आपने उनके विश्वास को धोखा दिया। आपने उनके साथ छल किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- देवेन्द्र जी, वह गांजे वाली बात डॉ. साहब करते हैं ना, वह किसके लिए करते हैं, आप स्वयं अंदाज लगा लीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- यदि आपको इसकी जानकारी होगी तो इसका उल्लेख कर दीजिए। आपके दल के किसी के लिए रखते होंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जिन माता-बहनों के परिवारों को संरक्षण देकर गंगा जल लेकर के शराबबंदी की बात करते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- गांजा के बारे में भी बोल दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं गांजा की भी बात कर लेता हूं। (हंसी) आपने शराबबंदी को लेकर के उनके परिवारों को। क्या आप आज इसका दुष्परिणाम जानते हैं ? मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने शराबबंदी का आश्वासन दिया।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, आप गांजा बोले थे या भांग बोले थे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- भांग। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- भांग का असर क्या होता है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं अभी उस पर आता हूं। आपने शराबबंदी की बात की, लेकिन परिणाम यह है कि गांव में इसकी खपत इतनी बढ़ गई है कि स्कूलों में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन बच्चों की दर संख्या नहीं बढ़ रही है। आप बताइये, कुछ भी नहीं हुआ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, स्कूलों में दर संख्या भी बढ़ रही है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- केवल जनसंख्या बढ़ रही है दर संख्या नहीं बढ़ रही है। कॉलेज में जिस अनुपात में शिक्षक होते हैं, उस अनुपात में नहीं है।

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या आपको भांग दे दिये हैं ? डॉ. साहब, भांग का असर है ?... (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- बांधी जी, पहले आप यह बताइये कि आपका भाषण किसने लिखा है ?

श्री उमेश पटेल :- आज पक्का भांग का असर है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि यह भांग चालू करने की बात करते हैं। इनको तो असर नहीं हुआ, भांग का असर तो आप लोगों में दिख रहा है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- अच्छा सुनिये, आप यह बता दीजिए कि आज इनका भाषण कौन लिखकर लाया है ? सही छल-कपट तो उसने किया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- रात को 2-2 बजे...। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओ थ्री इडियट्स कस होगे हवै। ओमा बीच-बीच के शब्द ला मिटा दे गे हवै। (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब यह शराबबंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुन लीजिए, जो पुन्नूलाल मोहले जी का क्लास अटेण्ड करेगा, उसको यही हाल होगा। (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शराब बंद करने के लिए दुनिया भर के प्रयास कर रहे हैं। कमेटियां बन रही हैं, यह कर रहे हैं। कभी यह बैठकर वैज्ञानिक लोगों को बुला ले और एकाध बार आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को बुला ले और भांग के महत्व को समझ ले। लोग नाइट्रा ले रहे हैं। कैमिकल, रसायन ले रहे हैं और दुनिया भर के अपराध कर रहे हैं तो ये लोग अल्टरनेट में सोच सकते हैं ? आप जब रिसर्च करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं तो आपके साथ पूरे आई.ए.एस. अधिकारी भी जा रहे हैं तो क्या ये लोग इस पक्ष में भी सोच करके प्रस्तुत करेंगे ? आप उसको गंभीरता से ले और मैंने कहा था कि इस भांग के कारण आपको 10 साल में एक भी अपराध की घटना देखने को नहीं मिलेगी। जिसने बलात्कार किया हो, हत्या किया हो या कोई और अपराध किया हो, इस पर आप विचार कीजिए। जब आप खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अल्टरनेट सोच रहे हैं तो आप इस पर भी सोचिये।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. बांधी जी, योर एडवाइज इज एक्सीलेंट प्वाइंटेड, आई एक्सेप्ट।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यू एक्सेप्ट न। एक्सीलेंट।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका समय समाप्त हो गया। आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में तो मुश्किल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, आप सहयोग करें। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में क्या होगा ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दूसरा, यह किसान की बात करते हैं। आपने किसानों की खुशहाली की बात की। आपने किसानों के खाद को प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट व्यापारियों को बहुत ज्यादा दिया और सोसाइटी में खाद को कम दिया। जब जरूरत पड़ी तो किसान उस खाद को 600-700 रूपये में खरीदने के लिए मजबूर हुए। किसानों को खुशहाल करने का यह आपका कैसा स्वभाव है और कैसी प्रवृत्ति है ? आपके पास उसके लिए क्या योजनाएं हैं ? दूसरी चीज, जब भूरा माहो का प्रकोप आया था तो आपने

बातचीत की थी। यह क्या है कि किसान 6 बार- 7 बार कीटनाशक दवाई डाले, लेकिन किसानों को कोई सलाह देने वाला नहीं है कि कौन सी दवाई उचित है और कौन सी दवाई अनुचित है। आप मौन बैठे हैं। आप उन दवाइयों के संबंध में किसको संरक्षण करने वाला बता रहे हैं ? इस तरीके से आपने लगभग किसानों को प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। यह सोची-समझी योजना है। इसलिए मैंने कहा कि आपने छल करके इस काम को किया है। आपने युवा बेरोजगारों से कई प्रकार के वायदे किये थे, घोषणाएं की थीं और जब दिया गया तो उनको शर्तों के साथ दिया गया। इसी तरीके से जितने कर्मचारी हैं, आपने उनके साथ छल किया, वादाखिलाफी किया कि ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति है, हम संविदा कर्मचारियों को रेग्यूलर करेंगे। कलेक्टर दर वालों को हम संविदा में देंगे। ऐसे वायदे किये गये थे, आपने उनको नहीं पूरा किया।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब, कृपया आप समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अनुसूचित जाति की और अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- बता दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं दुनिया भर का उदाहरण नहीं देता। आज ही के प्रश्नोंत्तरी में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए रामकुमार यादव जी, चंदन कश्यप जी, अमितेश शुक्ल जी, ममता चन्द्राकर जी ने भी प्रश्न किया है। मतलब कांग्रेस के सदस्यों ने भी प्रश्न किया है और सबने एक ही बात की है कि हम अनुसूचित जाति के हॉस्टल में अनुसूचित जाति, जनजाति के विशेष घटक का करीब 12 हजार करोड़ रूपए देते हैं और सबने एक ही बात की है कि हमारे पास सुविधा नहीं है । आपने अपने बजट में कितने पोस्ट ग्रेजुएट, गर्ल्स हॉस्टल बनाए हैं, आपने कितने पोस्ट ग्रेजुएट, ब्वायस हॉस्टल बनाया है, कितने हॉस्टलों की मरम्मत की बात की गई, वहां पर कुर्सी-टेबल की व्यवस्था नहीं है ? आप कैसे कल्पना करते हैं और उनके लिए विशेष घटक में बजट रखते हैं तो आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, अब आप समाप्त करें, नये सदस्यों को मौका दीजिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष जी, एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । कांग्रेस के पदाधिकारीगण मंत्री जी से एक सड़क के बारे में बोलकर आए हैं । मैं आपसे इस सदन के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में सोन, बसंतपुर, मुकुंदपुर, कुकुरदी, गोपालपुर, परसोड़ी सड़क में रेत वालों के इतने हाईवा चलते हैं कि वह बना हुआ सड़क डैमेज हो गया है । उसके लिए कई बार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आग्रह किया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है । जब डेव्हपलमेंट ही नहीं है तो कैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात आ रही है । ऐसे ही हमने खम्हरिया, जेवरा के लिए कॉलेज की बात की थी । उधर बड़े-बड़े गांव हैं, बिलासपुर संभाग में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, विधान सभा वाला

गांव है। मैंने ग्राम सोनसरी, पचपेड़ी या जोंध्रा में कॉलेज के लिए भी लगातार मांग की है । ऐसे में मंत्री जी मदद करेंगे तो बात बन जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल मदद करेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कई बार मैं मीडिल स्कूल के लिए भी प्रस्ताव करके आफिसियली भिजवाता हूं । कछार, नवागांव, रलिया गांव में मीडिल स्कूल नहीं खुल पा रही है । अब आपसे क्या उम्मीद की जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस चौकी की भी मांग आई थी । माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, खम्हरिया में पुलिस चौकी बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा । आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- डॉ. साहब, एक दिन आप भांग की पार्टी रखिए, उसके असर को पूरा सदन देखना चाहता है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कल करवा दें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- डॉ. साहब, आप अपनी पार्टी में सत्यनारायण जी को पहले आमंत्रित कीजिए और कवासी जी को भी आमंत्रित कीजिए, शराब और भांग में क्या अंतर है, वे बताएंगे ।

श्री उमेश पटेल :- डॉ. साहब, आज एक ही चीज बता दे । आज तोर भाषण ला लिखे कोन हे अउ के बजे लिखे हस, वहू ला बता दे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा । समय का ध्यान रखेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं । किसी भी देश की असली ताकत उस देश के जवान और किसान होते हैं । यह भी कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो किसान हैं, वे बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं । बंजर जमीन थी और इस बार साबित हुआ है कि जहां पर पूरी पथरीली जमीन थी, वहां भी धान हुआ है । यह कारनामा हमारे भूपेश सरकार ने किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये बात तो बिल्कुल सही है । भाषण ला तै लिखे हस कि सिन्हा जी लिखके देहे, एला बता । सिन्हा जी ह लिखकर दे होही ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- मैं लिखे हवं । माननीय उपाध्यक्ष जी, अईसन हमर सरकार हे, हमर मुखिया हे । जो ये बजट पेश होएहे, अब छत्तीसगढ़ी में ही बोल लेथव । जो हमर छत्तीसढ़िया सरकार हे, जो बजट आए हे, वो ह गरीब, किसान के लिए आए हे ।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, तै छत्तीसगढ़ी में बोलबे तो कोजनी शिवरतन शर्मा जी समझही कि नहीं, ते बड़ा दिक्कत हो जही ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोर से ज्यादा छत्तीसगढ़ी बोल सकथव अउ लिख सकथव । अपन आप ला तै बड़े छत्तीसगढ़ी झन समझ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बजट ह गरीब किसान के लिए, हमर आदिवासी भाई मन के लिए बजट हरे, हमर नौजवान साथी मन के लिए अउ हमर महिला वर्ग के लिए बजट हे । सभी वर्ग ला ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किए गे हे । भरोसे के बजट हे, ऐमा पता नहीं हमर विपक्ष के साथी ला का लगत हे, मिर्ची लगत हे कि का लगत हे ? अंदर मा कलबलाहट हे। एकदम बेचैन हो गय हे अउ बेचैन हो के कुछ के कुछ बोले जात हे। तभे भांग घलो आ गय हे। अभी तक दारू चलत रहिस हे, अब भांग आ गय हे।

श्री केशव चन्द्रा :- असली मा एमन ला कसकस खाय कस लागत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमर जो छत्तीसगढ़ राज्य हे, ये पहले धान के कटोरा कहलाय। पहली जो 15 साल रहिस हे, ओ 15 साल मा धान गायब हो गय रहिस हे, सिर्फ कटोरा रह गय रहिस हे। लेकिन आज हमर मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हमर जो धान कटोरा रहिस हे तेन धन के कटोरा बन गय हे। आप गांव मा जाके देखो गांव मा किसान भाई मन बहुत खुशहाल जिन्दगी जियत हे। आप मन जानत हव कि कर्जा माफ होय हे। ओमा कोई भी भेदभाव नहीं किए गय हे कि ये गरीब तबका के, ये बी.जे.पी. के हे, ये आदिवासी हे, ऐसे कोई भेदभाव नहीं हे। हमर सरकार हा पूरा झन के कर्जा माफ हे।

माननीय सभापति महोदय, वैसे ही समर्थन मूल्य के बात करथन। आप मन जानत हव कि 2500 रूपया धान के समर्थन मूल्य मिलत हावय। कितना परेशानी आइस, मोदी जी पैसा नहीं देन कह दिस, लेकिन हमर सरकार जम्मो किसान भाई मन ला देवत हे, पूरा एक साथ पैसा देवत जात हे और समर्थन मूल्य बढ़त भी जात हे। ऐसे ही आप धान खरीदी भी देखे हव। पिछले समय जो धान खरीदी होइस तो आप मन बारदाना के लिए कितना परेशान करे रहेव। 15 नवम्बर से धान खरीदी होय रहिस हे, लेकिन एक जगह से आवाज नहीं आइस कि कहीं बारदाना के कमी हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, पिछले साल के बारदाना अभी भी किसान मन के पैसा नहीं मिले हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, ये बार आप मन भी चुपचाप बैठे रहेव, नहीं तो अभी तक चढ़ाई कर देतेव। (हंसी) अभी तक जो सत्र चले हे, ऐमा कोई भी सदस्य एक बार नहीं बोले हे कि बारदाना के कमी हे। (मेजों की थपथपाहट) आप रिकार्ड निकाल लो, लेकिन बारदाना कमी के बात नहीं आय हे। नहीं तो आप हमन ला बैठे नहीं देतेव।

श्री अमरजीत भगत :- आज बांधी उड़ गय आंधी में। (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- संगीता जी, आप ही तो बताये हैं कि बारदाना केन्द्र की सरकार भेजती है। इसीलिए तो पूरी व्यवस्था जम गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ऐसा नहीं है। इस बार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने व्यवस्था पूरी की है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप बोले हैं कि बारदाना केन्द्र सरकार भेजती है। जब बारदाना नहीं था तो आपने कहा कि केन्द्र की सरकार बारदाना भेजती है। व्यवस्था बनी है तो हमने किया है।

सभापति महोदय :- चलिये, आपस में चर्चा ना करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोर पड़ोसी घर हे, हमन घर मा निपट लेबो।

श्री उमेश पटेल :- रंजना का हे कि पिछले बार केन्द्र सरकार हा अति परेशान करिस तो ये बार हमन ला पहली से अलग से व्यवस्था बनाय बर लगिस। समझ गय न?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, ऐसे ही नवीन धान खरीदी केन्द्र खोले के बात हे, चार साल होइस हे, 598 नवीन धान खरीदी केन्द्र खोले हे, जो आज तक नहीं होय रहिस हे। (मेजों की थपथपाहट) ये बार बहुत अच्छा धान खरीदी होय हे। आप भले ही इहां विधानसभा मा विरोध करथव लेकिन आप मन क्षेत्र मा तारीफ भी करथव। एक थन शायरी हे। ओ हा पिक्चर के हे, आप मन जानत हव।

एक चुटकी सिन्दुर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये हमर छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति मा लागू होथे।

"एक चुटकी सिन्दुर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू,
छत्तीसगढ़ की संस्कृति की कीमत तुम क्या जानो विपक्ष के भाईयो।" (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- एखर जवाब मोहले जी दे सकत हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जोन कीमत बोल, हम ओ कीमत जानत हन।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आज हमन आदिवासी दिवस मनात हन तो हमर विपक्ष के साथी मन ला इतना मिर्ची काबर लागत हे ? मतलब ओ मन ला इतना परेशानी हे, हमर राउत नाचा से परेशानी हे, हमर सुआ नृत्य से परेशानी हे, ये हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति हे। आप जंगल मा जा के देखव कि वहां नृत्य होवत हे। आज हमन आदिवासी दिवस मनात हन तो परेशानी होवत हे। आप मन करीना ला बुलाय, सलमान ला बुलाय तो हमन ला परेशानी नहीं होइस। ओ समय हमन बोलेन कि हमर संस्कृति के जितना बहिनी मन हे, ओ मन ला बुलाव। लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। काबर कि आप मन राज करत रहेव तो उहां कोई सुनाई देय। ये हमर संस्कृति के बात हे। संस्कृति ला उजाकर करने काम हमर माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया हा करे हे। (मेजों की थपथपाहट) आप मन आलंपिक गेम देखे हव। चन्द्राकर जी ओलंपिक गेम मे बात ररखे रहिसे, ए होना चाही, वो होना चाही, लेकिन एक

बार नई बोलिस कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति के ला 15 साल में ओलंपिक गेम कराय रतेंव कईके, त अईसे हमर मुखिया हरै । साथ में आत्मानंद स्कूल के बारे में कहना चाहूं । कभु 15 साल में कखरो दिमाग में ये बात नई चलिस कि गांव के लईका मन ला, गांव के गरीब तबका के जो लोग हे, गांव मन के जो लोग हे, वोला हमन ऊपर उठान या बच्चा मन के शहर में इंग्लिश मीडियम में पड़थे, वोमन ला सब चीज के सुविधा मिलथे, चाहे वो प्रयोगशाला के बात करंव, चाहे वह लायब्रेरी के बात करंव, चाहे इंग्लिश मीडियम के बात करंव । वोला हमर मुखिया सोचिस, समझिस, जो अमीर मनके बच्चा मन सुविधा मिलथे, ते सुविधा हमर गांव के बच्चा ला काबर नई मिले । आज हमर घर में जो काम करथे, गरीब तबका मन वई स्कूल में पढ़थे जिहां काम करथे, तिहां मालिक के बच्चा भी पड़थे । ये हरे हमर बराबरी और ...।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सब चीज ठीक हे भाभी, लेकिन पथरा में धान कइसे उगही, तेन समझ नई आईसे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उगे हे, आप आहु हमर क्षेत्र मा, आपला दिखा दिंगे । हमर माननीय भूपेश बघेल जी के सोच हे...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- शर्मा जी, धान उगाये बर मेहनत भी चाहिये । बिना जमीन के भी धान उग सकथे । खून पसीना ला सूखाहव तव ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हर वर्ग के बारे में सोचथें कि हम बच्चा मन जब तकि शिक्षित नई होही न तब तक वो आगे नई बढ़ सकै ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा तैंहा ये बता, तैं बोलथस मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के बारे में सोचथे, काली तोर ले पूछेन, सिन्हा जी बर तो नई सोचिस मुख्यमंत्री जी हा ?

श्रीमती संगीता सिनहा :-सोचिसे तभे मोला टिकट देहे । (हंसी) सोचे हव तभे त मोला टिकट दे हव ?

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- शिवरतन भईया, आज हर घर में लड़ाई क्यों करवा रहे हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- बार-बार संगीता जी बोल रही है कि हर वर्ग के लिये मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, सिन्हा जी बर सोचतिस तव ? पांच साल निकल गे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सोचिसे, तभे मोला टिकट मिलिसे, अऊ आज इंहा मैं बैठे हंव । ये आर्शीवाद हे । डबल सोच के मोला दे हे ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, दूसर के घर में ताक झांक ठीक नई हे, आदत ला सुधारौ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मन हा त मोदी जी ला बोल के रेट ला कम करवाय नई हव । महंगाई ला कम करवाय नई हव । पेट्रोल डीजल बड़थे । आज काम्पीटिशन होवथे डीजल और पेट्रोल के ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तैं ये बता कि दिल्ली सरकार जो टैक्स लेवथे, वोमा त प्रदेश ला हिस्सा मिल थे, बोलना डीजल अऊ पेट्रोल में वेट ला कम कर दे । माननीय मुख्यमंत्री जी ला तैं निवेदन कर ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज जनता सब ले ज्यादा क्षेत्र म उग्र हे गैस सिलेंडर ला लेके । गांव के महिला मन ला समझ आये नहीं बिचारी मन ला । आप लूटे के काम करे हव ।

श्री उमेश पटेल :- संगीता काहे, गांव के महिला मन एके झन ला खोजथे, वो स्मृति ईरानी कहां हे बतावव ?

श्री शिवरतन शर्मा :- काहे, यही सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण होय रहिसे । अऊ मुख्यमंत्री जी भाषण में बोले रहिसे कि हम गौठान के माध्यम से बायो गैस के प्लाण्ट लगाबो गोबर के । हर गांव में गैस के कनेक्शन देबो । केठिन कनेक्शन मिले हे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :-गोबर के पेंट बनथे, त वो दिन भी आही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, अजय चन्द्राकर जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गांव में इतना कनेक्शन मिला है, ये क्या बतायेगी, बतायेंगे तो सिन्हा जी बतायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, भाषण जारी रखिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गोबर से पेंट भी बनथे, गोबर से गोबर गैस भी बनही, गोबर से बिजली भी बन सकथे, का नई बन सकै । आप मन तो गोबर के कतका हंसी उडाये हव । जब इंहा गौ धन न्याय योजना आईस, सिर्फ गोबर-गोबर करके खत्म कर देव ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वोला बतादे, फेयर एण्ड लवली तको बनथे, जेला वोहा लगा सकथे ।

श्री रामकुमार यादव :- पहली छोटे-छोटे रहन त चुंदी झरै ना, गोबर लगान । मैं विश्वास के साथ कहाथंव पुन्नूलाल मोहले बाबू हा लगाही ना, सादा हा करिया हो जाही । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- यादव जी, ये यादव जी, दुनिया भर के बात करे बर, पहली तोर बर एकाठन बछिया खोल ले पहली । तेखर बाद दुनिया के चिंता करबे । बहुत गाय, गरूवा, बछिया गोठियाथ न, तोर बर बठिया खोज ले एकठो । तेखर बाद दुनिया भर के बरदी के ठेका लेबे ।

श्री अरूण वोरा :- मोहले जी, बाल तो करिया करवा लेबे, जवान कहां से होबे तैंहा । ए त बता ।

समय :
6.00 बजे

श्री अरूण वोरा :- मोहले ही बाल तो करिया करवा लेबे पर तै जवान कहां से होबे ? (हंसी) ये तो बता।

श्री अजय चंद्राकर :- उनको पीछे वाले को एक बछिया दिलवाओ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम क्षेत्र में जाथन तो तकलीफ तब होथे जब जी.एस.टी. के बात आथे। जी.एस.टी. के बात एकर सेती कहत हव, काबर के अभी बिहाव हुइस अऊ लोग मन साड़ी खरीदे बर गइस तो सब बिल ला धरकर मोर कर लाइस। कोई में 1 हजार के जी.एस.टी., कोई में 1 हजार 5 सौ के जी.एस.टी., कोई में 5 हजार के जी.एस.टी.। हम बोलेन कि कितना बड़े बात हरे, जो हमर क्षेत्र की जनता हे, वो जी.एस.टी. ला लेकर आइस। वाकई में जब हम भी ओला देखथन ना तो कामे-कामे कितना प्रतिशत जी.एस.टी. लगे हे, हम नहीं समझ पाए। ऐसे हमन ला लूटे के काम ये 15 साल से सरकार में बैठे हन ते सरकार करत रिहीसे और अभी मोदी करत रिहीस। साथ में आप मन थोड़ा-सा आरक्षण ला, जी.एस.टी. ला ठीक करवा दो, आपसे रिक्वेस्ट है। पेट्रोल-डीजल के रेट हा कम करवा दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- संगीता जी, सुनिये ना। जी.एस.टी. काउंसिल के जो निर्णय होथे, अब तक सर्वसम्मत होये हे। बाबा साहब बैठक में जाथे। ओला बोलबे कि विरोध करही।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शिवरतन भैया, एक बात बताव। जो हमर सरकार हे ना वो किसान मन के जेब ला भरे के काम करत हव। आप मन ओकर जेब ला खाली करै के काम करत हव। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अमरजीत भगत :- गुड स्पीच, गुड।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, तो अइसन थोड़ा सा बदलना हे। हमर सरकार हे, हमर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हे। जो हर वर्ग के लिये बात करथे अउ ओकरे सेती जो महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क खोले जाथे, वह RIPA के बहुत ही सराहनीय कार्य हे। अउ जो हमर RIPA के बेरोजगार युवा साथी हे, ओमन ला भी काम मिलही और यह जो काम के लिये शहर के लिये पलायन करत रिहीसे ओकर से हम दूर होबो। हमन हर बच्चा मन हा आज वह प्लांट के लिये इतना उत्साहित हे और जो हमर ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिये दूर हो चुके रिहीसे। आप मन तो यहां रायपुर में बड़े-बड़े उद्योग लगा चुके हो। यहां से आप हटे भी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। आप मन तो पूरे शहर ला इतना बड़े नया रायपुर बना देव, बड़े-बड़े रोड बना देव। आज वहां व्यक्ति जाथे तो गोल-गोल घूमत रहिथे। वहां पर कितना डिस्टर्ब होथे। आप मन सब बड़े-बड़े शहर ला डेव्हलपमेंट कर देव लेकिन आप मन गांव के बारे में कभी नहीं सोचे हव। गांव के व्यक्ति कैसे डेव्हलप होये, गांव के बच्चा कैसे शिक्षित होये, गांव के महिला कैसे आत्मनिर्भर होय, ये बात ला कभी नहीं सोचे हव। यदि आप सोचते तो आज हम ला ये करै के जरूरत नहीं रहतिस। आज हमर महिला मन स्वयं सहायता समूह में काम करत रहिस। (मेजों की थपथपाहट) अभी हमर 8 मार्च के होली रिहीसे। लेकिन में तो सोचथो कि होली 6 मार्च के रिहीसे। मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत-बहुत बधाई देथो। हमर मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई देथो, आज हमर मुखिया के कारण हर जगह 12.30 बजे बजट हा पेश होये हे अउ हर जगह 1.00 बजे होली खेले गे हे। (मेजों की थपथपाहट) जितना हमर विधान सभा के साथी मन भी हे, वो अपन क्षेत्र में गे हे सब रंगे गे हे। हम गे हे हम लोग पूरा रंगे गे हे। मितानिन बहिनी मन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय बढ़े हे, सब मन ला इतना खुशी के माहौल रहिस हे और ओकर लिये हम ला धन्यवाद बोलत हे। तो ऐसे हमर मुखिया हरे।

उपाध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, 15 मिनट से ज्यादा हो गया। माननीय धरम लाल कौशिक साहब।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट। इतना सुंदर बजट हरे। 25 सौ रूपये बेरोजगारी भत्ता दे हे। मैं इतना कहना चाहत हव कि ऐसे हमर मुखिया हरे, ऐसे हमर मुख्यमंत्री हरे। मैं इतना भी जानथव कि हमर विपक्ष के साथी मन इतना बुरे नहीं हे। ओमन अंदर मा तारीफ करथे लेकिन बोलना तो मजबूरी हे मोदी के डर से।(हंसी) यदि नहीं बोलही तो यहां से गायब कर दिही। यहां के रिकॉर्ड ला वहां पहुंचाना हे। ओकर सेती ओ मन हमर विपक्ष के साथी बात करथे लेकिन ओ मन दिल से खुश होथे। हर क्षेत्र की जनता खुश है। मैं धन्यवाद् देथो, यह बजट छत्तीसगढ़ के लिये बहुत ही बढ़िया बजट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद्, जय हिन्द।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद्। आदरणीय धरम लाल कौशिक साहब।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के द्वारा 2018 चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया। उस घोषणा पत्र के आधार पर यह सरकार आ गई। उसके बाद यह सरकार का अंतिम बजट है। हम अंतिम बजट को देख रहे हैं तो यह निश्चित रूप से भरोसे का बजट नहीं है बल्कि धोखे का बजट है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, यह अंतिम बजट नहीं है। यह पांचवा बजट है, अगला छटवां बजट आयेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह लोगों को दिग्भ्रमित करने का बजट है। लोगों से छलावा करने का बजट है। ऐसा कोई नहीं है जिसको इस सरकार ने छलने का काम नहीं किया है। चाहे कोई भी वर्ग हो, इस सरकार ने उस समय घोषणा पत्र के माध्यम से छलने का काम किया और अभी इस बजट के माध्यम से छलने काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 लाख 21 हजार करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया गया। वास्तविक में जो यह बजट है यह आंकड़ों की बाजीगरी है । मैं आंकड़ों की बाजीगरी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस बजट में हमारे सभी लोगों ने चर्चा की और बाकी लोगों ने चर्चा की। मैं आपको 2-3 सालों के बजट का विश्लेषण करके

बताना चाहता हूँ कि यह कैसे आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है। वर्ष 2020-21 का देखेंगे तो राज्य का कुल राजस्व केन्द्र से प्राप्त राशि व पूंजीगत प्राप्ति मिलाकर 90 हजार 620 करोड़ रूपये की आय और पुनरीक्षित बजट अनुमान में रखी गई। इसी वर्ष में जब लेखा प्रस्तुत हुआ और यह लेखा में आया तो इनका 90 हजार 620 करोड़ रूपये से घटकर 79 हजार 80 करोड़ रूपये आ गया। जो पुनरीक्षित बजट अनुमान से 11 हजार 540 करोड़ रूपये कम है। हमें अनुमान से लगभग 13 प्रतिशत राजस्व कम प्राप्त हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जब व्यय की बात करेंगे तो वर्ष 2020-21 में जो कुल व्यय, राजस्व और पूंजी दोनों मिलाकर 91 हजार 327 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित पुनरीक्षित बजट में रखा गया। जब इसी वर्ष का लेखा प्रस्तुत किया गया तो लेखा में दिया गया कि 79 हजार 56 करोड़ रूपए है जो कुल पुनरीक्षित बजट अनुमान से 12 हजार 271 करोड़ कम है। तो आपको जो व्यय करना था उसमें 14 प्रतिशत की कमी आई। आपकी आय में 13 प्रतिशत की कमी आई, जो आपने अनुमान लगाया। जो आपने व्यय की सीमा निर्धारित की, उसमें 14 प्रतिशत की कमी हुई। मैं वर्ष 2021-22 के बजट के बारे में बताना चाहूंगा कि राज्य का कुल राजस्व, केन्द्र से प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति मिलाकर 99 हजार 601 करोड़ रूपये आय पुनरीक्षित बजट अनुमान में रखी गई। इसी वर्ष में वास्तविक आय, लेखा जो प्रस्तुत हुआ, वह 86 हजार 348 करोड़ रूपये था, जो कि पुनरीक्षित बजट अनुमान से 13 हजार 253 करोड़ कम है। वर्ष 2021-22 में मतलब 13 प्रतिशत कम राजस्व प्राप्त हुआ। मैं व्यय की बात करूं तो कुल व्यय जिसमें वर्ष 2021-22 का है राजस्व और पूंजी व्यय दोनों मिलाकर 99 हजार 206 करोड़ रूपये का व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान में रखा गया। जब इसी वर्ष में वास्तविक व्यय लेखा प्रस्तुत हुआ तो 85 हजार 514 करोड़ रूपये जो कुल पुनरीक्षित बजट अनुमान से 13 हजार 692 करोड़ रूपये कम है। मतलब 14 प्रतिशत की कमी जो व्यय में हुई। अब वर्ष 2022-23 का आया नहीं है इसलिए मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब हम वर्ष 2023 और वर्ष 2024 की बात करेंगे तो वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल राजस्व, केन्द्र से प्राप्ति व पूंजीगत प्राप्ति को मिलाकर लगभग 1 लाख 81 हजार 500 करोड़ रूपये की आय बजट अनुमान में रखी गई है। यदि हम दो वर्षों का विश्लेषण करें तो इसमें 13 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की कमी आएगी। इसमें 13 प्रतिशत कमी आएगी तो यह होगा इसमें कमी हो जाएगी वास्तविक रूप से 16 हजार करोड़ रूपये कम प्राप्त होगा, जो अनुमानित किया गया है। तो यह बजट 1 लाख 81 हजार रूपये का नहीं, बल्कि यह जो बजट 1 लाख 5 करोड़ रूपये का होगा। यदि मैं व्यय की भी बात करूं तो राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों को मिला लेंगे तो 1 लाख 21 हजार 160 करोड़ रूपये का अनुमानित है और हम विगत दो वर्षों का वास्तविक लेखा देखेंगे तो इसमें हम 14 प्रतिशत की कमी घटाते हैं तो वास्तविक वर्ष का जो व्यय है 17 हजार करोड़ कम व्यय अनुमानित है आपका बजट 1 लाख 4 हजार करोड़ का ही होगा। मतलब क्या हुआ कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया,

बजट अनुमान प्रस्तुत किया। दूसरा आपका पुनरीक्षित बजट अनुमान है और उसके बाद में वास्तविक लेखा है। मैं एक वर्ष का बताना चाहूंगा कि हम वर्ष 2020-21 का देखेंगे कि बजट अनुमान कितना है? तो राज्य से प्राप्त होने वाला 35 हजार 370 करोड़ रूपये था। यह पुनरीक्षित बजट अनुमान में घटकर ऊपर नहीं आया, यह नीचे आ गया। यह नीचे आकर हो गया 31 हजार 45 करोड़ रूपये हो गया। वास्तविक कितना आया तो 30 हजार 26 करोड़ रूपये आया। मतलब आप देखेंगे तो जो अनुमान लगाया, आप उससे काफी दूर रहे। इसी प्रकार से अनुमान के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत कर दिया कि आने की संभावना है। लेकिन जब हम दो साल के बजट को देखेंगे तो दूर-दूर तक उसका धरातल से रिश्ता नहीं है। यह तो बजट है, मैंने इसीलिए कहा है कि यह भरोसे का बजट नहीं है, भूपेश बघेल का बजट धोखे का बजट है। आप बोलेंगे कि यह आकडें कहां से लाये? क्योंकि हर बार आप यह बोलते हैं कि यह आकड़ें कहां से लाये। यह तो हमारे है नहीं, आप कहां से लाये। मैं जो लाया हूं वह आपके ही विभाग का है। मैं पीछे ही जाकर बोला हूं। वर्ष 2023-24 से पीछे जा करके मैंने 2020-21 से शुरू किया है। और उसके भी पीछे चले जायेंगे तो यही आयेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा बजट इससे अच्छा रहा है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कौशिक जी ज्यादा बोलते हैं इसीलिए तो इधर से हटा दिये। आप और पीछे जायेंगे क्या ? आप ज्यादा तारीफ मत करना और पीछे जायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- पार्टी का जो आदेश होगा, वह मानना पड़ेगा। मैंने सुना है कि अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले हैं।

श्री कवासी लखमा :- सुकमा का।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब उसकी चिंता आप मत करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया और यह बजट जन विकास के लिये बताया गया। यह जन विकास नहीं, बल्कि जन विकास विरोधी बजट है। अधिकांश राशि जो उधारी लिये हैं, वह ब्याज पटाने में जा रही है। जब ब्याज ही पटायेंगे तो विकास के लिए आपके पास में कितनी राशि है ? हमारे अनेक सदस्यों ने इस बात को उठाया, आपने पी.डब्ल्यू.डी. का बजट देख लिया। आप छाप तो दिये हैं लेकिन छापने के बाद में आप प्रशासकीय स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि जो बजट का अनुमान लगाया है, उस बजट के अनुमान में खरे नहीं उतर रहे हैं। आपकी राशि ब्याज में जा रही है और वह भी उसमें पूंजीगत निर्माण नहीं हो रहा है। यदि पूंजीगत निर्माण हो तो आज नहीं तो कल आपको लाभ मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ऋण का बोझ कैसे बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 के वास्तविक लेखा में कुल प्राप्तियां लगभग 94 हजार करोड़ रुपये की थी, जिसमें 15,100 करोड़ रुपये ऋण है अर्थात 16 प्रतिशत ऋण से प्राप्त राशि थी। वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान में प्राप्तियां 1 लाख 14 हजार करोड़ थी, 16,500 करोड़ रुपये ऋण था, अर्थात 15 प्रतिशत ऋण से प्राप्त राशि थी।

वर्ष 2023-24 के बजट में प्राप्तियां लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये में से 19 हजार करोड़ रुपये ऋण से प्राप्ति थी, लगभग 15 प्रतिशत ऋण से प्राप्त राशि होगी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, वह तो लिखा हुआ है, जो भी बतायें तो और दूसरी बात बतायें। यह तो सबके पास है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2021-22 में 6,144 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 7,322 करोड़ प्रस्तावित था। वर्ष 2023-24 में लगभग 6900 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह केवल आपको ब्याज के भुगतान के लिए राशि देनी पड़ेगी। जो राशि आपने बाजार से, संस्थाओं से, निगम-मंडल से ली है, उसके बाद में आपको जो ब्याज की राशि पटानी पड़ेगी। मैंने इसीलिए कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति देने की स्थिति में इसलिए नहीं हैं कि आपके पास में दिखाने के लिए तो बजट है लेकिन काम करने के लिए आपके पास में वास्तविक में बजट नहीं है। कुछ दिनों के बाद में आप जो लोन लिये हैं, लोन की राशि पटाने का जब समय आयेगा, उस समय यह लोन तो ले लिये हैं, लेकिन जब भुगतान करने का समय आयेगा, उस समय यह सरकार नहीं रहेगी और आने वाली सरकार भुगतेगी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बाजू के प्रदेश में इसी महीने में शिवराज सिंह की सरकार ने 04 बार लोन लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, हम एक अशासकीय संकल्प ला रहे हैं। आपके रायपुर अधिवेशन में पास हुआ है। किसी भी प्रकार के नशा करने वाला आदमी, सूखा-गीला दोनों, वह कांग्रेस का सदस्य नहीं रहेगा। तो कांग्रेस का कौन-कौन सूखा-गीला वाला है, विधान सभा के अंदर में उसके पहले निकालो, हम एक अशासकीय संकल्प लायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसानों की सरकार की बात आती है, धान की रिकार्ड तोड़ खरीदी की बात आती है मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसी सदन के माध्यम से आपको मोदी जी को बधाई देना चाहिए था, क्योंकि जो किसानों की धान की खरीदी हुई है, उसमें आपका योगदान क्या है? आपका योगदान है, जो टोटल धान की खरीदी हुई है, वह 89 हजार ..।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक आप आंकड़े, वगैरह, सब बढ़िया बोल रहे थे। अच्छा लग रहा था। अजय जी बीच में खड़ा हो गये तो आपको याद आ गया और फिर आप कहां पहुंच गये। आपका भाषण ठीक चल रहा था। कौशिक जी, मैं यह कह रहा था कि आप केवल वर्ष 2019-20 का आंकड़ा मत बताईये। थोड़ा वर्ष 2016-17 का भी बता दीजिये। इसका भी आंकड़ा आपके पास होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है, आज वह भी बता देंगे। आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं वहीं से शुरू करता।

श्री भूपेश बघेल :- मुझे क्या पता कि आप क्या बोलने वाले थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान में जो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं और बड़ी-बड़ी बातें होने के बाद में मैं यह कह सकता हूं कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के किसानों की किन्हीं ने चिंता की है और उनके धान की खरीदी की है । पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। मैं नरेन्द्र मोदी जी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान की खरीदी हुई है।

श्री कवासी लखमा :- नरेन्द्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। डीजल का रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या ?

श्री दलेश्वर साहू :- कौशिक जी, आप 15 साल में कितना धान खरीदी केन्द्र खोलें और हमारे इस साल में कितना धान खरीदी केन्द्र खोलें, उसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लीजियेगा।

श्री कवासी लखमा :- कौशिक साहब, एक छोटा सा निवेदन है कि आपकी सरकार ने 15 साल में कितना धान खरीदी केन्द्र खोला?

श्री धरमलाल कौशिक :- जब जोगी मुख्यमंत्री थे, तब भी भूपेश बघेल जी मंत्री थे और उनको मालूम है कि उन्होंने कितना धान खरीदा। वास्तविक में 15 साल में हम आधारभूत संरचना खड़ा किये, पौने पांच लाख पंपों का कनेक्शन दिये, एक लाख रूपये की सब्सिडी दिये, किसान को वेटिंग लिस्ट में नहीं आना पड़ा, हम किसानों को धान समय में उपलब्ध करायें और जिस प्रकार से किसानों को खेतों तक सिंचाई के पानी को पहुंचायें। आज उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के किसान रिकार्ड तोड़ उत्पादन कर रहे हैं। यह डॉ. रमन सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल का है।

श्री कवासी लखमा :- उसको बढ़िया सज्जन आदमी मिल गया। रमन सिंह जी के लिए यह अच्छा आदमी है। मोदी सरकार में मोदी बोलेंगे, दूसरे को नहीं बोलना है। हमारे प्रतिपक्ष नेता जी बढ़िया हैं। आप बोलकर गलती कर दिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 से लेकर अभी तक जो कुल धान की खरीदी हुई, उसमें 89 हजार 609 करोड़ रूपये केन्द्र के सरकार के द्वारा दी गई है। उसमें कुल 89 हजार 609 करोड़ रूपये की धान खरीदी हुई है। उस खरीदी में राज्य ने 16 हजार 348 करोड़ रूपये का योगदान दिया है और केन्द्र ने 73 हजार 558 करोड़ रूपये का योगदान दिया है। मैं प्रतिशत में कहूंगा तो धान खरीदी में 18 प्रतिशत योगदान राज्य का है और 82 प्रतिशत योगदान नरेन्द्र मोदी जी का है, जिसके कारण में धान की खरीदी हुई है। (मेजों की थपथपाहट) आज तो मुख्यमंत्री जी ..।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष जी, धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा एक रूपया भी नहीं दिया गया है। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिये। आप खरीदी

की बात करिये। जो पैसा भारत सरकार से आता है। कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल बनाते हैं और उसको सेंट्रल पुल में जमा करते हैं, वह चावल का पैसा है। धान खरीदी का छत्तीसगढ़ की सरकार कर्ज लेकर धान खरीदी करती है।

श्री धमरलाल कौशिक :- यह जो कर्ज लेते हैं, वह केन्द्र सरकार के एवज में लेते हैं। लोन लेने के लिए, धान लेने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा अग्रिम लिया जाता है । आपके ही मंत्री का जवाब आया है, मैं उसको पढ़कर बता दूंगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष जी, धान खरीदी के लिए हर साल छत्तीसगढ़ की सरकार मार्फेड के माध्यम से कर्ज लेती है और राज्य सरकार गारण्टी देती है। इस साल के लिए राज्य सरकार ने 14 हजार करोड़ का गारण्टी दिया है। जब उससे अधिक साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये लगा तो उसमें कुछ ब्याज ज्यादा लगा, लेकिन धान खरीदी के लिए भारत सरकार एक रूपये भी नहीं देती। (शेम-शेम की आवाज)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने आपको बताया कि कुल योगदान केन्द्र सरकार का 73 हजार करोड़ और राज्य सरकार का 16 हजार करोड़ रूपये का है। अभी अकबर जी खाद्य मंत्री नहीं हैं। मेरे पास में खाद्य मंत्री जी के जवाब हैं। मैं पढ़कर बता दूंगा। आप पहले खाद्य मंत्री थे।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं केवल खरीदी की बात कर रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं भी खरीदी की बात कर रहा हूं। केन्द्र सरकार एडवांस में देती है। आप लोन लेते हैं और लोन में चावल की बाद की राशि ..।

श्री मोहम्मद अकबर :- खरीदी के लिए हम लोग कर्ज लेते हैं। मैं खरीदी की बात कर रहा हूं और जब हम सेंट्रल पुल में जमा करेंगे तो चावल का पैसा आप देते हो । खरीदी के लिये नहीं देते । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- खरीदी का मतलब ही चावल का है कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल जो आपको दिया गया और उसी 61 लाख मीट्रिक टन चावल के भरोसे आपने किसानों के धान की खरीदी की है । (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- नेता जी, क्या यह पहली बार मिल रहा है ? 8 साल से ही मिल रहा है ? क्या उसके पहले केंद्र सरकार नहीं देती थी ? (व्यवधान) यू.पी.आई. सरकार नहीं देती थी क्या ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- पहले भी देती थी । (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- तो फिर ? (व्यवधान) क्या पहली बार दे रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- छत्तीसगढ़ का इतिहास उठाकर देख लीजिये कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल यदि छत्तीसगढ़ में किसी ने दिया है तो नरेन्द्र मोदी ने दिया है ।(व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से मोदी जी आये, केंद्र सरकार कई योजनाओं में 90 परसेंट, 100 परसेंट देती थी । मोदी जी के आने के बाद 40-50-75 कर दी । आप लोग इसके बारे में भी बताओ । (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान) इसके बारे में कभी बोलते नहीं हो, क्या आपने कभी बोला है ? आदिवासी परियोजना में 100 परसेंट मिलता था, उसमें भी 50-50 कर दिया ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मनरेगा को भी कम कर दिया ।

श्री अजय चंद्राकर :- हओ, पूरा कम होगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान था कि आप लोग डॉ. मनमोहन सिंह जी को क्या श्रेय देते थे तो हम क्यों माननीय मोदी जी को श्रेय दें ? यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था, एक बात । दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, माननीय वित्तमंत्री जी भी बैठे हैं, भारसाधक वित्तमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी । 15वें वित्त आयोग से या वित्त आयोग से कितना पैसा बढ़ा है राज्य का हिस्सा और वित्त आयोग से राज्यों को कितना पैसा अधिक मिलने लगा, यह पूछ लीजिये । उसके बाद कम हुआ। वहीं से जानकारी ले लीजिये । (व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप धान से कहां भटक गये ? आप बोले थे कि गोबर खरीदोगे तो हम इस्तीफा देंगे, कर्जा माफ होगा । आप तो केवल असत्य ही बोलते जाते हो । यहां असत्य का पुलिंदा नहीं चलेगा, यह छत्तीसगढ़ की जनता है ।

(मुख्यमंत्री जी के सदन से बाहर जाने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी चल दिस, अब नइ खड़े होते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों का जिसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है । 56 हजार पम्प का कनेक्शन लंबित है, सवा लाख अस्थायी कनेक्शन किसानों के पास में है । इस सरकार की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वेटिंग लिस्ट को ये समाप्त कर सके और ये सरकार जब तक रहेगी, किसानों की जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी ये समाप्त नहीं कर पायेंगे क्योंकि इनके पास में जो 1 लाख का अनुदान देते थे वह अनुदान की राशि भी इनके पास में नहीं है और न ही बजट में जो राशि रखनी चाहिए वह राशि रखी गयी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । आज सबसे ज्यादा पीड़ित किसान है । सरप्लस पॉवर स्टेट और सरप्लस पॉवर स्टेट की क्या स्थिति है कि आपका 5 बजे से लेकर रात को 11.00 बजे तक पम्प की कटौती, 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की कटौती । ट्रांसफार्मर समय पर रिप्लेसमेंट करने की स्थिति में यह सरकार नहीं है और इसके कारण सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं, किसानों का धान सूख रहा है लेकिन सूखने के बाद में न ये कटौती को बंद कर रहे हैं और न ये ट्रांसफार्मर समय पर दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ा में है तो आज किसान है ।

श्री कवासी लखमा :- धान खरीदी केंद्र खोले हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- धान खरीदी केंद्र हमने खोला था, आपने थोड़ा सा विस्तार किया । हमने खोला था, उसका थोड़ा सा विस्तार आपने किया । धान खरीदी केंद्र तो कैसे खोले हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जायेगी । (व्यवधान) शिवरतन जी, इनका धान खरीदी कैसे खुला है, क्या किसी से छिपा हुआ है कि धान खरीदी केंद्र खोलेने के लिये, उसका अध्यक्ष बनाने के लिये कितना पैसा लिये हो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है । (व्यवधान) और इसलिये बढ़ाया कि उसमें पैसे ले सको । (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह धान खरीदी इसलिये कि इन्होंने इसको व्यवसाय बनाया । (व्यवधान) अध्यक्ष नियुक्ति में इन्होंने पैसा लिया इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 400 से ज्यादा धान खरीदी केंद्र खोले थे । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इन्होंने जो धान खरीदी केंद्र खोले और इन्होंने समिति में जो अध्यक्ष बैठाया, प्रमाणित वीडियो की क्लिपिंग दे देता हूं कि पैसे के लेन-देन की बात हुई या नहीं हुई । (व्यवधान) मैं क्लिपिंग दे देता हूं कि पैसे की लेन-देन हुई या नहीं हुई । बाद में उसको पार्टी से निलंबित किया । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हम वीडियो को नहीं जानते । आप इस्तीफा देने वाले थे, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- रिकॉर्ड है, इसको प्रस्तुत करा देते हैं और सुन लेना । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- विधानसभा में बोलने के बाद इन लोग उसको पार्टी से निलंबित किये हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- पार्टी से उसको निलंबित किये । (व्यवधान) आपकी पोल खुल गयी, अब पोल खुलने के बाद उसको निलंबित किये । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- कितना असत्य बोलेगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- पैसा लेकर नियुक्ति करते हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी 21 मिनट हो गया, कृपया समाप्त करिए। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आप लोग असत्य बोलते हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष को बोलने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किसानों की बात कर रहे हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि किसानों के लिए काले कानून लाये थे। पूरे देश के लोगों को पता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, टोका-टाकी न करें। आपस में संवाद न करें और सहयोग करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये खड़े हो जाते हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी की पीड़ा को समझें। अभी पूर्व के नेता प्रतिपक्ष थे। उन्हें थोड़ा समय और दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप लोग थोड़ा सा और सहयोग करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। आपको साढ़े 4 साल में बेरोजगारों की याद आयी और यदि बेरोजगारों की याद आयी तो पैसा कितना रखा आपने 250 करोड़। देना कितने को है? 10 लाख लोगों को देने की बात किये थे और अभी 18 लाख 79 हजार पंजीकृत हैं।

श्री कवासी लखमा :- आपने कितने लोगों को दिया था? पहले आप लोगों ने कितने लोगों को दिया था?

श्री धरमलाल कौशिक :- हमने असत्य नहीं बोला कि हम शराबबंदी करेंगे।

श्री कवासी लखमा :- आप असत्य बोले, असत्य। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारे सत्यनारायण भैय्या को आपने असत्य करा दिया। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान) ऐसा नहीं बोले। बाड़ी से डीजल मिलेगा बोले थे। अभी आपकी कौन सी बाड़ी से डीजल मिलता है। आप लोग असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- गंगा जल लेकर कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। असत्य बोले कि शराबबंदी करेंगे। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आपके यहां डीजल मिल रहा है क्या? असत्य कौन बोलता है कि हम आदिवासी को जरसी गाय देंगे। कभी दिये क्या?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- चिक-चिक, चिक-चिक। ये चिक-चिक चिक-चिक क्या है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- जरसी गाय मिला क्या? आपके बाड़ी से डीजल मिल रहा क्या? बाड़ी से डीजल मिला? तुम्हारे बाड़ी से डीजल मिलता था न? (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- ये चिक-चिक पोक-पोक क्या है? आप अपने विभाग में तो बोल नहीं पाते। ये दूसरे के विभाग में विशेषज्ञ होते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- कौशिक साहब, ये वर्ष 2003 का घोषणा पत्र है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2003 का घोषणा पत्र है। प्रत्येक जरूरतमंद बेरोजगार को 500 रूपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने कितनों को दिया? 15 साल आपकी सरकार रही है। कितनों को आपने दिया है? आप लोगों को सिर्फ असत्य बोलना आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ असत्य बोलते हैं। यह आपका संकल्प पत्र है। आपने दिया क्या? सिर्फ असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- ये सिर्फ असत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, अब आप बोलेंगे कि जल्दी करो। इधर मंत्री और उधर से मोहन मरकाम, तो बोलने वाले क्या बोलेंगे?

श्री कवासी लखमा :- ये केवल असत्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, वे आधा-अधूरा सत्य बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 के घोषणा पत्र को आधा-अधूरा पढ़ रहे हैं।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- कौशिक साहब, आपका भाषण जारी रखें। रजनीश जी, इसके बाद अभी आपकी ही बारी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो इतने रूपये का प्रावधान है, ये आप कई लोग ट्वीटर वगैरह में भी लिख रहे हैं और इसे कई लोग बोल रहे हैं। अब एक ने लिख दिया तो सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। भैय्या, ये मांग के अनुसार है। जितनी मांग आयेगी, उतना हम देंगे और अगर है तो उसके बाद अनुपूरक में जोड़ेंगे। इससे आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? टेंशन क्यों है?

समय :

6.28 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपकी नीयत दिखा रही है। साढ़े 4 साल में आपको होश आया, जब चुनाव नजर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- नीयत नहीं। आप सुनिए। यह मांग के अनुसार है। यह आपको भी पता है। कौशिक जी, ये आपको भी पता है कि कैसे होता है? बजट में प्रावधान क्या होता है?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको अभी याद आ रहा है। वास्तव में यदि इस सरकार की नीयत ठीक है तो आपको वर्ष 2019 से लेकर अभी तक हिसाब करके आपको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। आप लोगों ने बेरोजगारों को भी छलने का काम किया है। उनको भी आपने नहीं छोड़ा है।

श्री उमेश पटेल :- आप सुनिए तो। बेरोजगारी भत्ता में जितना बजट का प्रावधान है, वह काफी है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो उसको अनुपूरक में लाया जायेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- कुछ नहीं लाया जायेगा।

श्री उमेश पटेल :- आप ट्वीटर ट्वीटर खेल रहे हैं। आप क्या-क्या बोल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये अंतिम बजट है। इसके बाद आपके पास कुछ है नहीं।

श्री उमेश पटेल :- उसके बाद अनुपूरक भी आयेगा। आप टेंशन मत लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके पास कुछ भी नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- ये 6 महीने अभी बचा है। अनुपूरक में पता चलेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उनकी कुर्सी की थोड़ी जांच कराइए। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट। जब मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था। मैंने यही कहा था कि ऐसे मंत्री को भी हम लोग चला लेंगे। तो ऐसे मंत्री को चलाएं इसका ये मतलब नहीं है कि अपने प्रश्न के दिन में अपने विषय के दिन में चुप रहो।

श्री अरूण वोरा :- कौशिक जी, समझे। नौकरी के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया है। आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ नौकरी देने के मामले में सबसे आगे है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, हम लोग बोल रहे थे कि कुछ अकबर साहब से सीखो। अब ये तो अकबर साहब से नहीं सीख पाये, पर इनसे अकबर साहब कुछ सीख गये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद स्कूल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। स्वामी आत्मानंद क्या हैं, कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ढिंढोरा नहीं, हकीकत है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, एक मिनट अभी आपको बता देता हूं। 2 लाख 38 हजार बच्चे हैं। उसके बाद में आपने 6 जनरी को विधान सभा में बताया कि व्याख्याताओं के 871, शिक्षकों के 444, सहायक शिक्षकों के 442 पद रिक्त हैं । लेकिन इनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं है । जो हिंदी मीडियम स्कूलों में हैं उनको आपने नई स्कूलों में शिफ्ट कर दिया । उसके बाद अपनी ताकत पर चलाते । आप डी.एम.एफ. की राशि और उसके बाद कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं कि कलेक्टर जाने कैसे चलाएंगे, यह कलेक्टर की जवाबदारी है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, राज्यपाल के पास जाएंगे, जब आरक्षण पर साइन होगा तभी तो होगा ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आरक्षण विधेयक पर साइन कर दीजिए अभी कम्प्लीट हो जाएगा ।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिएगा, आधा घंटा हो गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जो पद खाली हैं इन पदों को भरना चाहिए ना । आवास योजना - आवास योजना में 16 लाख, 60 हजार 906 आवास का लक्ष्य दिया गया । कब, ये जो बात करते हैं कि हमने 8 लाख आवास दिया है । आपने 8 लाख नहीं दिया है, 8 लाख आवास जो बने हैं वे पूर्ववर्ती सरकार के समय के हैं, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के समय के हैं । इन्होंने जो किया है वह भी बता देता हूं आपको । इनके 2019 से लेकर 16 लाख 60 हजार 966 आवास का लक्ष्य केन्द्र सरकार ने दिया । 13 लाख, 52 हजार 51 आवास आज तक राज्यांश की राशि नहीं दे पाए ।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भइया, मेरी बात तो सुनिये । मैं आपकी सुनता हूं आप मेरी नहीं सुनेंगे । आदरणीय सुनिये तो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इन्होंने बनाया कितना, कुल मिलाकर 82 हजार 900 आवास ही इनकी चार साल की उपलब्धि है । चार साल में प्रधान मंत्री आवास में 16 लाख स्वीकृत आवास में से 82 हजार 900 आवास बना, ये इनकी क्षमता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, सारी बातें पूर्व वक्ताओं द्वारा आ गई हैं । आप खत्म करिएगा ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें राज्य और केन्द्र का कितना अंश है यह बताइए और पहले कितना केन्द्रांश मिलता था, अभी कितना मिल रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- पहले जितना मिलता था, अभी मिल रहा हे ।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, नहीं मिल रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अरे, तुम बना ही नहीं पा रहे हो तो कहां से मिलेगा?

श्री अमरजीत भगत :- पहले 75 प्रतिशत तक मिला है ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- पहले 90/10 मिलता था ।

श्री अमरजीत भगत :- जब से मोदी जी की सरकार आई है केन्द्रांश घटा दिया है । आप एक तरफ मुंह बंद कर देते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि हँसो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नाम बदलना और घटाना इनका काम है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- केवल बंगाल और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है । गरीबों को मकान मिल रहा है लेकिन केवल बंगाल और उसकी नकल कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ को गर्त में ले जा रहे हैं । सभापति महोदय, यह सरकार कर्मचारियों को डी.ए. देने की स्थिति में नहीं है । केन्द्र सरकार के देने के बाद एक साल, डेढ़ साल, दो साल के बाद ये दे रहे हैं । हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 हजार करोड़ का घाटा हुआ है, केवल इस सरकार के कारण ।

श्री कवासी लखमा :- उनको देने वाले पैसे को अडाणी को दोगे तो क्या होगा?

श्री धरमलाल कौशिक :- अनियमित कर्मचारियों को नियमित तो कर नहीं पाए। संविदा कर्मचारियों को इन्होंने छलने का काम किया । जो आंगनबाड़ी की बात बोल रहे हैं ना, इन्होंने अपने घोषणा पर में कहा था कि कलेक्टर रेट देंगे । कलेक्टर रेट यदि देते तो समय-समय पर वृद्धि होती रहती । उसके बाद उनको नौकरी मिलती । वे नियमित हो जाते तो आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर उपकार नहीं किया है, उनको धोखा देने का काम किया है क्योंकि आपने उनका आगे का रास्ता ब्रेक कर दिया है । जिससे वे जाकर आगे बढ़ सकें ।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिएगास ।

श्री कवासी लखमा :- 15 सालों में आपने कितना दिया था कौशिक जी । हम लोगों ने 4 सालों में ही 10 हजार कर दिया । इस उम्र में असत्य मत बोलो, पाप लगेगा । पाप लगेगा पाप ।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिएगा । सारी बातें पहले वक्ताओं के द्वारा आ गई थीं ।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भइया, अधर्म वाली बात मत करिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति जी, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2022-23 में जो शिक्षा में खर्च हुआ । छत्तीसगढ़ में 18.9 प्रतिशत, आसाम में 20.1 प्रतिशत । स्वास्थ्य पर जो खर्च हुआ, छत्तीसगढ़ में 6.02 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 7.01 प्रतिशत, उत्तराखंड में 7.04 प्रतिशत, गोवा में 9.01 प्रतिशत । यह हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति है ।

श्री कवासी लखमा :- गोवा में चुनाव लड़ोगे क्या । तुमको गोवा में लड़ना है क्या बताओ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सब जगह की बताते हो ना तो मैं कम से कम उन राज्यों की बता रहा हूं। हमारी सरकार जो काम कर रही है वह कैसे काम कर रही है।

श्री कवासी लखमा :- भाई, यहां छत्तीसगढ़ की बात करिए। आप लोग कितनी आत्मानंद स्कूल खोले थे ? जगरगुंडा की 3 हजार स्कूल को बंद कर दिए। उसको बताईए। जगरगुंडा, आम्रपल्ली की बात कीजिए। वह छत्तीसगढ़ में है। आप गोवा की बात क्यों कर रहे हो ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, चौबे जी नहीं हैं, मैं चौबे जी से पूछना चाहता हूं। यह स्वावलंबी गौठान है, स्वावलंबी का मतलब है कि अपने पैरा पर खड़ा होना, आर्थिक रूप से सक्षम होना। जब आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो यह साढ़े सात सौर रूपये अध्यक्ष को देना, 500 रूपये उनके सदस्यों को देना, हमारे जो निर्वाचित पंच हैं, उनका 200 रूपये है।

श्री कवासी लखमा :- 500 रूपये है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने अभी बढ़ाया है, उनको दिया नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- 500 रूपये दे रहे हैं। जनपद सदस्य को पांच हजार रूपये दे रहे हैं। आपके वार्ड पार्षद को 7 हजार मिलता था, अब 15 हजार रूपये मिल रहा है। कौशिक जी, आपका तन्ख्वाह भी बढ़ा दिए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- विभाग का असर आ गया है। टेस्टिंग की आवश्यकता है।

श्री कवासी लखमा :- असत्य बोलना पसंद नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि यदि गौठान स्वावलंबी बन गया है तो उनको पैसे देने की आवश्यकता क्यों ? यह अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ी बांट रहे हैं। यह रेवड़ी बांटने का काम है। जब स्वावलंबी गौठान को पैसा देना पड़ रहा है तो बाकी गौठानों की क्या

स्थिति होगी ? इनकी गोबर खरीदी की क्या स्थिति होगी ? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान है, जो निर्वाचित होकर आए हैं, उनको दो सौ रूपये मिल रहा है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मनोनीत हुए हैं, उनको 500 रूपये मिल रहा है। यह हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान है।

श्री कवासी लखमा :- आप वहां जाकर देखिए। मैंने देखा है, वहां ले जाऊं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति जी, यह अच्छा नहीं है। आप उनको समझाईए। हमारे वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, ऐसा टोकाटाकी बार बार करना ठीक नहीं हैं। आप आसंदी से निर्देश जारी करिए।

श्री कवासी लखमा :- नहीं, 200 के लिए असत्य क्यों बोलेंगे, आप ही बताईए 500 रूपये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी चार साल चैन की नींद से सोए रहे और अभी उनको याद आ रहा है कि सरप्लस स्टेट इनके आने के बाद में माईनस में कैसे चली गयी। हमने 15 साल में 1 घंटे की कटौती नहीं की है। यह 5 बजे से ले करके 11 बजे तक की कटौती कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- नेता जी, 40 मिनट हो गये हैं, समाप्त करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक मेगावाट बिजली के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ है। अभी नींद से जगे हैं, जब हर बार उठा रहे हैं, टोकन, कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 25 करोड़ रूपया दिया है, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बहादुरी की है, आपको बधाई। साढ़े चार साल में जो स्थिति आई है कि पहला ताप विद्युत का उन्होंने 25 करोड़ रूपये बजट रखा है।

सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उस दिन बोल दिया था तो गुरू जी नाराज हो रहे थे। भ्रष्टाचार का अड्डा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का केवल चरने के लिए है। जब पहले ही उसकी निविदा हुई तो मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री को लगा कि यह बदनामी हो रही है। इसलिए इनको जिले को दे दीजिए और जिला में कांग्रेस के कार्यकर्ता जी खा लेंगे। आज क्या स्थिति है ? इसमें अनेक लोगों का प्रश्न आया है। सत्ता पक्ष के लोगों का प्रश्न आया है। हम लोगों का प्रश्न आया है। पाईप है तो पाईप की स्थिति ऐसी है कि गुणवत्ताविहीन है। उसमें गुणवत्ता है ही नहीं। जो लक्ष्य निर्धारित किया उससे कोषों दूर है। यह जो निर्धारित किया गया था, सितंबर 2023 में उसकी पूर्णता है। यदि वृद्धि हुई होगी तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। उसके बाद आज जो स्थिति है कि आप 20

लाख में भी नहीं पहुंचे हैं। आपको 50 लाख घरों में पाईपलाईन के द्वारा पानी पहुंचाना है। आपने उसके लिए 2 हजार करोड़ रूपये बजट रखा है।

सभापति महोदय :- 40 मिनट हो गया, आप समाप्त करिए। अभी दो और सदस्य को बोलना है। नेता प्रतिपक्ष जी और मुख्यमंत्री जी को बोलना है, कृपया समाप्त करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, सडकों की जो हाल है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आपने 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यह 500 करोड़ में क्या स्थिति बनेगी, आपको यह अंदाजा है। मैं एम.ओ.यू की बात नहीं करूंगा, जब एम.ओ.यू. की बात करूंगा कि कितने लोगों का एम.ओ.यू. हुआ है ? उसमें कितने लोंगों की पूंजी आनी थी और कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला ? वह तो आप बता नहीं पाएंगे, तो मोहम्मद अकबर जी को इसका जवाब देना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरा अंतिम विषय है। परिवहन, रोड, ब्रिज, ऊर्जा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। परिवहन के लिए वर्ष 2022-2023 के पुनरीक्षित बजट में 7 हजार 200 करोड़ रूपये प्रस्तावित था और वर्ष 2023-2024 में 6 हजार 617 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। इस बार 8 प्रतिशत की कमी है। आपके रोड, ब्रिज के लिए वर्ष 2022-2023 में पुनरीक्षित बजट में 7 हजार 100 करोड़ रूपये प्रस्तावित था और वर्ष 2023-2024 में 6 हजार 595 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। इस बार 8 प्रतिशत की कमी है और उसके बाद आपके ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2022-2023 के पुनरीक्षित बजट में 6 हजार करोड़ रूपये प्रस्तावित था और वर्ष 2023-2024 में..।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- दो मिनट, माननीय सभापति महोदय, मैं अपने अंतिम विषय पर आ रहा हूं। आपने स्वास्थ्य पर बाकी चर्चा तो की है लेकिन इस सरकार की जो प्राथमिकता है, शिक्षा के क्षेत्र में यह पीछे है। आपके पी.एच.ई. विभाग में यह पाइप लाइन में पीछे है। पाइन लाइन घर में लग गया है इसलिए आप उसमें पीछे हैं। आप बाकी योजनाओं में पीछे हैं। आप आगे किसमें हैं ? केवल शराब में आगे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार शराब में राजस्थान और झारखण्ड को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2021-2022 में शराब से 5 हजार 100 करोड़ की प्राप्ति हुई। वर्ष 2022-2023 में 6 हजार 400 करोड़ रूपये की प्राप्ति और अभी 6 हजार 700 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। यह एकाएक जो वृद्धि हुई है यह 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यह जो 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्या यहां शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई है या यहां पर ई.डी. आ गई, उसके कारण 32 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद। श्री आशीष कुमार छाबड़ा जी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट है यह विकास और भरोसा का नहीं बल्कि धोखे का बजट, प्रदेश के विकास को पीछे ले जाने वाला बजट और यह जितना घोषणा पत्र जारी किये, वादा निभाने का नहीं वादाखिलाफी का बजट है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, धोखा तो आपके साथ हुआ है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2023-2024 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार हमारे महापुरूषों, संत, महात्माओं के रास्ते में चलकर सभी वर्गों का ध्यान रखकर एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।

ऐसा राज चाहूं मैं, सबको मिले अन्न।

छोटे-बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभ वर्गों को साधने का काम किया है। मैं विपक्ष के साथियों को दावे के साथ बोल सकता हूं। आप यह बोल रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अंतिम बजट है। यह पंचम विधान सभा का अंतिम बजट हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ प्रदेश की जनता अभी बतौर मुख्यमंत्री वह यहां पर 20 बजट और प्रस्तुत करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश के किसानों का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रदेश की महिलाओं का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रदेश के बेरोजगारों, युवाओं का आशीर्वाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ है क्योंकि इन्होंने इस बजट के माध्यम से उनका विश्वास जीतने का काम किया है। भूपेश है तो भरोसा है। यह भरोसे का बजट है और इस भरोसे के बजट का इंतजार पूरे प्रदेश की जनता कर रही थी। इस भरोसे के बजट पर खरा उतरने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 6 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में माध्यम से किया है। मैं उनको बहुत-बहुत साधूवाद देता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वर्ष 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधान सभा के चुनाव हुए, उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे विपक्ष के साथियों ने प्रदेश को ठगने का काम किया। जब भी कोई राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखती थी तो जनता कभी भी उन पर विश्वास नहीं करती थी। सबको ऐसा लगता था कि हमने 15 सालों तक घोषणा पत्र को देखा। 2100 रूपये समर्थन मूल्य और 300 रूपये बोनस और 15 सालों तक इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बड़ी-बड़ी बातें की। लेकिन इन्होंने एक

वायदे का पूरा करने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष, जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से यह वायदा किया कि जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम किसानों का कर्जा माफ करने का करेंगे। मैं एक घटना बताना चाहता हूं यह 2017, दिसम्बर-जनवरी की घटना है । उस समय मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कठियागांव पड़ता है । वहां पर अच्छे परिवार से जुड़ा हुआ किसान है-रामाधार साहू। उसने मात्र 80 हजार रूपए के कर्ज तले दबकर आत्महत्या की थी । उन्होंने पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि इस सरकार से मेरा भरोसा उठ चुका है, सरकार की रीति-नीति के नाम से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन मैं माननीय भूपेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कुछ घंटों में उन्होंने 17 लाख, 96 हजार किसानों का 8744 करोड़ रूपए का कर्ज माफ किया, जिससे किसानों के प्रति कांग्रेस की सरकार का भरोसा जागा है । (मेजों की थपथपाहट) किसानों ने यह सोचा कि छत्तीसगढ़ में अब कोई सरकार बनी है, जो किसान की बात सुनेगी । लोगों ने पहली बार महसूस किया है कि छत्तीसगढ़ में किसान के बेटे ने बजट बनाया है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री है । इस सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति किसानों की उम्मीद जागी है, किसानों का विश्वास जागा है ।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लोगों ने 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल एक मुश्त किसानों को दिया, लेकिन देश में एक तुगलक शाही सरकार जो देश में राज कर रही है, वहां से एक फरमान जारी हुआ कि अगर कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक में धान की खरीदी करेगी तो केन्द्र के पुल में उनका चांवल नहीं लिया जाएगा । हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दृढ़ इच्छाशक्ति, उनका संकल्प था कि मैंने किसानों से वायदा किया था, प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया है कि 25 सौ रूपये मतलब 25 सौ रूपये में किसानों का धान खरीदूंगा । मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, मंत्रिमण्डल को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की, जिसके माध्यम से जो अंतर की राशि थी, वह डायरेक्ट किसानों के खातों में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने किया है । मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं । अभी कुछ देर पहले विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि पैसा केन्द्र से आता है, पैसा दिल्ली की सरकार से आता है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल सत्ता में रही, जिसमें खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से अधिकतम 57 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी 15 साल की इनकी सरकार ने की और हमारी सरकार के 4 साल में, जबकि बीच में 2 साल कोरोना का रहा । खेती के प्रति किसानों का विश्वास जागा है, खेती के प्रति उत्साह जगी है । उनको यह यकीन हुआ है कि कोई सरकार है, जो हमारे अन्न का, हमारी मेहनत की, हमारे खून-पसीने का उचित दाम देगी । उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया और वर्ष 2022 में 23 लाख, 42 हजार किसानों से

107 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हमारी सरकार ने की । ये आंकड़े बताते हैं । (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी एक ही बात करते हैं-झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ । लेकिन प्रदेश की जनता यह जान चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है । उनको मालूम है कि अगर किसानों के लिए कोई योजना बना सकती है तो कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बना सकती है। इस साल भी राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी के लिए बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं भूमिहीन खेतिहर किसान न्याय योजना के बारे में कहना चाहता हूं । यह एक ऐसी योजना है, जिसका कल्पना प्रदेश में किसी ने नहीं की थी कि जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनके भी खाते में हम डायरेक्ट पैसा डालेंगे। पहले जब सरकारें बजट प्रस्तुत करती थीं, 15 साल के मुख्यमंत्री जी जब इस सदन में बजट को लाते थे तो जैसे ही बजट पेश होता था, वैसे ही बजट आने के बाद तुरंत दलाल सक्रिय हो जाते थे कि किस मद में कितना पैसा मिला है ? हम लोगों को कहां सप्लाई करनी है, कहां मोबाईल, टिफिन, जूतों की सप्लाई करनी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल से वह दलाल अपने घर में बैठ गए हैं, उनको मालूम है कि ये कांग्रेस की सरकार है, हमारी बात बीच में चलने वाली नहीं है, किसानों और गरीबों के खाते में सीधा पैसा डालने का काम कांग्रेस की सरकार करने जा रही है । भूमिहीन खेतिहर किसान न्याय योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थी, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको नगर पंचायत में भी लागू किया है, जिससे हमारे नगर पंचायत में भी बहुत सारे भूमिहीन मजदूर हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा । उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने शिक्षित बेरोजगारों की चिन्ता की । उन्होंने 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 25 सौ रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से युवाओं में इस सरकार के प्रति विश्वास जागा है । इसी तरीके से एक बहुत सुन्दर राजीव गांधी युवा मितान क्लब का भी गठन कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। पहले हमारे गांव के जो युवा थे, उनकी उर्जा का दुरूपयोग हो रहा था। वे लगातार गलत रास्तो में जा रहे थे। लेकिन जब से राजीव गांधी युवा मितान क्लब का गठन हुआ है, युवा की सक्रियता, भागीदारी गांव के विकास के प्रति बढ़ी है। वह सरकार की योजनाओं को भी देख रहे हैं। सरकार की योजना और अन्य गतिविधि, खेल की जो गतिविधि है, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति गांव में जागरूकता लाने का काम हमारे युवा कर रहे हैं। यदि युवा के उर्जा का किसी ने सदुपयोग किया है तो हमारे कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। जो लगातार युवाओं को दिशा देने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री अशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, मैं तो अभी बस बोलना शुरू किया हूं। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए साधुवाद देना चाहता हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम यहां पर किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलकर किया है। आज हम जिस गांव में जाते हैं, हर गांव से यही मांग आती है कि हमारे गांव एक आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलना चाहिए। पूरे प्रदेश में 247 अंग्रेजी माध्यम स्कूल और 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरूआत हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, मैं आपको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमने 4 साल में 247 स्कूल पहले खोले हैं और इस साल एक सौ से अधिक स्कूल खोलने जा रहे हैं।

सभापति महोदय :- आशीष जी, समाप्त करें।

श्री अशीष कुमार छाबड़ा :- आज विपक्ष के साथी बोल दें कि इस प्रदेश में गरीबों के लिए 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाया हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई 4 स्कूल नहीं बता सकते, जो अंग्रेजी मीडियम के गरीब के बच्चों के लिए, मजदूर के बच्चों के लिए बनाया हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये हो गया।

श्री अशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, आपका थोड़ा सा सरंक्षण चाहता हूं। हम लोग नये सदस्य हैं, हम लोगों को मौका कम मिलता है, थोड़ा सा मौका दीजिये। तो एक बहुत अच्छी सुन्दर योजना, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हमारी सरकार के माध्यम से आई है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब रहा करती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, उस सरकार में शिक्षा कभी प्राथमिकता नहीं रही। उनके द्वारा लगातार स्कूल बंद करने का काम किया गया। हमारी सरकार और उस सरकार में अंतर यही है। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। जब केन्द्र में हमारी सरकार हुआ करती थी, तो उस समय भी शिक्षा के अधिकार का कानून लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने ही लाया था। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चों को, हर गांव, गरीब के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हो, हिन्दी मीडियम से पढ़ाई हो। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाया करते थे स्कूलों के हालात बड़े खराब हुआ करते थे। हमारे बहुत सारे विधायक साथी भी जीतकर आये हैं। हम जहां भी जाते थे, वहां एक ही मांग होती थी कि स्कूल का भवन जर्जर है। कई जगह तो भवन ही नहीं था, बच्चें धूप में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। लेकिन इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लगभग 800 करोड़ रूपया जारी किया है, जिसमें जितने भी भवन विहीन शालाएं हैं, जहां

अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है, वहां अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हो। जहां मरम्मत की आवश्यकता हो, वहां मरम्मत हो। जहां अहाता की आवश्यकता है, अहाता का निर्माण हो। इस साल भी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत लगभग 500 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में रखा है, ताकि स्कूलों के मरम्मत की व्यवस्था हो सके। बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिल सके, जिसमें बच्चें अच्छा वातावरण में रहकर अच्छी, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं जो चाहते हैं कि प्रशासन और जनता में ज्यादा दूरी न हो। ज्यादा से ज्यादा इकाईयां जनता के करीब हो। इसी उदेद्श्य के साथ हमारी सरकार आने के बाद लगातार नवीन जिलों का गठन, नवीन तहसीलों का गठन, नवीन उप तहसीलों का गठन किया गया है। इतिहास में पहली बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में हिम्बोरी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, उसको मुख्यमंत्री जी ने उप तहसील बनाया और एक साल के अंदर ही तहसील बनाने की घोषणा की। आज वहां तहसील कार्यालय प्रारंभ हो चुका है। इस समय बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 नवीन तहसील की भी घोषणा बजट के माध्यम से की है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बजट के माध्यम से मेडिकल कालेज की भी यहां पर घोषणा की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बेमेतरा वासियों की भी बड़ी उम्मीद है, आस है। मुख्यमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपके माध्यम से आने वाले समय में बेमेतरा जिले को भी मेडिकल कालेज मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं विपक्ष के साथियों के लिए एक अंतिम बात बोलना चाहता हूं।

" है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए,
जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए,
जो रोज बदलते हैं चेहरे, नकाबों की तरह,
जनाजा बड़ा धूम से उनका निकलना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 2022-2023 का जो बजट पेश हुआ है, उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2018 से लेकर आज वर्ष 2023 नया सरकार के गठन के पश्चात् यदि हम देखें कि 89 हजार करोड़ के बजट, जो आज 1 लाख 21 हजार करोड़ के बजट पेश होये हे, यदि एमा हम देखी, कोई राज्य के विकास के लिये राजस्व व्यय को छोड़कर पूंजीगत व्यय काहे वोखर ध्यान दिये जाये । वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-202, 2022-2023, 2023-2024 में यदि हर साल के देखी त जौन बजट अनुमान हे, ओमा

पूंजीगत व्यय हर साल कम होय हे । बजट पेश होये के दिन जब बड़े-बड़े विज्ञापन आईस, सरकार हे त भरोसा हे, भूपेश जी हैं त भरोसा हे, कांग्रेस के साथी जब सदन में आईन त बड़ा सबके चेहरा खिले, खिले रहिसे, बहुत बड़े-बड़े आज घोषणा होने वाला हे । जौन जौन बचे है, सब एव मस्तु हे । भले सब कागज म रही, जैसे भी रहि, लेकिन सब एवमस्तु होने वाला हे, बजट भाषण के बाद निकलिन त सबके चेहरा लटके हुये रहिसे, आज जरूर बोलथें, भाई आशीष छाबड़ा जी 2017 के बात याद करथ रहिन हे । शायद 2020 के बाद याद नई हे, एक बेरोजगार मुख्यमंत्री के सामने म जाके आत्मदाह कर लेथे ।

श्री उमेश पटेल :- रजनीश जी, चेहरा लटका है, मैं तो सामने से देखा । जैसे बजट भाषण शुरू हुआ तो सारे नेताओं का चेहरा चमक रहा था, लेकिन बजट भाषण के खत्म होते होते सब का डाउन हो गया था ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- एती बर वही बात होय हे । वही बात मैं काहथंव, जेन बात ला आप करथव ।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ताम्रध्वज साहू जी की चर्चा कल है, आज है, जब भी शुरू होगी । जब से सत्र शुरू हुआ है, आज सबसे ज्यादा देर तक बैठे हैं और हाऊस से बाहर जा ही नहीं रहे हैं और दिन भर पढ़ रहे हैं। आप उनको इतना टेंशन क्यों दे दिये हो । हम लोग कोई आरोप-वारोप नहीं लगायेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- क्या है, सभापति जी । उनको मालूम हो गया है कि ओपनिंग आप करने वाले हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग आरोप-वारोप नहीं लगायेंगे । बोलो तो उनका बजट गिलोटिन में पास कर देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- अभी जितने भाषण हुये, उसमें आंकड़े आपने प्रस्तुत किये, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने किया, वह भूल गये थे कि वह नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन पूरे आंकड़े उन्होंने रखे हैं । तैयारी कर रहे हैं । जैसे ही अनुदान मांग में चर्चा होगी, आप आंकड़ें रखोगे तो एक-एक आंकड़े का जवाब देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, लेकिन आप टेंशन फ्री करिये ।

श्री भूपेश बघेल :- वह कभी टेंशन में नहीं रहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :-आप बोलो तो हम लोग गिलोटिन में पास कर देते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- देखों, कैसे मुस्कुरा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- निकल ही नहीं रहे हैं, सुबह से कागज ही पकड़े हैं । कई बार आते-जाते टोक चुका हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- 72 साल के उम्र में 36 साल की मुस्कान है । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है और आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और यहां के जितने विधायक, इन सभी को बात रखने का अधिकार है और शायद मैं बात रखा तो मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा है । नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए ।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत अच्छा लगा, नेता प्रतिपक्ष रहते तो ज्यादा अच्छा लगता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष से बड़ा पद तो यह है कि वह पूर्व विधान सभा अध्यक्ष हैं । यदि पूर्व विधान सभा अध्यक्ष हैं तो एक्सटेंपोर हैं भई । उनके पास अनलिमिटेड टाईम है ।

श्री भूपेश बघेल :- देख-देख के पढ़ रहे थे ।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भईया, बात को दिल से ले लिये ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिये ।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- द्वितीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्यय के पत्रक पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं बतात रेहेंव जब आशीष भाई किसान के आत्महत्या के बारे में बात करिस, शायद दुर्ग मा जौन होय हे, नकली बीज के कारण जौन किसान आत्महत्या अभी करे रहिसे, वो शायद याद नई रहिसे ।

समय :
7.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, जोन बजट मा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य पूंजिगत जोन व्यय है। मैं पिछले तीन, चार साल के बाद खाली जो प्रदेश में होये हे ओला रखे हव। अभी यदि देखही तो 7 मिडिल स्कूल, 8 हाई स्कूल और 17 हायर सेकेण्डरी स्कूल, यह बजट में हे, जोन बताथे कि छत्तीसगढ़ मा शिक्षा मा कतका ध्यान दिये जात हे। सिर्फ आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद स्कूल करके बाकी हिन्दी मीडियम के जोन लाखों स्कूल हे, लाखों बच्चे मन के भविष्य अंधकार मा डाले के लगातार प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार आग्रह भी होये रिहीस हे और ओकर घोषणा है कि हाई स्कूल का

हायर सेकेण्डरी मा उन्नयन करे जाहे, वह लगातार 4 साल से नहीं हो पाथे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कतका प्राथमिकता है, यह बार-बार दिखथे। बार-बार बात आथे, जब राज्यपाल जी के अभिभाषण होये रिहीसे, उहु मा केन्द्र सरकार के जोन शासकीय अनुदान के बारे में बता रहा हूं। अभी सिर्फ आंकड़ा दे देथव कि वर्ष 2019 में यह सरकार का 47 हजार 991 करोड़, वर्ष 2020-21 मा 48 हजार 661 करोड़ और वर्ष 2021-22 मा 44 हजार 350 करोड़, इनको 1 लाख 40 हजार 700 करोड़ के कई प्रकार के जो अनुदान मिलथे, वह सब मिले हे। लेकिन यह बताये जाथे कि मोदी जी के आये के बाद हमका यह राशि रोक दिये गे हे, जी.एस.टी. रोक दिये गे हे। कोई कहिथे 55 हजार करोड़ हे, कोई कहिथे 3 हजार करोड़ हे, वास्तविक आंकड़ा आज भी नहीं बताये हे कि कतका हे। माननीय मोदी जी के आये के बाद ये बात का नइ बताये जाये कि जोन 32 प्रतिशत कर रहिसे ओका बढ़ाकर राज्य मन का 42 प्रतिशत, एक ही बार में 10 प्रतिशत बढ़ा दिये गइस। अभी छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान बजट है, वह 8 हजार करोड़ के अतिरिक्त बजट दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ बर 17 नये रेल परियोजना की स्वीकृति किये गे हे। जब माननीय नितिन गडकरी जी जब आये रिहीन हे, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रिहीन हे वह कह के गये हे कि आप हमको सहयोग करो, जमीन बताओ, रोड बताओ, 01 लाख करोड़ का काम सिर्फ सड़क परिवहन में करूंगा। लेकिन आज भी यह सरकार काम नहीं दे पाथे, ये नहीं बता पाथे कि एक लाख करोड़ के का रोड बनाना हे। छत्तीसगढ़ मा जतका भी काम चलत हे, जोन भी काम हो रहे, वह सब केन्द्र सरकार द्वारा पोषित काम ही होथे।

माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान योजना के जोन शुरूआत होये रिहीसे वह छत्तीसगढ़ के जांगला ले शुरू होये रिहीसे। पूरा देश ओका वरदान के रूप में लेहे रिहीसे और वरदान के रूप में माना थे। लेकिन हम सब के लिये दुर्भाग्य है कि ओला एक बड़े योजना बनाये जाही करके आज भी ओ आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ में बंद होने के कगार पर है। हम रोज देखथन कि रोड एक्सीडेंट होथे, मृत्यु होथे, गंभीर रूप से घायल होथे। उनको किसी प्रकार के योजना मा लाभ नहीं मिल पाथे। लगातार हमर तीर, आप सब मन तीरे आत रहिथे। लेकिन यह सरकार एक बहुत बड़ी योजना जोन गांव ,गरीब और हर वर्ग से जुड़ी हुई योजना हे। ओकर बंद कर देहे।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, बस अपन क्षेत्र के दो-तीन विषय बोल के वादा तो सब बता दिहीन। मैं दो-तीन विषय बता देथो।

सभापति महोदय :- जल्दी खत्म करिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक बिलासपुर मा बेलतरा विधान सभा में एक क्षेत्र हे फदहाखार गणेश नगर। वो एक अइसनहा क्षेत्र हे, जोन लोक सभा मा वोट डालथे, विधान सभा मा वोट डालथे लेकिन ओकर बाद वह कोई वार्ड के वोट नहीं करै, कोई पार्षद नहीं चुनै, कोई पंच नहीं

चुनै। वह न ग्राम पंचायत में हे, न नगर निगम में हे और उंहा यदि कोई भी मूलभूत काम स्वीकृत करना है तो विधायक निधि से, सांसद निधि से, चाहे अन्य जोन भी निधि से, उंहा कोई काम नहीं हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी भी रहिन हे। मैं आग्रह करिहव, वह बहुत बड़ा वन एरिया हे, रिजर्व एरिया हे, लेकिन 3 हजार वोटर हे अउ 10 हजार के आबादी हे। एक साइड बिलासपुर हे, एक साइड मस्तूरी, एक साइड बिल्हा अउ बीच में बेलतरा। आपसे आग्रह है कि एकर लिये जोन बसाहट हे, वहां कम से कम उनकी मूलभूत सुविधा के लिये ओकर लिये काम हो सके। नलकूल खनन हो सके। रोड बन सके।

सभापति महोदय :- चलिये रजनीश जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, बस दो मिनट। एकर लिये मोर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह हे कि एकर बर कोई न कोई रास्ता निकाल कर के , वह क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र हे। जेकर लिये रास्ता निकाला जाये। जे मा उनको कम से कम मूलभूत सुविधा मिल सके। बिलासपुर नगर निगम का क्षेत्र अतका बड़े कर दिये गे हे कि वो पांच विधान सभा के एक क्षेत्र बन गे हे। वर्गफल की दृष्टि से वह दुगुना से ज्यादा हो गे हे। जनसंख्या दुगुना से ज्यादा हो गे हे। लेकिन पिछले चार साल से सिर्फ 25 करोड़ रूपये गये हैं। जबकि पंचायत रिहीसे तो पंचायत मा नगर पालिका, नगर पंचायत मन 25-25 करोड़ रूपये के कर लेत रिहिन हे। दू-दू, तीन-तीन ठन नगर पंचायत, नगर पालिका, बड़े-बड़े ग्राम पंचायत शामिल हो गे हे। ए विषय ला में बार-बार उठावत हों कि उहां 10-20 करोड़ रूपए में नइ होए। बिलासपुर नगर निगम ला कम से कम 200 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान करे जाए। तब अतका बड़ क्षेत्र में ए काम हो पाही।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक शब्द बोलके बात ला खत्म करहूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी आत्मानंद विद्यालय के बात चलत रिहिस हे। जो बिलासपुर के बेलतरा विधान सभा में साईंस कॉलेज हे ओकर बिना कोई पहिली के पूर्व सूचना के ओ ला आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम मा तब्दील कर दिये गिस। पूरा ओ क्षेत्र ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र हे। गांव-गांव के लइका मन आके ओ साईंस कॉलेज मा पढ़थे अउ उकर बड़े-बड़े उपलब्धि हे। उहां से बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लइका पढ़के गे हे, लेकिन एकाएक अंग्रेमी माध्यम होए के कारण अउ ओमन ला फार्म भरवाए जावत रिहिस हे कि आप चयन करो कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे नहीं तो आप यहां को छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाएंगे। तो बिना सोचे-समझे ओ ग्राम पंचायत क्षेत्र के आसपास हे, ओ मे बहुत दिक्कत होवत हे। हालांकि अभी ओ कोर्स, विषय रूक गे हे। लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट करवात हों कि उहां स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय खोले जाए, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करके, नया बिल्डिंग, नया सेटअप करके खोले जाए।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- रजनीश भाई, आप चिंता मत कीजिए। सब हिन्दी मीडिम वाले भी साथ में पढेंगे।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद्। आप आश्वासन दे दे हौ।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक विषय बोलके बात ला खत्म करहूं। में दो तीन ठन वादा ला कर देथौ बस, जोन बोले हे। जोन सरकार के घोषणा रिहिस हे में तीन-चार बिन्दु ला ले लेथौ। पूर्ण शराब बंदी के घोषणा रिहिस हे। होम डिलवरी शुरू हो गे हे। बेरोजगारी के भत्ता के घोषणा होए रिहिस हे अब ओमा क्राईटएरिया फिक्स कर दे गे हे, कब आही कैसे आही ? अभी कोई के मालूम नइ हे। किसानों के बकाया एक-एक दाना धान खरीदे जाही । दो साल के बोनस दिये जाही।

सभापति महोदय :- अब आपकी सारी बातें आ गईं। अब आप बैठिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं ए सरकार के बजट के विरोध करत हुए अपन बात समाप्त करथौ। माननीय सभापति महोदय, आप बोले के अवसर देव, एकर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 6 तारीख को वर्ष 2023-24 का आम बजट प्रस्तुत किया। हमने समाचार पत्रों में पहली बार इतना बड़े-बड़े विज्ञापन देखें। यह बजट के पहले दिन, बजट वाले दिन, बजट के दूसरे दिन विज्ञापन देखें। पता नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है। यह कौन सा ऐसा अंतरिक्ष है जहां से परी उतरने वाली है। माने यहां होगा क्या ? यह भरोसे, विश्वास का बजट है। क्या पहले 4 सालों का बजट अविश्वास का बजट था। क्या वह छलने, धोखे का बजट था। जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो कहा जाता था कि अमीर धरती के गरीब लोग। यह धरती अमीर है और इस अमीर धरती में गरीब लोग हैं। इन गरीबों के उत्थान का जिम्मा, जब वर्ष 2018 से आपकी सरकार बनी, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र के उन 36 बिन्दुओं में अंकित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बजट 5 हजार, 700 करोड़ रूपये का था, जब राज्य की स्थापना हुई। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 में कुल बजट 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपये का था और इस बार 1 लाख, 32 हजार 370 करोड़ रूपये का है। इस बजट में क्या है ? मैं इस बजट में दो-तीन बातों को छोड़कर कुछ भी नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं-

आज शेर बकरी को शाकाहार होने के फायदे गिना रहा है।

लोमड़ चोला बदलकर, शराफत का पाठ पढ़ा रहा है।

बिल्ली कहे चूहे से डर मत, मैं तो तेरी मौंसी हूं, भतीजे।

तो समझ लो जंगल में चुनाव आने वाला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, सदन के नेता का भाषण होगा। आपके लिए समर्पित है। हरियाणा की एक कहावत-

जाट कहे जाटिनी से, इसी गांव में रहना।

और ऊंट बिलाई ले गई तो हां जी, हां जी कहना।

यह आप लोगों के लिए समर्पित है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इस बजट में होगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। बजट में सिर्फ कागजी प्रावधान है। बजट का कोई क्रियान्वयन नहीं होने वाला है। इस सरकार की अवधि कितनी है? आज से गिने तो मात्र 6 महीने हैं। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में रखा था, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उसमें से कितने काम हुए हैं ? क्या पुराने बजट के कामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी जो प्रावधान था? क्या उसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी ? क्या उन कामों की निविदा हो गई थी? क्या उस बजट में जो प्रावधान था, उसके भूमिपूजन हो गये थे? क्या उन कामों के टेंडर हुए थे? क्या उसके वर्क आर्डर हो गये?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री बृहस्तप सिंह :- माननीय नेता जी, संभल कर रहियेगा। ऐसे ही ब्रेक करके कौशिक जी को उधर बिठा दिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, अभी जो अनुपूरक बजट आया है, उसको देखियेगा। राहुल गांधी जी से शहीद स्मारक का शिलान्यास हो गया। बिना एजेंसी तय हुए, बिना डिजाईन, बिना टेंडर के वह शहीद स्मारक का शिलान्यास हो गया। उसका आयोजन अभी चौथे बजट में किया है तो आप कहां बाकी कामों का पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी का तो ये हाल है।

श्री नारायण चंदेल :- मैं पिछले बजट के बारे में बात कर रहा था। राहुल जी आये होंगे। लेकिन माननीय सभापति जी..।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय नेता जी, माननीय अजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमने राहुल गांधी जी से शिलान्यास कराया और उसका बजट में अभी प्रावधान किया है। ये तो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब से विधायक विश्राम गृह का भूमि-पूजन करा दिये। आज तक वह बना नहीं, वहां complex बन गया है। वह आज तक नहीं बना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हमारी नकल कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, ये तो बनेगा। बन रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- शिलान्यास बिना अनुमोदन के, बिना बजट के, बिना एजेंसी के हो गया।

श्री भूपेश बघेल :- मैं वही तो कह रहा हूं। अजय जी, आप यह तो बताईये कि आपने राष्ट्रपति से शिलान्यास कराया, हिन्दुस्तान में इससे बड़ा कोई पद होता है। (शेम-शेम की आवाज) उनसे आपने शिलान्यास करवाया था। वह कहां है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डा. शिवकुमार डहरिया) :- उस जगह को जमीन दलालों को बेच दिया।

उच्च शिक्ष मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- नेता जी, आपका भाषण चल रहा है, इधर से कोई टोक नहीं रहा है। आपके ही लोग टोका टाकी करके आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, मैं तीन विभागों की जानकारी चाहता हूं। पिछले बजट में उसमें कितना खर्च हुआ है, वह आप बता देंगे। लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन और जल संसाधन, पिछले बजट का मात्र 03 विभागों का बता देंगे। मैदानी स्तर पर, सतही स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। वह कागजों में घूम रहा है। मैंने अपने क्षेत्र के 02 पुल-पुलिया का दो साल पहले जब प्रस्ताव दिया था तो इस बार फिर वह प्रस्ताव मांगने आ गये। मैंने कहा कि यह तो 02 साल पहले के बजट में आ गया है। वह बोले कि भैया, वह तो नामिनल बजट प्रावधान था, वह तो लेप्स हो गया है, आप फिर से प्रस्ताव दे दीजिए। यह बजट एक भ्रमजाल है। यह धोखे का बजट है। छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का बजट है। आपने अपने जन-घोषणा पत्र में क्या-क्या वादा किया था। उसमें से आपने कितना पूरा किया ? इस बजट में आपने कितने के लिए बजट प्रावधान रखा? सिर्फ आंगनबाड़ी को छोड़ कर बेरोजगार नौजवानों को भी आपने छलने का प्रयास किया। उसमें भी आपने कंडीशन डाल दिया। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नरवा, गरूवा, घुरूआ, बाड़ी, एकर ले ज्यादा मैं नइ जानव संगवारी। उसके लिए कोई बजट प्रावधान है क्या ? या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिल्ली तक इसके पोस्टर लगे हैं, होल्डिंस लगे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में जनसंपर्क विभाग का करोड़ों रूपये इस पर खर्चा हो रहा है, लेकिन इसके लिए बजट में कहीं उल्लेख नहीं है कि कितना प्रावधान आपने रखा है। यह कैसे संचालित होगा? आज गौठानों की क्या हालत है। गौठानों में गौमाता मर रही हैं। गौठानों में चारा नहीं है, पानी नहीं है, छाया नहीं है, चौकीदार नहीं है। ईलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। भूपेश जी, आपके जमाने में गौमाता मर गई गौठानों में। यह छोटी-मोटी बात नहीं है। पहले यदि एक गौ हत्या होती थी, एक गौ-माताएं कहीं मरती थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के हर गौठानों की स्थिति दयनीय है। नरवा, घुरूवा की क्या हालत है?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, मैं नेता जी को याद दिला दूं। इनको डॉ. रमन सिंह जी के समय में कवर्धा वाला, बेमेतरा वाला घटना याद होगा। उसको भी याद कर लीजिये। बालोद वाला भी बताईये।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- हमारे यहां जामुल वाला। चार जगह पूरा धान के भूसे में दबाकर रख दिये थे। उसके हड्डी को बेचे, मांस को बेचे, चमड़ा को बेचे, सबको बेचे और परपोड़ी के पास गांव में

बेचे। राजपुर के चौबे जी के क्षेत्र में बेचें। तीन जगह एक ही आदमी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पदाधिकारी, जो पूरा पैसा लेता गया, उसको खा भी डाला और गाय को मार कर बेच भी डाला।

समय :

7.17 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ-साथ नगर पालिका, जामुल के अध्यक्ष का भतीजा था। नगर पालिका अध्यक्ष किस पार्टी के थी, यह भी आपकी जानकारी में होगी।

श्री उमेश पटेल :- बृहस्पत सिंह जी, सबसे बड़ी बात कि वह भाजपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहा।

श्री बृहस्पत सिंह :- बहुत बड़े नेता थे भाई।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, मैं एक बात बता दूं। आप लंबी-लंबी मत दीजिये। आपकी उम्र 72 साल जान-बूझकर बताई गई है। इसको ध्यान रखिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- चाहो तो उसको बढ़ाकर बता सकते हो।

श्री अजय चंद्राकर :- आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उनका विशेष आग्रह है, विशेष कृपा है, विशेष प्यार है। आप चाहो तो जितना बढ़ाना है, बढ़ा लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- बताया जा रहा है कि आप सीनियर सिटीजन्स में भी 10 साल आगे बढ़ गये हो।

श्री नारायण चंदेल :- कुछ नहीं हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, आप रामपुकार जी की सीट केा देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, मैं तो आपको देखकर घड़ी को देख रहा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मुझे केाई सीट देखने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी का निर्देश होता है, उसको मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मैं आपको देखकर घड़ी को देख रहा हूं और कुछ नहीं किया।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, घड़ी को देखकर मुझे मत देखिये। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- घड़ी को देखकर आपको घड़ी-घड़ी देखने की इच्छा हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन चंद्राकर जी आपके साथ गणितबाजी कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह क्षेत्रीय प्रेम है बाबू।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सा विषय आया। जब भी कोई बात होती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं। वे केन्द्र के ऊपर डालते हैं। जनादेश आपको मिला है, मुख्यमंत्री आप हैं, जनघोषणा पत्र आपने जारी किया है और बार-बार मोदी जी की तरफ देखते हैं, बार-बार केन्द्र को कोसते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जैसे कि मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, उसको नहीं बोलूंगा। (हंसी) मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि पक्ष में है या विपक्ष में हैं। कई बार राजभवन का घेराव करने जाते हैं, दिल्ली में धरना देने जाते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं। सरकार आपकी है। जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और काम के लिए किया है। आप पूरा समय धरना प्रदर्शन, रैली, गवर्नर हाऊस में व्यतीत कर दे रहे हैं। जनता के विकास के लिए कोई कांक्रीट योजना, यह सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जायेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आरक्षण बिल वही अटका हुआ है। इसलिए जब तक क्लियर नहीं होगा, वहां तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग भी आग्रह करिये कि वह आरक्षण में दस्तखत करें।

श्री उमेश पटेल :- उस दुखती रत में हाथ मत रखो। वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही आरक्षण की बात आयेगा न तो दही जम जायेगा।

श्री नारायण चंदेल :- मैं बता रहा हूं । क्या आप लोगों ने डाटा आयोग की रिपोर्ट आज तक सदन में प्रस्तुत की है ? क्यों नहीं की ? डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की ? आपको किसने रोका था ? जो ओ.बी.सी. आरक्षण का विरोध किया, उस शुक्ला जी को आपने कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा । इसके बारे में आप कुछ कहेंगे ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आपने सर्वसम्मति से पास किया कि नहीं ? चलिये आज आप यह बता दीजिये कि आप आरक्षण के पक्ष में हैं कि नहीं हैं ? (व्यवधान) आप केवल इतना ही बोल दीजिये, बाकी सब देख लेंगे । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- हमने सर्वसम्मति से पारित किया है ।

श्री उमेश पटेल :- आप पक्ष में हैं न ? आरक्षण आपको चाहिए, आप बताईये। आज बोल दीजिए । देखिये आज फिर से दही जम गया न ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बार-बार केंद्र की बात करते हैं । मैं इनको बताना चाहता हूं कि केंद्र शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को दिनांक 1.04.2019 से 28.02.2023 तक कितनी राशि दी गयी है, सभी मदों को मिलाकर 1 लाख 66 हजार 514 करोड़ 57 लाख रूपये अभी तक इनको दिया जा चुका है । मैंने आपको अवधि बतायी है, पैसा कहां गया ? वह राशि कहां गयी ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय नेता जी, वह तो नीति आयोग की है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- वह हमारा अधिकार है ।

श्री मोहन मरकाम :- नेता जी, वह हमारा अधिकार है । (व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप लोग क्या कर रहे थे ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो सदन को संचालित करिये इसलिये सदन को संचालित करिये । सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी, यह प्रजातंत्र का मंदिर है, यह कोई चौक-चौराहा नहीं है, यह कोई मछली बाजार भी नहीं है इसलिये सुनने की आदत डालनी पड़ेगी । हम मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे, वे बतायें । लेकिन सदन में हमारा कोई भी सदस्य बोले तो बार-बार मंत्री उठकर व्यवधान उत्पन्न करे यह लोकतंत्र के लिये उचित नहीं है और पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है । हम इस विधानसभा में यह नई नजीर देख रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, खाने-पीने वाला डिपार्टमेंट है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग बैठे-बैठे कमेंट्स मत करिये ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खड़े होकर बोलता हूं कि दिल्ली में जिस प्रकार से चल रहा है । नेता जी, आपको मालूम है कि सदन में लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माईक बंद कर दिया जाता है । यह जो पूरे देश में चल रहा है यह प्रजातंत्र के लिये ठीक नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि लोकसभा की बात हो रही है तो माईक बंद करने के आरोप के मामले में प्रिविलेज कमेटी ने संज्ञान लिया है । कब बंद हुआ है, कैसे बंद हुआ है उसका उत्तर दीजिये करके ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सुनने की आदत डालो ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में बजट सत्र कितने दिन चलता है मालूम है । छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह सबसे कम 14 सिटिंग का बजट सत्र है और आपके कार्यकाल में, आप जब संसदीय कार्यमंत्री हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप 14 लोगों के हिसाब से रखा है न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मध्यप्रदेश 230 विधायकों का विधानसभा है । यहां 14 दिवसीय वहां 12 दिवसीय । कभी आपने सोचा है, अभी नवरात्रि है, अभी होली है । उसके कारण तिथि और चूंकि मार्च का अंतिम बजट पारित करना जरूरी होता है । आप कहें तो फिर बुला लेंगे उसमें क्या बात है ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना के लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है । पूरे छत्तीसगढ़ में विकास ठप्प है और गांव में विकास बंद है । जो समग्र की राशि आती थी, चौबे जी के कार्यकाल में बंद है । 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्राम गौरव पथ के लिये जो राशि मिलती थी उसको विलोपित कर दिया गया है । विधायकों का आदर्श ग्राम योजना

के लिये एक पैसा नहीं है, बजट में उसका उल्लेख नहीं है । एक पैसा नहीं है, समग्र की पूरी राशि बंद कर दी है । गांव में कैसे विकास होगा ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन 15 साल में 1 करोड़ मिलता था, अब 4 करोड़ मिल रहा है। थोड़ा तो बधाई दीजिए। 4 करोड़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह बताओ। नहीं मिल रहा है तो बताइए। आपके लोकसभा में 5 करोड़, हमारे अध्यक्ष जी की मैडम लोकसभा के मेंबर हैं। वहां 5 करोड़ मिल रहा है। 8 विधान सभा है। आपको 1 ही विधान सभा में 4 करोड़।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, आज गांव के जितने लोग हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। गांव के जितने लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब इस सरकार से दुखी हैं। कहीं कोई गांव में सी.सी. रोड नहीं बन रहा है। कहीं कोई सामुदायिक भवन नहीं बन रहा है। कोई मुक्तिधाम नहीं बन रहा है। सारा जो केन्द्र का पैसा है 15वें वित्त आयोग का पैसा है, मनरेगा का पैसा है, गौठान में लाकर डाल दे रहे हैं और दुनियाभर का उसका विज्ञापन कर रहे हैं। इसलिए गांव के हित के लिए, गांव में जो बुनियादी समस्या है, उसका निदान कैसे होगा? छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है। आप ही कहते हैं। आप कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं गांव से आया हूं। लेकिन विकास की दिशा गांव की तरफ नहीं मुड़ रही है। गांव की तरफ नहीं जा रही है और इसलिए इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपने कहा था और आपके माननीय नेता जी ने हिमाचल के चुनाव में कहा था कि हर ब्लॉक में 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की हमारी योजना है, घोषणा की थी। इस बजट में उसका कहीं उल्लेख है? माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था। अपने नेता का तो सम्मान करो। हम लोग कंडिल लेकर खोज रहे हैं। टार्च लेकर। कोई मोबाइल जलाकर देख रहा है कि कहां पर है? लेकिन कहीं पर कोई अता-पता नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- क्या चीज ढूंढ रहे हो? (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- पाताल बेचना है कही के खोजथन भाई।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, बहुत से हमारे सदस्यों से इस बात का उल्लेख किया, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है। सत्यनारायण शर्मा जी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हैं न।

श्री कवासी लखमा :- हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चश्मा लगाओ। चश्मा।

श्री नारायण चंदेल :- अच्छा, पाव लागथव। वे जब से बिहार से आये हैं, बीमार पड़ गये हैं। (हंसी) अभी मणिपुर गये थे। बिहार गये थे। शराब नीति का अध्ययन करने गये थे। गंगा जल उठाकर इस सरकार ने कसम खाया था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वो

बाबा साहब तो नहीं हैं। वो संयोजक थे। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? गंगा जल उठाकर कसम खाये कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे और जिस समय लोगों को कोरोनाकाल में दवा की जरूरत थी, उस मसय इन्होंने घर-घर में दारू पहुंचा दिया। दारू की होम डिलीवरी हो गई।

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग थाली पीटवाये थे।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, गांव-गांव में गली-गली में ये नारा चल रहा है कि दूध के बंधा गे हे चंडी, अउ शराब के खुल गेहे गांव-गांव में मंडी। शराब की धारा बह रही है। अवैध शराब का खुलेआम करोबार चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में शराब के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। नित नये किस्म के अपराध हो रहे हैं, लेकिन उसकी जननी में शराब है। जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था, आज शराब वह शराब के गिरफ्त में है। रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। शराब के नशे में लोग गाड़ी चला रहे हैं। कोई राष्ट्रीय राजमार्ग जिला मार्ग, स्टेट हाइवे, जहां पर पान ठेला, होटल में ढाबे में शराब नहीं मिलता, हर दुकान में शराब सराबोर है। शराब को रोकने के लिए अवैध शराब के करोबार को रोकने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, उल्लेख नहीं है। हम बढ़-चढ़कर बात किये। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस 2 अक्टूबर को आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती में शराबबंदी की घोषणा करेंगे या आखिरी बजट सत्र में उसकी घोषणा करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, जितनी भी अवैध शराब की गाड़ी पकड़ी जाती है, सब यू.पी. से आ रही है, मध्यप्रदेश से आ रही है । जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहीं से आ रही है, आप उनको मना क्यों नहीं करते हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, एक लोक लुभावन घोषणा की गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे अमरजीत जी ने कहा मैंने कल भी उल्लेख किया था और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि आप शिकायत पटल पर रख दीजिए । मैं अभी कह रहा हूं कि माननीय मुख्य सचिव जी को रायपुर के एक आंदोलनकारी ने नाम सहित अवैध शराब कौन कहां से लाता है, शिकायत की है । आप अनुमति देते हैं, सरकार जांच कराने का आश्वासन देती है तो मैं पत्र को अभी टेबल कर सकता है । अभी टेबल करूंगा, ये नैतिक बल होना चाहिए । संसदीय कार्यमंत्री जी टेबल करने की अनुमति दिलवा दीजिए, आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं, यदि वे बोलें टेबल करने के लिए तो मैं उस पत्र को टेबल कर देता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक लोक लुभावन घोषणा की । अटल नगर से दुर्ग तक लाईट मेट्रो सेवा शुरू करने की । कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, इस सरकार की अवधि क्या है । न सर्वे हो सकता, न ड्राइंग डिज़ाइन बन सकता,

यह सिर्फ बजट पुस्तिका की शोभा है । कुछ भी नहीं हो सकता । इसके लिए कोई बजट प्रावधान है । सर्वे करने के लिए भी तो बजट लगेगा । लेकिन इसका कोई बजट प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, आपने जनघोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें कहीं थीं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे । कर्मचारियों का नियमितिकरण भी नहीं हो पाया । केन्द्र के समान डी.ए. देने की बात की थी, क्या इसका उल्लेख है ? क्यों नहीं दिया ? आज राज्य के साढ़े चार लाख से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी नहीं है, वे साढ़े चार लाख परिवार हैं । उन साढ़े चार लाख परिवारों के साथ में आपने खड़े खड़े धोखा कर दिया। अब वे फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं । एक तरफ चुनाव आने वाला है, सारा अमला चुनाव की तैयारी में लगने वाला है । ऐसी परिस्थितियों में साढ़े चार लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं । सरकार के झूठे वायदे के खिलाफ, धोखे के खिलाफ । इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है । अध्यक्ष जी, मैं बातचीत कर रहा था, आपने गौठान की समितियों का भी राजनीतिकरण कर दिया । जो ग्राम सभा ने पारित किया है । आप ग्राम सभा की बात करते हैं कि ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए । आप राजीव जी की बात करते हैं कि उनकी कल्पना थी, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कल्पना थी कि हम पंचायत को मजबूत करें, पंचायत को अधिकार दें, पंचायत को सशक्त बनाएं । अध्यक्ष जी, ग्राम सभा ने गौठान समिति के लिए जो नाम दिया, उसको काट दिया गया । एक भी व्यक्ति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव वाला व्यक्ति नहीं है । उसमें उस क्षेत्र के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं । इसको लेकर भी वहां के पंच, सरपंचों में नाराजगी है । सारी चीजों का राजनीतिकरण करना है । अरे, हम कुछ तो छोड़ें, कुछ को भगवान भरोसे छोड़ें, गांव के भरोसे छोड़ दें । वो लोग भी मनुष्य हैं, इंसान हैं उन पर भी हम भरोसा करें । अध्यक्ष महोदय, पूरे क्षेत्र में गांव-गांव में राजनीतिकरण कर दिया गया कि आपने राजीव मितान क्लब बना दिया। कैसे कुछ लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने सरकारी पैसा दे दिया। किस हिसाब से दिया ? जब हम यह कहते हैं कि प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। इसका क्या उद्देश्य है ? वे क्या करेंगे ? अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने किसानों की बात करते समय कहा था, किसान छत्तीसगढ़ के भगवान हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जब किसान का फसल लहलहाता है, किसान के खेत में अच्छी फसल होती है तब बाजार में रौनक होती है। जिस समय अकाल पड़ता है, दुकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, उस समय बाजार में बीरा नहीं होती है। लेकिन उन किसानों के साथ भी छल हो रहा है। क्या राष्ट्रीयकृत बैंक से जिन किसानों ने कर्ज लिया था, निजी बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज लिया था, क्या उनके कर्ज माफ हुए ? वे आज भी उस बैंक की चौखट पर हैं। वे आज भी आवेदन लेकर घूम रहे हैं कि हमर का होही, हमर का होही। वह किसान आज भी ठगा सा महसूस कर रहा है। अध्यक्ष जी, उन किसानों का भी कर्ज माफ करवा दीजिए। आपकी जो

नीति किसानों के बारे में है, मैं दावे से कहता हूं, 20 प्रतिशत किसानों को 80 प्रतिशत आपकी नीति से लाभ हो रहा है और 80 प्रतिशत किसानों को मात्र 20 प्रतिशत लाभ हो रहा है।

संसदीय सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्बद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट समय चाहूंगा। किसानों की बात है, आप इस बात को भी याद कीजिए, एक साल जब किसानों की धान को 2500 रूपये में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खरीदे और केन्द्र की सरकार नहीं ली तो वह धान 1600 रूपये में नीलामी हुई, 3500 रूपये क्विंटल पूरी धान की खरीदी और उसको जोड़ा जाए तो 4 हजार रूपये में भी किसानों की धान खरीदने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) अगर मैं इस बात को असत्य बोल रहा हूं तो रिकार्ड से प्रमाणित हो सकता है। 2500 रूपये में खरीदा हुआ धान, 1600 रूपये में नीलामी हुई, 3500 हुआ और सोसायटी का खर्च, ट्रांसपोर्टिंग का खर्च जोड़ेंगे तो 4 हजार रूपये में भी धान को खरीद करके किसानों के साथ वादा निभाने वाली कोई मुख्यमंत्री है तो भूपेश बघेल है और भूपेश है तो भरोसा है। सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि किसान के वादे को पूरा करने के लिए 1 क्विंटल में 4 हजार रूपये की राशि देने वाली कोई सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है। भूपेश है तो भरोसा है। इसी बात से प्रमाणित होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय यादव जी, आप थोड़ा रिकार्ड दिखवा लेना, वर्ष 2019-20 में जो किसानों को पेमेंट हुआ है, वह 2415 रूपये के हिसाब से हुआ है और वर्ष 2020-21 में किसानों को जो पेमेंट हुआ है, वह 2485 रूपये के हिसाब से हुआ है। गलत जानकारी देकर पूरे प्रदेश के किसानों को भ्रमित मत करिए। पहले जानकारी लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सुनिए ना, मैं तैयार हूं। 9 हजार करोड़ कर्ज माफी हुआ है। यह रिकार्ड में है और आप 15 साल में 102 करोड़ बस कर्ज माफ किए हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- तीन साल के भाषण ला पढ़ ले, 10 हजार ले 8 हजार करोड़ में आ गे हो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, चलिए 8 हजार करोड़ भी हुआ। आप 15 साल में केवल और केवल 102 करोड़ रूपए कर्ज माफ कर पाए।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन 15 साल में कोई ठुठी बीड़ी भी माफ करे हव का। एको आना, एको आना।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं ता मे काय करव। तै ओला हड़कबे त तो गा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं मैं हड़कव नहीं गा। ओ हा खड़े होही ता तैं का बोलबे।

श्री अमरजीत भगत :- रामकुमार हा कहत हे कि 15 साल में तुमन ठुठी बीड़ी माफ नहीं करे हव।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा 2500 रूपया। 2040 रूपया और 2060 रूपया तो भारत सरकार का है। आप 2500 रूपये कहां दे रहे हैं। आप खाली उसके उपर का दे रहे हैं। उतना पैसा तो भारत सरकार का सपोर्ट प्राईज है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- भैया, यू.पी.ए. के समय में भी तो देते थे।

श्री नारायण चंदेल :- 2040 और 2060 रूपये तो भारत सरकार का सपोर्ट प्राईज है।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, एक मिनट। आपको मालूम होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषिमंत्री जी और मैं, जब हम तीनों भारत सरकार के पास गये थे और हम लोग उनसे इस बात की अनुमति मांग रहे थे कि हमको 2500 रूपये में धान को खरीदने की अनुमति दी जाये तो क्या भारत सरकार ने हमको इसकी अनुमति दी? उन्होंने एक लाइन में बोला कि यदि आप एम.एस.पी. से एक पैसा भी ज्यादा देंगे तो हम केन्द्रीय पुल में आपका चावल नहीं लेंगे। क्या आप लोगों ने एक बार भी हमारा समर्थन किया और क्या आपने किसानों के पक्ष में आवाज उठाया? आपने नहीं उठाया।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, यह ऊपर और नीचे की बात कहां से आ गई?

श्री नारायण चंदेल :- देखिये, ऐसा है कि यह तो संघीय व्यवस्था है। यदि भारत सरकार की कोई पॉलिसी बनती है तो वह पूरे देश के लिए बनती है। छत्तीसगढ़ उनके लिए कोई अलग थोड़ी न है और भारत सरकार बड़े मन से काम करती है। लेकिन हमें हमारी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा। मतलब, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 2 साल के बोनस का एक लाइन भी जिक्र नहीं किया। उस समय उन्होंने बढ़-चढ़कर कहा था कि हमारे जो गरीब किसान हैं, मैं फिर से कहूंगा कि हमारे गांव में रहने वाला दुकालू, सुकालू, वैशाखू, समारू, पहाड़ू, डहारू।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- ए बबा, तुंहर मूड़ के बोझा ला हमर ऊपर काबर उतारत हवौं ? ओला तो तुमन कहे रहे हवौं।

श्री नारायण चंदेल :- वह गांव का रहने वाला दुकालू, सुकालू, वैशाखू, समारू, पहाड़ू, डहारू है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप एला तो बताओ जी कि ए वायदा ला कौन करे रीहिस हे ?

श्री कवासी लखमा :- अजीत जोगी।

श्री नारायण चंदेल :- मुख्यमंत्री जी ने बढ़-चढ़कर कहा कि मैं 2 साल का बोनस भी दूंगा। यहां पर इसके 1 रूपये का भी कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एमन अपन मूड़ के बोझा ला हमरे ऊपर ठेलत हे। आप मन तो कहे रहे हो कि हमन हर साल बोनस देबे कि के। हमन थोरे कहे रहे हवन। हमन जो वायदा करे रहे हन, तेला हमन पूरा करत हन। 2500 रूपये में धान खरीदी अऊ कर्जा माफी, एला ए दारी हमन 2640 रूपया दे हन। ओमन ला 31 मार्च को मिल जाही।

श्री नारायण चंदेल :- कालू, ते थोड़ा चुप बइठ न।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप मन ला सही बात ला कहात हो तो आप कालू चुप कहात हो। देखो। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- ते चोरो-बोरा कर डारेस। ते बइठ तो।

श्री मोहित राम :- आप ला एखर भाषा समझ में आथे ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह किसानों की बात करते हैं। अभी कृषि मंत्री जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इसमें उसका उल्लेख है कि रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यह जितने धान खरीदी करते हैं। यह कहते हैं कि जितना हमारा लक्ष्य है उतने ही धान का उत्पादन हो जाता है। इनके पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमने रिकॉर्ड धान की खरीदी की है। मैंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करते थे और हम आपसे दुगुना धान खरीदी कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जमीन का रकबा घट गया और धान का उत्पादन बढ़ गया। यदि इस करिश्मे को कोई कर सकता है तो यह भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो सकता है, चौबे जी के दिशा-निर्देश में यह हो सकता है। गिरदावरी में किसानों का रकबा किसने घटाया ? आपके पटवारी, आर.आई., तहसीलदार, नायब नायब तहसीलदार गांव में एक एकड़, डेढ़ एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़ के जो छोटे-छोटे सीमांत किसान हैं, उनके यहां गये, उनके खेत का नाप-जोंक किया ? उनके खेत विलुप्त हो गये। जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, वैसे उन बेचारों के खेत विलुप्त हो गये। वह मोहनजोदड़ा, हड़प्पा जैसे हो गये। वह बेचारे अपने खेत को खोज रहे थे। बहुत से आये कि भैया, हमर खेत गवा गे, हम रिपोर्ट कहां लिखाये ? उसके बाद यह बोलते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ गया। इस प्रदेश में छोटे किसान, मंझोले किसान, सीमांत किसान ज्यादा हैं। आपने सब जमा कर दिखा दिया, उत्पादन बढ़ा दिया। इतना धान कहां से आया ? जब आपने रकबा घटा दिया तो धान का उत्पादन कैसे बढ़ा ?

श्री अजय चंद्राकर :- पूरा धान बागबहरा के रास्ते से आया।

श्री नारायण चंदेल :- इसके लिए भी जांच आयोग गठित करवा देते।

संसदीय सचिव (श्री द्वारिधीश यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी आप बोल रहे हैं कि रकबा कम कर दिया गया और आप ही के दल के बहुत ही विद्वान और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी इसी सदन में बोले हैं कि धान खरीदी के पहले न कोई गिरदावरी हो रही है और न कुछ और हो रहा है। एक तरफ आप बोलते हैं कि गिरदावरी नहीं हो रही है और एक तरफ नेता जी बोलते हैं कि रकबा घट गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह कहा था कि बारिश में गिरदावरी माननीय भूपेश जी की सरकार ही करवा सकती है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इन्होंने तालाब को भी खेत बनाया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कागज में गिरदावरी होती है, मौके में गिरदावरी नहीं होती है, मैंने यह कहा ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, आप बोलथौं, तेनला पूरा नोट करावथे, भोरहा में मत रहिहौ ।

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, तोर डहार के दूनों झन मन चोचो-बोरो करथे । (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री, दोनों को बताना चाहता हूं कि हमारे जांजगीर-चांपा जिले में, अध्यक्ष जी आपके जिले में बड़े-बड़े तालाब को खेत बताकर उसका रकबा-खसरा नम्बर देकर कई सोसायटियों में धान बेच दिये हैं, आपको मालूम है या नहीं ? यह संभव आपकी सरकार में हो सकता है । मैं एक जिले की बात बता रहा हूं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं बता रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण शुरू किया है, वे किसानों के अपमान के सिवाय कोई बात नहीं कह रहे हैं । उत्पादन बढ़ा है तो किसानों ने अपनी मेहनत से बढ़ाया है । आप बार-बार प्रश्न लगा रहे हैं, आप किसानों का अपमान करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके आर्थिक सर्वेक्षण में खोलकर पढ़ लीजिए, उत्पादन गिरा है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, किसानों की बात को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन उसको दिखवा लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, आपने जितना धान बेचा है, उसका रिकार्ड है । आपको कितना पैसा मिला है, वह भी रिकार्ड में है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, तालाब को खेत बताकर धान खरीदी की गई है । मैं आपको सोसायटी का नाम बता दूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- नेता जी, हम किसानों को 2640, 2660 रूपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं और अगली बार 28 सौ रूपए देंगे । आप कह रहे हैं कि तरिया का भी नाप हुआ है । हमारे छत्तीसगढ़ के किसान एक डिसमिल भी जमीन नहीं बचाने वाले हैं । तरिया होगा तो धान बोएंगे, जहां धान होगा, वहां बोएंगे, लेकिन आदरणीय भूपेश जी की सरकार धान खरीदी करेगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी किसी ने बताया कि पत्थर के खदान में भी धान उगा है । इन्होंने स्व सहायता समूह का बहुत उल्लेख किया। वह गरीब महिलाएं, गांव की महिलाएं छोटा-छोटा काम करती हैं, इन्होंने जन घोषणा-पत्र में उनके कर्ज माफ करने का वादा किया था । उन हजारों स्व सहायता समूह की हमारी जो बहिनें हैं, जो छोटा-छोटा काम करती थीं और जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन उनके प्रति भी इस सरकार की कोई संवेदना नहीं है । संवेदनाहीनता की जो चरम सीमा

है, वह इन्होंने इस बजट में व्यक्त किया है । उमेश जी हर समय खड़े हो रहे थे । उमेश जी, आप यह बताईए ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- नेता जी, आप उमेश जी को खड़े होने के लिए मत बोलो, हम उनको बार-बार बिठा रहे हैं । वह क्या-क्या बोलने लग गए हैं । सत्तू भैया आज उनके टेबल में बैठे थे, उमेश जी बोल रहे हैं कि सब चोरो बोरो हो गया, चोचोर बोचोर हो गया । (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी उनको लखमा जी का असर नहीं आया है । उमेश जी, आप मुझे यह बताईए । आप उच्च शिक्षा, खेल विभाग के मंत्री हैं । छत्तीसगढ़ के जितने उदीयमान खिलाड़ी हैं, आपकी सरकार आने के बाद इन चार वर्षों में खिलाड़ी कोटे से आपने कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी ? आपने एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, अभी छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक होईए, ओला तै गेड़ी चढ़े हस का, ओला बता ।

श्री रामकुमार यादव :- ओकर सेहे के पूरती बांस नहीं मिलथे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने खेल मैदान के लिए 1 हजार रूपए कहीं नहीं दिया है । खिलाड़ियों का जितना सम्मान होता था, इन सवा चार सालों में किसी खिलाड़ी का सम्मान नहीं हुआ है ।

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, आपने खेल मैदान की बात की है । उसके लिए खेल विभाग से बजट जाये या पंचायत विभाग से बजट जाये या नगरीय निकाय से बजट जाये, खेल मैदान बन रहा है । उससे आप संतुष्ट रहिए । खेल विभाग से ही मैदान बने, यह जरूरी थोड़ी है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, ओला बोलन दे न ।

अध्यक्ष महोदय :- लेना तहूं संकेरहा कर गा । थोड़ा सकेल ले ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप कौन-कौन सा छत्तीसगढ़िया खेल ला जानथव ।

अध्यक्ष महोदय :- ओला जल्दी बोलन दव ना । डिस्टर्ब मत करो । नेता जी ह एति, ओति भटकथे ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अभिनव योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना पिछले 15 साल से चल रही थी। 15 साल में ना जाने कितने बुजुर्गों को किन-किन तीर्थों का दर्शन कराया, भ्रमण कराया। लेकिन इस पूरे बजट में उसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है, उस योजना का पता नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, वे अभिशाप देंगे। जिनके बच्चे उन बुजुर्गों को, माता-पिता, दादा-दादी को कभी तीर्थ यात्रा नहीं करा पाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया था।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं बोला था कि आप लोग तीर्थ स्थान में भेजते थे, वहीं लोग आकर बोलते थे इनको हटा दो।

श्री नारायण चंदेल :- लेकिन दुर्भाग्य है उस योजना का कहीं पर उल्लेख नहीं है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- 15 साल से हैं, बहुत बढ़िया इनको हटा दो। वही माथा टेके, वही फल हम लोगों को मिला।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- तीर्थ यात्रा जरूरी है या कुपोषण को दूर करना जरूरी है ?

श्री दलेश्वर साहू :- कितने बुजुर्ग रेल्वे स्टेशन में छूटे थे, उसके बारे में भी बतो बताओ कि उनको कैसे लाये हैं। उनके बारे में भी बता दो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरस्वती सायकल योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना थी। आज कहीं पर दिखाई नहीं देता। आपने उल्लेख जरूर किया है, लेकिन स्कूलों में सायकल नहीं बंट रहा है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। पता नहीं, वह पैसा कहां जा रहा है ?

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- नेता जी, बंट रहा है। हम लोग सायकल बांटकर आये हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मेरे विधानसभा के 8 स्कूलों में बांट चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अनावश्यक व्यवधान मत करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- नारायण, नारायण, ऐसा असत्य क्यों बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अंदर आ गए क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज व्यवधान मत डालिये ? बोलने दीजिये।

श्री नारायण चंदेल :- देखिये, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के जितने विधायक हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिये। प्रोटोकाल का जो पालन होना चाहिए, ये जो बता रहे हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम में जो सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान नहीं मिलता है। जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, कई बार निमंत्रण कार्ड में उनका नाम तक अंकित नहीं रहता है। मनोनीत लोगों का नाम रहता है। आजकल छाया विधायक आ गए हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक मिनट नेता जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा के कार्यक्रम में बुलाते हैं, इही कमरा मा बैठे हो, नहीं आत हव। नाम छाप डारे हन, तभो नहीं आत हव तो कैसे बनही बता ? दूसरा-दूसरा आरोप लगात हस।

श्री नारायण चंदेल :- इसलिए आपको निर्देशित कर रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट नेता जी, छाया विधायक का एक किस्सा है। मुंगेली जिले में कोई एक सरकारी कार्यक्रम था। उसमें कुछ नेता बैठे थे, उसमें से संचालक ने कहा कि यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में 3-3 छाया विधायक हैं। उसको सौभाग्य की बात बोल रहा था, बताओ। भईया, यह बहुत बड़ी समस्या है, कारगिल समस्या से ज्यादा खतरनाक है।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, पहले कई बार आसंदी से आदेश हुआ है कि प्रोटोकाल का पालन करना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है, हम आपके सामने कहेंगे। अगर

जनप्रतिनिधि का कहीं अपमान होगा तो हम आपके सामने में व्यक्त करेंगे। आप सारे विधायकों के सरंक्षक हैं। विपक्ष के किसी विधायक को मालूम नहीं है कि कब सरस्वती सायकल योजना का सायकल बंटा है। किसी भी कार्यक्रम में, भूमि पूजन में, लोकार्पण में ना इनका नाम छापा जाता है ना इनको सम्मान से बुलाया जाता है। हम लोग तो पेपर में पढ़ते हैं कि इसका भूमिपूजन हो गया, इसका लोकार्पण हो गया। यह प्रजातन्त्र में उचित नहीं है। अध्यक्ष जी, विधायिका का सम्मान होना चाहिए। अगर विधायिका का सम्मन नहीं होगा तो यह सिर्फ हमारे दल के लिए पूरी विधानसभा के लिए उचित नहीं है, प्रजातन्त्र के लिए उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने शुरू किया था ? माननीय अटल जी ने शुरू किया था। अगर आज देश के गांव-गांव में और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुदूर गांव में अगर पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है तो यह अटल जी की देन है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उनकी देन है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मानीटरिंग हमारे पंचायत विभाग के मंत्री करते हैं। जो उसकी राज्य में गुणवत्ता होनी चाहिये, जो उसका काम होना चाहिये, जो मानिटरिंग होनी चाहिये, जो उसका देखरेख होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है । गांव तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम कुछ है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है । पंचायत मंत्री जी व्यस्त हैं, उसमें जो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रावधान किया गया है, वह 500 करोड़ रूपया है । इतने बड़े छत्तीसगढ़ प्रदेश में 500 करोड़ रूपया ऊंट के मुंह में जीरा है । ये है क्या, इसमें मैंन्टेनेंस होगा कि दो-चार नई सड़क का निर्माण होगा। अध्यक्ष जी, बड़ी आस लगाकर बैठे थे । जितने हमारे पेंशनधारी हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, महीने की जब पहली तारीख आती है, बड़ी उम्मीद रहती है । टकटकी लगाकर देखते रहते हैं । दुर्भाग्य है, बढ़ाये हे त कतका बढ़ाय हे । माननीय अध्यक्ष जी, कुछ भी नहीं बढ़ा है । बड़े-बड़े वायदे किये थे, मैं आपको जनघोषणा पत्र आपको पढ़कर बता देता हूँ । कितने बड़े वायदे किये थे ।

श्री कवासी लखमा :- नेता जी, हम लोग 4 साल में इतना किये हैं, 15 साल में कितना किये हो, बताओ ? 15 साल में कितना बढ़ाये थे ? बताओ ना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐ भाई साहब ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भाषण देने वाले हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम इंट्रप्ट करें, यदि लगातार ये बतायेंगे तो हमको मर्यादा मत सिखायेंगे आप ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- देखिये, यह धमकी उचित नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्यों धमकी नहीं है । यह चरित्र नहीं है, यह व्यवहार सही है आपका ? बार-बार इंट्रप्ट कर रहे हैं, मंत्री खड़े हो रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के लिये यह भाषा उपयुक्त नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये मैंने कुछ नहीं कहा है, आपको कहा है, आप फ्लोर मैनेजमेंट करते हो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के भाषण में इंट्रप्ट करेंगे करके ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ये नही कहा मैंने । आप गलत मत बोलिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अपने मंत्रियों को नियंत्रित करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम सुनना चाहते हैं, लेकिन आप जो व्यवहार कर रहे हैं, फिर हम वही व्यवहार करेंगे, इसलिये अपना फ्लोर मैनेजमेंट ठीक रखिये ।

श्री अमरजीत भगत :-यह तो धमकाने वाली बात है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, माननीय कवासी लखमा इस सदन के...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नहीं समझोगे । फ्लोर मैनेजमेंट आप नहीं समझोगे ?

श्री अमरजीत भगत :- हास परिहास को आप दिल से लगा लोगे । आप मजाक करते हो तो हम नहीं बोलते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मुख्यमंत्री जी का भाषण कभी-कभी होता है । सुनना चाहते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- धमकाने वाली बात क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी के भाषण को किस तरह से लिया जा रहा है आप देख लीजिए । आपके फ्लोर मैनेजमेंट में हमको मत दोष दीजिएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके हाथ में अभी तक कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उससे आगे बढ़कर थोड़ा बजट-वजट में आ जाओ ना भई । आप खाली कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है, उसी मे बोलोगे क्या, चार साल बोल डाले हो । थोड़ा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसमें आ जाईये ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सदन की परम्परा रही है कि दोनों बोलने के लिये खड़े हों तो उसे बाधित न किया जाये । यदि बोलना है तो फिर अनुमति लेकर बोला जाता है । यह बहुत ही उच्च परम्परा है । इसको कायम रखा जाना चाहिये, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जी बोलने के लिए खड़े हुये हैं, सबसे पहले इंट्रप्ट किसने किया । सबसे पहले अजय चन्द्राकर ने इंट्रप्ट किया । आपने शुरूआत क्यों कर दिये । अपने दल के नेता की शुरूआत की है और हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत उदार हैं । जब भी कोई सदस्य खड़े होते हैं, वह बैठ जाते हैं । उसकी अनुमति है, तभी बोल पा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बिना बाधा के नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता जी, वह इंट्रप्ट नहीं कर रहे हैं, वह सहयोग कर रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा हम इंट्रप्ट कर रहे हैं । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, असल में आज क्या है, कवासी लखमा जी की आंख छोटा-छोटा दिख रही है । (हंसी)

समय :

8.00 बजे

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे हैं इसका मतलब धरम भैया आप गलतफहमी में उठ गये। (हंसी) वह माननीय नारायण चंदेल जी के लिये बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके तरफ के कुछ लोगों की इमानदारी से जांच करवाने की जरूरत है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, टाइम क्रॉस हो गया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप बजट में कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। जल जीवन मिशन, उसकी बहुत चर्चा होती है और वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक मात्र 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। आपने इसमें 2 हजार करोड़ रूपये की राज्यांश की राशि रख दी है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि उसका टेण्डर दो-दो बार क्यों निरस्त हुआ ? क्या हो गया था ? छत्तीसगढ़ के पूरे जल जीवन मिशन की चर्चा भारत में है, पूरे देश में है। उड़ीसा जैसे राज्य, तेलंगाना जैसे राज्य, झारखण्ड जैसे राज्य, इस जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिये तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पीछे जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। जल जीवन मिशन बंदरबाट हो रहा है और जल जीवन मिशन का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, कल इसी विभाग में बहुत सारे क्वेश्चन लगे हैं। मैं सबका जवाब दे दूंगा और भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो पहले आप सबूत पेश करो।

श्री नारायण चंदेल :- क्या ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो पहले आप सबूत पेश करिये। मैं आपको सम्मान के साथ बोल रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको कहने का अधिकार है। किस बात का सबूत चाहिए ? आपकी कार्यप्रणाली बता रही है। दो-दो बार क्यों टेण्डर निरस्त हुए ? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जल जीवन मिशन की क्या क्वालिटी है ? कहीं कोई मॉनिटरिंग करने जाता है ? यह आपके सदस्य बोलते हैं, यह हम नहीं बोलते हैं। यह उनकी पीड़ा है। यह पूरे सदन की पीड़ा है, आप इसको ठीक करवाईये। देखिए ऐसा है यह टालने वाली बातों से काम नहीं चलेगा। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की

सरकार की हर गरीब परिवार के घर में, हर घर में पीने का शुद्ध पानी देने की महती योजना है। यह क्रांतिकारी कदम है और यदि हम इसको टालेंगे, इसको हम हल्के में लेंगे तो हम इस प्रदेश में गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आखिरी में कविता पाठ है ।

श्री नारायण चंदेल :- जी, कविता है।

अध्यक्ष महोदय :- टाइम लगेगा।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, बस माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये हैं। मैं बात सकेलहू। नहीं आजकल बंद कर दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, क्या कवि सम्मेलन होने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी आखिरी में कविता पढ़ते हैं ना इसलिये मैंने पूछा।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, बस एक-दो बात, फिर कविता में आऊंगा।

श्री अमरजीत भगत :- तुम हमसे दूर कैसे हो, हम तुमसे दूर कैसे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- हां, थोड़ा-सा दूर तो है।

श्री अमरजीत भगत :- यह तुम्हारा दिल जानता है, यह हमारा दिल जानता है।

श्री नारायण चंदेल :- उधर का बिल जानता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में तेजी के साथ साढ़े चार साल में नक्सलवाल की घटनाएं बढ़ी है। सुदूर बस्तर के लोगों का जीना हराम है। हम पिछली 16 तारीख को बस्तर गये थे। भातरीय जनता पार्टी के हमारे चार प्रमुख पदाधिकारियों की नृशंस हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। लेकिन दुर्भाग्य...।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आप नक्सली की बात ले आये हैं तो आपको याद करा दूं। थोड़ा पीछे पन्ना पलट कर देखो।

श्री नारायण चंदेल :- आपके यहां तो पूरा खत्म हो गया है। आप कहां चक्कर में हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं पहले नक्सली पीड़ित रहा हूं। सबसे पहली घटना मेरे साथ हुई थी।

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। यह लोग कह रहे हैं कि चार पदाधिकारियों की हत्या हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप चार की बात कर रहे हैं हमने .. (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आपने मुझसे अनुमति नहीं ली। बृहस्पत सिंह जी बैठिये। आपकी बातों के लिये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी तैयार नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- नक्सलियों के बारे में ज्यादा रोने का (व्यवधान) अधिकार नहीं है। हम लोगों ने तो प्रथम लाइन के सारे नेताओं को खोया है। आप पाठ पढ़ाने लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सरकार को चेता रहा हूं। लेकिन नक्सली उन्मूलन के लिये, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिये, हम प्रदेश में अमन-चैन को कैसे कायम करेंगे। कैसे निरीह लोगों की जानें मत जाये। दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, सरकार की कोई कार्ययोजना नहीं है, यह दुर्भाग्य है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, एक सेकण्ड। इनके शासन में एक बहुत बड़े अधिकारी पंजाब से आये थे। इनके मुख्यमंत्री जी उनको बोलते थे कि आप आये हो तो रेस्ट हाउस में आराम करिये। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रेस्ट हाउस में आराम करो, हम लोग नक्सलाइड से बात करेंगे। गिल साहब।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, आप कृषि मंत्री हैं आप किसान भी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रदेश में बहता हुआ पानी है, उसको खेत की तरफ कैसे मोड़े? अभी हमारे जिले में रबी फसल के लिए पानी दिया गया। इस प्रदेश में मनरेगा के तहत बहुत से काम होते हैं। मैंने कृषि मेले में इनको कहा था कि जो यहां बहता हुआ है उसको हम खेत की तरफ मोड़ने की योजना बनाएं, निस्तारी तालाब की तरफ मोड़ने की योजना बनाएं, लेकिन बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रदेश का पानी व्यर्थ बह रहा है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के पानी और जवानी को सही दिशा देने की आवश्यकता है। इस प्रदेश में जल, जंगल और जमीन को बचाने की आवश्यकता है। यहां जब तक जल, जंगल और जमीन नहीं बचेगा छत्तीसगढ़ का उत्थान नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ विकासशील से विकसित प्रदेश नहीं बन सकता। इस सरकार को एक विजन के साथ में काम करने की आवश्यकता है। अभी तो आपके मंत्रिमण्डल में ही सामन्जस्य नहीं है। आपके मंत्रियों की टीम में सामन्जस्य नहीं है। आपके विधायक इतने दु:खी हैं, वह बाहर कुछ और कहते हैं और अंदर कुछ और कहते हैं। और सरकार की यह स्थिति अच्छी नहीं है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय नेता जी, आप दायीं ओर देखकर बोलिए कि आपमें सामन्जस्य है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, आप बजट में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवल बांए-दायें बोल रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नवाचार आयोग गठन की बात कही है। उसके लिए बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है। वह क्या कार्य करेगा ? उसका

क्या काम है ? वह आयोग बिना बजट के क्या करेगा ? केवल आपने उसका उल्लेख कर दिया है। अभी पेट्रोल, डीजल, यह वह की बहुत सी बातें हो रही थी। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेट्रोल और डीजल में 35 प्रतिशत वेट बढ़ाया है। हर समय यह केन्द्र को कोसते हैं। वह अन्य राज्यों झारखण्ड की तुलना कर लें, जिसमें इन्हें कुल राशि 6 हजार 643 करोड़ रूपये मिलना अनुमानित है। इनको इतनी राशि मिली है। आपने तेल का रेट, वेट कम क्यों नहीं किया ? जब दूसरे राज्यों ने कम किया । आपने कम नहीं किया। केन्द्र ने कम किया था। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र ने कम किया है। छत्तीसगढ़ ने कहां कम किया ? मैं आपको बता देता हूँ। सेन्ट्रल गवर्नमेंट प्रति लीटर 19 रूपये 48 पैसे प्रति लीटर वेट लेती है और आप 27 रूपये 2 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर वेट है तथा डीजल पर 25 रूपये 81 पैसे का वेट लगा रखा है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कम है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, गैस सिलेण्डर का उल्लेख कर दीजिएगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कम है। आपका ज्यादा है और आप बार-बार केन्द्र की तरफ देखते हैं और केन्द्र की बात करते हैं। यहां आप अपने उत्तर में वेट घटाने की घोषणा करिये। कल माननीय मोहन मरकाम जी का डी.एम.एफ. को लेकर प्रश्न था। यहां डी.एम.एफ. मद की बहुत चर्चा होती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके, हमारे जिले में भी डी.एम.एफ. मद की चर्चा हुई। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बहुत पीड़ित थे, लेकिन लॉबी में जाकर रो भी रहे थे। मैंने उनको देखा और वह बोल रहे थे कि हमरो सुनईया भईया कोनो नइ हे गा। कल डी.एम.एफ. मद को लेकर, उन्होंने सदन की कमेटी बनाकर जांच की मांग की। पूरे बस्तर संभाग में जिस तरीके से डी.एम.एफ. का स्वार्थपूर्ण बंटवारा हो रहा है, लूट पाट हो रहा है, उसमें कमीशनखोरी हो रही है और प्रदेश में सुनियोजित ढंग से डी.एम.एफ.एक भ्रष्टाचार का अगाध अड्डा बन गया है। मेरा, आपसे आग्रह है कि डी.एम.एफ. को खर्च करने की कोई नीति सरकार को बनानी चाहिए। इसमें बड़ा पैसा है, बड़ी राशि है। वह सही दिशा में लगनी चाहिए। हम उस राशि से पुल-पुलिया, सड़क बना लें, हम गांव में रंग-मंच बना लें, सामुदायिक भवन, मुक्तिधाम बना लें। ऐसे-ऐसे काम डी.एम.एफ. फंड से हो रहे हैं हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। डी.एम.एफ. फंड से कलेक्ट्रेट में ए.सी. खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं। उनकी आरामदायक कुर्सी खरीदी जा रही है, सोफा खरीदा जा रहा है, बड़ी-बड़ी लक्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। डी.एम.एफ. की कोई कारगर नीति इस सरकार को तय करनी चाहिए। यहां बड़े-बड़े उद्योग हैं, लेकिन सी.एस.आर. की राशि का क्या होता है? दिल्ली चली गई या यहां बिल्ली ले गई। आपने कलेक्टर को अधिकार दे दिया है। सी.एस.आर. की राशि कलेक्टर को जमा कराते हैं। कोई जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं जाता। हमारे क्षेत्र में बहुत से उद्योग हैं और कलेक्टर अपनी इच्छा से उसको आवंटित करता है। क्या कलेक्टर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है? आपकी सरकार में तो ये हाल है।

श्री दलेश्वर साहू :- सर, आपके ही कार्यकाल का सी.एस.आर. का जो फंड है, उसका क्या उपयोग, दुरूपयोग हुआ, उसको भी आप देख लीजियेगा। तालाब गहरीकरण के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- आप ही बोलते हो कि आज के बजट में चर्चा करो, फिर 15 साल की बात करते हो।

श्री अरूण वोरा :- माननीय नेता जी, आप डी.एम.एफ. फंड के बारे में कह रहे थे कि नहीं मालूम कहां-कहां लग रहा है। मैं आपको बताता हूं कि कोरोनाकाल में यह जो हॉस्पिटल में डी.एम.एफ. फंड का उपयोग हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में जितना उपयोग इन 04 वर्षों में हुआ है, हमने 15 साल में कहीं नहीं देखा। आप दुर्ग में देखिये, न केवल दुर्ग आप कई हॉस्पिटलों में जाकर देखिये। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। लोगों को आक्सीजन नहीं मिल रही थी। तब डी.एम.एफ. फंड से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट डाले गये। दुर्ग में आकर देखिये, वहां पर मुख्यमंत्री जी की अनुंशसा पर 5-5 प्लांट लगे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- डी.एम.एफ. फंड का बलरामपुर में भी थोड़ा जाकर देख लीजिए। सारे विशेषज्ञ डॉक्टर, ब्लड बैंक, डायलिसिस मशीन और जिले में बड़े-बड़े ऑपरेशन, मेडिकल कॉलेज में उस तरह का हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, वह डी.एम.एफ. फंड के सहयोग से कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- तो फिर कल मोहन मरकाम जी की पीड़ा क्या थी ? वह तो सदन की कमेटी से जांच की बात कर रहे थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह तो आप ही बता पायेंगे। लेकिन डी.एम.एफ. का काम कैसा होता है, आप कभी बलरामपुर दौरे में आये थे, एक बार हॉस्पिटल भी घूमकर देख लीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- मैं आया था और देखा भी था। सड़क अंडमान-निकोबार है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एस.पी. का क्या है ?

श्री नारायण चंदेल :- वह बेचारा क्या करे, वह खुद दु:खी आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, उनकी पूरी सरकार बैठी है। आज छत्तीसगढ़ का जो रेशो है, वह मैं बताना चाहता हूं कि यहां किस प्रकार से क्राईम बढ़ा है। छत्तीसगढ़ चोरी के मामले में 17वें नंबर में है, डकैती के मामले में 5वें नंबर पर है, हत्या के मामले में तीसरे नंबर पर है, आत्महत्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, अपहरण में सांतवे नंबर पर है, फिरौती और अपहरण के मामले में चौथे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में ये विषय है। नित नये किस्म के अपराध हो रहे हैं, अपराध को रोकने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है ? सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है ? इसलिए मैं समझता हूं कि इस सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। सरकार की न तो दशा ठीक है और न दिशा ठीक है। हर मामले में राजनीति करना भी बंद करें। बड़े विजन के साथ में काम करना, बड़े मन से काम करना, बड़े दिल से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, आज हम लोगों ने कवर्धा के विषय को ले करके कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार संसद के अंदर में कहा था कि सरकारें आती हैं,

जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। आज सरकार में आप हैं, हो सकता है कि कल इधर आयें। पूरी सरकार यहां बैठी है, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मन से काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो फर्जी मुकदमे लादे गये हैं, जिलाबदर की कार्यवाही की जा रही है। क्या आपने उनका बैकग्राउण्ड देखा है ? जिला बदर की कार्यवाही किस पर की जाती है ? क्या धरना-प्रदर्शन करना, रैली निकालना, चक्काजाम करना जिला बदर की परिधि में आता है? यह उचित नहीं है। अध्यक्ष जी, इस पर लगाम लगना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर यह कहना चाहता हूं कि बड़े मन से काम करें। आज आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैं अपनी कुछ कविता सुना दूं। आज छत्तीसगढ़ की जनता चीख-चीख कर कह रही है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए आज छत्तीसगढ़ की जनता चीख-चीख कर कह रही है कि 'तुमने हमको ऐसे लूटा इस भरी बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फाल्गुन के त्यौहार में'। (मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण पुस्तक में संशोधन संबंधी सूचना

अध्यक्ष महोदय :- श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट) वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक-04 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक-13 की छठवीं पंक्ति में संशोधन की सूचना देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक-04 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक-13 की छठवीं पंक्ति में शब्द "मासिक" स्थान पर "वार्षिक" संशोधित पढ़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय :- अभिलेखों में यथा स्थान संशोधित किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर चर्चा (क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर चर्चा में भाग लेने वाले वक्ता सर्वश्री माननीय अजय चंद्राकर जी, शैलेश पांडे जी, सौरभ सिंह जी, अरूण वोरा जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, शिवरतन शर्मा जी, डॉ. विनय जायसवाल जी, प्रमोद कुमार शर्मा जी, देवेन्द्र यादव जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, धर्मजीत सिंह जी, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, रामकुमार यादव जी, केशव प्रसाद चंद्रा जी, पुन्नूलाल मोहले जी, राजमन बेंजाम जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, धरमलाल कौशिक जी, आशीष कुमार छाबड़ा जी, रजनीश कुमार सिंह जी और अंत में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी। सभी वक्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सामान्य बजट में चर्चा में भाग लिये और आलोचना के साथ-साथ

अपना बहुमूल्य सुझाव भी दिये, उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे अन्य दल के हमारे साथीगण हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग का आकार 01 लाख 32 हजार 370 करोड़, बजट का आकार 01 लाख 21 हजार 500 करोड़, राजस्व प्राप्ति 01 लाख 06 हजार 1 करोड़, राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 501 करोड़, राजस्व आधिक्य 03 हजार 500 करोड़, पूंजीगत व्यय 18 हजार 607 करोड़, वित्तीय घाटा 15 हजार 200 करोड़, जो जी.एस.डी.पी. का 2.99 प्रतिशत है। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कहीं। मैं आंकड़ों के साथ कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। चालू वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक प्राप्त लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य 4 हजार 771 करोड़ है। चालू वर्ष 2022-23 में आज दिनांक तक सरकार द्वारा बाजार से कर्ज नहीं लिया गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के तीन राज्य उड़ीसा और त्रिपुरा के अलावा में से एक है। उड़ीसा पिछले 2 साल से नहीं ले रहा है और त्रिपुरा इस साल से नहीं ले रहा है। पूरे देश में हम तीसरे राज्य है, जहां अभी तक हम लोगों ने बाजार से ऋण नहीं लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन से प्राप्त जानकारी अनुसार इस वर्ष 2022-23 में तीन राज्यों को छोड़कर 30 राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा 14 मार्च तक 06 लाख 81 हजार 520 करोड़ का बाजार ऋण लिया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं 10 लाख 5 हजार 711 करोड़ रूपये का बाजार ऋण लिया है। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक 83,000 करोड़ तमिलनाडु द्वारा, महाराष्ट्र 64,000 करोड़, उत्तरप्रदेश 44 हजार 500 करोड़, गुजरात 40 हजार करोड़, हरियाणा 40,500 करोड़, कर्नाटक 36 हजार करोड़, मध्यप्रदेश 35,158 करोड़ और असम 17,100 करोड़ शामिल है जबकि छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है बल्कि 2000 करोड़ से पुराने बाजार ऋण का पुर्नभुगतान किया है । (मेजों की थपथपाहट) अजय चंद्राकर जी आप जो आंकड़े बता रहे थे कि 24 परसेंट हो गया, आप 17 परसेंट बता रहे हैं । यह जो आंकड़ा है, यह पुर्नभुगतान 2000 करोड़ करने के बाद आपने जो पढ़ा है वह जनवरी का आंकड़ा है और ये जो आंकड़ें हैं, वर्तमान के आंकड़े हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो प्रतिशत है वह मात्र 17.9 प्रतिशत है । राज्य निर्माण से जनवरी 2023 तक राज्य पर कुल 82 हजार 125 करोड़ का ऋण भार जो कि राज्य के जी.एस.डी.पी. का मात्र 17.9 प्रतिशत है । यह 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत से बहुत कम है जबकि इसी समय में कर्नाटक 19.8 प्रतिशत, झारखंड 20.9 प्रतिशत, उत्तराखंड 21.08 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 22.5 प्रतिशत, तमिलनाडू 24.9 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश 27.2 प्रतिशत, हरियाणा 27.4 प्रतिशत । भारत सरकार का सबसे अधिक वह 47.2 प्रतिशत, भारत सरकार खुद जो जी.एस.डी.पी. का 47.2 प्रतिशत बाजार से ऋण लिया है । हमारे माननीय विद्वान सदस्य हमारी सरकारी की इस मामले में आलोचना करते हैं तो मैंने आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दिये हैं । इन आंकड़ों को आप

वेरीफाई कर लीजिये, यह सही है या गलत ? और उसके बाद मैं इस बात को आपके विवेक पर छोड़ता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान 6144 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 7.7 प्रतिशत है । चालू वर्ष में जनवरी माह तक ब्याज भुगतान 4277 करोड़ है जो राजस्व प्राप्तियों का मात्र 6 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि गत् वर्ष एवं इस वर्ष कम ऋण प्राप्त होने के कारण ब्याज भुगतान भी कम हो रहे हैं। यह 15वें वित्त आयोग के 10 प्रतिशत तक के निर्धारित मापदंड हैं उससे बहुत कम है । हम 10 परसेंट तक ऋण ले सकते हैं लेकिन राजस्व प्राप्तियों का उसमें केवल 6 प्रतिशत है तो आप देखेंगे कि वर्ष 2021-22 में 4642 करोड़ का राजस्व अधिक रहा । इस वर्ष भी जनवरी माह तक 4471 करोड़ राजस्व अधिक होने से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भी या आधिक्य बने रहने की पूर्ण संभावना है । इस प्रकार लगातार 2 वर्षों में राजस्व आधिक्य की स्थिति आगामी वर्ष 2023-24 में भी 3500 करोड़ का अनुमानित राजस्व आधिक्य के साथ निरंतर रखा गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में राज्य का कमिटेड व्यय जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे । मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान शामिल है । कुल व्यय का मात्र 40 प्रतिशत रहा है । इस वर्ष भी यह 40 प्रतिशत के भीतर ही रहने की पूर्ण संभावना है । जबकि पंजाब जैसे राज्य हैं जिसमें 80 प्रतिशत है और दक्षिण का एक राज्य है जो 82 परसेंट तक पहुंच गया है तो उस हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे राज्य हमसे बहुत अधिक हैं और 40 प्रतिशत तक का हम लोगों ने रखा है तो यह स्थिति राजस्व की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चूंकि माननीय सदस्यों ने जो बात कही कि राज्य को केंद्र से अधिक राशि मिलने का आरोप आपने लगाया । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 14,946 करोड़ का ऋण था । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों को कहते हैं कि आपने बहुत ऋण लिया है । जबकि आपके समय वर्ष 2013-14 उस समय 14,949 करोड़ था और दिसंबर 2018 तक 41,695 करोड़ रूपये हो गया मतलब 14,000 से बढ़कर 42,000 करोड़ इसका मतलब यह है 5 वर्षों में आपने 3 गुना ऋण लिया। आप हमें कहते हैं कि आपने ऋण लिया, लेकिन वर्ष 2013 के हिसाब से करें और वर्ष 2018 वित्तीय वर्ष के अंत में देखेंगे तो आपने जो ऋण लिया है वह 3 गुना है। अध्यक्ष महोदय, दिसंबर, 2018 में राज्य सरकार को 41 हजार 695 करोड़ का ऋण था तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक 82 हजार 195 करोड़ रूपये संभावित है। यह ऋण दोगुना है। तो ऋण आपने ज्यादा लिया या हमने ज्यादा लिया? आपने तो 3 गुना लिया, हमने तो दोगुना लिया। अध्यक्ष महोदय, और इसी समय मैं बताना चाहूंगा कि यह स्थिति तब है, जब वित्तीय वर्ष 2022-23 में जून, 2022 के बाद केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. मिलना बंद हो गया। जो आप कहते हैं न, आपने

नवोदित राज्य के साथ जो छल किया है, वह छत्तीसगढ़ कभी माफ नहीं करेगा। आप ही जाकर हस्ताक्षर किये हैं कि 5वें वर्ष तक के आपको जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति मिलेगा, यह नवोदित राज्य, गरीब राज्य, उसके साथ यदि किसी ने अन्याय किया है तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने किया हे। (मेजों की थपथपाहट) अब हमारा जी.एस.टी. मिलना बंद। 5-5, 6-6 हजार करोड़ का हर साल का नुकसान है। बार-बार वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो उत्पादक राज्य है, उसके साथ अन्याय न हो, ये हमें मिले, लेकिन इस मामले में मौन हैं। अध्यक्ष महोदय, अब इस मामले में सब मौन हैं। एक शब्द भी नहीं बोलते। जो क्षतिपूर्ति मिल रहा था, उसके बारे में हमारे सदन के विपक्ष के साथी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुंह में ताला लग गया है।

श्री भूपेश बघेल :- वह मैं नहीं कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोयला रॉयल्टी, उसको रोक दिये हैं। जितने भी हमारे जो खनिज है, उसमें रॉयल्टी हर 3 साल में रिव्यू करना था, उसे बढ़ाना था, लेकिन उसमें रॉयल्टी में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप विदेश से 12 हजार, 14 हजार में कोयला लायेंगे, उसे आप हमें महंगा खरीदने के लिए बाध्य करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कोयला उत्पादन होता है, लोहा उत्पादन होता है, उसमें आप रॉयल्टी नहीं बढ़ायेंगे। इस मामले में हमारे विपक्ष के साथी मौन हैं। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार बनी है, अब मैं उसके ऋण के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कुल ऋण जब पहले बना, जब आप केन्द्र में सत्ता में आये तब कुल ऋण 55 लाख 87 हजार करोड़ रूपया था और विगत 9 वर्ष में वह बढ़कर 152.61 प्रतिशत मतलब कहां 55 और कहां 152, 3 गुना आपने बढ़ा दिया। जब आप यहां थे तब आपने 3 गुना बढ़ाया, जब आप वहां गये तब भी आपने 3 गुना बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से वित्तीय स्थिति आज केन्द्र के कुल ऋण के अनुसार देश के प्रति व्यक्ति 1.09 लाख रूपये का ऋण भार है। प्रति व्यक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान ऋण के अनुसार जनवरी, 2023 की स्थिति में प्रति व्यक्ति ऋण भार 27 हजार 139 रूपया है। भारत सरकार ने हर व्यक्ति पर 1 लाख 9 हजार रूपया का ऋण भार डाला है और हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 27 हजार 139 रूपये है। अध्यक्ष महोदय, इसमें धरमलाल कौशिक जी बोल रहे थे कि इतना कम कैसे हो गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 के बाद केन्द्र सरकार से जो हमें मिलना था, उसमें 11 हजार करोड़ की कमी आयी। अध्यक्ष महोदय, 11 हजार करोड़ रूपये केन्द्र से कमी आयी। मात्र 4 हजार करोड़ की कमी हमारी राज्य सरकार से हुआ और इस कारण से एक लाइन में आपका जवाब मैं देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने धान संग्रहण पर बहुत बातें कीं, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे। माननीय अजय जी, शिवरतन जी सभी सदस्यों ने यह बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति क्या थी, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी

की व्यवस्था आपने शुरू नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने की थी। हम लोग सब मंत्रिमंडल में थे। धान खरीदी की शुरूआत हमारी सरकार में हुई और उसको निरन्तरता आपने दी । आपने सोसायटियां बढ़ाईं, संग्रहण केन्द्र बढ़ाए । लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था । आपको 15 सालों का अवसर मिला लेकिन इन 15 सालों में आपने किया क्या ? आपके समय में स्थिति यह थी कि जब कोई किसान धान बेचने जाए तो वह रात-रात भर रतजगा करता था । धान की तौलाई नहीं होती थी, उसके लिए लाईन लगाना पड़ता था, यदि धान बिक गया तो फिर बैंकों में पेमेंट के लिए लाईन लगती थी । हर साल राईस मिलों की हड़ताल होती थी, जैसे ही धान खरीदी शुरू हुई तो 15 दिनों तक तो राईस मिलर्स हड़ताल पर रहते थे । बृजमोहन जी ज्यादा अच्छे से जानेंगे क्योंकि उस समय हमारे योगेश भाई अध्यक्ष हुआ करते थे । इन्हीं की सरकार के खिलाफ इन्हीं की पार्टी के नेता आंदोलन करते थे । मिलिंग चार्ज, जब आप मध्यप्रदेश में मंत्री थी उस समय दिग्विजय सिंह जी ने 40 रूपए किया था, उसके बाद से बढा ही नहीं, बल्कि कम हो गया । 35 रूपया कर दिया गया था । अध्यक्ष महोदय, उनकी समस्याओं को हम लोगों ने देखा, सुना और समझा । उसको बढ़ाकर 120 रूपया किया । अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम क्या हुआ ? आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश का हमने कोई 52 लाख, 57 लाख मेट्रिक टन धान नहीं खरीदा, इस साल हमने 107 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा । आज पूरे सोसायटियों से 98 प्रतिशत धान उठ गया । कहीं धान संग्रहण केन्द्र में जाना नहीं पड़ा । केवल 2-3 लाख मेट्रिक टन धान ही संग्रहण केन्द्र में गया है । हमारा ट्रांसपोर्टिंग बचा, हैंडलिंग चार्ज बचा, सूखत बचा । यदि आप इसका हिसाब करेंगे तो हजार/बारह सौ करोड़ से अधिक की राशि राज्य सरकार की बची है । आपके समय में भी और हमारे समय में भी हुआ । जब उठाव नहीं हो रहा था, बरसात में धान पड़ा रहता था, कैप कव्हर नहीं है, अगर आप विधान सभा की कार्यवाही निकालेंगे तो कितनी चर्चाएं होती थीं । लेकिन उसका निष्कर्ष निकला । जैसे ही हमने राईस मिल चलाने को लाभकारी बनाया तो आज 300 से अधिक राईस मिल छत्तीसगढ़ में खुल गई हैं । उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है । अगर मैं अकेले बलौदाबाजार जिले की बात करूंगा तो ट्रांसपोर्टिंग-ट्रांसपोर्टिंग में, सोसायटी से धान संग्रहण केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र से राईस मिल इसको व्यवस्थित कर दिया तो अकेले बलौदाबाजार जिले में सरकार का 22 करोड़ रूपए की बचत हो गई । आज हम पर आरोप लगा रहे हैं । आपके समय में क्या होता था ? धान का सूखत, धान की कमी, धान गीला और उसके बाद ट्रांस्पोर्टिंग, फिर कौन करता था ट्रांसपोर्टिंग । स्कूटर में ट्रांसपोर्टिंग होती थी । यह स्थिति थी । अध्यक्ष महोदय, आज इतनी धान खरीदी होने के बाद भी एक भी शिकायत न तो बारदाना की, न तौलाई की, न टोकन की । टोकन तो ऑनलाईन कर दिया है । सोसायटियों में, धान खरीदी केन्द्रों में लम्बी लम्बी लाईन भी नहीं लग रही है । उसके बाद 3 दिन के अंदर भुगतान हो रहा है । इनके समय में तो 8-15 दिनों तक भुगतान नहीं होता था । उसके लिए भी चक्काजाम होता था, हड़ताल होती थी, आंदोलन होता था । यह परिवर्तन आया है । अध्यक्ष महोदय,

हमारे सौरभ सिंह जी नहीं हैं । वे कहते हैं कि ई.डी. के कारण राजस्व में वृद्धि हुई । अध्यक्ष महोदय, सामान्य ज्ञान के मामले में इनकी बुद्धि पर तरस आता है । यदि ऐसा ई.डी. के कारण है तो मैंने आंकड़े बताए कि मध्यप्रदेश में कितना लोन लिया गया, उत्तर प्रदेश में कितना लोन लिया, कर्नाटक में बाजार से कितना लोन लिया ? तो ई.डी. का छापा वहां भी डलवा देते तो जी.एस.टी. बढ़ जाता, राजस्व बढ़ जाता । केन्द्रीय कार्यालयों में छापा क्यों नहीं डाल देते, बाजार से 47 परसेंट कर्जा तो वहीं लिया गया है । केन्द्र सरकार ने कर्ज लिया है, यदि इस प्रकार से होता है तो उन्हीं के कार्यालयों में डालना चाहिए । माननीय बृजमोहन जी शून्यकाल में अच्छी बात कह रहे थे । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी उठाया और शून्यकाल में बृजमोहन जी ने भी उठाया । देश में लोकतंत्र है, सत्ता का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा। किस प्रकार से आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग रायपुर में आंदोलन किए। हम सबने देखा कि पुलिस वालों को किस प्रकार से उकसा रहे थे, किस प्रकार से उस पर हाथापाई कर रहे थे, किस प्रकार से उससे झूमाझटकी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर में जो [XX] किया है, पुलिस पर हमला, इंस्पेक्टर को उठाकर पटक रहे हैं। एस.पी. के सर को फोड़ दिए। (शेम-शेम की आवाज) उसके बाद भी आप कहते हैं कि कार्रवाई न हो। आपको लोकतंत्र पर विश्वास है। क्या आप यही प्रशिक्षण देते हैं ? आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हिंसा करवाईए। आप कवर्धा की बात कह रहे हैं। आप कवर्धा में पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

(माननीय सदस्य (श्री शिवरतन शर्मा) द्वारा हाथ उठाने पर)

मुझे पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.डी. का दुरूपयोग तो आपने किया। जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, तीन दिन पहले हमारे सब नेताओं के यहां, यहां दो-दो विधायक हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबके यहां छापा डाल दिए। जिस दिन 24 तारीख को हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया तो जो वेण्डर हैं, उसके यहां 6 घंटे जाकर बैठ गये। मतलब आप अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए किस स्तर पर जा रहे हैं और मिला क्या ? किसके यहां क्या मिला ? देवेन्द्र के यहां क्या मिल गया, रामगोपाल के यहां क्या मिल गया, गिरीश देवांगन के यहां क्या मिला ? अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गयी जो हमारे विनोद तिवारी हैं, उसके घर में गये। वे किराये के मकान में रहते हैं, उसका भाई उपर में रहता है, वहां दरवाजा खटखटाए, बोले विनोद तिवारी हैं, यहां तो विनोद तिवारी नहीं हैं, हम लोग ई.डी. वाले हैं, अच्छी बात है, कहां हैं ? नीचे के कमरे में हैं। उनका कमरा नीचे है। ई.डी. इतना बड़ा, इंफोर्समेंट डायरेक्टर, जो परिवर्तन निदेशालय कहलाता है। किसके घर छापा डाले ? उनके कमरे में गये तो आधा में टाईल्स लगा हुआ था, आधा में नहीं लगा था। उसके घर में उनके कमरे में कुछ पेपर पड़े थे, वह जो रमन सिंह जी के आय से अधिक संपत्ति के कागजात थे, वह

सब पूरा कमरे भर फैला दिए। उन्होंने फोटो भी डाला। उसको जप्त करने के लिए इसको ले जाओ। कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह ई.डी. की कार्रवाई है। आप सत्ता का दुरूपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। यह पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है। बृजमोहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रकार की शक्तियों का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात को आप भी समझ लीजिए। (मेजों की थपथपाहट) आज आपने जिस प्रकार से दुरूपयोग किया है, उसकी कोई मिशाल नहीं मिलेगी। आप कुछ बोल रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारायणपुर की घटना की जिक्र किया कि पुलिस वालों को मार रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपकी संज्ञान में ला देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को टी.आई. अपनी मोटरसाइकल में बैठाकर ले गया, चलिए उत्तेजित भीड़ है, उसको समझाने में सहयोग करो और वह समझा रहा था, लेकर गया और उनको बंद कर दिया। आप नारायणपुर की घटना में जिस टी.आई. को मारने की बात कर रहे हो, जिनने मारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा टी.आई. ने लिखकर दिया कि मैं दौड़ रहा था तो गिर गया। मारने वाले कौन लोग थे आप पता करवा लेना।

श्री भूपेश बघेल :- वह वीडियो हमने देखा है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर की घटना मार खाने वाला मंडल अध्यक्ष, मारने वाला भाजपा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और पुतला सी.एम. साहब का जला रहे हैं। यह ऐसा ही इनका करतूत है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आवास के मामले में अब देख लिए। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। क्यों, इनके समय में 12 लाख किसान थे, आज बढ़कर साढ़े 23 लाख हो गया जो धान विक्रय कर रहे हैं। रकबा 24 से बढ़कर 31 लाख हेक्टेयर हो गया। जो धान खरीदी करते थे, वह 55-60 लाख से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, किसानों का विश्वास बढ़ा है और 11 लाख से अधिक किसान जो खेती को छोड़ चुके थे, वह किसान लौटे हैं। (मेजों की थपथपाहट) जो शहर में थे, वह किसान गांव गये हैं। यह स्थिति बनी है। जो रेग देते थे, अधिया देते थे, उसमें बहुत कमी आ गई है। किसान के खाते में 22 हजार करोड़ रूपये गये हैं। किसान तो इनके साथ नहीं हैं। जो गरीब मजदूर हैं, उनके लिए हम योजना लाये हैं। हम साल भर से सालाना उनको 7 हजार रूपये दे रहे हैं। अब उस योजना का विस्तार करते हुए नगर पंचायतों में ले जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) नगर पंचायत भी करीब-करीब ग्रामीण परिवेश ही होता है। वहां के मजदूरों को भी हम इसका लाभ देने वाले हैं। मजदूर भी इनके साथ नहीं हैं। तो यह आंगनबाड़ी, मितानिन के आंदोलन में पहुंच गये। यह उनको खूब समर्थन दिये। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता वहां गये थे। घोषणा पत्र में है कि आपने यह किया है, वह किया है, इसका बढ़ाओ।

जैसे ही यह बजट प्रस्तुत हुआ तो अब कभी यह इसको रेवड़ी कहते हैं तो कभी कहते हैं कि यह लागू नहीं हो पाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक चीज बताइये कि हमने कोटवार का वेतन बढ़ाया, हमने पटेलों का वेतन बढ़ाया, हमने रसोइया का वेतन बढ़ाया, हमने सफाईकर्मी का वेतन बढ़ाया, हमने मितानिन का वेतन बढ़ाया, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया, हमने सहायिका का वेतन बढ़ाया, हमने मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन बढ़ाया। यह पैसा तो 1 अप्रैल के बाद से इनको मिलना शुरू हो जाएगा, क्या या यह भी चुनाव के बाद मिलेगा? इस पवित्र सदन में यह बजट पास होगा और उसके तुरंत बाद उनको मिलना शुरू हो जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) तो यह कहां से लॉलीपॉप हो गया? यह कहां से चुनावी बजट हो गया? यह कहां का रेवड़ी है? यदि इन गरीब लोगों, किसान लोगों, मेहनतकश लोगों को पैसा मिल रहा है, उनके मानदेय में वृद्धि हो रही है तो यह उसे रेवड़ी कहते हैं। जनता देख रही है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है तो एक मुद्दा बच गया है, आवास। आवास में रोज आंकड़े आ रहे हैं। कोई बोलता है 18 लाख, कोई बोलता है 16 लाख, कोई बोलता है 7 लाख, कोई बोलता है 10 लाख और कोई बोलता है 11 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है। माननीय अजय जी कहते हैं कि हमारे शासन काल में सबसे ज्यादा आवास बने हैं। यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि यह आपके शासन काल में शुरू हुआ था। बनने ही बनने हैं। क्यों नहीं बनेंगे? आपने और आपकी सरकार ने इसकी शुरूआत की थी। लेकिन यदि आप वित्तीय वर्ष 2016-2017 में देखेंगे तो 18 लाख हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में आया कि 18 लाख लोग नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरे देश में यहां सर्वाधिक गरीबी है। यहां 40 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। यह आर.बी.आई. की रिपोर्ट है। यदि उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और आप लोग हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपने छत्तीसगढ़ की जनता को गरीब बनाकर रखा है। 18 लाख लोग मकान भी नहीं बना पा रहे हैं। यह कोई कम आंकड़ा नहीं होता है लेकिन आपने कितने आवास स्वीकृत किये? 2 लाख 32 हजार। फिर वर्ष 2017-2018 में आपने 2 लाख 6 हजार आवास स्वीकृत किये। वर्ष 2018-2019 चुनावी वर्ष था तो 3 लाख 48 हजार 960 आवास स्वीकृत किये गये। लेकिन इसके लिए आपने कर्ज लिया। उस कर्ज को कौन पटाएगा? आपने आवास को स्वीकृत तो कर दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मजेदार आंकड़ा तो अब आएगा कि आपने यह राशि कब आहरित की? मतदान कब हुआ? 20.11.2018 को मतदान हुआ। मतलब, उस वक्त आचार संहिता लग गया था। आपने आचार संहिता लगने के बाद, मतदान होने के बाद दिनांक 29.11.2018 को 250 करोड़ रूपये की राशि आहरित की। यह तो हद हो गई जब मतगणना हो गई, तब आपने दिनांक 05.12.2018 को 346 करोड़ रूपये का ऋण लिया। कुल मिलाकर आपने 900 करोड़ रूपये का ऋण लिया है। आपकी यह स्थिति है और आप गरीबों की बात कर रहे हैं। आपको 3-3 बार मौका मिला। यह बिल्कुल सही है कि हम 2 साल

नहीं कर पाये। वह कोरोना काल था। हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी तो हमारी वित्तीय स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? इसीलिए आप जो आंकड़े दे रहे हैं, उसमें मैं कहना चाहूंगा । आपके जितने मिस्ड कॉल आये हैं, जितने फार्म भरवाये हैं, हमको सब दे दीजिए । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, वह आंकड़े मुझे दे दीजिए, लेकिन कृपा करके यह बताएं कि जो डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे हैं, वह आंकड़ा सही है या माननीय बृजमोहन जी कह रहे हैं, वह आंकड़ा सही है या माननीय केदार कश्यप जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिए, वह सही है ? एक सदस्य 17 लाख का आंकड़ा बताते हैं, दूसरे सदस्य 12 लाख, तीसरे सदस्य 10 लाख और कोई 7 लाख का आंकड़ा बताते हैं । ए.सी.सी.सी. के जो 18 लाख के आंकड़े हैं, उससे बढ़कर 27 लाख का आंकड़ा हो रहा है । हो सकता है कि उससे भी अधिक हो । इसीलिए मैं कह रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने बहुत सही प्वाइंट उठाया । जनगणना केवल भारत सरकार करा सकती है । उन्होंने बहुत सही कहा, मैं उस बात से सहमत हूं, इससे पूरा देश सहमत है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने 2021 की जनगणना नहीं करायी । जो आपने गलती की है, उसके लिए गरीब लोग दंड क्यों भोगे ? (मेजों की थपथपाहट) आप जनगणना करा दें । जनगणना हुए 12 साल हो गए, यदि जनगणना होती तो नये हितग्राही बनते, नये हितग्राहियों को आवास की सुविधा मिलती । जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की शासकीय योजना है, उसका लाभ मिलता । इससे किसी ने वंचित किया है, वह पाप किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- मुख्यमंत्री जी, अभी आपने ही कहा कि कोरोना के कारण सरकार बहुत से काम नहीं कर पायी । 2021 में जो जनगणना नहीं हो पायी, उसमें भी तो कोरोना है, कोरोना के कारण तो जनगणना नहीं हुई ।

श्री भूपेश बघेल :- फिर फार्म भराने की नौटंकी क्यों ? ये जो गम्मत की बात हो रही थी न, वह गम्मत कर रहे हैं । कल गम्मत होने वाला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना नहीं हुई तो कोरोना के कारण नहीं हुआ । माननीय धरम लाल कौशिक जी बोल रहे हैं कि आपने वित्तीय वर्ष में इतना कम खर्च किया है तो छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं था ? केवल देश के बजट के लिए कोरोना था । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कोरोना काल के बाद भी कितने ही राज्य हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के वेतन में 30-30 प्रतिशत की कटौती की, केन्द्र सरकार ने स्वयं ही सांसदों के वेतन-भत्तों में कटौती की । और तो और दो साल तक जो एम.पी. लेड है, उसको भी बंद कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ ने नहीं किया, (मेजों की थपथपाहट) बल्कि वेतन भी बढ़ा है और क्षेत्र विकास निधि भी 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए किया, अब तो वह 4 करोड़ हो गयी, न हमने कर्मचारियों का वेतन कम किया ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब ने अपने पत्र में 08 लाख मकान, 08 लाख गरीब परिवार लिखा है । कम से कम आप उसकी बात कर लेते । यह आपके ही मंत्री ने पत्र में लिखा है । कल विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में 14 लाख का आंकड़ा दिया है ।

श्री भूपेश बघेल :- उन्होंने कहा । नेता जी, आप पता नहीं कहां-कहां से आंकड़े ले आते हैं । आप सज्जन आदमी हैं, इनके चक्कर में मत आईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, यह ऑन रिकार्ड है । माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब ने अपने पत्र में 08 लाख का जिक्र किया है । कल माननीय रविन्द्र चौबे जी ने धरम कौशिक जी के प्रश्न के उत्तर में 16 लाख मकान का जिक्र किया है, उसमें 14 लाख मकान देना शेष है, यह लिखा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको भटकाने के लिए लिखा था इसीलिए आप अभी तक भटकते रह गए ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपके समय में 8 लाख मकान बने थे। 18 लाख मकान में 11 लाख मकान स्वीकृत हो गए तो कितना बचा ? 7 लाख मकान की बचेंगे न । तो गलत कहां है ? लेकिन आप लोग जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं । अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत देर से आपका हाव-भाव बता रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कुछ नहीं कहना चाहता । आपको इस पवित्र सदन पर भरोसा है ?

श्री भूपेश बघेल :- लो, कर लो बात ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपने जो-जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, कल समय दीजिए, मैं उसको प्रस्तुत कर दूंगा । आपका आंकड़ा दुरूस्त नहीं है तो कार्यवाही कीजिए । विधान सभा में गलत उत्तर दिए हैं तो उधर बैठे हैं, उनके ऊपर आप कार्यवाही कीजिए । आप अवसर दीजिए, आपके अधिकारियों ने जो-जो उत्तर दिये हैं, उसको मैं पटल पर रख दूंगा । फिर आंकड़े सामने आ जाएंगे । मैंने कल आपके मंत्री जी को कहा कि मेरे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उसे छोड़िए । हम दोनों किसी के सामने बहस कर लेते हैं । अभी चुनौती स्वीकार करवा लीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इस सदन में हम बहस करने के लिए ही बैठे हैं । न भाग रहे हैं, न डर रहे हैं । आप बोलिए न, हम उत्तर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी क्या विश्वसनीयता है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- यहां बैठे क्यों हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी क्या विश्वसनीयता ?

श्री रविन्द्र चौबे :- यहां बैठे क्यों हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी क्या विश्वसनीयता ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको उत्तर देने के लिए बैठे हैं। कोई नहीं भाग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो विधानसभा के आकड़ें हैं, कल मैं पटल पर रख देता हूं। मैं विधानसभा का आकड़ा पटल पर रख देता हूं।

डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशीष सिंह :- कल के आंदोलन के पहले यह सब पेपर में छप जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये वर्षवार आकड़े विधानसभा में टेबल करने की अनुमति दीजिये, आकड़ा निकल जायेगा।

अमरजीत भगत :- और आप इस्तीफा दिए ? अजय चन्द्राकर जी, आपके बात करने में कोई दम ही नहीं है। आपने तो कहा था कि अगर किसानों को पैसा मिलेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। आपने दिया क्या ? आप मुंह से बात करते हैं या किस चीज से बात करते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उनको उत्तर दूं ?

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है न भईया, आपने जो सवाल किया है, मैं उसका उत्तर दे देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका जवाब दे देता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- जब वह बोलेंगे, उस समय दे दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपको सुनना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने जो बात कही कि कल चर्चा हो जाये। अध्यक्ष महोदय, आप जिस दिन सुनिश्चित करेंगे, पंचायत विभाग की चर्चा होगी, उसमें आपको जितना भी बहस करना है, जितना आकड़ेबाजी देना है, वह आप रखियेगा, इधर मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सदन तो चर्चा के लिए ही है। अध्यक्ष महोदय, ये कौन से आकड़े गलत है। आपको उसको चुनौती देना है तो उसकी प्रक्रिया है, आप चुनौती दीजिये, आपको कौन रोक रहा है। अजय जी, सदन में चर्चा करने का समय, तिथि करने का अधिकार मुझे नहीं है, आसंदी को है। जहां तक चर्चा की बात है। तो हर विभाग की चर्चा होनी है, आप पलायन मत करियेगा। सभी विभाग की चर्चा होगी, उसमें जवाब मिलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चाहते हैं क्या कि हम पलायन करें ? हम चर्चा ना करें, आप चाहते हैं क्या ? हाऊस कम चलाना चाहते हैं क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- बिलकुल कम नहीं चलाना चाहते हैं, पूरा चलाना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्योंकि आप तो 13 दिन वैसे ही कम कर दिए हो। हम कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि पलायन मत करियेगा। तो मंशा स्पष्ट कर दीजिये। अभी भी गिलोटिन चलायेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यदि गिलोटिन ही कराना होता तो रात को चर्चा क्यों करते। रात को 9 बजने वाला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें आप ही भर भागीदार नहीं हो, हम भी 9 बजे तक बैठने में भागीदार हैं, आपके जितने जिम्मेदार हम भी हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आसंदी ने सबसे ज्यादा मौका आपको दिया है। अभी जितने नाम पढ़े हैं, अधिकांश नाम आपके हैं। जो अनुपस्थित हैं, उनको भर बोलने का मौका नहीं मिला, जितने हैं, उन सबको मौका मिला है। हमारे इतने साथी उपस्थित हैं, उनके बाद भी आपको मौका मिला। हम सदन चलाना चाहते हैं। सुनिये अजय जी, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने भी सहयोग दिया है, आपने भी सहयोग दिया है, यह सदन 3-3 बजे रात तक चला है।

श्री भूपेश बघेल :- हां चला है न, मैं कहां कह रहा हूं। अजय जी, उत्तेजित तो मत होइये। थोड़ा रूको।

श्री रविन्द्र चौबे :- जैसे-जैसे रात चढ़ते जाती है आप उत्तेजित क्यों होते जाते हो, पहली बात।(हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, मैंने आपको कहा कुछ लोगों की जांच की व्यवस्था कीजिये। जो मंत्री जी की तरफ से खाना है, इतना गरीब मत बनाईये। उधर व्यवस्था करवाईये। मंत्री जी को बोलिये, कम से कम चाय रखवा दे। नहीं है तो फिर हम नेता प्रतिपक्ष की ओर से व्यवस्था करवा देते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- दादी थोड़ा ध्यान रखा कीजिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपका भी टाइम हो गया है क्या ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- जब आपने मेरी ओर इशारा किया है तो मैं बता देता हूं कि 10 घंटे 23 मिनट की चर्चा हुई है। ये लोग (विपक्ष) 6 घण्टे बोले हैं और 3 घण्टे इधर (सत्तापक्ष) के लोग बोले हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अब इससे उदार अध्यक्ष और क्या चाहिए। आप उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते। हम लोग धैर्यपूर्वक सुनते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारा काम संतुष्ट होने कैसे हो सकता है। हमको जनादेश असंतुष्ट रहने के लिए है। (हंसी) बोलिये, अब आपको कोई आपत्ति हो तो।

श्री भूपेश बघेल :- भगवान करे आप जिन्दगी भर असंतुष्ट रहें। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिये, हमारी शुभकामनाएं हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमेशा असंतुष्ट रहें।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पता नहीं कहां-कहां से आकड़े ले आयेंगे। डॉ. रमन सिंह उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ 8 हजार मकान बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की वेबसाइट देख लीजिये, वर्ष 2019-20 में 88,764 आवास पूर्ण किए गए। अब वह कहते हैं कि दाऊ 16 लाख आवास छीनने वाले व्यक्ति हैं। टोटल 18 लाख तो आवास है, आप लोग 8 लाख आवास

बना चुके हैं, 11 लाख आवास स्वीकृत है तो मैं कहां से 16 लाख आवास छीन लूंगा ? अध्यक्ष महोदय, यदि इनकी बात सही भी मान लूं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी आवेदन, फार्म भरवाये हैं, मुझे दे दीजिये, मै एक-एक आवेदन का वेरीफिकेशन करवाऊंगा, जो मिस्ड काल कराये हैं, उसको भी दे दीजिये, उसका वेरीफिकेशन कराऊंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- फर्जी नहीं निकलना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वह जैसे सदस्यता अभियान चलाये हैं। अच्छा शहरी के बारे में नहीं बोलेंगे न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने तो उसके बारे में नोटिस दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- शहरी के बारे में नहीं बोलेंगे ना । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूँ । शहर में राज्यांश नहीं दिया है, यह आरोप लगाते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में योजना प्रारंभ हुई । वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2018-2019 तक राजस्व जो जारी किया है, वह 271 करोड़ है, फिर हमारी सरकार आई । वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2022-2023 तक हमने 2116 करोड़ रूपया राज्यांश जारी किया। अध्यक्ष महोदय, कहां 271 करोड़, कहां 2116 करोड़, 8 गुना ज्यादा हमने राज्यांश जारी किया है, राशि जारी की है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में कुल राशि जो व्यय हुई है वह 1241 करोड़, हमारी सरकार ने व्यय किया 2763 करोड़, इसमें भी सवा दो गुना से ज्यादा हमने व्यय किया । अध्यक्ष महोदय, भौतिक प्रगति की बात करें तो वर्ष 2015 से प्रारंभ योजना में वर्ष 2018-2019 तक इन्होंने मात्र 19042 आवास बनाये हैं, आंकड़ा याद रखियेगा 19042 आवास है और हमने 2019-2020 से लेकर वर्ष 2022-2023 तक 93,0725 यानी आपने जितना बनाया है, उससे हमने 5 गुना ज्यादा आवास बनाये हैं । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, 8 गुना ज्यादा राज्यांश दिया है, दोगुना से ज्यादा व्यय किया है, 5 गुना से अधिक आवास हमने बनाया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूँ । आप आवास के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं ना ? अध्यक्ष महोदय, इनके नेताजी ने कहा है कि जितने भी उज्जवला योजना वाले हैं ना, उनके साथ सेल्फी लेना है, शौचालय के साथ बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि केवल उज्जवला के लिये बोले हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- शौचालय सेल्फी लेने मत जाना । कोनो भंईसा वगैरह रगड़ेगा ना तो भसक जायेगा । खतरा हो जायेगा भईया । सारे शौचालय इतना कमजोर बनाये हो ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ। जहां मैं आवास और उज्जवला के बारे में बोलना शुरू किया, बस इसके बाद खत्म कर दूंगा । अध्यक्ष महोदय, यह उज्जवला योजना वर्ष 2016-2017 में शुरू हुआ है । आज स्थिति क्या है कि ऐसे हितग्राही जिन्होंने एक बार भी सिलेण्डर रिफिल नहीं किया है, वर्ष 2017-2018 में 23 परशेंट, वर्ष 2018-2019 में 49 परशेंट, वर्ष 2019-2020 47 परशेंट, वर्ष 2020-2021 में क्योंकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत 3

सिलेण्डर रिफिल ऑफ कास्ट दिया था, उस समय 6.5 प्रतिशत था, लेकिन दिसम्बर में 46.17 प्रतिशत, आधी आबादी ने जितना सिलेण्डर दिया, उन्होंने एक बार भी रिफिल नहीं कराया है, यह स्थिति है । (मेजों की थपथपाह) आपने 400 रूपये से बढ़ाकर 1200 रूपये कर दिया है । जब 400 रूपये था तो स्मृति ईरानी जी सिलेण्डर लेकर बैठती थी, हेमामालिनी बैठती थी, अब लोग खोज रहे हैं कि कहां है ? अब 1200 रूपये हो गया है । अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से जब मैं लगातार दौरे में था, शौचालय की बड़ी शिकायत आई । बना नही, पैसा नहीं मिला, शौचालय का भुगतान भी अभी नहीं हो पाया है, आज तक नहीं हो पाया है । आपने ओ.डी.एफ.घोषित कर लिया है, ओ.डी.एफ. प्लस करवा लिया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, भौतिक जांच करायेंगे तो सब की कलई खुल जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नवीन जनगणना और एसीसी सर्वे की आवश्यकता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, पत्र भी लिखा है कि जनगणना कराईये, सर्वे कराईये, ताकि नये हितग्राहियों को उसका लाभ मिल सके । अध्यक्ष महोदय, तीनों चीज का सर्वे कराने की मैंने घोषणा की थी, इन लोग पलायन कर दिये थे । आवास का भी, इन लोग जो आवेदन देंगे उसको भी, जो नये हितग्राही होंगे, उसके लिये भी हम फारमेट बना रहे हैं ।

समय :

9.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला का भी और शौचालय का भी। हमने तीनों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है, ताकि पता चले कि क्या स्थिति है। ये बार-बार कहते हैं कि केन्द्र सरकार से पूरी मदद मिल रही है लेकिन अध्यक्ष महोदय 2013-14 केंद्रांश और राज्यांश कितना था अब 2014-15 में केंद्रांश और राज्यांश की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 75-25 था, इनके समय में 60-40 हो गया, सर्व शिक्षा अभियान 75-25 था, वह 60-40 हो गया, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम 65-35 था, वह बढ़कर 60-40 हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 100 प्रतिशत भारत सरकार से मिलता था अब 60-40 हो गया, नरेगा 90-10 था, अब 75-25 हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने उसमें भी कटौती कर दी है, बजट में कटौती कर दी है। ग्रामीण राष्ट्रीय पेयजल योजना, पहले 75-25 था, अब वह 50-50 प्रतिशत हो गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 65-35 था, अब उसमें 60-40 का अंतर आ गया है, एकीकृत बाल विकास योजना 85-15 था, अब वह 57-43 हो गया। यह कहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति..। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बृजमोहन जी को अब कहीं और जाना है, उनको कल की तैयारी करना है। परसो थोड़ा-सा फोटो छपे, मीडिया में आये, इसलिये मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, यह गरीबों के लिये, किसानों के लिये, मजदूरों के लिये, आदिवासियों के लिये, अनुसूचित जाति के लिये और नौजवानों के लिये है। अब मैं समाप्त कर रहा हूं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, समाप्त होने से पहले ही बोलना है।

श्री भूपेश बघेल :- मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसके बाद नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, समाप्त करने के पहले बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- फिर मुझे बोलना पड़ेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, क्या है वह सुन तो लीजिये । समाप्त हो रहा है इसीलिये ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह क्या बार-बार ऊंगली-ऊंगली करते रहते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- मैं अब समाप्त कर रहा हूं। आप बोलेंगे तो फिर लंबा खीचेगा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा विनम्र आग्रह है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- (व्यवधान) मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा था।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कहा कि मेरा विनम्र आग्रह है।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह गलत परंपरा है, यह गलत परंपरा है।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट सुन तो लीजिये। हर बात में खड़े मत होया करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- बार-बार ऊंगली करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो भी कहा होगा। उसमें समय आने पर प्रत्युत्तर, उत्तर करेंगे, वह अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के भाषण में, खासकर कि बजट भाषण में सबको अपेक्षा रहती है कि मुख्यमंत्री, चाहे वह पक्ष के हो या विपक्ष के, माननीय विधायकों की मांग में कोई घोषणा करेंगे। इतना निरश, आपने लोगों को इतना निराश कर दिया। इतने सदस्यों ने बोला, आपने उसमें एक घोषणा नहीं की।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल में .. (व्यवधान)।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट सुनो तो।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, यह क्या है ? मैं आपसे एक आग्रह करूंगा।

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान) कितना था ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपसे एक आग्रह करूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- अभी तो विनियोग बचा है।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिये तो, यह बजट भाषण की बात है। अपने लिये घोषणा कर दीजिये, साजा के लिये कर दीजिये या तो मेरे लिये कर दीजिये। छोटा-मोटा कुछ भी बोल दीजिये। आपके बजट भाषण में एक-आत घोषणा हो जायेगी तो उससे सदन की गरिमा बढ़ जायेगी।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा का और माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी मुझे पूरा ध्यान है। बहुत सारे साथियों ने मुझसे बोला भी। धर्मजीत भैया भी आये थे और कई

माननीय विधायकों ने लिखकर दिया है। मैंने कहा कि सबको एक्जाई कर लेता हूं और उसके बाद विनियोग में इसकी घोषणा करूंगा। आप सिर्फ अपनी बात कहते हैं, सुनते नहीं है। मैंने यही कहा कि अभी बहुत सारे साथी दे रहे हैं, कुछ दे चुके हैं, कुछ लोग देने वाले हैं। क्योंकि ऐसे हर क्षेत्र में मांग तो बहुत होती है। आप ही जाते हैं तो आपके पास 4 करोड़ रूपये देने का लिमिटेशन है लेकिन डिमांड कितने की आती है, 6 करोड़ की। आप आखिर में कहते हैं कि यह काम पहले कर ले, यह काम बाद में करेंगे। जो प्राथमिकता है वह काम तय कर ले। मैंने सभी सदस्यों से कहा कि आप मुझे लिखकर दे दीजिये मैं सभी की समीक्षा कर लेता हूं, अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा कर लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने भी मुझे कक्ष में बुलाकर कुछ बातें कही।

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोगों की भी बैठक बुलवा लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आप से भी मिला हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कहा कि बजट के लिये बैठक बुला लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- बजट नहीं। मैं आपसे मिला हूं। ऐसी बात क्यों करते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ इनसे पूछे। हम लोगों से भी पूछ लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- हां, हां, बिल्कुल।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, अकेले में मिलते हो और यहां सबके सामने ऐसा बोलते हो।

श्री भूपेश बघेल :- पुन्नू भैया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अजय जी को थोड़ा समझाईये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह उधर बैठ गये। यह उधर भी बैठते हैं, इधर भी बैठते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हां, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं सबको मौका देना चाहता हूं..।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम लोग भी है। अब एस.सी. के वफादार है तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल-बिल्कुल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की यहां बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, उसके बाद कुछ बचा भी है। कुछ लोगों को और अपेक्षाएं हैं। अभी जब क्षेत्र में जाते हैं या फोन करते हैं कि भईया, बजट हुआ है सब साथी लोग बोलते हैं कि यह काम छूट गया, वह काम छूट गया। मैंने कहा कि ठीक है इसमें मैं आज घोषणा नहीं करूंगा। मैं विनियोग के दिन इसकी घोषणा करूंगा, यह मैंने कहा है। आज निश्चिंत रहिए कि आपकी भावनाओं का सम्मान किया जायेगा। आपने जो याद दिलाया, मैं उसके लिए धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमारे नेता प्रतिपक्ष जी सरस्वती साईकिल योजना के बारे में बोल रहे थे कि बजट में इसके लिए कुछ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 के बजट में

भी अनुमानित से निश्चित रूप से क्योंकि कोरोना काल था तो उस बजट में 14 प्रतिशत की कमी हुई थी, सरस्वती साईकिल योजना के लिए नहीं है। कुल बजट में 14 प्रतिशत की कमी आई थी और मैं आपको सरस्वती साईकिल योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में 1 लाख 58 हजार हितग्राहियों को साईकिल वितरण किया गया, उसके लिए 66 करोड़ रूपये का प्रावधान था, यह व्यय हुआ और वर्ष 2023-24 के बजट में इसमें 73 करोड़ 40 लाख रूपये की व्यवस्था है। माननीय नेता जी, अब आपने कविता के माध्यम से समाप्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक कविता बोल देता हूँ:-

अध्यक्ष महोदय :- आपको कुछ न कुछ तो सुनना पड़ेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

"अभी तो वक्त को संवारने में लगा हूँ।।

वक्त मिले तो तुम्हारी जुल्फे भी सवारूंगा। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो जुल्फे संवार चुके हों।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 15 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(9 बजकर 7 मिनट पर विधान सभा बुधवार दिनांक 15 मार्च, 2023) (फाल्गुन 24, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 14 मार्च, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं